राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक: 08] पन्द्रहवीं विधान सभा के आठवें सत्र का बाईसवां दिवस [संख्या: 07

सोमवार,

13 फरवरी 2023

(राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे
राजस्थान विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।)

(श्री सी.पी. जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

बधाई एवं आभार

गुलाब चन्द कटारिया, श्री, नेता प्रतिपक्ष के राज्यपाल पद पर मनोनयन पर बधाई

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, विधान सभा अध्यक्ष के रूप में मुझे आप सबको यह सूचित करते हुए बहुत प्रसन्नता है कि विधान सभा के प्रतिपक्ष के नेता माननीय गुलाब चन्द जी कटारिया को राज्यपाल मनोनीत किया। मैं सदन की तरफ से, अपनी तरफ से और राजस्थान की समस्त जनता की तरफ से शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि माननीय कटारिया जी अपनी संवैधानिक मर्यादा को उन्हीं गौरवपूर्ण परम्पराओं से निर्वहन करेंगे जैसा एक जन-प्रतिनिधि के रूप में अभी तक निर्वहन करते रहे हैं।

माननीय कटारिया जी का स्वागत, जब वह गर्वनर ज्वाइन करके आ जाएंगे तब सदन में हम इनका स्वागत करेंगे। मैं अपने आपको गौरवान्वित इसलिए अनुभव करता हूं कि शायद मैं विरला ही विधान सभा का अध्यक्ष होऊंगा, जब विधान सभा चल रही हो और विधान सभा के सदस्य, प्रतिपक्ष के नेता को राज्यपाल मनोनीत करने का अवसर मिला, उनका स्वागत करने का मुझे अवसर मिला। मैं अपने आपको बहुत गौरवान्वित अनुभव करता हूं। विशेष तौर पर इसीलिए कि मुझे राजेन्द्र जी ने कहा कि आपको यह भी कहना है कि कटारिया जी और हम एक ही महाविद्यालय में पढ़े हैं और कटारिया जी मेरे निर्वाचन क्षेत्र के गांव देलवाड़ा से जहां हमारे पिताजी अध्यापक के रूप में थे, वहां पर उन्होंने अपना जीवन प्रारम्भ किया। इसलिए मुझे बहुत प्रसन्नता है कि यह अवसर मुझे मिला। मैं व्यक्तिगत तौर पर भी आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएं देता हूं और आशा करते हैं कि हम सब सदन में इसी तरह से अपने सदस्यों को गौरवान्वित होकर, हम सबको आप दोबारा एक राज्यपाल के रूप में स्वागत करने का अवसर देंगे।

श्री रघु शर्मा (केकड़ी): अध्यक्ष महोदय, पढ़ने में दोनों में से होशियार कौन था, यह नहीं बताया?

श्री अध्यक्ष: वह जब राज्यपाल महोदय बनकर आएंगे, तब मैं जवाब दूंगा।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, वैसे प्रश्न काल के अंदर समय लेना तो उचित नहीं है, परंतु आपने और सदन के सभी माननीय सदस्यों ने मेरी इस नियुक्ति पर जो बधाई दी, मैं अपनी ओर से सदन के सभी माननीय सदस्यों का बहुत आभारी हूं और आप सबको, राजस्थान की जनता को विश्वास दिलाता हूं कि राजस्थान के प्रतिनिधि के रूप में जो संवैधानिक मर्यादाएं हैं, उनमें रहते हुए मैं अपने काम को अंजाम देने का प्रयास करूंगा और आप सबका सम्मान बना रहे, यह प्रतिक्षण मैं अपने जीवन में उसका पालन करूंगा। आप सबका बहुत-बहुत आभार।

तारांकित प्रश्नोत्तर

प्रश्न संख्या 111

श्री अध्यक्ष: प्रश्न काल। डा. राजकुमार शर्मा।

(अनुपस्थित। कृपया आगे देखें।)

अगला प्रश्न। श्री बाबुलाल।

जनजाति उपयोजना क्षेत्र में खाद का वितरण

112. श्री बाबुलाल (झाडोल): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि जनजाति उपयोजना क्षेत्र में किसानों को खाद की कमी के कारण महंगा खाद लेना पड़ रहा है? यदि हां, तो उक्त की कमी के क्या कारण रहे? विवरण सदन की मेज पर रखें?

कृषि मंत्री (श्री लालचन्द कटारिया): जी नहीं। जनजाति उपयोजना क्षेत्र में मांग के अनुसार निर्धारित मूल्य पर उर्वरक उपलब्ध हो रहे हैं।

श्री बाबुलाल (झाडोल): अध्यक्ष महोदय जी, माननीय मंत्री जी विद्वान हैं और मैं उन पर ज्यादा विश्वास भी करता हूं कि कभी-कभी अपनी बात को स्वीकार भी करते हैं, सकारात्मक जवाब भी देते हैं, लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि आपके उत्तर में जनजाति उपयोजना क्षेत्र में मांग के अनुसार निर्धारित मूल्य पर उर्वरक उपलब्ध हो रहे हैं। उपलब्ध थी तो मंत्री जी यह

(श्री बाबुलाल)

बताने की कृपा करेंगे कि लम्बी-लम्बी लाइनें और पुलिस के सुरक्षा घेरे में और कहीं-कहीं तो आपको हल्का बल प्रयोग भी करना पड़ा, क्या कारण से? आप बताने की कृपा करें।

दूसरा सवाल मेरा यह है कि जब आपके पास उपलब्धता भी थी, बांट रहे थे तो ये लोग शौक से जाकर के काले बाजार से 500 से 600 रुपये में कट्टा लाते थे? यह बताने की कृपा करें।

श्री लालचन्द कटारिया (कृषि मंत्री): अध्यक्ष महोदय, जनजाति उपयोजना क्षेत्र में जो गत वर्ष 2022-23 का आपने पूछा है, उसमें सितम्बर व अक्टूबर माह के द्वितीय सप्ताह में बारिश समय से पहले हो गयी। स्टाक हमारे पास था, परंतु चूंकि पूरे प्रदेश के अन्दर बारिश बिजाई से पहले होने के कारण, क्योंकि ज्यादातर नवम्बर का टारगेट लेकर चलते हैं, परंतु सितम्बर व अक्टूबर माह के द्वितीय सप्ताह में अच्छी वर्षा होने व जलाशयों में पानी की पर्याप्त उपलब्धता के कारण रबी 2022-23 में अग्रिम बुवाई हुई। जहां नवम्बर, 2021 में 8 लाख 73 हजार हैक्टेयर में ही बुवाई हुई थी, उपयोजना क्षेत्र की बता रहा हूं, नवम्बर, 2022 तक 10 लाख 40 हजार हैक्टेयर में रबी फसलों की बुवाई हुई, जो कि गत वर्ष की तुलना में 1 लाख 67 हजार हैक्टेयर यानी की 19 प्रतिशत अधिक हुई। यह जो माहौल ऐसा बना कि अचानक लोगों की डिमांड बढ़ी, पूरे एरिये में बिजाई के कारण, स्टाक हमारे पास था। भारत सरकार भी जो नवम्बर में हमारे को खाद उपलब्ध कराती है, उसे भी, एक महीने पहले बुवाई होने के कारण हमने भारत सरकार को भी लिखा और भारत सरकार ने भी हमको एक्स्ट्रा ट्रेनें भी दीं और हमारा मार्ग भी प्रशस्त किया, किसी भी प्रकार की कोई, एक माहौल ऐसा जरूर बना उस समय में कि पूरा प्रेशर बनाया कि खाद नहीं मिल रहा, खाद नहीं मिल रहा।

श्री बाबुलाल (झाडोल): माननीय अध्यक्ष महोदय जी, माननीय मंत्री महोदय ने बताया कि बारिश होने की वजह से ज्यादा खेती बोने के कारण यह कमी आयी। आप ये भी तो बताएं कि पहले की एवज में कितने हैक्टेयर ज्यादा अपने बुवाई हुई थी, जिसके कारण से आपको यह परेशानी का सामना करना पड़ा?

श्री लालचन्द कटारिया (कृषि मंत्री): 1 लाख 67 हजार हैक्टेयर में बुवाई अधिक हुई, 8 जिलों के अन्दर।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री प्रताप सिंह।

परवन परियोजना डूब क्षेत्र के किसानों को मुआवजा

113. श्री प्रताप सिंह (छबड़ा): क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या परवन परियोजना के डूब क्षेत्र में तहसील छीपाबड़ौद के प्रभावितों को मुआवजा दे दिया गया है? यदि हां, तो किन-किन को, कितना-कितना मुआवजा दिया गया व किन-किनको कितना-कितना मुआवजा दिया जाना शेष है? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त परियोजना के डूब क्षेत्र के प्रभावितों हेतु पुनर्वास योजना बनाई गई है? यदि हां, तो कहां-कहां पर किन-किन का पुनर्वास किया गया है? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

जल संसाधन मंत्री (श्री महेन्द्रजीत सिंह मालविया): (1) परवन सिंचाई परियोजना के कारण छीपाबड़ौद तहसील के 7 ग्राम पूर्ण डूब क्षेत्र में तथा 9 आंशिक डूब क्षेत्र में प्रभावित हैं। इन ग्रामों के प्रभावित कृषकों की भूमि के मुआवजे की स्थिति का विवरण परिशिष्ट 'अ' पर, पूर्ण डूब प्रभावित आबादी क्षेत्र के मकानों के मुआवजे का विवरण परिशिष्ट 'ब', विस्थापितों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन हेतु अवार्ड का विवरण परिशिष्ट 'स' पर तथा आंशिक डूब प्रभावित क्षेत्र के विस्थापितों के लिए पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन अवार्ड का विवरण परिशिष्ट 'द' पर संलग्न है।

(2) जी हां। उक्त परियोजना में डूब क्षेत्र प्रभावितों के लिए ग्राम छत्रपुरा, तहसील अटरू में पुनर्वास हेतु योजना पर कार्यवाही प्रगतिरत है। विवरण परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

श्री प्रताप सिंह (छबड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि डूब क्षेत्र में आने वाले किसानों को मुआवजा 2012 की डीएलसी की दर पर 2017 में दिया गया है, जो बहुत ही कम है। मुआवजा राशि वर्ष 2017 की डीएलसी दर से दी जानी चाहिए थी और इसी प्रकार पुनर्वास हेतु राशि 2018 की डीएलसी दर से 2022 में दी गयी है, जो 2022 की दर से दी जानी चाहिए थी। मात्र 5 लाख 46 हजार...

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्रश्न पूछिए।

श्री प्रताप सिंह (छबड़ा): इसी प्रकार से पुनर्वास 2022 की डीएलसी रेट से मुआवजा वर्ष 2014 के मकानों का मुआवजा, 2014 की डीएलसी की दर के

(श्री प्रताप सिंह)

अनुसार 2023 में दिया गया है। क्या यह इतने लम्बे समय बाद किसानों को मुआवजा दिया जाना, आज की तारीख में 2014 की डीएलसी रेट से मुआवजा दे रहे हैं, क्या यह उचित है? नंबर एक और दूसरा, मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि विस्थापित होने वाले कुछ परिवारों को पात्रता के दस्तावेज होने के बावजूद मुआवजे की राशि से वंचित किया गया है, ऐसे परिवारों को पुन: निष्पक्ष जांच कराकर मुआवजा राशि दी जाए। दो पूछ लिए, फिर तीसरा पूछ लूंगा।

श्री अध्यक्ष: दो ही अलाउ हैं। बैठिए आप।

श्री महेन्द्रजीत सिंह मालविया (जल संसाधन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, धारा 11 राज्य सरकार की आज्ञा संख्या 5, 12/2022 के प्रकाशित जिस दिन से होता है उसी दिन से मुआवजा दिए जाने का प्रावधान है। शेष रहे किसानों का हमने एग्जामिन करा लिया है और बहुत जल्दी उनको मुआवजा दे दिया जाएगा।

श्री प्रताप सिंह (छबड़ा): मेरा आपसे सीधा-सीधा प्रश्न है माननीय अध्यक्ष महोदय के माध्यम से कि 2014 में आपने मुआवजा डीएलसी रेट पर तय किया और उसको 2023 में दे रहे हैं तो ये किसान के साथ तो अन्याय ही है। आप उसको मुआवजा आज की रेट में दीजिए या एक्सग्रेसिया के तहत उनको कुछ इंसेंटिव दीजिए कि उनकी भरपाई हो सके। जहां तक राजस्थान में नीति के अनुसार, एक नीति है मुआवजे की, झालावाड़ में अलग रेट पर मुआवजा दिया गया, छीपाबड़ौद में अलग रेट से मुआवजा दिया गया, इसका क्या कारण है?

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, क्वेश्चन नहीं पूछना आपको, एक्सप्लेन करना है? माननीय मंत्री जी, मैं ही पूछ लेता हूं, आप बैठो। सीधा प्रश्न यह है कि जब एक एक्विजिशन करते हैं लैंड और डिस्बर्समेंट, इसके बीच बहुत गैप है। किसान को यदि समय पर पैसा मिल जाता है तो उसको रिलीफ मिलती है। उस समय की जो रेट होती है, सपोज 2012 की रेट थी, पेमेंट हो रहा है 2022 में, 10 साल के करीब गैप हो जाता है, तो क्या सरकार इस तरह की नीति बनाएगी, जब आप एक्विजिशन करो उसके सर्टेन पीरियड में उसको पैसा मिल जाए? माननीय मंत्री जी।

श्री महेन्द्रजीत सिंह मालविया (जल संसाधन मंत्री): माननीय अध्यक्ष

(श्री महेन्द्रजीत सिंह मालविया)

महोदय, आपने मुझे या पूरे सदन को निर्देश दिया है, मैं विभाग से पुन: इसका एक बार पूरा एग्जामिन करा लूंगा। अगर हम कर सकते होंगे तो सहानुभूतिपूर्वक विचार करके करेंगे।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न।

श्री प्रताप सिंह (छबड़ा): अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्लीज। I will not allow it. प्लीज नीचे बैठें। I will not allow it. अगला प्रश्न। श्रीमती कल्पना देवी।

लाडपुरा में बहुमंजिला इमारतों में पेयजल की आपूर्ति

114. श्रीमती कल्पना देवी (लाडपुरा): क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा बहुमंजिला इमारतों का अनुमोदन करते समय बाहय विकास शुल्क वसूल किया जाता है? यदि हां, तो कितना व उक्त शुल्क से क्या-क्या कार्य करवाये जाते हैं? नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि विधान सभा क्षेत्र लाडपुरा में बहुमंजिला इमारतों में पेयजल पाइपलाइन नहीं होने के कारण उक्त इमारतों के निवासियों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है? यदि हां, तो सरकार की उक्त को पेयजल आपूर्ति हेतु क्या कार्ययोजना है? विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री (डा. महेश जोशी): (1) नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग द्वारा बहुमंजिला इमारतों के भवन मानचित्र अनुमोदन करते समय बाहय विकास शुल्क (ई.डी.सी.) वसूल किये जाने का प्रावधान नहीं है, किन्तु योजना अनुमोदन/एकल पट्टा जारी किये जाने के समय राजस्थान टाउनशिप पालिसी-2010 (10 हैक्टेयर से अधिक के बिन्दु संख्या 8.00 (4)/10 हैक्टेयर तक की योजनाओं के बिन्दु संख्या 10.00 (4)) के अनुसार सेक्टर रोड, नाले का निर्माण, रोड लाइटिंग, वृक्षारोपण आदि कार्ययोजना की परिधि में किये जाने हेतु संबंधित शहर की आबादी के अनुसार बाहय विकास शुल्क (ई.डी.सी.) वसूल किये जाने का प्रावधान है। (परिशिष्ट-अ)

(2) नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग के आदेश दिनांक 11.05.2011 व 10.08.2017 के द्वारा बाहय विकास शुल्क (ई.डी.सी.)

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

की राशि 4 समान किस्तों में भी जमा कराये जाने का प्रावधान किया गया है। (परिशिष्ट-ब)

विधान सभा क्षेत्र लाडपुरा के शहरी क्षेत्र की जिन कालोनियों में पेयजल वितरण तंत्र विद्यमान है उनमें निर्मित बहुमंजिला इमारतों में पेयजल आपूर्ति अन्तर्गत विकासकर्ता/सोसायटी द्वारा जल सम्बन्ध हेतु की गई मांग एवं तकनीकी उपादेयता के आधार पर विभागीय परिपत्र दिनांक 23.03.2012 में जारी दिशा-निर्देशानुसार जल सम्बन्ध जारी किये जा रहे हैं। (परिशिष्ट-स)

जिन क्षेत्रों में विभागीय वितरण प्रणाली विकसित नहीं है उन क्षेत्रों में पेयजल वितरण तंत्र अमृत-2.0 योजनान्तर्गत विकसित किया जाना प्रस्तावित है। विधान सभा क्षेत्र लाडपुरा के शहरी क्षेत्रों को सम्मिलित करते हुए कोटा नगर निगम उत्तर व कोटा नगर निगम दक्षिण हेतु अमृत-2.0 योजना के तहत क्रमशः राशि रुपये 175.00 करोड़ व 220.00 करोड़ राज्य स्तरीय उच्चाधिकार प्राप्त समिति की अभिशंसा पर आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार की अमृत योजना की एपेक्स कमेटी की बैठक दिनांक 04.01.2023 द्वारा अनुमोदन किया जा चुका है। नगर विकास न्यास कोटा द्वारा उक्त स्वीकृति के अन्तर्गत डी.पी.आर. में योजना क्षेत्र का निर्धारण कर पेयजल कार्य नगर विकास न्यास, कोटा द्वारा करवाये जायेंगे। (परिशिष्ट-द)

विभाग द्वारा प्रदेश के सभी शहरी क्षेत्रों में बहुमंजिला इमारतों में जल सम्बन्ध जारी करने हेतु पूर्व में जारी नीतियों में आवश्यक संशोधन तथा एक व्यापक एवं प्रभावी नीति तैयार करने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा कमेटी का गठन किया जाकर, समस्त हितधारकों से चर्चा उपरान्त सभी पक्षों के हित में सामंजस्य रखते हुए नवीन पालिसी का तैयार किया गया प्रारूप (ड्राफ्ट) अनुमोदन हेतु प्रक्रियाधीन है।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके आगे भी मैं जानकारी देना चाहता हूं। जब हमने जवाब दिया, उसके बाद का डवलपमेंट है कि माननीय मुख्य मंत्री महोदय द्वारा दिनांक 10.02.2023 को सदन में पेश बजट 2023 में शहरी क्षेत्रों में बहुमंजिला इमारतों में पेयजल कनेक्शन दिया जाना हमको उन्होंने अनुमत कर दिया है। बजट पारित उपरान्त नवीन पालिसी को अनुमोदन करवा कर शीघ्र लागू किया जाएगा।

श्रीमती कल्पना देवी (लाडपुरा): माननीय अध्यक्ष जी, आपकी अनुमति से मैं मंत्री जी से पूछना चाहती हूं कि प्रश्न के खण्ड-1 के उत्तर में आपने कहा है कि ई.डी.सी. की राशि को आप 4 समान किस्तों में लेते हैं। मेरा आपसे निवेदन है, आप मुझे बताएं कि इस राशि में से आपने कितनी राशि को पेयजल व्यवस्था के लिए पीएचईडी को ट्रांसफर किया है?

दूसरा प्रश्न है, खण्ड-2 के उत्तर में आपने बताया है कि अमृत-2.0 के तहत कार्य कराये जाने का उल्लेख। इसमें मैं आपसे पूछना चाहती हूं, आपने कहा है कोटा उत्तर में 175 करोड़ एवं कोटा दक्षिण में 220 करोड़ के प्रोजेक्ट हैं, मेरा मूल प्रश्न है कि इसमें से कितनी राशि लाडपुरा में खर्च करने का आपका प्रोजेक्ट है? यह बताएं।

तीसरा प्रश्न, आपने परिशिष्ट-ख में पाइंट-5 में लिखा है - "PHED shall only be responsible for providing water supply to under ground tank of the building premises." ऐसी कई मल्टीस्टोरी बिल्डिंग हैं, मेरे ख्याल से दस साल से ज्यादा हो गए हैं जो यू.आई.टी. द्वारा ही बनाई गई हैं, परन्तु आज भी वहां पानी का प्रावधान नहीं किया गया है। केवल आधा घंटा पानी आता है या हम टैंकर्स से पानी पहुंचाते हैं। अगर पानी के लिए पीएचईडी रिस्पांसिबल है तो आपने इस अमृत योजना में यू.आई.टी. को कार्य एजेंसी क्यों बनाया है, पीएचईडी को क्यों नहीं बनाया कि वह इस पानी की व्यवस्था करे? धन्यवाद।

डा. महेश जोशी (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रारम्भिक बात तो यह है जो एक्सटर्नल डवलपमेंट चार्जेज की बात माननीय सदस्या ने कही है, इसका हमने जरूर जवाब दिया है, पर यह हमारे विभाग के अंतर्गत नहीं आती। हमने यूडीएच से मांग कर यह जवाब दिया है। यह एक्सक्लूसिव यूडीएच का मैटर है। आपने दूसरी बात कही, उसका मैं बाद में जवाब दूंगा।

तीसरी बात आपने कही कि हम नीचे टैंक तक कनेक्शन देते हैं, वह हमारी पालिसी है कि जो निर्माणकर्ता है वह एप्लाई करता है, जो वर्तमान पालिसी लागू है और आगे भी पालिसी में, यह सारी बिल्डर्स से और स्टेक होल्डर्स से बात हुई है। कनेक्शन एक ही मांग के अनुरूप दिया जाएगा। आधा इंच की मांग है, एक इंच की मांग है, दो इंच की है, तीन इंच की है। कनेक्शन एक दिया जाएगा नीचे। ऊपर का सारा तंत्र है वितरण प्रणाली का, वह निर्माण का तंत्र प्रमोटर को ही विकसित करना होता है। यह सिस्टम आफ पालिसी है।

(डा. महेश जोशी)

आपने लाडपुरा के बारे में पूछा, लाडपुरा में कितना पैसा सैंक्शन हो रहा है तो अभी यह जो रिपोर्ट है, यह प्रारम्भिक तौर पर गवर्नमेंट आफ इंडिया की कमेटी है, उसने मंजूर की है। स्टेट लेवल पर इसकी डिटेल डी.पी.आर. बनेगी। कितना पैसा, कितनी मांग है, उस हिसाब से इसका सारा तय किया जाएगा। आपने लाडपुरा के बारे में जानना चाहा, तो लाडपुरा के कोटा शहरी, कुल 30 वार्ड जिसमें नगर निगम कोटा उत्तर के 14 वार्ड, वार्ड संख्या 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 38, 39, 40, 41, 43 तथा नगर निगम कोटा दक्षिण के कुल 16 वार्ड 9, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 38, 42, 43, 44, 45, 58, 59 सम्मिलित हैं।

लाडपुरा विधान सभा के कोटा शहरी क्षेत्र में प्राथमिक सर्वे के अनुसार, मैं आपको वर्तमान की स्थिति भी बता देता हूं, 47 बहुमंजिला इमारतें स्थित हैं, उन 47 में से 6 बहुमंजिला इमारतों में पेयजल आपूर्ति की जा रही है। सोसायटी द्वारा जो मांग तकनीकी आधार पर, उपादेयता के आधार पर तय किया जाता है, 35 ऐसी इमारतें हैं जिसमें वितरण प्रणाली हमारी पीएचईडी की नहीं है और 6 इमारतों में अभी उन्होंने कोई आवेदन नहीं किया है।

हमने दो में, कोटा शहर के वह क्षेत्र जहां विभागीय पेयजल वितरण तंत्र विद्यमान नहीं है, इन सभी क्षेत्रों को पेयजल व्यवस्था हेतु दो के अन्तर्गत, कोटा शहर नगर निगम उत्तर एवं नगर निगम दक्षिण के समेकित प्रस्ताव हैं, 175 करोड़ व 220 करोड़ के।

लाडपुरा विधान सभा क्षेत्र में बजरंग नगर, बोर खेडा, नया नोरा, धाकड खेडी, उम्मेदगंज, रायपुरा, कैथून रोड पर विकसित नये क्षेत्रों में उच्च जलाशयों का निर्माण कर एवं नई डीआई पाइप लाइन डालकर पर्याप्त मात्रा एवं जल दबाव से पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित कराई जानी प्रस्तावित है। कितना बजट लगेगा, यह पूरी डी.पी.आर. बनेगी, उसके बाद में यह तय होगा।

श्रीमती कल्पना देवी (लाडपुरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं दुबारा से यह पूछना चाहती हूं कि ये यह कह रहे हैं कि सात ऐसी जगह है जहां पर पी.एच.ई.डी. द्वारा पानी दिया जा रहा है। मैं आपको यह कहना चाहती हूं, प्रेम नगर हो, चंद्र शेखर अफोर्डेबल हो या कंसुआ अफोर्डेबल हो, यह यू.आई.टी. द्वारा बनाई गयी मल्टीस्टोरीड बिल्डिंग्स हैं, मैं सिर्फ इनके बारे में पूछना चाहती हूं। आप वहां पर केवल बीस मिनट या तीस मिनट ही पानी दे रहे हैं और प्रेम नगर में तो कभी-कभी तो तीन-दिन तक पानी नहीं देते हैं, तो आप यह कैसे कह रहे हैं कि इनमें तो हम पानी दे रहे हैं?

डा. महेश जोशी (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, चाहे यू.आई.टी. कालोनी बनाये, डवलप करे या चाहे निजी क्षेत्र में हो, हमारा जो सिस्टम है वह नीचे तक एक कनेक्शन देने का है और यू.आई.टी. ही क्यों काम कर रही है, क्योंकि यह जो पूरी अमृत योजना है, यह पूरी की पूरी शहरी विकास जो मंत्रालय है गवर्नमेंट आफ इंडिया का, उसके द्वारा बनायी गयी यह नीति है तो उनके हिसाब से ही यह तय होता है कि किसको इम्प्लीमेंट करना है। यू.आई.टी. की जिन बिल्डिंग्स में हम पानी दे पा रहे हैं या नहीं दे पा रहे हैं, वह वितरण तंत्र हमारा जहां-जहां है, वहां-वहां तो हम दे पा रहे हैं और जहां पर नहीं है, वहां पर हम डवलप कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी।

प्रदेश में पंजीकृत संस्थाएं

115. श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) राजस्थान संस्था पंजीकरण अधिनियम 1958 के अंतर्गत कितनी संस्थाएं पंजीकृत हैं? जिलेवार संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) जिलेवार पंजीकृत कितनी संस्थाओं की सूचनाएं एवं प्रविष्टियां विभाग के पोर्टल पर ऑनलाइन नहीं हैं? उक्त को पोर्टल पर करने के लिए सरकार ने अब तक क्या प्रयास किये व उनके क्या परिणाम रहे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि पूर्व में पंजीकृत संस्थाओं से उनकी प्रोफाइलिंग विभागीय पोर्टल में करने के समय कई ऐसी सूचनाएं पोर्टल पर मांगी जा रही हैं, जो संस्था अधिनियम, 1958 के प्रावधानों के अनुसार आवश्यक नहीं हैं? यदि हां, तो सरकार उक्त विसंगति को दूर करने के लिए क्या प्रयास कर रही है?

सहकारिता मंत्री (श्री अंजना उदयलाल): (1) राजस्थान संस्था पंजीकरण अधिनियम, 1958 के अंतर्गत राजस्थान में कुल 2,59,582 संस्थाएं पंजीकृत हैं। जिलेवार संख्यात्मक विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) कुल 1,35,664 पंजीकृत संस्थाओं की सूचनाएं एवं प्रविष्टियां विभागीय पोर्टल पर ऑनलाइन नहीं हैं। जिलेवार सूचना परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(सहकारिता मंत्री)

पूर्व में पंजीकृत संस्थाओं की सूचनाएं एवं प्रविष्टियां पोर्टल पर ऑनलाइन करने हेतु सरकार के स्तर पर निम्न प्रयास किये गये हैं-

1. सहकारिता विभाग द्वारा दिनांक 18.11.2019 को इस सम्बन्ध में विस्तृत निर्देश जारी किये गये। (परिशिष्ट-3 पर संलग्न है।)
2. दिनांक 12-11-2019 को राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, दैनिक नवज्योति, समाचार जगत एवं राष्ट्रदूत समाचार पत्रों के माध्यम से संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 के अंतर्गत पंजीकृत संस्थाओं को 31 दिसम्बर, 2019 तक जानकारियां अपलोड करने हेतु सूचित किया गया था।
3. विभाग द्वारा दिनांक 29.09.2022 को विभागीय पोर्टल पर प्रोफाइलिंग के क्रम में आने वाली समस्याओं के निदान हेतु आदेश जारी किये गये। (परिशिष्ट-4 पर संलग्न है।)

विभाग द्वारा शेष पंजीकृत संस्थाओं की सूचनाएं विभागीय पोर्टल पर अपलोड कराये जाने के प्रयास किये जा रहे हैं किन्तु अधिनियमानुसार संस्थाओं को बाध्य नहीं किया जा सकता है।

(3) जी नहीं। राजस्थान सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 की धारा 4 एवं 4(क) के अनुसार ही ई-प्रोफाइलिंग के लिए सूचनाएं मांगी जा रही हैं।

(विवरण एवं सूचना पुस्तकालय में रखे गये।)

श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं सबसे पहले तो यह जानकारी चाहूंगी कि अभी तक भी 1,35,664 पंजीकृत संस्थाएं ऑनलाइन नहीं हैं, इनको ऑनलाइन करने के लिए आपने यह कहा है कि इनको हम बाध्य नहीं कर सकते, यह मैं समझती हूं पर क्या सरकार द्वारा ऐसा कुछ ईजी प्रोसेस हम अपना रहे हैं जिससे यह ऑनलाइन हो जाये क्योंकि 2019 में आपने प्रयास किया, फिर 2022 में कहा। चार साल हो गये और आज तक भी अगर हम ऑनलाइन ई-प्रोफाइलिंग के द्वारा नहीं कर रहे हैं तो क्या हम ऐसे स्टेप्स उठा रहे हैं जिसकी वजह से हम इसको ऑनलाइन कर सकें?

माननीय अध्यक्ष महोदय, दूसरी बात मैं यह कहना चाहूंगी कि प्रश्न के खण्ड तीन का जो उत्तर दिया गया है वह बिलकुल तथ्यों के अकोर्डिंग नहीं है। उसमें यह कहा गया है कि सेक्शन 4 और 4(क) में ऐसा कुछ भी हम नहीं

(श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी)

मांग रहे हैं एक्स्ट्रा जो पहले ई-प्रोफाइलिंग सिस्टम के पहले नहीं मांगते थे। इसके अन्दर आप अगर देखेंगे तो बहुत क्लीयरली यह नियम मांगे जाते हैं। उसमें यह कहा गया है कि वार्षिक सूची जो अपलोड करनी होती है, उसके साथ बोर्ड मीटिंग का प्रस्ताव, बोर्ड मीटिंग के मिनट्स और उपस्थिति सूची, वार्षिक सभा का नोटिस एवं उसका डिलीवरी प्रूफ, वार्षिक सभा की मिनट्स एवं उपस्थिति सूची, यह सारी चीजें मांगी जा रही हैं जबकि जब यह ऑनलाइन नहीं था प्रोसेस, तब यह नहीं मांगी जाती थी, तो मैं आपसे यही निवेदन करूंगी कि अगर आप इस प्रोसेस को थोड़ा ईजी करेंगे, यह सारी चीजें एक्स्ट्रा नहीं मांगेंगे तो कहीं न कहीं सोसायटीज ईजीली ऑनलाइन एनुअल रिपोर्ट्स अपलोड कर पायेंगी क्योंकि आज भी एनुअल रिपोर्ट, सोसायटीज में क्या काम हो रहा है, क्या काम नहीं हो रहा है वह आल ओवर राजस्थान उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं।

श्री अंजना उदयलाल (सहकारिता मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या ने जो बात उठायी है, केवल इसके अन्दर जो सूचनाएं मांगी जाती हैं, यह चार सूचनाएं हैं, इसके अलावा और कोई ज्यादा सूचना नहीं मांगी जा रही है और चार सूचनाएं तो नियमानुसार देनी पड़ती हैं, जब ही यह अपलोड होगा। इसको और ज्यादा साफ-सुथरा करने के लिए नया अधिनियम ला रहे हैं, जिसमें संशोधन करके संस्था को यह बाध्य किया जायेगा कि आपको अपनी प्रोफाइलिंग, हर साल मीटिंग करने के बाद अपलोड करनी है क्योंकि यह अधिनियम 1958 में बना था, अब तक वैसे ही चल रहा था इसलिए हमारा दबाव नहीं है, इसलिए वे सही सूचनाएं नहीं देते हैं।

सूचनाएं तो केवल चार मांगी हैं जो 1958 अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत संस्थाओं को प्रतिवर्ष साधारण सभा की बैठक आहूत किये जाने के उपरांत 14 दिन की अवधि में उनका कार्यवाही विवरण रजिस्ट्रार को प्रस्तुत किया जायेगा, तो यह तो सभी रूटीन की बातें हैं लेकिन ऐसी संस्थाओं के द्वारा एक बार रजिस्ट्रेशन करवाकर, वे वापस नाम ही नहीं लेती हैं तो उनके लिए कानून में यह संशोधन करके उनको बाध्य किया जायेगा कि आप अपनी सब सूचनाएं दें ताकि पारदर्शिता आ सके।

श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह बोलना चाह रही हूं कि इसके अन्दर गवर्निंग बोर्ड की सूची भी मांगी जा रही है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्या, जब अगले अमेंडमेंट में ये सब चीजें आ जायेंगी तो फिर यह रेलेवेंट ही नहीं है। अगला प्रश्न। श्री रामलाल शर्मा।

चौमूं में खाद्य सुरक्षा के लम्बित आवेदन पत्र

116. श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा विगत तीन वर्षों में दस लाख को खाद्य सुरक्षा सूची में जोड़ने की घोषणा की गई थी? यदि हां, तो अब तक कितने नाम जोड़े गए? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त घोषणा की क्रियान्विति में जयपुर में एक भी नाम नहीं जोड़ा गया है? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि जिला जयपुर में खाद्य सुरक्षा सूची में नाम जोड़ने के लिए अब भी सम्बन्धित उपखण्ड अधिकारी के पास आवेदन लम्बित हैं? यदि हां, तो विधान सभा क्षेत्र चौमूं में उक्त के कितने आवेदन अब तक लम्बित हैं? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री (श्री प्रताप सिंह खाचरियावास): (1) बजट घोषणा वर्ष 2022-23 में दस लाख परिवारों के नाम खाद्य सुरक्षा सूची में जोड़ने की घोषणा की गई थी।

प्रदेश में दिनांक 08.02.2023 तक कुल 14,76,456 (चौदह लाख छिहत्तर हजार चार सौ छप्पन) नाम जोड़े गये हैं।

(2) जी नहीं। उक्त घोषणा की क्रियान्विति में जिला जयपुर में नाम जोड़े गये हैं।

(3) जी हां। विधान सभा क्षेत्र चौमूं में खाद्य सुरक्षा सूची में नाम जोड़ने के लिए 6,644 आवेदन लम्बित हैं।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि आपने खण्ड 3 के अन्दर यह स्वीकार किया है कि 6,644 प्रकरण अभी भी लम्बित हैं तो एक तो यह 6,644 आवेदन जो लम्बित हैं इनका नाम आप कब तक जोड़ देंगे? नम्बर एक।

नम्बर दो, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह भी जानना चाहूंगा कि एसडी.एम. के द्वारा नाम जोड़ने के उपरांत भी कई महीनों तक आपके स्टेट पोर्टल के ऊपर ऑनलाइन नहीं होने की

(श्री रामलाल शर्मा)

वजह से उनको खाद्य सुरक्षा का लाभ नहीं मिल पा रहा है तो इसमें भी आप कोई समय सीमा निर्धारित करने का विचार रखते हैं कि एस.डी.एम. के द्वारा नाम जोड़ने के इतने दिन बाद में आपको खाद्य सुरक्षा का लाभ मिल जायेगा?

नम्बर तीन, आपातकाल के अन्दर अगर पात्र व्यक्ति को यह सूचना मिलती है कि आप असाध्य रोग से ग्रसित हैं और आपका ऑनलाइन पोर्टल कभी चलता है और कभी नहीं चलता है, तो क्या आप पात्र व्यक्ति की आपातकालीन असाध्य रोग से ग्रसित व्यक्ति का तत्काल नाम जोड़ने के लिए निर्देश प्रदान करोगे? क्योंकि उनकी असाध्य बीमारी का इलाज करवाना है।

चिरंजीवी योजना में 850 रुपये जमा करवाने के उपरांत भी तीन महीने तक उसको वेटिंग करनी पड़ती है तो क्या आप सरकार के द्वारा ऐसा निर्देश प्रदान करेंगे कि यदि कोई परिवार असाध्य रोग से ग्रसित है तो तत्काल उसका एस.डी.एम. नाम जोड़कर उस योजना का लाभ दिया जा सके?

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो असाध्य रोग की बात कही गयी है, पहले से इस तरह के यह आदेश जारी हैं। कहीं पर ऐसा कोई आपको लगता है कि ऐसे एस.डी.एम. वगैरह कौन नहीं जोड़ रहे हैं, नाम तो तुरंत जोड़ा जाता है और यह प्रावधान इसमें है। पोर्टल में, यह जो घोषणा की गयी बजट घोषणा में, बजट घोषणा जो की गयी है, वह लागू हो गयी है और अब शुरू कर दिया गया है और लोगों को गेहूं मिलना भी शुरू हो गया है।

आपके जो आवेदन लम्बित हैं, उसके अलावा लोगों को चौमूं में भी गेहूं मिलने लगा है, पूरे राजस्थान में मिलने लगा है। प्रक्रिया चल रही है, कोशिश यह कर रहे हैं कि 22 तारीख तक यह पूरा काम कर लिया जायेगा।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन सिर्फ इतना ही था, क्योंकि इनका ऑनलाइन पोर्टल बंद होने की वजह से एस.डी.एम. यह कहता है कि, साहब, पोर्टल ऑनलाइन नहीं है और आपको ऑनलाइन ही आवेदन करना पड़ेगा, तो मैं तो सिर्फ यह चाहता हूं कि असाध्य रोग के अन्दर कोई गम्भीर बीमारी से ग्रसित है तो तत्काल उसका नाम जोड़ा जाये।

श्री प्रताप सिंह (छबड़ा): उनका नाम जोड़ा जाये।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्लीज। क्या आपको प्राब्लम है क्या? ये प्रश्न पूछ रहे हैं और आप खड़े हो रहे हैं। माननीय मंत्रीजी।

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): देखिये, ये असाध्य रोग की बात कह रहे हैं। यह सारी प्रक्रिया ऑनलाइन है, लेकिन असाध्य रोग की कहीं पर बात आयेगी तो इस तरह के निर्देश जारी कर दिये जायेंगे। यदि कहीं सूचना है, शिकायत है तो उसको दूर कर दिया जायेगा।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री बलवीर सिंह लूथरा।

रायसिंहनगर में खालों का निर्माण

117. श्री बलवीर सिंह लूथरा (रायसिंहनगर): क्या कृषि सिंचित क्षेत्र विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर के बहुत से चकों, गांवों में पक्के खालों का निर्माण अब तक नहीं हुआ है? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र में दिनांक 01 जनवरी, 2019 से दिसम्बर, 2022 के मध्य सिंचित क्षेत्र विकास एवं जल उपयोगिता व अन्य योजनाओं द्वारा कितने चकों में पक्के खाले निर्माण का कार्य स्वीकृत हुआ है व कितने खाले पूर्ण हो चुके हैं व उक्त में से कितने खाले बनाये जाने शेष हैं? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त अवधि के मध्य उक्त विधान सभा क्षेत्र में खालों के निर्माण पर कितनी राशि व्यय की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

कृषि सिंचित क्षेत्र विकास मंत्री (श्री शाले मोहम्मद): (1) जी हां। यह सही है कि रायसिंहनगर विधान सभा क्षेत्र में गंग नहर परियोजना फेज-II के अन्तर्गत 15 चकों में खाला निर्माण कार्य करवाये जाने शेष हैं, जिनका विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र में 01 जनवरी, 2019 से दिसम्बर, 2022 के मध्य सिंचित क्षेत्र विकास एवं जल उपयोगिता विभाग की गंग नहर परियोजना फेज-II में कुल 126 चकों का कार्य स्वीकृत हुआ था जिनमें से 102 चकों में कार्य पूर्ण कर दिया गया है, 9 चकों में कार्य प्रगतिरत है एवं 15 चकों में निर्माण कार्य शेष है। विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(3) उक्त अवधि में विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर में खालों के निर्माण पर राशि रुपये 5,125.69 लाख रुपये व्यय हुए। विवरण परिशिष्ट-स पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

श्री बलवीर सिंह लूथरा (रायसिंहनगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं। मैंने मेरे विधान सभा क्षेत्र के सम्पूर्ण गांवों में पक्के खालों के बारे में पूछा था, मगर आपने सिर्फ गंग नहर परियोजना से बने खालों के बारे में ही बताया है। उसमें भी 126 गांवों में से 112 गांवों में ही कार्य पूर्ण हुआ है, बाकी 15 चकों में कार्य पूर्ण नहीं हुआ है। पहली बात तो यह है कि जो 15 चक बाकी हैं, उनका काम कब तक पूर्ण करवा दिया जाएगा?

दूसरा प्रश्न मेरा यह है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में गंग नहर परियोजना के अलावा आईजीएनपी की दो ब्रांच सूरतगढ़ एवं अनूपगढ़ से सिंचाई हेतु पानी की सुविधा चल रही है, उन गांवों में बने हुए कच्चे और पक्के खालों के बारे में आपने कोई जिक्र नहीं किया, उन गांवों के बारे में भी मुझे बताया जाए। आईजीएनपी के खालों के बने हुए आज 40-45 साल हो चुके हैं, सारे के सारे खाले क्षतिग्रस्त हो चुके हैं।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न पूछो, माननीय सदस्य। माननीय मंत्रीजी, आप बोलो।

श्री शाले मोहम्मद (अल्पसंख्यक मामलात मंत्री): अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने अपनी बात कही है। गंग नहर परियोजना के बारे में तो हमने इनको जानकारी दी है। बाकी आपके आईजीएनपी में जो खाले आ रहे हैं, उनकी सम्पूर्ण जानकारी लेकर मैं आपको अलग से भिजवा दूंगा। वैसे आपके विधान सभा क्षेत्र में कुल 126 चक हैं जिनका 27088 हैक्टेयर क्षेत्रफल है। इस पर 56 करोड़ रुपये खर्च करने थे। 102 चकों में तो 22067 हैक्टेयर में 51 करोड़ का काम हो चुका है, 09 चकों में 1893 हैक्टेयर का कार्य प्रगति पर है और 15 चक ऐसे हैं जिनका 3128 हैक्टेयर है, उनका काम अभी नहीं हुआ। कुल मिलाकर आपके विधान सभा क्षेत्र में विभाग ने बहुत ज्यादा काम किया और समय पर भी किया। बाकी हमने आपको जो परिशिष्ट दिये हैं उसमें समय सीमा लिखी है। इनका 2024 लास्ट तक का समय है। 126 में से 15 चक ही बाकी रहे हैं, इन 15 चकों का काम जल्दी ही हम पूर्ण कर देंगे।

श्री बलवीर सिंह लूथरा (रायसिंहनगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर में लगभग 650 गांव हैं। 126 गांव तो गंग नहर परियोजना से सिंचित हो रहे हैं, बाकी के लगभग 425 गांव इंदिरा गांधी

(श्री बलवीर सिंह लूथरा)

नहर परियोजना की सूरतगढ़ और अनूपगढ़ ब्रांच से सिंचित हो रहे हैं। उनके खालों के बारे में आपसे जानना चाहता हूं कि उन गांवों में जो खाले बने हुए हैं, वह क्षतिग्रस्त हैं, नाकारा हो चुके हैं, उनमें आप क्या कर रहे हो? खाले कब तक पक्के बनवा देंगे?

श्री शाले मोहम्मद (अल्पसंख्यक मामलात मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले भी कहा कि गंग नहर के बारे में हमने जानकारी दी है। आईजीएनपी में आपके जो गांव आ रहे हैं, उनकी जानकारी पूरी लेकर आपको जानकारी दूंगा। उसकी बजट की अनुकूलता के अनुसार आपका आगे का कार्य करेंगे। जब तक बजट स्वीकृत नहीं होगा, जानकारी पूरी नहीं होगी, उससे पहले कुछ कहना सम्भव नहीं होगा।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी, इन्होंने अपनी कांस्टीट्यूएंसी का पूछा है डिटेल में। आपने जवाब केवल गंग नहर का दिया है। उनका प्रश्न यह है कि 426 गांवों से जो गंग नहर के अलावा के हैं, उनके सम्बन्ध में माननीय सदस्य चिन्तित हैं, उसके बारे में आप बतायें। जानकारी नहीं है तो जानकारी करके दुबारा बतायें।

श्री शाले मोहम्मद (अल्पसंख्यक मामलात मंत्री): अध्यक्ष महोदय, आईजीएनपी में इनके जो गांव आ रहे हैं उनकी जानकारी दे दूंगा।

श्री अध्यक्ष: नहीं-नहीं। प्लीज बैठें, एक मिनट, माननीय मत्रीजी। माननीय मंत्रीजी, आपस में बातें नहीं। (व्यवधान) आप बैठ जाओ वहां पर। बैठे-बैठे बोलने की आदत गलत है। सीनियर मैम्बर बनते जा रहे हो, वरिष्ठता बढ़ती जा रही है, उतना ही नया काम सीख रहे हो आप।

माननीय मंत्रीजी, प्रश्न जो लिखा है, वह देखो आप। प्रश्न में लिखा हुआ है कि 'क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर के बहुत से चकों में' रायसिंहनगर की पूरी डिटेल मांगी है इन्होंने, आपने सूचना केवल गंग कैनाल की दी है। मैं अपेक्षा करूंगा कि प्रश्न का उत्तर पूरा आये। जितने भी सिस्टम हैं चाहे वह गंग कैनाल है, चाहे दूसरा है, उसके बारे में भी आना चाहिए। प्रश्न का उत्तर केवल गंग कैनाल का ही आया है। 425 गांव जो हैं, उन सभी के बारे में पूछा गया है। मैं समझता हूं कि हम इस प्रश्न को पोस्टपोन करते हैं। दुबारा जब प्रश्न आये तब डिटेल लेकर इस प्रश्न का उत्तर आये। मुंहजुबानी नहीं। उत्तर तो मेरे पास भी आता है।

(श्री अध्यक्ष)

मैं सभी मंत्रियों से निवेदन करूंगा कि सरकार जब जवाब दे तो प्रश्न के सम्बन्ध में जितनी सूचना चाही है, वह सूचना उसके साथ जोड़ें। इसलिए मैं इस प्रश्न को पोस्टपोन करता हूं।

श्री शाले मोहम्मद (अल्पसंख्यक मामलात मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मेरा एक निवेदन है।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी। I will not allow it. मेरे पास भी लिखा हुआ है। मैं भी पढ़ कर ही बोल रहा हूं। बोलें आप क्या बोल रहे हैं?

श्री शाले मोहम्मद (अल्पसंख्यक मामलात मंत्री): इनके विधान सभा क्षेत्र की अभी तक जो राशि स्वीकृत हुई है उसके बारे में हमने जानकारी दी है।

श्री अध्यक्ष: नहीं-नहीं। पहले प्रश्न पढ़ें। प्रश्न पैसे के बारे में नहीं पूछा है। उन्होंने पूछा है 'क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर के बहुत से चकों/गांवों में पक्के खालों का निर्माण अब तक नहीं हुआ है? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।' पूरी डिटेल चाहिए इसमें। गंग कैनाल ही थोड़े चाहिए। रायसिंहनगर में जो दूसरा सिस्टम है, उसकी जानकारी भी इसमें चाहिए। वह जानकारी इस उत्तर में नहीं है, इसलिए मैंने इस प्रश्न को पोस्टपोन किया है।

माननीय मंत्रीजी, प्लीज। You are setting a wrong precedent. मंत्रीगण ही आपस में बात करेंगे तो फिर बाकी आदमी क्या करेंगे? I am extremely sorry!

अगला प्रश्न। श्री राजेन्द्र राठौड़।

सलारपुर (भिवाड़ी) एवं बोरानाडा (जोधपुर) में मल्टी स्टोरीड इण्डस्ट्रीज काम्प्लेक्स विकसित करने हेतु आवंटित बजट

118. श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा बजट 2022-23 में टेक्नोलॉजी आधारित इंडस्ट्री लगाने हेतु सलारपुर औद्योगिक क्षेत्र-ग्रेटर भिवाड़ी तथा बोरानाडा-जोधपुर में Multi Storied Industrial Complex विकसित किये जाने की घोषणा की गई थी? यदि हां तो माह दिसम्बर 2022 तक उक्त Complex का कितना कार्य पूर्ण हो चुका है व शेष कार्य कब तक पूर्ण कर दिया जायेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

(2) उक्त औद्योगिक क्षेत्रों में Multi Storied Industrial Complex विकसित करने हेतु कुल कितना बजट आबंटित किया गया तथा अब तक कितनी राशि व्यय की जा चुकी है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उद्योग मंत्री (श्रीमती शकुन्तला रावत): (1) जी हां। सरकार द्वारा बजट घोषणा 2022-23 में की गई घोषणा की अनुपालना में भिवाड़ी के औद्योगिक क्षेत्र सलारपुर में 13236 वर्गमीटर तथा बोरानाडा-जोधपुर में औद्योगिक क्षेत्र बोरानाडा तृतीय चरण में 14860 वर्गमीटर क्षेत्रफल के भूखण्डों का नियोजन किया गया है।

तत्पश्चात् रीको द्वारा उक्त भूखण्डों पर मल्टी स्टोरीड काम्प्लेक्स विकसित करने हेतु डवलपर्स से ई.ओ.आई. (एक्सप्रेशन आफ इन्टरेस्ट) के माध्यम से प्रस्ताव प्राप्त करने हेतु समाचार पत्रों में विज्ञप्ति जारी की गई थी, किन्तु किसी भी डवलपर द्वारा इस प्रोजेक्ट को विकसित करने में कोई रुचि नहीं दिखाई है। अत: Multi Storied Industrial Complex विकसित करने की वैकल्पिक प्रक्रिया निर्धारित करने हेतु कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(2) सलारपुर औद्योगिक क्षेत्र-ग्रेटर भिवाड़ी तथा बोरानाडा-जोधपुर में Multi Storied Industrial Complex विकसित करने हेतु रीको द्वारा किसी भी प्रकार का बजट नहीं दिया गया है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से, मंत्री महोदय, आपसे जानना चाहूंगा। क्या यह सही है कि 2022-23 में ग्रेटर भिवाड़ी और बोरानाडा, जोधपुर में Multi Storied Industrial Complex के लिए 250-250 करोड़ की बजटीय घोषणा की गई थी? यदि हां, तो इससे पहले बजट एस्टीमेट भी बने होंगे? आपके विभाग द्वारा यह जो बजटीय घोषणा की गई थी, उसके हिसाब से रिलीजेज कब जारी की गई?

खण्ड 2 में आपने कहा कि Multi Storied Industrial Complex विकसित करने हेतु रीको को बजट आबंटित नहीं हुआ। आपने बजट के लिए मांग कब-कब की? आप मुझे यह भी बतायें कि आपने क्या वैकल्पिक प्रक्रिया प्रारम्भ की? बजट प्रस्ताव के समय जब मूल रूप से यह बनाया गया था तब इसकी फिजिबिलिटी देखी होगी, फिर यह गलती क्यों हुई?

श्रीमती शकुन्तला रावत (उद्योग मंत्री): अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो यह है कि 250-250 करोड़ की घोषणा की गई थी कि Multi Storied

(श्रीमती शकुन्तला रावत)

Industrial Complex विकसित किये जायेंगे। भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा एम ओ यू किया हुआ है। इसमें भारत सरकार से अभी जोधपुर और भिवाड़ी को अनुमति मिली है। उसके लिए जमीन हमने जो आबंटित की है, रीको द्वारा आद्योगिक क्षेत्र बोरानाडा तृतीय चरण में लगभग 14860 जो बतायी है वह 03.06.2022 को हमने निर्णय कर लिया था कि इतनी भूमि हम लेंगे। यह कोई छोटा क्षेत्र नहीं है। यह बड़ा काम्प्लेक्स बनाने का है और इसमें अभी निश्चित रूप से भूमि का भी कोई नहीं है कि इतना ही हम ले सकते हैं, इसके विस्तार के लिए कितनी भी भूमि ले सकते हैं। हमने जून, 2022 में मीटिंग करके भी किया था और उसके बाद भी जब हमने मीटिंग की, उस समय भी जब कोई नहीं आया तो हमने इसको बदलने के लिए 50-50 में या फिर जमीन बेचकर कोई मल्टी स्टोरीड बनाना चाहेगा तो भी उसको जमीन हम दे देंगे जिससे कि यह कारगर हो सके। भिवाड़ी के 143 गांवों का सम्पूर्ण क्षेत्र लगभग 165 वर्ग किलोमीटर जो खुशखेड़ा, भिवाड़ी, नीमराना 28.12.2020 से रीको की पहले की जमीन थी, उसको हमने इसके लिए आबंटित किया था।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने कहा कि भारत सरकार और राजस्थान सरकार के बीच एम ओ यू के आधार पर यह योजना बनाई। यह एम ओ यू कब हुआ? क्या यह सही नहीं है कि आपने एम ओ यू होने के पहले बजटीय घोषणा कर दी जिसके कारण से बजटीय घोषणा अधर में लटक गई?

श्रीमती शकुन्तला रावत (उद्योग मंत्री): वर्ष 2008 में भारत सरकार से एम ओ यू हुआ था और एक DMIC के नाम से औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने के लिये भारत सरकार से MOU हुआ कि जो गुड़गांव और यह जो अदर स्टेट हैं तमिलनाडु, दिल्ली, उस तर्ज पर यहां पर औद्योगिक क्षेत्र मल्टी स्टोरीड में किये जायेंगे। उस आधार पर हमें दो की अनुमति मिली, इसमें 49 परसेंट भारत सरकार देगी, 51 परसेंट राजस्थान सरकार देगी। यह 250 करोड़ के लगभग राशि, जब कभी भी बजट होता है, यह कोई प्लानिंग होती है तो उसमें लगभग राशि तय की जाती है कि इतने करोड़ के लगभग फलां काम का विकास किया जायेगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): अब मुझे अंतिम में बता दो, वैकल्पिक प्रक्रिया आप अपना रहे हो?

श्री अध्यक्ष: आप टैस्ट क्यों कर रहे हो? हो गया न, हो गया। माननीय मंत्रीजी, विराजें। अगला प्रश्न। श्री धर्मनारायण जोशी।

वाहनों से प्राप्त ग्रीन टैक्स

119. श्री धर्मनारायण जोशी (मावली): क्या परिवहन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) सरकार को विगत पांच वर्षो में वाहनों के ग्रीन टैक्स के मद में कब-कब, कितनी-कितनी राशि कितने वाहनों के पंजीयत से प्राप्त हुई? वर्षवार, जिलेवार संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) विगत पांच वर्षो में उक्त टैक्स मद में प्राप्त राशि को कहां-कहां पर, कब-कब व कितना-कितना, किस-किस मद में व्यय किया गया? कितनी राशि शेष है? सरकार उक्त का कब तक व क्या उपयोग करने का विचार रखती है? उक्त मद से पर्यावरण संरक्षण व गैर पर्यावरणीय कार्यो पर हुए व्यय का मदवार पृथक्-पृथक् संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, परिवहन (श्री बृजेन्द्र सिंह ओला): (1) परिवहन एवं सडक सुरक्षा विभाग में ग्रीन टैक्स के मद में वाहनों के पंजीयन से प्राप्त हुई राशि का विवरण परिवहन जिलेवार परिशिष्ट-1 पर एवं पंजीकृत वाहनों की परिवहन जिलेवार सूची परिशिष्ट-2 पर संलग्न है। उल्लेखनीय है कि विभाग में वाहनों के पंजीयन से प्राप्त ग्रीन टैक्स की जिलेवार सूचना वर्ष 2018-19 से संधारित की गई है।

(2) राजस्थान मोटरयान कराधान अधिनियम, 1951 के तहत एकमुश्त कर एवं अन्य करों पर अधिभार एवं पुराने तथा नवीन वाहनों पर अधिरोपित ग्रीन टैक्स तथा राजस्थान स्टाम्प अधिनियम के तहत स्टाम्प ड्यूटी पर अधिभार की राशि राजस्थान परिवहन आधारभूत विकास निधि (RTIDF) में संग्रहित की जाती है। उक्त राशि में से मोटरयान कराधान अधिनियम, 1951 के तहत एकमुश्त एवं अन्य करों पर अधिभार की दरों में दिनांक 11.10.2017 से हुई वृद्धि की राशि (जो कि राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम को उपलब्ध करवाई जाती है) को अलग करने के पश्चात् शेष राशि का उपयोग (समग्र रूप से) क्रमश: स्वायत्त शासन विभाग एवं परिवहन विभाग के माध्यम से 75:25 के अनुपात में जयपुर मैट्रो रेल कारपोरेशन, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम एवं शहरी बस सेवाओं यथा जे.सी.टी.एस.एल., कोटा बस सर्विस लिमिटेड, अजमेर बस सर्विस लिमिटेड व

(राज्य मंत्री, परिवहन)

अन्य संभागीय मुख्यालयों पर संचालित शहरी बस सेवाओं की संचालन हानि के पुनर्भरण हेतु अनुदान/अंशपूंजी उपलब्ध कराने, आरओबी/आरयूबी, शहरी गौरव पथ, पार्किंग निर्माण, नगरीय निकायों में आधारभूत विकासात्मक गतिविधियों हेतु आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाए जाने इत्यादि हेतु किया जाता है, अतः ग्रीन टैक्स की राशि में से किस मद में व्यय हुआ, इसका पृथक् से विवरण दिया जाना सम्भव नहीं है।

गत 5 वर्षों में निधि से व्यय (मोटरयान कराधान अधिनियम के तहत प्राप्त अधिभार, ग्रीन टैक्स, स्टाम्प अधिनियम के तहत प्राप्त अधिभार की राशि) का मदवार विवरण परिशिष्ट-3 पर संलग्न है।

वर्षवार/एजेन्सीवार विवरण परिशिष्ट-4 पर संलग्न है।

दिनांक 06.02.2023 को आर.टी.आई.डी.एफ. निधि में (मोटरयान कराधान अधिनियम के तहत अधिभार, ग्रीन टैक्स, स्टाम्प अधिनियम के तहत अधिभार से प्राप्त राशि) 1138.38 करोड़ रुपये उपलब्ध हैं। (वित्तीय वर्ष 2021-22 तक अंतिम तथा 2022-23 के अनंतिम आकड़ों के अनुसार) उक्त राशि का उपयोग RTIDF निधि के नियमों के अनुसार एवं वित्त विभाग की सहमति से किया जाएगा।

सुव्यवस्थित, सुरक्षित, प्रदूषणरहित, द्रुतगामी एवं सुगम शहरी यातायात प्रबंधन, नगरीय निकायों में आधारभूत विकासात्मक गतिविधियों हेतु अनुदान इत्यादि हेतु राजस्थान परिवहन आधारभूत विकास निधि (आरटीआईडीएफ) से राशि उपलब्ध करवाई जाती है।

गत पांच वर्षों में पौधारोपण/पार्क निर्माण कार्यों हेतु RUIRP-II के अंतर्गत कुल राशि 34.23 करोड़ रुपये तथा मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान के तहत जल संरक्षण, वन विकास (Forestation) इत्यादि हेतु 17.20 करोड़ रुपये व्यय किये गये हैं।

शेष व्यय राशि 2,232.44 करोड़ का उपयोग शहरी क्षेत्रों में प्रदूषण नियन्त्रण हेतु सुव्यवस्थित यातायात प्रबन्धन एवं संचालन हेतु जयपुर मेट्रो रेल कारपोरेशन, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम एवं शहरी बस सेवाओं यथा जे.सी.टी.एस.एल., कोटा बस सर्विस लिमिटेड, अजमेर बस सर्विस लिमिटेड व अन्य संभागीय मुख्यालयों पर संचालित शहरी बस सेवाओं की संचालन हानि के पुनर्भरण हेतु अनुदान/अंशपूंजी उपलब्ध कराने, आरओबी/आरयूबी, शहरी गौरव पथ, पार्किंग निर्माण, नगरीय निकायों में आधारभूत

(राज्य मंत्री, परिवहन)

विकासात्मक गतिविधियों/Waterbodies/river front development इत्यादि के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाये जाने हेतु किया गया है।

(विवरण व सूची पुस्तकालय में रखे गये)

श्री धर्मनारायण जोशी (मावली): माननीय अध्यक्ष महोदय, बिन्दु संख्या-2 के उत्तर में कहा गया है कि ग्रीन टैक्स की राशि का किस मद में व्यय हुआ है, इसका पृथक् विवरण दिया जाना सम्भव नहीं है। सरकार में आय-व्यय का कोई हिसाब-किताब नहीं होता है क्या? इसी में दूसरा मेरा प्रश्न यह है कि 1,138.38 करोड़ रुपये आपकी आय हुई है और आपने अभी इसमें खर्चा बताया है वृक्षारोपण में 34.23 करोड़ का और दूसरा बताया है 17.20 करोड़, तो बाकी का पैसा कहां गया और इसका आपके देने का आधार क्या है?

श्री बृजेन्द्र सिंह ओला (राज्य मंत्री, परिवहन): अध्यक्ष महोदय, मूल प्रश्न के परिशिष्ट-4 में पूरा विवरण दिया गया है कि किस कार्य पर कितनी राशि खर्च की गयी है। यह राशि 75 और 25 के अनुपात में खर्च होती है। 75 प्रतिशत राशि स्वायत्त शासन विभाग खर्च करता है। परिशिष्ट-4 में जो सूचना दी गयी है, उन संस्थाओं या उन कार्यों के लिये पैसा देते हैं, उसकी डिटेल कार्य का मैं आपको उदाहरण बताऊं, आपकी सरकार के समय गौरव पथ शहरों में बनाये, उसके पैसे इससे मिलते हैं। अगर हम वह सारी सूचना मंगायें तो एक वैन गाड़ी में भरकर सूचना आयेगी। यह सम्भव नहीं है और परिशिष्ट-4 को आप पढ़ लें, उसमें हर कार्य पर कितना पैसा दिया गया है, वह उसमें दिया हुआ है। 25:75 का रेशो है। 25 प्रतिशत परिवहन विभाग को पैसे मिलते हैं वह सारे के सारे हम रोडवेज को देते हैं उसके घाटे की पूर्ति के लिये।

श्री धर्मनारायण जोशी (मावली): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा प्रश्न है कि इस राशि में से 50 प्रतिशत राशि भी व्यय नहीं हुई है। फिर यह बार-बार कह रहे हैं कि उसको देना सम्भव नहीं है। कुछ हैड्स तो दे ही सकते हैं कि इस हैड में यह राशि वितरण की जायेगी। वितरण क्या रेवड़ी बांटने का आधार है? आपका देने का क्या अधिकार है?

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आपका कोई स्पेशल प्रपोजल हो तो उसके लिये बात करें। (व्यवधान) माननीय मंत्रीजी, मैं बताता हूं। मैं जो इसमें समझ पाया हूं कि ग्रीन टैक्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, उसके नियम बने हुए नहीं हैं, मोटे तौर पर किस-किसमें खर्च करें। बेहतर यह रहेगा कि विभाग इस

(श्री अध्यक्ष)

बारे में नियम बनाये जिससे कि सदस्यों को भी मालूम हो कि किस-किस हैड में अपनी मांग कर सकते हैं, जिससे इसका सदुपयोग हो सके।

श्री बृजेन्द्र सिंह ओला (राज्य मंत्री, परिवहन): माननीय अध्यक्ष महोदय, कुछ काम तो अनुमत कर रखे हैं, कुछ अनुमत नहीं कर रखे। वह सूचना मेरे पास है। वह बहुत डिटेल में है माननीय सदस्य को मैं उपलब्ध करा दूंगा और जो नियम बने हुए हैं, वह गजट नोटिफिकेशन 20 पेज का है, वह भी मैं सदस्य महोदय को भेज दूंगा।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्रीमती प्रीति गजेन्द्र सिंह।

वल्लभनगर के कुराबड़ में जनजाति छात्रावास की स्थापना

120. श्रीमती प्रीति गजेन्द्र सिंह शक्तावत (वल्लभनगर): क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र वल्लभनगर के कुराबड़ क्षेत्र में जनजाति छात्रावास खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, जनजाति क्षेत्रीय विकास (श्री अर्जुन सिंह बामनिया): विधान सभा क्षेत्र वल्लभनगर के कुराबड़ क्षेत्र में नवीन छात्रावास खोलने के संबंध में अन्य क्षेत्रों के सापेक्ष क्षेत्र विशेष की आवश्यकता, अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या, संसाधनों तथा बजट उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए जनजाति छात्रावास खोलने हेतु निर्णय किया जायेगा।

श्रीमती प्रीति गजेन्द्र सिंह शक्तावत (वल्लभनगर): अध्यक्ष महोदय, मेरी विधान सभा का कुराबड़ क्षेत्र अनुसूचित जनजाति बहुल क्षेत्र है। मंत्री महोदय का जो जवाब है उसके अनुसार कुराबड़ में छात्रावास खोलने के पूरे मापदंड पर यह खरा उतरता है। अत: मेरा माननीय मंत्री महोदय से आग्रह है कि क्षेत्र में छात्रावास खोलने हेतु अधिकारियों को प्रस्ताव तैयार कर भिजवाने के निर्देश प्रदान कर अनुग्रहित करें।

साथ ही यह जानना चाहती हूं कि बम्बौरा में छात्र संख्या में वृद्धि का विचार रखते हैं या नहीं?

श्री अर्जुन सिंह बामनिया (राज्य मंत्री, जनजाति क्षेत्रीय विकास): माननीय अध्यक्ष महोदय, बम्बौरा में बालकों का आश्रम छात्रावास चालू है। हम वहां पर छात्र संख्या बढ़ाने पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री कन्हैया लाल।

मालपुरा में अधिशासी अभियन्ता कार्यालय की स्थापना

121. श्री कन्हैया लाल (मालपुरा): क्या ऊर्जा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि टोडारायसिंह, मालपुरा व डिग्गी में जेवीवीएनएल के सहायक अभियंता कार्यालय संचालित हैं? यदि हां, तो क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र मालपुरा में अधिशासी अभियंता कार्यालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, ऊर्जा (श्री भंवर सिंह भाटी): (1) जी हां। विधान सभा क्षेत्र मालपुरा में अधिशासी अभियन्ता कार्यालय खोलने का प्रस्ताव वर्तमान में विचाराधीन नहीं है क्योंकि उक्त प्रस्ताव नया अधिशासी अभियन्ता कार्यालय खोलने के निर्धारित मापदण्डों को पूर्ण नहीं करता है।

श्री कन्हैया लाल (मालपुरा): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में लगभग 75 हजार उपभोक्ता हैं। अभी मालपुरा उपखण्ड से निवाई की लगभग 80 किलोमीटर की दूरी है। जब बनास में 5 महीने पानी चलता है तो टोडारायसिंह से भी लगभग 80 किलोमीटर की दूरी पड़ती है।

उपभोक्ताओं को कभी ट्रांसफार्मर लोड बढ़ाना हो, कभी ट्रांसफार्मर खराब हो जाता है तो 5-5, 7-7 दिन तक ट्रांसफार्मर्स मिलते नहीं हैं। आपके नोर्म्स क्या हैं और इन नोर्म्स में नहीं आ रहे हैं तो आप करने का विचार रखते हैं या नहीं रखते हैं?

श्री भंवर सिंह भाटी (राज्य मंत्री, ऊर्जा): माननीय अध्यक्ष महोदय, अधिशासी अभियन्ता देवली व अधिशासी अभियन्ता निवाई को विखंडित कर सहायक अभियन्ता कार्यालय, टोडारायसिंह, मालपुरा व डिग्गी हेतु नवीन अधिशासी अभियन्ता कार्यालय, मालपुरा खोले जाने की मांग की गयी है। यदि मालपुरा खोला जाता है तो नये खण्ड कार्यालय पर तीनों ए ईएन आफिस मिलाकर के 80 हजार उपभोक्ता होंगे। जो हमारे निर्धारित मापदंड हैं, उनमें उपभोक्ताओं की संख्या मिनिमम 90 हजार है।

अध्यक्ष महोदय, साथ ही नया खण्ड कार्यालय मालपुरा में प्रस्तावित करने के बाद पहले से कार्यरत अधिशासी अभियन्ता देवली के अधीन 49,730 उपभोक्ता व अधिशासी अभियन्ता निवाई के अधीन 54,654 उपभोक्ता ही रह

(श्री भंवर सिंह भाटी)

जायेंगे, जिससे यह कार्यालय तर्कसंगत नहीं रह पायेंगे। अत: नये प्रस्तावित मालपुरा तथा पूर्व में कार्यरत देवली एवं निवाई अधिशासी अभियन्ता कार्यालयों में उपभोक्ताओं की संख्या राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मापदंडों के अनुरूप नहीं होने के कारण विधान सभा क्षेत्र मालपुरा में अधिशासी अभियन्ता कार्यालय खोले जाने के संबंध में वर्तमान में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री पब्बाराम।

प्रश्न संख्या 122, स्थगित।

फलौदी के आयुष चिकित्सा भवन के निर्माण हेतु बजट का आवंटन

122. श्री पब्बाराम (फलौदी): क्या आयुर्वेद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र फलौदी में आयुष चिकित्सा भवन निर्माण हेतु बजट व वित्तीय स्वीकृति जारी होने के पश्चात् उक्त को आबंटित बजट सेवर (भरतपुर) को आबंटित कर दिया गया?

(2). क्या सरकार अब फलौदी में उक्त चिकित्सालय के भवन निर्माण हेतु बजट आबंटित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(स्थगित)

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री शंकर सिंह रावत।

ब्यावर के राजकीय अमृतकौर चिकित्सालय का नवीन भवन निर्माण

123. श्री शंकर सिंह रावत (ब्यावर): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) राजकीय अमृतकौर चिकित्सालय, ब्यावर के मुख्य भवन का निर्माण कब हुआ? उक्त में प्रतिदिन कितने मरीजों का आउटडोर रहता है? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त चिकित्सालय का मुख्य भवन बहुत पुराना एवं जीर्णशीर्ण अवस्था में है? क्या सरकार उक्त चिकित्सालय के पुराने

(श्री शंकर सिंह रावत)

भवन के स्थान पर नया भवन बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री (श्री परसादी लाल): (1) राजकीय अमृतकौर चिकित्सालय, ब्यावर के मुख्य भवन का निर्माण 1954 में हुआ था। वर्तमान में चिकित्सालय में प्रतिदिन मरीजों का ओपीडी औसत 1355 है।

(2) चिकित्सालय का भवन पुराना है, परन्तु सम्पूर्ण भवन जीर्ण-शीर्ण न होकर कुछ भाग जीर्ण-शीर्ण है, जो जिला कलेक्टर, अजमेर द्वारा गठित कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में रेखांकित किया है। जीर्ण-शीर्ण भाग के उपयोग पर कमेटी द्वारा पूर्ण पाबन्दी लगा दी गई है तथा मरम्मत योग्य भाग की मरम्मत हेतु संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) राजस्थान सरकार के पत्रांक प.25(1)चिस्वा/2/2021 जयपुर दिनांक 07.02.2022 ए.के. राजकीय चिकित्सालय ब्यावर में रिपेयर रिनोवेशन कार्य हेतु राशि रुपये 208.00 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की गई है। सिविल व विद्युत कार्य के प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की जा चुकी है एवं कार्य पूर्ण करने की संभावित तिथि 13.07.2023 है।

जिला कलेक्टर, अजमेर द्वारा गठित कमेटी की रिपोर्ट में रेखांकित किये गये जीर्ण-शीर्ण भाग के उपयोग पर कमेटी द्वारा पूर्ण पाबन्दी लगा दी गई है। उक्त भाग के नवीन निर्माण हेतु चालू/आगामी वित्तीय वर्षों में वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं गुणावगुण के आधार पर निर्माण कराये जाने पर विचार किया जा सकेगा।

श्री शंकर सिंह रावत (ब्यावर): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन कर रहा हूं कि जब यह अस्पताल बना था, उसके साथ में ब्यावर का डाक बंगला भी बना था, वह 5 साल पहले रात के समय में भरभरा कर गिर गया। इस बिल्डिंग का 2 बार माप हुआ है। क्या यह सही है? पहली रिपोर्ट में तो पूरी बिल्डिंग को धराशायी माना गया है। वह दोनों मेरे पास में हैं। दूसरी रिपोर्ट में आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त माना है। अध्यक्ष महोदय, अगर यह बिल्डिंग गिर गयी तो कितनी जनहानि होगी? डाक बंगले में तो एसडीएम कार्यालय चल रहा था, रात को कोई कर्मचारी नहीं था। पूरा का पूरा गिर गया।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न पूछें, माननीय सदस्य।

श्री शंकर सिंह रावत (ब्यावर): यह गिर गयी तो बहुत जनहानि हो सकती है।

श्री अध्यक्ष: आप प्रश्न पूछें सीधा कि पूरी बिल्डिंग बनायेंगे कि नहीं बनायेंगे? भूमिका बनाने से क्या है।

श्री शंकर सिंह रावत (ब्यावर): पूरी बिल्डिंग के लिए आप बजट दें, यह मैं आपको कहना चाहता हूं। ऐसे गिर गयी तो कौनसा अधिकारी या सरकार जिम्मेदारी लेगी, इतनी जनहानि हो गयी तो?

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य। माननीय मंत्री जी, 1954 की बिल्डिंग है और उसको 2 करोड़ रुपये भी दिये हैं। आधी बिल्डिंग को रोक रखा है। क्या सरकार इस पूरी बिल्डिंग को बनाने के लिए सोचेगी?

श्री परसादी लाल (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैंने उत्तर में भी कहा कि कुछ भाग को ही रोका गया है। बाकी का रिनोवेशन करवा रहे हैं। सम्भव होगा तो बात करके, माननीय सदस्य की भावना के अनुसार और आपके निर्देश के अनुसार पूरी बिल्डिंग बनाने का भी प्रावधान करने के लिए माननीय मुख्य मंत्री महोदय को अपनी ओर से, विभाग की ओर से अभिशंसा भिजवा देंगे।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्रीमती मीना कंवर।

शेरगढ़ के भवन विहीन पशु चिकित्सालय

124. श्रीमती मीना कंवर (शेरगढ़): क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ में संचालित पशु-चिकित्सालय एवं उप केन्द्रों में पशु चिकित्सकों के कितने पद स्वीकृत हैं? उक्त में कौन-कौन चिकित्सक कार्यरत हैं तथा कितने पद रिक्त हैं? क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र में माह दिसम्बर, 2020 से माह दिसम्बर, 2022 तक कितने नवीन पशु-चिकित्सालय एवं उप केन्द्रों की स्थापना की गई? स्थानवार संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त विधान सभा क्षेत्र में उक्त अवधि में सरकार द्वारा किस-किस योजना में क्या-क्या कार्य करवाये गये? उक्त विधान सभा क्षेत्र में कौन-

(श्रीमती मीना कंवर)

कौनसे पशु-चिकित्सालय एवं उप केन्द्र भवन विहीन हैं? क्या सरकार उक्त के भवन बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

पशुपालन मंत्री (श्री लालचन्द कटारिया): (1) विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ की पशु चिकित्सा संस्थाओं में कुल स्वीकृत, रिक्त पदों एवं उन पर कार्यरत पशु चिकित्सा कर्मियों का नामवार विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

जी हां। रिक्त पदों को कार्मिकों की उपलब्धता अनुसार भरा जाता है।

(2) विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ में दिसम्बर, 2020 से अब तक नवीन खोली एवं क्रमोन्नत की गई पशु चिकित्सा संस्थाओं का वर्षवार एवं नामवार विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(3) विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ में दिसम्बर, 2020 से अब तक पशुपालन विभाग द्वारा संचालित योजनाओं अन्तर्गत किये गये कार्यों का विवरण परिशिष्ट-3 पर संलग्न है।

जी हां। आवश्यकता एवं वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता अनुसार नवीन पशु चिकित्सा संस्थाएं स्वीकृत की जाती हैं।

विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ की पशु चिकित्सा संस्थाओं की भवन व्यवस्था का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है। इस विधान सभा क्षेत्र की जिन पशु चिकित्सा संस्थाओं के राजकीय भवन नहीं हैं वे पंचायत द्वारा प्रदत्त/ वैकल्पिक व्यवस्था में उपलब्ध करवाये गये भवनों में संचालित हैं।

जी हां। पशु चिकित्सा संस्थाओं के भवन निर्माण कार्य विभाग के नाम भू-स्वामित्व के दस्तावेज उपलब्ध होने पर वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता अनुसार प्राथमिकता से करवाये जाते हैं।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

श्रीमती मीना कंवर (शेरगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ में संचालित 'ए' श्रेणी के चिकित्सालय व पशु चिकित्सालय, पशु उप चिकित्सा केन्द्रों के भवन बनाने व रिक्त पदों को श्रेणीवार भरने को सरकार कब तक पूरा करेगी?

खण्ड-2, शेरगढ़ विधान सभा क्षेत्र की पशु उप केन्द्र विहीन ग्राम पंचायतों में कब तक केन्द्र स्वीकृत करेंगे? यह आप बतायें। धन्यवाद।

श्री लालचन्द कटारिया (कृषि मंत्री): अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने इसमें बताया था कि कुल 103 ग्राम पंचायतें हैं। शेरगढ़ विधान सभा क्षेत्र में 48 ग्राम पंचायतों में पशु उप केन्द्र नहीं हैं। 55 संस्थाएं कार्यरत हैं। अभी हाल ही में नये बजट में 1200 उप केन्द्र खोलने की मुख्य मंत्री जी ने घोषणा की है। मैं माननीय सदस्या को कहना चाहूंगा कि आप मुझे एक लिस्ट बनाकर दे दें 5 उप केन्द्र तो हम इसी वर्ष खोल देंगे। बाकी आने वाले वर्ष में जो और बजट आयेगा, उसमें होंगे।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्रीमती सफिया जुबेर।

सिलीसेढ़ व जयसमन्द बांध (अलवर) के बहाव क्षेत्र में अतिक्रमण

125. श्रीमती सफिया जुबेर (रामगढ़): क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि जिला अलवर के सिलीसेढ़ व जयसमंद बांध के भराव व बहाव क्षेत्र में अतिक्रमण हैं? यदि हां, तो किस-किस के? उक्त अतिक्रमणों को हटाने के संबंध में क्या कार्यवाही की गई? उक्त के लिए कौन-कौन अधिकारी व कर्मचारी दोषी हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त दोषी अधिकारियों व कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

जल संसाधन मंत्री (श्री महेन्द्रजीत सिंह मालविया): (1) जी हां। जयसमंद बांध के भराव/बहाव क्षेत्र में कुल 13 अतिक्रमण चिन्हित किये गये जिन्हें 06.09.22 को अतिक्रमण मुक्त करवाया गया है। विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

सिलीसेढ़ बांध की भराव/बहाव क्षेत्र में एवं नहर पर कुल 61 अतिक्रमण चिन्हित किये गये, जिनमें से 11 अतिक्रमणों को दिनांक 06.10.2022 को हटवाया गया है। विवरण परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न है। शेष चिन्हित अतिक्रमणों को हटवाने की कार्यवाही नियमानुसार प्रक्रियाधीन है।

सिलीसेढ़ एवं जयसमंद बांध के भराव/बहाव क्षेत्र में हुए अतिक्रमण के संबंध में समय-समय पर नोटिस जारी कर नियमानुसार कार्यवाही किये जाने से कोई अधिकारी/कर्मचारी दोषी नहीं है।

(2) उपरोक्तानुसार।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, उत्तर माना गया। प्रश्न पूछ लें।

श्रीमती सफिया जुबेर (रामगढ़): सर, जवाब मिल गया है। यह संबंधित है जो हमारे बांध हैं या उसका कैचमेंट एरिया और उसमें जो अतिक्रमण किया जा रहा है, मैं पिछले 31 सालों से देख रही हूं, खासतौर से अलवर में जो बांध सिलीसेढ़, जयसमंद है।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न, प्रश्न।

श्रीमती सफिया जुबेर (रामगढ़): सर, प्रश्न तो है ही। सर, जवाब में मुझे दिया गया है कि इसमें कोई अधिकारी दोषी नहीं है। अगर इतनी लंबी लिस्ट है जिन्होंने अतिक्रमण कर रखा है तो कोई न कोई तो दोषी होगा न, जिस वजह से इतना अतिक्रमण बढ़ गया। बड़े-बड़े होटल बन गये हैं। व्यावसायिक गतिविधियां हो रही हैं।

(समय: 12.00 बजे)

सर, दूसरी बात यह है कि चलो, अतिक्रमण हो गया। इन बांधों में विशेषकर सिलीसेढ़ बांध में भराव क्षेत्र एवं कैचमेंट क्षेत्र में जो अवैध निर्माण हुए हैं, उनको सरकार कब तक तय करेगी और कब तक हटाएगी? यह समय सीमा इस सदन में तय होनी चाहिए।

दूसरा है, आगे से इन पर अतिक्रमण न हो, इसके लिए सरकार क्या कदम उठा रही है?

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी।

श्री महेन्द्रजीत सिंह मालविया (जल संसाधन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जयसमंद बांध में 13 व्यक्तियों का अतिक्रमण था, 13 के 13 को हमने हटा दिया। दूसरा बांध है सिलीसेढ़, उसमें 61 लोगों का अतिक्रमण था, जिसमें से हमने 13 लोगों को हटा दिया है। एसडीएम की मौजूदगी में हमने एक कमेटी बनाई है और लगातार हम इनको हटाने की कार्रवाई कर रहे हैं। इसमें अगर और भी सख्ती बरतनी पड़े तो हम सख्ती बरतेंगे, भराव क्षेत्र में इस तरह के काम को हम पूरी ताकत के साथ हटाने की कोशिश करेंगे।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न काल समाप्त हुआ।

(शेष तारांकित व समस्त अतारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया आगे देखें।)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई हैः-

(श्री अध्यक्ष)

(1) श्री प्रताप सिंह, सदस्य की ओर से प्रदेश में मिड-डे मील के अंतर्गत कॉनफैड एवं महिला बाल विकास विभाग द्वारा टेंडर प्रक्रिया में की गई अनियमितता एवं भ्रष्टाचार से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(2) श्री चन्द्रभान सिंह आक्या, सदस्य की ओर से चित्तौड़गढ़ में राजस्थान-मध्यप्रदेश सीमा पर निम्बाहेड़ा-नीमच मार्ग पर परिवहन विभाग के अधिकारियों द्वारा आमजन से अवैध वसूली करने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(3) श्री पुखराज गर्ग, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र भोपालगढ़ में बन्द पड़े जनता जल योजना के अंतर्गत किये गये ट्यूबवैलों को पुन: खुदवाकर समुचित पेयजल की व्यवस्था करने के संबंध में।

(4) श्री बाबुलाल (झाडोल), सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र झाडोल में बिगड़ती हुई कानून-व्यवस्था से आपराधिक व असामाजिक तत्वों के बढ़ते हुए मनोबल से आमजन में व्याप्त भय से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(5) श्री धर्मेन्द्र कुमार, सदस्य की ओर से जिला हनुमानगढ़ में आपराधिक व असामाजिक तत्वों के बढ़ते हुए मनोबल से आमजन मे व्याप्त भय से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(6) श्री जगसी राम, सदस्य की ओर से रेवदर में संचालित राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में लम्बे समय से महिला विशेषज्ञ चिकित्सक के पद रिक्त होने से आमजन को हो रही असुविधा के संबंध में।

(7) श्री जब्बर सिंह सांखला, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र आसीन्द के ग्राम रामपुरा के सापोला गांव में देवनारायण मन्दिर के पास खनन ब्लास्टिंग से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(8) श्री समाराम गरासिया, सदस्य की ओर से बत्तीसा बांध के डूब क्षेत्र के विस्थापितों को भू-आबंटन करने के संबंध में।

(9) श्री शंकर सिंह रावत, सदस्य की ओर से प्रदेश में निजी विश्वविद्यालयों द्वारा एमबीबीएस विद्यार्थियों से अत्यधिक फीस लिए जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(10) श्री जोराराम कुमावत, सदस्य की ओर से प्रदेश में कुटीर उद्योग से जुड़े कुम्हार वर्ग को पिछले माह अतिवृष्टि से हुए नुकसान का मुआवजा दिलवाने के संबंध में।

(श्री अध्यक्ष)

(11) श्री कालीचरण सराफ, सदस्य की ओर से जयपुर शहर में जेसीटीएसएल के अंतर्गत चलने वाली बसों में निरन्तर कमी से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(12) श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र केशोरायपाटन में बेवरेज कंपनी द्वारा स्थानीय लोगों को रोजगार से वंचित रखने के संबंध में।

(13) श्री बिहारीलाल, सदस्य की ओर से बीकानेर इंजीनियरिंग कालेज के 18 अशैक्षणिक कार्मिकों को विधिक प्रक्रिया अपनाये बिना सेवा मुक्त किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

उपरोक्त प्रस्ताव ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाये, अतः इन पर अनुमति देने में असमर्थ हूं। फिर भी माननीय सदस्य श्री पुखराज गर्ग, श्री बाबुलाल (झाडोल), श्री समाराम गरासिया, श्री कालीचरण सराफ एवं श्री बिहारीलाल को उनके प्रस्ताव की विषयवस्तु पर दो-दो मिनट बोलने की अनुमति होगी।

नियम 295 के अंतर्गत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं

(1) श्रीमती अनिता भदेल, सदस्य की ओर से अजमेर शहर में कतिपय राजकीय विद्यालयों का संचालन मूल स्थान से न होकर अन्यत्र स्थान से होने के कारण परीक्षार्थियों को हो रही परेशानी से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(2) श्री प्रताप सिंह, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र छबड़ा के छीपाबड़ौद में विशिष्ट लहसुन मण्डी में साफ-सफाई की समुचित व्यवस्था नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(3) श्री जोगिन्दर सिंह अवाना, सदस्य की ओर से प्रदेश में पहाड़ी क्षेत्रों में निवासरत गुर्जर समुदाय के आर्थिक दृष्टि से कमजोर छात्रों की समुचित शिक्षा हेतु विशेष व्यवस्था करने के संबंध में।

(4) श्री अशोक डोगरा, सदस्य की ओर से बून्दी शहर के धार्मिक आस्था केन्द्र मान्धाता बालाजी तक सड़क निर्माण करवाने के संबंध में।

(5) श्री संजय शर्मा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र अलवर शहर में कचरा संग्रहण हेतु समुचित व्यवस्था करने के संबंध में।

(श्री अध्यक्ष)

(6) श्री बलवीर सिंह लूथरा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर में संचालित शहीद भगतसिंह महाविद्यालय की प्रबन्ध समिति एवं सरकार के मध्य हुए एमओयू की अनुपालना नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(7) श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र केशोरायपाटन में अतिवृष्टि से फसलों को हुए नुकसान का मुआवजा दिए जाने के संबंध में।

(8) श्री गोपाल लाल शर्मा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र माण्डलगढ़ में विगत चार वर्षों से सड़कों का नव निर्माण नहीं होने एवं क्षतिग्रस्त सड़कों की समय पर मरम्मत नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(9) श्री गोपी चन्द मीणा (जहाजपुर), सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर की ग्राम पंचायत बिशनिया के सरपंच एवं ग्राम विकास अधिकारी को कथित अनियमितताओं की जांच में दोषी पाये जाने के उपरान्त भी इनके विरुद्ध कार्यवाही नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(10) श्री फूल सिंह मीणा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र उदयपुर ग्रामीण के राजकीय विद्यालय देवाली को भू-आबंटन एवं निर्माण की स्वीकृति नहीं मिलने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(11) श्री जब्बर सिंह सांखला, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र आसीन्द में सभी राजकीय विभागों में रिक्त पदों को नहीं भरने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(12) श्रीमती संतोष, सदस्य की ओर से अनूपगढ़ को नया जिला बनाये जाने के संबंध में।

(13) श्री गुरदीप सिंह, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र संगरिया की ग्राम सेवा सहकारी समिति रतनपुरा में हुए घोटालों की निष्पक्ष जांच नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(14) श्री शंकर सिंह रावत, सदस्य की ओर से ब्यावर शहर को नया जिला बनाने के संबंध में।

(15) श्री रामप्रताप कासनियां, सदस्य की ओर से सूरतगढ़, श्रीगंगानगर एवं

(श्री अध्यक्ष)

हनुमानगढ़ क्षेत्रों में अतिवृष्टि एवं शीतलहर से फसलों के नुकसान का किसानों को मुआवजा दिलवाये जाने के संबंध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गयी सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी।

श्री पुखराज गर्ग।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

भोपालगढ़ में जनता जल योजना से पेयजल व्यवस्था

श्री पुखराज (भोपालगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे कार्य संचालन और प्रक्रिया के नियम 50 के तहत मेरे विधान सभा क्षेत्र में जेजेवाई के ट्यूबवैल जो बंद हैं और जिनके टेंडर नहीं हुए हैं, उस पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद और आभार।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र भोपालगढ़ में अभी सर्दी के अंदर भी पानी की भयंकर समस्या है। ग्राम पंचायतों में बहुत सारे ट्यूबवैल हैं जो जेजेवाई के थे लेकिन अभी बंद पड़े हैं, उनके स्थान पर नये ट्यूबवैल खुदवाने के लिए बार-बार पीएचईडी के अधिकारियों को कहने के बावजूद, वो एक ही बात कहते हैं कि अभी तक जेजेवाई में हमें किसी तरह का बजट नहीं दिया गया है। जेजेवाई में बहुत सारी ग्राम पंचायतें हैं जिनके अंदर ट्यूबवैल खराब हैं, जिनमें प्रमुख रूप से ग्राम पंचायत लबेरा, खदावों की ढाणी, मेलाणा में मेघवालों का मोहल्ला, सोयला में रैगरों का मोहल्ला, ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप जनरल बोलें, डोंट रीडिंग।

श्री पुखराज (भोपालगढ़): बहुत सारे जो जेजेवाई के ट्यूबवैल हैं वो बंद पड़े हैं। उनके स्थान पर दूसरे ट्यूबवैल खुदवाने के लिए बार-बार उच्च अधिकारियों से बात की जा रही है लेकिन वो बार-बार एक ही बात कह रहे हैं कि जेजेवाई का हमें अभी तक बजट नहीं मिला है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री महोदय से और सरकार से मांग करना चाहूंगा कि जेजेवाई के जो ट्यूबवैल बंद हो गये हैं और यह स्कीम टोटली पीएचईडी को हैंडओवर कर दी है, तो उन अधिकारियों को बजट उपलब्ध करवाकर उनके स्थान पर नए ट्यूबवैल खुदवाए जाएं। जेजेएम में मेरी पंचायत समिति, मंडोर है, उसमें टेंडर हुए डेढ़ साल हो

(श्री पुखराज)

गये हैं लेकिन अभी तक वहां किसी तरह का काम नहीं हुआ है। वो ठेकेदार काम नहीं कर रहा है, उसको ब्लैक लिस्टेड करके दूसरे ठेकेदार को काम दिया जाए। बावड़ी पंचायत समिति में जो मेरी 17 ग्राम पंचायतें हैं उनमें जेजेएम के अभी तक टेंडर ही नहीं हुए हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि उसमें जल्दी से जल्दी टेंडर कराये और सरकार की जो महत्वपूर्ण स्कीम है कि हर घर को नल से जल दिया जाए, वो पूरी की जा सके।

श्री अध्यक्ष: श्री बाबुलाल (झाडोल)।

झाडोल में बिगड़ी कानून-व्यवस्था

श्री बाबुलाल (झाडोल): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे प्रक्रिया के नियम 50 के अंतर्गत बोलने का मौका दिया, उसके लिए मैं आपका आभारी हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान दिलाना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में पुलिस की जो स्थिति है, आमजन के पास में फोर-व्हीलर भी है और टू-व्हीलर भी है, कई लोगों के पास लाइसेंस नहीं है, यह समस्या है वहां की क्योंकि जनजाति क्षेत्र है और वो इतना ज्यादा आईक्यू नहीं रखता कि मुझे लाइसेंस बनाना चाहिए। जब वो गाड़ी लेकर जाते हैं तो पुलिस चैकिंग के नाम पर आज पकड़ा, दो दिन बाद गया तो फिर पकड़ा, तो सरकार से मैं जानना चाहता हूं कि एक वाहन का एक बार चालान कटेगा या बार-बार कटेगा? इस तरह से बार-बार चालान कटता है तो वहां का गरीब आदमी परेशान होता है। कई बार तो कुछ सिपाही चैकिंग के नाम से बैठे रहते हैं और अवैध वसूली करते हैं। यह हम लोगों के लिए बहुत बड़ी समस्या है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि ओगणा थाना में, एक महिला, विधवा है, बेसहारा है। उसकी जमीन पर एक किसी सामान्य व्यक्ति ने कब्जा किया। उसके आगे-पीछे कोई नहीं है। अब उस जमीन पर वह जाती है तो उसके साथ मार-पीट होती है। कुछ समय पहले उस महिला के साथ उन्होंने घसीट-घसीटकर मार-पीट की। वे थाने में जाते हैं, एप्लीकेशन देते हैं, रिपोर्ट देने के बाद भी उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। वे डीवाईएसपी साहब से मिलते हैं, उसके बाद भी कुछ नहीं होता है। फिर मैंने थानाधिकारी से पूछा, थानेदार साहब, यह एसटी की महिला है, अनावश्यक रूप से कोई व्यक्ति अपने प्रभाव का उपयोग करके इसकी जमीन पर कब्जा करना चाहता है, आप या तो उसे एट्रोसिटी एक्ट में लीजिये। उन्होंने आज तक कार्रवाई नहीं की।

(श्री बाबुलाल)

एक तो मुझे यह समझ में नहीं आता कि यह पानरवा थाना ही ऐसा क्यों है कि वहां का अधिकारी ऐसा हो जाता है या वहां का शायद वातावरण ही ऐसा है। वहां एक बालिका है, जिसकी मां विधवा है, आगे-पीछे कोई नहीं है। उस बालिका को एक व्यक्ति गुजरात लेकर जाता है और अपने मोबाइल पर उसका फोटो अपलोड करके किसी व्यक्ति को भेजता है। उसके बाद उसका वहां पर बेचान होता है, सौदा होता है। ढूंढते-ढूंढते उसके परिवार वालों को पता लगता है कि लड़की वहां हो सकती है। पता किया, लाकर पूछ-ताछ की गयी तो उस व्यक्ति ने स्वीकार भी किया कि उसने बेची है। फिर भी पुलिस ने मुकदमा दर्ज नहीं किया। वह परिवार बहुत दुखी है, व्यथित है।

वह परिवार जब मेरे पास आया तो मैंने उनसे पूछा और पता लगा कि उसने कोर्ट मैरिज कर दी, जब उन्होंने पहली रिपोर्ट दी 20 तारीख को, उन्होंने कहा, रिश्तेदारी में ढूंढो। फिर 22 को रिपोर्ट दी, गुमशुदगी दर्ज की। फिर मेरे कहने के बाद भी उन्होंने एफआईआर दर्ज नहीं की। बाद में 2 तारीख को उन्होंने एफआईआर दर्ज की। अब वे कह रहे हैं, कोर्ट मैरिज की है, बालिग है, हम कुछ भी नहीं कर सकते। वह परिवार बहुत दुखी है। वह मां बहुत दु:खी है। परिवार के कुछ लोग कह रहे हैं कि उसकी मां के आगे-पीछे कोई नहीं है, कम से कम वह आये और कहे कि मैं इनका पालन-पोषण वहन करूंगा। वह इंटरकास्ट शादी है लेकिन वह भी नहीं हो पा रहा है।

दूसरा, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, एक बालिका को उसके घर से दलाल उठाकर ले जाते हैं और उसका बेचान हो जाता है। वह परिवार ढूंढ रहा है, लेकिन उसे मिल नहीं रही है। सरकार को इस बिगड़ती कानून-व्यवस्था पर सख्त से सख्त कार्रवाई करने के निर्देश देने चाहिए। उन गरीब लोगों को न्याय मिलना चाहिए।

श्री अध्यक्ष: श्री समाराम गरासिया। (व्यवधान) माननीय मंत्री जी, प्लीज। यहां तक आवाज आ रही है।

बत्तीसा बांध के डूब क्षेत्र के विस्थापितों को भू-आवंटन

श्री समाराम गरासिया (पिंडवाड़ा-आबू): अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे नियम 50 के अन्तर्गत स्थगन प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया, उसके लिए धन्यवाद। बत्तीसा नाला भाखर में जो बन रहा है, वहां जिस प्रकार से 200 परिवारों को विस्थापित करने के लिए जगह दी गयी, वहां पर पूरा मगरा क्षेत्र है, आदिवासी मगरों में तो रह सकते हैं लेकिन आजीविका कैसे चलाएंगे? उन्हें

(श्री समाराम गरासिया)

300 बीघा जमीन अलाट की गयी। मेरा तो यही निवेदन है कि उन्हें खेती योग्य जमीन दी जाये ताकि वे अपनी आजीविका चला सकें।

जिस प्रकार से 11 पंचायतों में देलदर तहसील बनायी गयी है, वह पहले तो 13 किलोमीटर पड़ती थी, अब बत्तीसा बांध बनने के बाद वह 50 किलोमीटर के दायरे में पड़ती है। ऐसे में वे हमेशा तहसील के अन्दर पंचायत में कैसे आ पाएंगे? हास्पिटल वहां हैं। सारे तहसील के अधिकारी, उप-खण्ड अधिकारी वहां बैठेंगे। कम से कम साढ़े 13 किलोमीटर का 32 करोड़ का रोड लगभग है। मैं तो यही कहूंगा कि उन्हें कुछ मदद मिले और कम से कम उन्हें उपजाऊ जमीन दी जाये, क्योंकि वह चरागाह जमीन है, जिसका समतलीकरण नहीं किया जा सकता।

अध्यक्ष महोदय, कई एक्सीडेंट होते हैं, जैसे हनुमानटेकरी पर आये दिन पॉटहोल्स बनते हैं, आदिवासी अशिक्षित लोग होते हैं, एक्सीडेंट की मारा-मारी टल जायेगी। कई एक्सीडेंट होते हैं, इसलिए मेरा तो आपसे यही निवेदन है कि सरकार आदेश करे कि कम से कम 13-13.50 किलोमीटर के दायरे में तहसील बने, ताकि लोगों को राहत मिले। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री कालीचरण सराफ।

जयपुर में जे.सी.टी.एस.एल. द्वारा संचालित बसों में निरन्तर कमी

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि जयपुर शहर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जे सी टी एस एल की महत्वपूर्ण भूमिका है, इसके अन्तर्गत चलने वाली बसों में निरन्तर गिरावट होती जा रही है। चार साल पहले 408 बसें थीं। चार साल में एक भी नयी बस की एंट्री नहीं हुई। 408 से घटकर 300 रह गयीं। अब 1 अप्रैल से 100 बसें और कबाड़ में चली जाएंगी। अब 208 बसें केवल जे सी टी एस एल के माध्यम से चल रही हैं। गत चार साल में जयपुर शहर की आबादी 40 लाख से 55 लाख हो गयी और शहरी विकास मंत्रालय के पैमाने के अनुसार 10,000 की आबादी पर 6 बसें लगभग होनी चाहिए इस हिसाब से 3,300 बसें होनी चाहिए।

जयपुर शहर, जो कि राजस्थान की राजधानी है, यहां केवल 200 बसें चल रही हैं। इसके कारण निजी बसों का एकछत्र शासन हो गया। 1 अप्रैल से 100 बसें और कबाड़ में चली जाएंगी तो 200 बसें रह जाएंगी। 1 अप्रैल से 8 रूट बन्द हो जाएंगे, जिसके कारण आस-पास के कस्बे- बगरू, चाकसू, बस्सी,

(श्री कालीचरण सराफ)

कूकस, गोनेर और पत्रकार कालोनी की कनेक्टिविटी खतम हो जायेगी। इन रूट्स पर बसें बन्द होने के कारण प्राइवेट बसों का एकछत्र शासन हो जायेगा और वे मनमाना किराया वसूल करेंगी, जिसके कारण छात्र-छात्राओं को जो आईडी कार्ड दिखाकर 50 परसेंट की छूट मिलती है, सीनियर सिटीजंस हैं, महिलाओं को 30 परसेंट की छूट मिलती है, जो दिव्यांगों को फ्री यात्रा की सुविधा मिलती है, इन सबकी सुविधाएं और छूट बन्द हो जाएंगी।

विभाग ने 100 इलैक्ट्रिक बसों के लिए वित्त विभाग को तीन महीने पहले मंजूरी के लिए भेजा था, उनकी भी अभी तक कोई व्यवस्था नहीं हो पायी। मेरा यह कहना है कि जयपुर में 55 लाख की आबादी को देखते हुए आपने जो केवल 100 बसों की अनुशंसा भेजी है, वह पर्याप्त नहीं है, इसमें निश्चित रूप से बढ़ोतरी होनी चाहिए। जयपुर शहर में प्राइवेट बसों की मोनोपॉली खतम हो, इसके लिए ज्यादा से ज्यादा बसें चलायी जानी चाहिए।

अभी मुख्य मंत्री जी ने अपने बजट में एक घोषणा की है कि राजस्थान सिटी ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन का गठन किया जाएगा। जयपुर, जोधपुर, अजमेर, कोटा में सर्विस मॉडल पर 500 नयी बसें खरीदी जाएंगी। अब चार शहरों के लिए यदि 500 नयी बसें खरीदेंगे तो उसमें से जयपुर के लिए 100-150 बसें मिलेंगी, यह पर्याप्त नहीं हैं। मेरा यह कहना है कि जयपुर शहर का पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम न बिगड़े, इसके लिए सरकार को पर्याप्त बसों की व्यवस्था करनी चाहिए। यह मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री बिहारीलाल।

बीकानेर इंजीनियरिंग कालेज के अशैक्षणिक कार्मिकों की बिना विधिक प्रक्रिया सेवामुक्ति

श्री बिहारीलाल (नोखा): माननीय अध्यक्ष जी, एक महत्वपूर्ण विषय की तरफ आपका और सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। ईसीबी (इंजीनियरिंग कालेज, बीकानेर) के 18 अशैक्षणिक कर्मचारियों को बिना किसी जांच के, बिना किसी विधिक प्रक्रिया को अपनाये ही अचानक सेवा से मुक्त कर दिया गया। उनके समर्थन में पूरा बीकानेर कलेक्टर कार्यालय, बीकानेर के बाहर धरने पर है, अनशन चल रहा है। अनशनकारियों का स्वास्थ्य बिगड़ रहा है। आज कलेक्टरेट का बहुत बड़ा घेराव भी है।

(श्री बिहारीलाल)

माननीय अध्यक्ष जी, 08.01.2018 को ईसीबी में स्वीकृत अशैक्षणिक पदों पर नियुक्ति हेतु प्रक्रिया प्रारम्भ करने की पत्रावली अध्यक्षा, ईसीबी और मंत्री, तकनीकी शिक्षा, राजस्थान सरकार के समक्ष प्रस्तुत की गयी थी। 12 मार्च, 2018 को राज्य सरकार द्वारा 18 अशैक्षणिक पदों हेतु विज्ञापन जारी करने के निर्देश दिये गये। 25.03.2018 को राज्य स्तरीय समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित हुआ। चार सदस्यीय चयन कमेटी बनायी गयी, जिसमें कालेज के नोमिनी, यूनिवर्सिटी के नोमिनी, सरकार के नोमिनी शामिल थे। लिखित परीक्षा हुई, टाइपिंग एवं स्टेनो परीक्षा हुई, साक्षात्कार हुआ और विधिक प्रक्रिया अपनाते हुए उन्हें नियुक्तियां दी गयीं। सरकार बदलते ही राजनीतिक दुर्भावना से उन कर्मचारियों को सेवा के दो वर्ष पूर्ण करने के बाद भी न तो नियमित किया गया और न ही अन्य वेतन लाभ और परिलाभ दिये गये और अचानक सातवें वेतन आयोग की जगह छठे वेतन आयोग के अनुसार उन्हें वेतन दिया गया। माननीय अध्यक्ष जी, हद तो तब हो गयी जब चार वर्ष की सेवा पूर्ण करने के बाद अचानक 18 कर्मचारियों की बिना किसी आधार के सेवा ही समाप्त कर दी गयी। जब उनकी सरकार ने, मंत्री ने, प्रशासन ने नहीं सुनी तो वे हाई कोर्ट गये।

(समय: 12.19 बजे)

(श्री जे.पी. चन्देलिया, सभापति, पदासीन)

हाई कोर्ट द्वारा 7 मई, 2022 को आदेश पर स्टे लगा दिया गया और 77 दिन बाद कालेज डबल बेंच में गया और 24 जनवरी, 2023 को हाई कोर्ट की डबल बेंच ने भी इंजीनियरिंग कालेज, बीकानेर की अपील खारिज कर दी। माननीय सभापति जी, हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने फैसला कर दिया, कालेज के आदेश को स्टे कर दिया। डबल बेंच ने कार्मिकों के पक्ष में फैसला करते हुए कालेज की अपील को खारिज कर दिया, फिर भी कानून का राज नहीं है। वहां किस तरह का राज है कि उनके 18 कर्मचारियों को फिर भी नियुक्ति नहीं दी जा रही, उन्हें सेवा में नहीं लिया जा रहा। आज वे 10 महीनों से दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं, आन्दोलन कर रहे हैं। उनके परिवार के समक्ष अपना पेट पालने का संकट खड़ा हो गया है।

माननीय सभापति जी, सरकार से निवेदन करना चाहूंगा, आज भी ईसीबी में 116 पद रिक्त पड़े हैं। 18 कर्मचारियों को बिना किसी विधिक प्रक्रिया अपनाये इस तरह निकाल दिया गया है। नियमित प्रक्रिया से उनकी

(श्री बिहारीलाल)

नियुक्ति हुई है, उन्हें न्याय दिलाने का काम करें। पूरा बीकानेर आन्दोलनरत है। सरकार अपनी हठधर्मिता छोड़े, अपना यह पक्षपातपूर्ण रवैया छोड़े और कार्मिकों के साथ न्याय करे। धन्यवाद।

श्री सभापति: 295, श्रीमती अनिता भदेल।

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

अजमेर शहर में राजकीय विद्यालयों के पतों में परिवर्तन

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): सभापति महोदय, अजमेर शहर में कई सरकारी स्कूल हैं जिनका नाम और मूल पता कुछ और है, किन्तु कई सालों से चल कहीं ओर रहे हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं में ऐसे शहरी स्कूलों में जिन परीक्षार्थियों का केन्द्र आता है उन्हें परेशानी होती है। परीक्षार्थी प्रवेश कार्ड पर अंकित पते के अनुसार सम्बन्धित सेंटर पर पहुंचते हैं तो स्कूल नये पते पर संचालित होने की जानकारी मिलती है। ऐसे परीक्षार्थी केन्द्र पर पहुंचने में देरी के चलते परीक्षा देने से वंचित भी रह जाते हैं। राजकीय बाउमावि, नगरा भजनगंज, भजनगंज में है, लेकिन इसके नाम के साथ नगरा जुड़ा हुआ है। यदि विद्यालय का नाम राबाउमावि, भजनगंज किया जाये तो परीक्षार्थियों के साथ ही सरकारी दस्तावेजों में भी व शिक्षा विभाग में कार्यरत कार्मिकों को भी सुविधा होगी। राउमावि, नगरा बालूपुरा रोड; राउमावि, ओसवाल जैन पट्टी कटला; रामावि, बालूपुरा व राउमावि, बालूपुरा पुलिस लाइन जैसे स्कूल हैं। कई राजकीय विद्यालयों के डाक पते अधूरे हैं। जैसे राबाउमावि, श्रीनगर रोड का संचालन पाल बीछला में हो रहा है। यदि इसका नाम राबाउमावि, पाल बीछला श्रीनगर रोड किया जाये तो अनजान भी सही पते पर पहुंच सकता है। राउमावि नगरा बालूपुरा रोड प्रकाश रोड पर संचालित है, यदि इसका नामकरण राउमावि प्रकाश रोड किया जाये तो सभी को सुविधा होगी। राउमावि, पीपल का कुआं धोलाभाटा क्षेत्र में अवस्थित है। इस अधूरे पते के साथ धोलाभाटा जोड़ दिया जाये तो डाक का पूरा पता होने से किसी भी डाक को गंतव्य स्थान पर पहुंचाने में सुविधा होगी।

राउप्रावि जनता कालोनी, घी मण्डी नागफनी, गुर्जर बस्ती, भोपों का बाड़ा, भागीरथ भवन के नाम से स्कूलों का नामकरण चला आ रहा है, जिन्हें आज की परिस्थितिनुसार संशोधन की आवश्यकता है। अतः परीक्षार्थियों एवं अभिभावकों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए ऐसे विद्यालयों के नामकरण एवं पते में संशोधन आवश्यक है। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री प्रताप सिंह।

छीपाबड़ौद स्थित विशिष्ट लहसुन मण्डी में साफ-सफाई की समुचित व्यवस्था

श्री प्रताप सिंह (छबड़ा): माननीय सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र छबड़ा के छीपाबड़ौद कस्बे में लहसुन की विशिष्ट मण्डी है। हाड़ौती क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में लहसुन की खेती की जाती है। राज्य सरकार द्वारा छीपाबड़ौद में विशिष्ट लहसुन मण्डी का निर्माण कराया गया है। राजस्थान प्रदेश के किसानों सहित मध्यप्रदेश के किसान भी प्रतिदिन अपनी लहसुन की फसल का बेचान करने के लिए विशिष्ट लहसुन मण्डी छीपाबड़ौद में आते हैं। उक्त लहसुन मण्डी में कई प्रकार की समस्याएं व्याप्त हैं। मण्डी परिसर कच्चा होने के कारण कीचड़ व गन्दगी बनी रहती है। लहसुन मण्डी परिसर में पानी की निकासी के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। मंडी में साफ-सफाई की समुचित व्यवस्था नहीं होने के कारण गंदगी का अम्बार लगा रहता है। मण्डी परिसर में असामाजिक तत्व घूमते रहते हैं। मण्डी परिसर में पुलिस चौकी नहीं होने के कारण आये दिन चोरी की घटनाएं होती रहती हैं। सरकार द्वारा 08 बीघा भूमि आबंटित की गई है, किन्तु अभी तक मंडी परिसर में उसको शामिल नहीं किया गया है। लहसुन मण्डी को पूर्व में आबंटित की गई भूमि की चारदीवारी नहीं होने के कारण परिसर में आवारा पशु अंदर घुस जाते हैं। आबंटित भूमि की चारदीवारी कराया जाना नितांत आवश्यक है। विशिष्ट लहसुन मण्डी छीपाबड़ौद को छबड़ा मण्डी से अलग किया जाए और सचिव व कार्मिकों की नियुक्ति की जाये।

निवेदन है कि विशिष्ट लहसुन मण्डी छीपाबड़ौद को आबंटित भूमि की चारदीवारी सहित अन्य समस्याओं का समाधान किये जाने हेतु आवश्यक निर्देश प्रदान करावें। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री जोगिन्दर सिंह अवाना।

गुर्जर समुदाय के आर्थिक दृष्टि से कमजोर छात्रों हेतु समुचित शिक्षा व्यवस्था

श्री जोगिन्दर सिंह अवाना (नदबई): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 295 के तहत बोलने का मौका दिया उसके लिए धन्यवाद।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आपने जो 295 का लिखकर दिया है, kindly keep confined to it.

श्री जोगिन्दर सिंह अवाना (नदबई): महोदय, उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि आज वर्तमान में प्रतिस्पर्धा की भावना बच्चों में रहती है। गुर्जर समाज के अधिकतर निवासी पहाड़ों में रहते हैं, कमाई का भी कोई साधन नहीं है तथा पशुपालन एवं खेती करना ही मुख्य धंधा है। अपने बालकों की जयपुर में प्राइवेट कोचिंग सेन्टरों की फीस नहीं भर सकते तथा बसों का इतना सारा किराया भी देने में असमर्थ हैं।

सभापति महोदय, मेरा निवेदन है कि सभी ग्रामीण क्षेत्रों से 12वीं पास करके कम्पीटिशन परीक्षाओं में हिस्सा लेने के लिये जयपुर में कोचिंग एवं जयपुर यूनिवर्सिटी में पढ़ सकें, इसलिए जयपुर शहर के बीच में कहीं पर भी उचित जगह पर बालिकाओं के लिए साहू माता छात्रावास एवं छात्रों के लिये देवनारायण छात्रावास के नाम से, दो अलग-अलग नाम से भूमि आबंटित करने का कष्ट करें। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री अशोक डोगरा।

बूंदी शहर में मानधाता बालाजी तक सड़क निर्माण

श्री अशोक डोगरा (बूंदी): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया व कार्य संचालन के नियम 295 के तहत बूंदी विधान सभा क्षेत्र के बूंदी शहर के धार्मिक आस्था केन्द्र मानधाता बालाजी तक सुगम पहुंच हेतु कार्य कराने बाबत।

महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र बूंदी के बूंदी शहर की पहाड़ी पर प्रसिद्ध धार्मिक आस्था केन्द्र मानधाता बालाजी स्थित है। यहां पर सैकड़ों दर्शनार्थी रोजाना दर्शन हेतु जाते हैं परन्तु यहां पर जाने के लिए कोई रास्ता सुगम नहीं है। इसी पहाड़ी पर बाबा मीरा साहब का स्थान है, जहां तक सरकार द्वारा सीसी सड़क/बिजली व पानी आदि सभी सुविधाएं की हुई हैं। मानधाता बालाजी के यहां हर वर्ष 4-5 दिवसीय मेला लगता है, जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं परन्तु न तो यहां पर सीढ़ियां हैं और न ही सीसी सड़क, साथ ही बिजली पानी की भी कोई व्यवस्था नहीं है। इस सम्बन्ध में मैंने विधायक कोष से 20 लाख रुपये की अनुशंसा की हुई है, परन्तु इस पर कोई स्वीकृति जारी नहीं की जा रही है। इसी प्रकार कोटा-बूंदी सांसद महोदय द्वारा 50 लाख रुपये की अनुशंसा की हुई है, जिस पर भी स्वीकृति नहीं दी जा रही है, जबकि इसी पहाड़ी पर अन्य समुदाय के स्थान पर सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। यह भेदभाव मानधाता बालाजी के श्रद्धालुओं को सहन नहीं हो रहा है और वो आये

(श्री अशोक डोगरा)

दिन इस बाबत जन-प्रतिनिधियों व प्रशासन को उलाहना देते आ रहे हैं और आन्दोलन करने की चेतावनियां दी जा रही हैं।

अतः मीरा साहब के स्थान की तरह ही मानधाता बालाजी तक सुगम पहुंच के लिये सड़क/सीढ़ियां व यहां पर बिजली पानी की समुचित व्यवस्था के कार्य कराये जाने अति आवश्यक हैं। इसमें यदि वन विभाग की तरफ से कोई रोक है तो वन विभाग के माध्यम से ही कार्य कराये जाकर यहां के श्रद्धालुओं को राहत देना अति आवश्यक है। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री संजय शर्मा।

अलवर शहर में कचरा संग्रहण

श्री संजय शर्मा (अलवर शहर): सभापति महोदय, नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के तहत निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र अलवर शहर में नगर परिषद द्वारा प्रतिमाह करोड़ों रुपये खर्च करने के बाद भी सफाई व्यवस्था चरमराई हुई है। नगर परिषद ने शहर में सफाई कार्य के लिए प्रतिमाह करीब 55 लाख रुपये का ठेका दिया हुआ है। सफाई कर्मियों को हर माह 56 करोड़ रुपये से ज्यादा वेतन का भुगतान किया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी शहर की सफाई व्यवस्था सुचारु रूप से नहीं हो रही है। हर वर्ष सफाई रैंकिंग में अलवर शहर पिछड़ रहा है। शहर में सफाई व्यवस्था में पिछड़ने के पीछे एक कारण डोर-टू-डोर नियमित कचरा संग्रहण की व्यवस्था का नहीं होना है। नगर परिषद के पास नियमित कचरा संग्रहण हेतु ऑटो टिपरों का भी अभाव है। अलवर नगर परिषद में 65 वार्ड होने के बाद भी प्रत्येक वार्ड के लिए अलग से ऑटो टिपरों की व्यवस्था नहीं है, जिस कारण से वार्डों से नियमित कचरा संग्रहण नहीं होता है और लोग कचरे को खाली स्थानों पर फेंकने को मजबूर होते हैं जिससे शहर में जगह-जगह कचरे के ढेर नजर आते हैं, जिसके कारण आवारा पशुओं का सड़कों पर ही जमावड़ा लगा रहता हैं और आवारा पशु पड़े हुए कचरे में भी मुंह मारते रहते हैं।

अतः नियम 295 के तहत मैं आपके माध्यम से माननीय नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री महोदय से मांग करता हूं कि नगर परिषद, अलवर में प्रत्येक वार्ड के लिए ऑटो टिपरों की व्यवस्था कर सफाई की समस्या का निराकरण कर आमजन को राहत प्रदान करने की कृपा करें।

श्री सभापति: श्री बलवीर सिंह लूथरा।

रायसिंहनगर के शहीद भगतसिंह महाविद्यालय एवं सरकार के मध्य एम.ओ.यू. की अनुपालना

श्री बलवीर सिंह लूथरा (रायसिंहनगर): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव। मेरे विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर में संचालित शहीद भगत सिंह महाविद्यालय, रायसिंहनगर को वर्ष 1983-84 में राज्य सरकार ने इस महाविद्यालय को अनुदान पर लिया। जुलाई 2011 को अनुदानित कर्मचारियों का राजकीय सेवा में समायोजन कर दिया गया। वर्तमान में महाविद्यालय पूर्ण रूप से निजी महाविद्यालय के रूप में संचालित है। आयुक्तालय कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर के पत्र क्रमांक एफ4(131)आयो/आकाशि/2020-21 पार्ट/1847 दिनांक 23.07.2021 आदेशानुसार माननीय मुख्य मंत्री महोदय की बजट घोषणा वर्ष 2019-20 की अनुपालना में राज्य सरकार के आदेश दिनांक 01 अगस्त, 2020 के द्वारा राज्याधीन किये गये शहीद भगतसिंह महाविद्यालय, रायसिंहनगर, जिला श्रीगंगानगर के पास उपलब्ध समस्त चल-अचल सम्पत्ति का हस्तान्तरण सन्दर्भित मंत्रिमण्डल आज्ञा की अनुपालना में राज्य सरकार के हक में दिनांक 02.08.2021 तक किया जाना था। इस कार्य हेतु पूर्व में एमओयू सम्पादित करवाने हेतु कालेज शिक्षा आयुक्तालय, जयपुर, राजस्थान द्वारा आदेशित किया गया था। महाविद्यालय में वर्ष 1991 से राज्य सरकार के आदेशानुसार स्थानीय एसडीएम को प्रशासक नियुक्त कर दिया गया था, जो कि आज दिनांक तक नियुक्त हैं। महाविद्यालय कार्मिकों की कुल देनदारियां लगभग 7 करोड़ रुपये बनती हैं, जो महाविद्यालय द्वारा अवहनीय हैं।

उल्लेखनीय है कि महाविद्यालय में आयुक्तालय कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर से एमओयू सम्बन्धित पत्रानुसार महाविद्यालय के अध्यक्ष प्रबंध समिति को आदेशित किया गया है, जबकि महाविद्यालय में वर्ष 1991 में प्रबंध समिति के भंग हो जाने पर राजस्थान सरकार द्वारा पत्र क्रमांक 11/20/शिक्षा-5/89 दिनांक 14.02.1991 के आदेशानुसार उप जिलाधीश, रायसिंहनगर (एसडीएम) को आगामी आदेश तक संस्था का प्रशासक नियुक्त किया गया है।

निवेदन है कि आयुक्तालय कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर व प्रशासक, एसडीएम शहीद भगतसिंह महाविद्यालय, रायसिंहनगर से सामंजस्य स्थापित कर एमओयू को संपादित करवाने का श्रम करें। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्रीमती चन्द्रकान्ता जी मेघवाल।

केशोरायपाटन में अतिवृष्टि से फसलों का नुकसान

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (केशोरायपाटन): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत केशोरायपाटन विधान सभा में अतिवृष्टि से हुए नुकसान के मुआवजा हेतु विशेष उल्लेख प्रस्ताव। पिछले वर्ष अगस्त माह में हुई अतिवृष्टि व चंबल नदी में आई बाढ़ से केशोरायपाटन विधान सभा क्षेत्र में अनेक कच्चे-पक्के मकान, सरकारी भवन, विद्यालय भवन, आंगनबाड़ी, श्मशान, अस्पताल, मंदिर आदि भवन क्षतिग्रस्त हो गए, सड़कें पूरी तरह से उखड़ गईं तथा अनेक जगह पानी के तेज बहाव के कारण पुलियाएं टूट गईं, जिससे आवागमन बाधित हो गया था। पशुपालकों का पशुधन एवं चारा बह गया। अतिवृष्टि एवं बाढ़ के कारण हुए नुकसान का मेरे द्वारा अवलोकन करने के बाद पूरी स्थिति से प्रशासन को अवगत करवाया गया, बावजूद इसके आज तक किसी को कोई सहायता राशि प्राप्त नहीं हुई है या किसी को हुई भी तो नाममात्र हुई है।

क्षेत्र का अधिकांश हिस्सा चंबल नदी के किनारे बसा हुआ है, जिनमें मुख्य रूप से दर्जनों गांव, जिसमे डोलर, कोटाखुर्द, जाड़ला, बगली, बहढावली, खाखटा, पीपल्दा थाग, जगदरी, पाली, चाण्दाखुर्द, आजन्दा, घाट का बराना, गोहाटा, जाड़ला, बड़ाखेड़ा, माखीदा, बसवाडा, रोटेदा आदि गांव एवं पंचायतें हैं, जिनमें व्यापक नुकसान हुआ है। जिनमें निजी एवं सरकारी सम्पत्तियों का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। इन्हें दुरुस्त करवाने के लिए कोई फंड जारी नहीं हुआ है। मेरा अनुरोध है कि क्षेत्र में हुए नुकसान हेतु शीघ्र सहायता राशि उपलब्ध कराई जाए व जिन भवनों, सम्पत्तियों का नुकसान हुआ है, उनको चिह्नित कर दुरुस्त करवाएं।

अतः विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से निवेदन है कि उक्त खराबे व नुकसान का मुआवजा शीघ्र देने हेतु आदेश राज्य सरकार को प्रदान करने की कृपा करें।

श्री सभापति: श्री गोपाल लाल शर्मा।

माण्डलगढ़ में सड़कों का नव-निर्माण एवं क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत

श्री गोपाल लाल शर्मा (माण्डलगढ़): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम 295 के तहत

(श्री गोपाल लाल शर्मा)

विशेष उल्लेख प्रस्ताव। निवेदन है कि प्रक्रिया एवं कार्य संचालन के नियमों के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के जरिए सरकार से आग्रह है कि जिला भीलवाड़ा में माण्डलगढ़ विधान सभा क्षेत्र की सड़कों का नव निर्माण व रख-रखाव में पिछले सवा चार साल के दौरान भेदभावपूर्ण रवैया अपनाया गया है। विधान सभा क्षेत्र की अहम लाइफ लाइन काम करने वाली सड़कें, जिनके लिए मेरे द्वारा बार-बार सरकार को अवगत करवाने के बावजूद पिछले सवा चार साल में भी क्षतिग्रस्त पड़ी हुई हैं। कुछ सड़कों की स्वीकृति जारी होने के बावजूद कार्य प्रारम्भ नहीं किये और जो सड़कें इन सालों में नव निर्माण पेचवर्क किये गये हैं, उनमें गुणवत्ता का ध्यान नहीं रखा गया तथा कुछ सड़कों की घोषणा की गई, उनका कार्य अभी तक शुरू नहीं हुआ है। कोटड़ी से ककरोलिया घाटी, राजगढ़ काछोला सड़क, कोटड़ी से नन्दराय बीगोद तक सड़क, बिजौलिया से शकरगढ़ सड़क, त्रिवेणी से सिंगोली सड़क मय मैनाली नदी पुलिया, जो 2019 में बह चुका था तथा और जो भी मेरी विधान सभा में क्षतिग्रस्त सड़कें हैं, उनका कार्य अविलम्ब प्रारम्भ करवाया जावे।

श्री सभापति: श्री गोपी चन्द जी मीणा।

बिशनिया ग्राम पंचायत (जहाजपुर) में सरपंच एवं ग्राम विकास अधिकारी द्वारा अनियमितताएं

श्री गोपी चन्द मीणा (जहाजपुर): राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख। मैं सदन का ध्यान आकर्षित करते हुए अवगत कराना चाहता हूं कि जहाजपुर विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की मूल अवधारणा को दरकिनार करते हुए ग्राम पंचायत बिशनिया, पंचायत समिति कोटड़ी के सरपंच एवं ग्राम विकास अधिकारी द्वारा नरेगा में मृत व्यक्तियों के नाम से फर्जी भुगतान व अनियमितताएं की जा रही हैं। उक्त प्रकरण जिला कलेक्टर, भीलवाड़ा को बैठक में परिवाद संख्या 27/21 दिनांक 16 जून, 2021 को श्री महावीर धाकड़, निवासी ग्राम पंचायत बिशनिया, तहसील कोटड़ी दर्ज करवाया गया था। जिसके पश्चात् मुख्य कार्यकारी अधिकारी, भीलवाड़ा द्वारा अध्यक्ष महोदय (सतर्कता) द्वारा विचार-विमर्श पश्चात् कमेटी गठित की गई। उक्त जांच कमेटी द्वारा पत्रांक 10557 दिनांक 02/09/2021 को रिपोर्ट प्रस्तुत कर अवगत कराया गया कि एक ही व्यक्ति ने दो जॉब कार्ड जारी कर मृत व्यक्ति के खाते में राशि का हस्तान्तरण किया गया है।

(श्री गोपी चन्द मीणा)

उक्त प्रकरण में अध्यक्ष, सतर्कता द्वारा प्रस्तुत तथ्यों के आधार पर दोषी मेट व ग्राम विकास अधिकारी को निलंबन की कार्रवाई एवं दोषी सरपंच के विरुद्ध धारा 38 के अन्तर्गत कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये थे, किंतु आज दिनांक तक उक्त प्रकरण में उपरोक्त दोषी कार्मिकों व सरपंच के विरुद्ध कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई, जो कि घोर लापरवाही को दर्शाता है। नरेगा के निर्माण कार्यों की उच्च स्तरीय जांच करायें।

इस क्रम में मेरा आग्रह है कि उपरोक्त प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच कराते हुए दोषी कार्मिकों व जनप्रतिनिधि के विरुद्ध कठोर कार्रवाई अमल में लाये जाने का श्रम करावें।

श्री सभापति: श्री फूल सिंह मीणा।

देवाली (गिर्वा) स्थित राजकीय विद्यालय को भू-आवंटन एवं निर्माण स्वीकृति

श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव। निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र के गिर्वा क्षेत्र में ग्राम पंचायत, देवाली राजस्व ग्राम में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, देवाली ग्रामीण में विद्यालय 4 कमरों में चल रहा है, जिसमें बच्चों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। विद्यालय की जमीन उपलब्ध करवाने हेतु पिछले लम्बे समय से प्रार्थना पत्र जनप्रतिनिधि द्वारा प्रशासन को अनेक बार दे दिया, लेकिन अभी तक कहीं पर जमीन उपलब्ध नहीं करवाई गई है। ऐसी स्थिति में विद्यालय का सुचारु रूप से चलना सम्भव नहीं है। जिसमें न ही खेल मैदान है, न ही बैठने के लिए कमरे हैं और इन चार कमरों के अलावा एक इंच जमीन भी नहीं है। इस कारण चार वर्षों से लगातार मैंने विधान सभा में भी यूआईटी के सचिव को व जिला कलेक्टर को भी अनेक बार बताया, लिखकर दिया, मगर अभी तक इस विद्यालय के लिये कोई समस्या का समाधान करने की कोई कार्यवाही नहीं होने पर गांव व पंचायत में बहुत आक्रोश है।

अतः मैं सरकार से मांग करता हूं कि ऐसे में इन आदिवासी गरीब बालक-बालिकाओं को उचित शिक्षा मिलना सम्भव नहीं है, इसलिए विद्यालय के लिये जमीन आबंटन के लिए बजट स्वीकृत कर भवन बनाने की अनुमति प्रदान करावें। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री जब्बर सिंह सांखला।

आसीन्द में सभी राजकीय विभागों में रिक्त पद

श्री जब्बर सिंह सांखला (आसीन्द): सभापति महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र आसीन्द हुरड़ा में ऐसा कोई विभाग नहीं है जिसमें अधिकारियों/कर्मचारियों के पद भरे हुए हों। नगरपालिका में ईओ सहित कई पद खाली पड़े हैं, बदनोर में एसडीएम नहीं है। प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 90 प्रतिशत पद खाली हैं। चिकित्सा विभाग में कई डा. के पद खाली व कम्पाउण्डर व अन्य कई पद खाली हैं। पटवारी पूरे नहीं हैं, सचिव पूरे नहीं हैं। बिजली विभाग, जलदाय विभाग व तहसील कार्यालय में और अन्य सभी विभागों में कई पद खाली पड़े हुए हैं। इस वजह से शिक्षा, चिकित्सा, नगरपालिका, पंचायती राज विभाग में, बिजली विभाग में तथा ऐसे कई विभागों में आम गरीब तथा किसानों व आम जनता के कई कार्य अटके हुए हैं, इससे हर आम नागरिक परेशान है तथा विभागों में रोजाना चक्कर लगाकर आता है और उसका कार्य नहीं होता है। आसीन्द-हुरड़ा की जनता का कसूर सिर्फ इतना है कि उनका विधायक भाजपा का है और सरकार कांग्रेस की, यह बातें वहां आपके नेता बोलते भी हैं कि सरकार हमारी है।

मैं आपके माध्यम से प्रदेश के मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि इन सभी विभागों के अधिकारियों/कर्मचारियों की लिस्ट मंगवा कर जो पद खाली हैं उन्हें तुरन्त भरने की कृपा करावें, जिससे आम जनता को राहत मिल सके और राजस्थान में कोई सरकार है तथा जनता की सुन रही है, यह भी एहसास हो सके। धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री सभापति: श्रीमती संतोष।

अनूपगढ़ को नया जिला बनाया जाना

श्रीमती संतोष (अनूपगढ़): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम 295 के अंतर्गत अनूपगढ़ को राज्य का नया जिला बनाये जाने के सम्बन्ध में विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से निवेदन है कि मेरा निर्वाचन क्षेत्र अनूपगढ़ भारत-पाक अंतरराष्ट्रीय सीमा का सीमावर्ती उपखण्ड है। राज्य के प्रशासनिक ढांचे की मजबूती के लिए नये जिले बनाये जाने की आवश्यकता है। अनूपगढ़ जिला बनाने को लेकर

(श्रीमती संतोष)

लगभग 11 वर्षों से उपखण्ड अनूपगढ़ कार्यालय के सामने अनिश्चितकालीन धरना जारी है। प्रशासनिक आवश्यकता के आधार पर भी अनूपगढ़ सभी मापदण्ड पूर्ण करता है। अनूपगढ़ में प्रशासनिक दृष्टि से समस्त विभागों के कार्यालय स्थापित हैं। उपतहसील 2 केएलडी (365 हैड) व घड़साना उपखण्ड से जिला मुख्यालय 215-180 किमी. दूरी पर है। अनूपगढ़ भी जिला मुख्यालय से लगभग 130 किमी की दूरी पर है। आमजन को अपने जिला स्तरीय कार्यों के लिए जिला मुख्यालय जाना पड़ता है। मेरे क्षेत्र की स्थानीय जनता को परेशानी हो रही है, जिसमें समय व पैसे की भी बर्बादी होती है। अनूपगढ़ को जिला बनाने को लेकर मेरे द्वारा राजस्थान विधान सभा सत्र काल के दौरान सदन में और प्रतिनिधि मण्डल भी काफी बार माननीय मुख्य मंत्री जी से मिल चुका है।

(समय: 12.44 बजे)

(श्री सी.पी. जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

नये जिले बनाने को लेकर सरकार द्वारा कमेटी भी बनायी गई, लेकिन जिले की घोषणा नहीं हुई है। अनूपगढ़ मुख्यालय पर राज्य सरकार द्वारा 23 राज्य स्तरीय कार्यालय व 10 केन्द्र सरकार से सम्बन्धित कार्यालय हैं, जिसमें अनूपगढ़ भौगोलिक दृष्टि व प्रशासनिक स्तर पर भी सभी मापदण्ड पूर्ण करता है, लेकिन अभी तक क्रियान्विति नहीं हो पाई है। अनूपगढ़ को जिला बनाया जाना उचित है। अतः आपके माध्यम से राजस्व मंत्री जी का ध्यान अनूपगढ़ को जिला बनाने के लिए विशेष उल्लेख के माध्यम से आकर्षित कर रही हूं। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री गुरदीप सिंह।

संगरिया की रतनपुरा ग्राम सेवा सहकारी समिति में हुए घोटाले की निष्पक्ष जांच

श्री गुरदीप सिंह (संगरिया): अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमों के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से निवेदन है कि ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमिटेड, रतनपुरा तहसील संगरिया के तत्कालीन व्यवस्थापक श्री रमेश कुमार पुत्र श्री देवीलाल जाति-जाट साहरण निवासी रतनपुरा द्वारा-ग्राम सेवा सहकारी समिति, रतनपुरा में बने मिनी बैंक में जमा राशि कुल 13,38,42,825/- (अक्षरे तेरह करोड़ अड़तीस लाख बयालीस हजार आठ सौ पच्चीस रुपये) का घोटाला किया गया है। गांव के गरीब लोगों द्वारा उक्त रमेश कुमार साहरण के पास अपनी मेहनत की कमाई की राशि

(श्री गुरदीप सिंह)

समिति के सदस्य संख्या 1 से 397 तक के द्वारा एफ.डी. राशि 10,49,57,676/- व बचत खाता के कुल 193 सदस्यों द्वारा राशि 2,02,85,149/- तथा खाद की राशि 33,00,000/- कृषि यंत्र व स्वरोजगार लोन के पेटे राशि करीब 33,00,000/- एवं हिस्सा राशि 20,00,000/- जमा की थी। इस घोटाले की जांच एम.डी. दीपक कुकड़ व डी.आर. अमीलाल द्वारा जांच में अनियमितता पाये जाने व मामले की सही एवं निष्पक्ष जांच नहीं करने पर उन्हें ए.पी.ओ. किया गया था। इस प्रकरण में शीघ्र ही उचित कार्यवाही करने के लिए ग्रामीणों द्वारा सहकारी समिति लिमिटेड, रतनपुरा व हनुमानगढ़ के यहां धरना-प्रदर्शन भी किया जा चुका है तथा वर्तमान में सहकारी समिति, रतनपुरा में धरना-प्रदर्शन चल रहा है।

अतः निवेदन है कि इतने बड़े घोटाले की अविलम्ब किसी उच्च अधिकारी से निष्पक्ष जांच करवाकर गरीब ग्रामवासियों को उनकी राशि दिलवाई जाये तथा प्रकरण में घोटाला करने के लिए दोषियों के विरुद्ध भी समुचित कार्यवाही की जाये।

श्री अध्यक्ष: श्री शंकर सिंह रावत।

ब्यावर शहर को नया जिला बनाया जाना

श्री शंकर सिंह रावत (ब्यावर): अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख। ब्यावर को इसी बजट सत्र में जिला बनाने बाबत निवेदन है कि ब्यावर को जिला बनाने हेतु काफी वर्षों से ब्यावर की जनता एवं जनप्रतिनिधियों द्वारा आन्दोलन, धरना-प्रदर्शन किये जा रहे हैं।

जिला बनाने हेतु ब्यावर के आसपास के क्षेत्रों एवं जनप्रतिनिधियों द्वारा भी अपना समर्थन दिया जा चुका है लेकिन सरकार द्वारा मात्र कमेटी बनाकर जनता की भावनाओं के साथ न्याय नहीं किया जा रहा है। ये जिलों के पुनर्गठन/सृजन हेतु राज्य सरकार द्वारा दिनांक 28/05/2012 को श्री जी.एस. संधु, सेवानिवृत्त आई.ए.एस. की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया। इसके पश्चात् पुनः राज्य सरकार द्वारा दिनांक 20.01.2014 को श्री परमेशचन्द्र, सेवानिवृत्त आई.ए.एस. की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया था। इस कमेटी ने 2018 में राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी। इस कमेटी के सुझावों को भी सरकार ने कचरे के डिब्बे में डाल दिया और अब पुनः श्री रामलुभाया, सेवानिवृत्त आई.ए.एस. की अध्यक्षता में एक नई

(श्री शंकर सिंह रावत)

कमेटी का गठन कर दिया, जो छह माह में सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। जब सरकार ने पूर्व में गठित कमेटियों की रिपोर्ट पर ही अमल नहीं किया तो अब क्या गारंटी कि सरकार नई कमेटी के सुझावों/रिपोर्ट पर अमल करेगी जबकि पूर्व में तत्कालीन मुख्य मंत्री श्री भैरोंसिंह शेखावत द्वारा बनाये गये जिलों के दौरान किसी प्रकार से कोई कमेटी का गठन नहीं किया गया था।

अतः माननीय अध्यक्ष महोदय के माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है कि जन भावनाओं की कद्र करते हुए अपने आप में जिले की योग्यता रखने वाले शहर ब्यावर को इसी बजट सत्र में जिला बनाने की कृपा करावें। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: धन्यवाद। श्री रामप्रताप कासनियां।

सूरतगढ़, श्रीगंगानगर एवं हनुमानगढ़ क्षेत्रों में अतिवृष्टि एवं शीतलहर से फसलों के नुकसान का किसानों को मुआवजा

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़): अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से निवेदन है कि हाल ही शीतलहर से सरसों व चना की फसल का खराबा हो गया है। अधिकतम सरसों व चने की फसल 30 प्रतिशत से 50 प्रतिशत तक ख़राब हो गई है। सरकार को जो फसल में खराबा हुआ है उसकी सर्वे करवाकर पीड़ित किसानों को मुआवजा देकर राहत प्रदान करनी चाहिये, परन्तु देखने पर पता चला है कि सरकारी तंत्र अभी तक इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। पटवारी फील्ड में नहीं जाकर घर बैठे गिरदावरी कर रहे हैं व 10 प्रतिशत से 20 प्रतिशत कम खराबा दिखा रहे हैं। पटवारी से किसान मिलते हैं तब पटवारी किसानों को कहते हैं, कलेक्टर साहब व एसडीएम साहब ने कम खराबा आंकने के लिए कहा है। इससे प्रतीत होता है कि सरकार की मंशा फसल खराबा पीड़ित किसानों को न्याय करने की नहीं लगती है।

मेरा सदन के माध्यम से विशेष आग्रह है कि विधान सभा क्षेत्र सूरतगढ़, गंगानगर व हनुमानगढ़ जिले में शीतलहर से सरसों व चने की खराब हुई फसल का सही आकलन कर पीड़ित किसानों को फसल खराबे का मुआवजा दिलवाने का श्रम करें। जय हिन्द।

श्री अध्यक्ष: जो लिखा हुआ है उससे ज्यादा पढ़ना नहीं है। धन्यवाद।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल।

सदन पटल पर रखे गये पत्र

अधिसूचना

वित्त विभाग

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार वित्त विभाग की निम्न अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं:-

1. अधिसूचना संख्या: प.4(2)वित्त/कर/2023-25 दिनांक 10.02.2023 जिसके द्वारा नगरीय स्थानीय निकायों या सरकारी निकायों द्वारा आवंटित या विक्रीत अचल सम्पत्ति के संबंध में ऐसे प्राधिकरणों से लीज डीड प्राप्त करने से पूर्व निष्पादित प्रत्येक मध्यवर्ती और असम्यक रूप से स्टाम्पित दस्तावेजों पर देय स्टाम्प शुल्क में छूट प्रदान की गई है;
2. अधिसूचना संख्या: प.4(2)वित्त/कर/2023-26 दिनांक 10.02.2023 जिसके द्वारा लम्बे समय से लम्बित बकाया के मामलों में एमनेस्टी द्वारा ब्याज एवं शास्ति में शत-प्रतिशत तथा स्टाम्प शुल्क में 60 प्रतिशत छूट प्रदान की गई है;
3. अधिसूचना संख्या: प.4(2)वित्त/कर/2023-27 दिनांक 10.02.2023 जिसके द्वारा राजस्थान टाउनशिप पालिसी, 2002 एवं 2010 के तहत अनुमोदित प्रोजेक्ट के संबंध में निष्पादित असाइनमेंट की लिखत पर देय स्टाम्प ड्यूटी में छूट प्रदान की गई है;
4. अधिसूचना संख्या: प.4(2)वित्त/कर/2023-28 दिनांक 10.02.2023 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: प.4(2)वित्त/कर/2021-272 दिनांक 24.02.2021 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है;
5. अधिसूचना संख्या: प.4(2)वित्त/कर/2023-29 दिनांक 10.02.2023 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: प.4(2)वित्त/कर/2021-280 दिनांक 24.02.2021 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है;
6. अधिसूचना संख्या: प.4(2)वित्त/कर/2023-30 दिनांक 10.02.2023 जिसके द्वारा राजस्थान स्टाम्प नियम, 2004 में संशोधन किया गया है;
7. अधिसूचना संख्या: प.4(2)वित्त/कर/2023-31 दिनांक 10.02.2023

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

जिसके द्वारा कृषिक प्रयोजनों के लिए उपलब्ध करवाये जाने वाले विद्युत संयोजन के लिए निष्पादित करार पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क का परिहार किया गया है;

8. अधिसूचना संख्या: प.4(2)वित्त/कर/2023-32 दिनांक 10.02.2023 जिसके द्वारा दिव्यांगजन के पक्ष में निष्पादित स्थावर सम्पत्ति के हस्तान्तरण विलेख पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क में छूट प्रदान की गई है;

9. अधिसूचना संख्या: प.4(2)वित्त/कर/2023-33 दिनांक 10.02.2023 जिसके द्वारा 70 वर्ष या अधिक आयु वाले अथवा 80 प्रतिशत या अधिक दिव्यांगता वाले किसी व्यक्ति द्वारा उसके निवास पर दस्तावेजों के रजिस्ट्रीकरण किये जाने पर प्रभार्य फीस में छूट प्रदान की गई है;

10. अधिसूचना संख्या: प.4(2)वित्त/कर/2023-34 दिनांक 10.02.2023 जिसके द्वारा बहुमंजिला इमारतों में 50 लाख रुपये मूल्य तक के फ्लैट या आवासीय इकाई के दस्तावेजों पर प्रभार्य स्टाम्प ड्यूटी में छूट प्रदान की गई है;

11. अधिसूचना संख्या: प.4(2)वित्त/कर/2023-35 दिनांक 10.02.2023 जिसके द्वारा पथ विक्रताओं से लिए जाने वाले वचनबंध या घोषणा पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क में छूट प्रदान की गई है;

12. अधिसूचना संख्या: प.4(2)वित्त/कर/2023-36 दिनांक 10.02.2023 जिसके द्वारा परिवार के सदस्यों के पक्ष में निष्पादित दान की लिखत के दस्तावेजों पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क में छूट प्रदान की गई है;

13. अधिसूचना संख्या: प.4(2)वित्त/कर/2023-37 दिनांक 10.02.2023 जिसके द्वारा पारिवारिक व्यवस्थापन की लिखत पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क तथा रजिस्ट्रीकरण फीस में छूट प्रदान की गई है;

14. अधिसूचना संख्या: प.4(2)वित्त/कर/2023-38 दिनांक 10.02.2023 जिसके द्वारा भूमि कर के वर्तमान में बकाया के मामलों में एमनेस्टी द्वारा स्टाम्प शुल्क में 50 प्रतिशत तक की छूट तथा ब्याज एवं शास्ति में शत-प्रतिशत छूट प्रदान की गई है;

15. अधिसूचना संख्या: प.4(2)वित्त/कर/2023-39 दिनांक 10.02.2023 जिसके द्वारा भूमि कर की वर्तमान दरों में 50 प्रतिशत की कमी की गई है;

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

16. अधिसूचना संख्या: प.4(2)वित्त/कर/2023-40 दिनांक 10.02.2023 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: प.4(3)वित्त/कर/2018-198 दिनांक 12.02.2018 को विखंडित किया गया है;

17. अधिसूचना संख्या: प.4(2)वित्त/कर/2023-41 दिनांक 10.02.2023 जिसके द्वारा दस्तावेजों के रजिस्ट्रीकरण के प्रयोजनों के लिए जिलों तथा उप जिलों का गठन तथा उनकी सीमाओं का अवधारण किया गया है;

18. अधिसूचना संख्या: प.4(2)वित्त/कर/2023-42 दिनांक 10.02.2023 जिसके द्वारा दस्तावेजों के रजिस्ट्रीकरण के प्रयोजनों के लिए गठित किये गये जिलों तथा उप जिलों में उप-रजिस्ट्रारों की नियुक्ति की गई है;

19. अधिसूचना संख्या: प.4(2)वित्त/कर/2023-43 दिनांक 10.02.2023 जिसके द्वारा स्टार्ट-अप की स्थापना के प्रयोजनों के लिए निष्पादित 25 लाख रुपये मूल्य तक के ऋण की लिखत पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क में छूट प्रदान की गई है;

20. अधिसूचना संख्या: प.4(2)वित्त/कर/2023-44 दिनांक 10.02.2023 जिसके द्वारा स्टार्ट-अप के लिए कार्यस्थल की स्थापना के प्रयोजनों के लिए निष्पादित 50 लाख रुपये मूल्य तक के बाजार मूल्य वाली स्थावर सम्पत्ति के संबंध में हस्तान्तरण की लिखत या 10 वर्ष से अधिक कालावधि के पट्टे की लिखत पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क में छूट प्रदान की गई है;

21. अधिसूचना संख्या: प.4(2)वित्त/कर/2023-45 दिनांक 10.02.2023 जिसके द्वारा राजस्थान शहरी पेयजल, सीवरेज एवं आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड (रूडसिको) के पक्ष में हाउसिंग एण्ड अरबन डवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड (हुडको) द्वारा 2235 करोड़ रुपये के ऋण के लिए निष्पादित किये जाने वाले ऋण के करार की लिखत पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क में छूट प्रदान की गई है;

22. अधिसूचना संख्या: प.4(2)वित्त/कर/2023-46 दिनांक 10.02.2023 जिसके द्वारा 02 या अधिक कंपनियों के आमेलन, डिमर्जर या पुनर्गठन के आदेश से संबंधित हस्तान्तरण विलेख पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क में छूट प्रदान की गई है;

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

23. अधिसूचना संख्या: प.12(5)वित्त/कर/2023-98 दिनांक 10.02.2023 जिसके द्वारा कर की रिबेट और परादेय मांगों और विवादित रकम के निपटान के लिए एमनेस्टी स्कीम, 2023 लागू की गई है;

24. अधिसूचना संख्या: प.12(5)वित्त/कर/2023-99 दिनांक 10.02.2023 जिसके द्वारा कैप्टिव सौर ऊर्जा जनरेटिंग संयंत्र से उत्पादित ऊर्जा के उपभोग पर विद्युत शुल्क की दर रुपये 0.60 प्रति यूनिट से घटा कर 0.40 प्रति यूनिट की गई है;

25. अधिसूचना संख्या: प.12(5)वित्त/कर/2023-100 दिनांक 10.02.2023 जिसके द्वारा राज्य में संचालित वाणिज्यिक उड़ानों के लिए एविएशन टरबाइन फ्यूल पर 02 प्रतिशत से अधिक देय वैट पर छूट प्रदान की गई है;

26. अधिसूचना संख्या: प.12(5)वित्त/कर/2023-101 दिनांक 10.02.2023 जिसके द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की अनुसूची-2 में संशोधन किया गया है;

27. अधिसूचना संख्या: प.6(179)परि/कर/मु./2023-24/1 दिनांक 10.02.2023 जिसके द्वारा नष्ट हो चुके वाहन, पुरानी बकाया तथा ऐसे वाहन जिनके पंजीयन प्रमाण-पत्र 24 फरवरी, 2021 से पूर्व समर्पित हैं, हेतु कर शास्ति एवं ब्याज के लिए एमनेस्टी स्कीम लागू की गई है;

28. अधिसूचना संख्या: प.6(179)परि/कर/मु./2023-24/2डी दिनांक 10.02.2023 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: प.6(179)परि/कर/मु./2019-20/2 दिनांक 10.07.2019 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है;

29. अधिसूचना संख्या: प.6(179)परि/कर/मु./2023-24/3 दिनांक 10.02.2023 जिसके द्वारा दो पहिया गैर-परिवहन यानों और दस तक की बैठक क्षमता वाले चार पहिया गैर-परिवहन यानों के स्वामित्व के अन्तरण के समय पर संदेय अतिरिक्त एकबारीय कर में 50 प्रतिशत की छूट प्रदान की गई है;

30. अधिसूचना संख्या: प.6(179)परि/कर/मु./2023-24/4 दिनांक 10.02.2023 जिसके द्वारा नगरपालिका/नगर सुधार न्यास की सीमाओं में केवल सीएनजी से चलने वाली मंजिली गाड़ियों पर देय मोटर यान कर में छूट प्रदान की गई है;

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

31. अधिसूचना संख्या: प.6(179)परि/कर/मु./2023-24/3जी दिनांक 10.02.2023 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: प.6(179)परि/कर/मु./2019-20/3 दिनांक 10.07.2019 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है;

32. अधिसूचना संख्या: प.6(179)परि/कर/मु./2023-24/5 दिनांक 10.02.2023 जिसके द्वारा स्ट्रांग हाईब्रिड इलेक्ट्रिक वाहनों पर संदेय एकबारीय कर में 25 प्रतिशत की छूट प्रदान की गई है;

33. अधिसूचना संख्या: प.7(47)परि/नियम/मु./87/पार्ट1/1 दिनांक 10.02.2023 जिसके द्वारा खान विभाग से प्राप्त ई-रवन्ना की सूचना के आधार पर अतिभरण के प्रकरणों पर शमन राशि के लिए जिला परिवहन अधिकारी को प्राधिकृत किया गया है; एवं

34. अधिसूचना संख्या: प.7(3)परि/नियम/मु./2021/2 दिनांक 10.02.2023 जिसके द्वारा महिला आवेदकों को आटो रिक्शा/टैक्सी कैब/मैक्सी कैब पर परमिट के संबंध में संदेय फीस से छूट प्रदान की गई है।

श्री अध्यक्ष: श्री बुलाकी दास कल्ला।

प्रतिवेदन एवं लेखे

लोकायुक्त राजस्थान का 34वां वार्षिक प्रतिवेदन (वर्ष 2022)

श्री बुलाकी दास कल्ला (शिक्षा मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान लोकायुक्त एवं उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1973 की धारा-12(5) के अंतर्गत लोकायुक्त राजस्थान का 34वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2022 सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष: श्री परसादी लाल।

राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, जयपुर के वार्षिक प्रतिवेदन (वर्ष 2020, 2021 एवं 2022)

श्री परसादी लाल (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, 2005 की धारा-44 के अंतर्गत राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, जयपुर के वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2020, 2021 एवं 2022 सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष: श्री शान्ती कुमार धारीवाल।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नांकित प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखता हूं:-

आउटपुट बजट (वर्ष 2021-22) एवं आउटकम बजट (वर्ष 2022-23)

1. आउटपुट बजट वर्ष 2021-22 एवं आउटकम बजट वर्ष 2022-23;

राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग, जयपुर का वार्षिक प्रतिवेदन (वर्ष 2022-23)

2. मानव अधिकार अधिनियम, 1993 की धारा-28 की उप धारा 2 के अंतर्गत राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग, जयपुर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2022-23 ।

आय-व्ययक

आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2023-24 के पैरा संख्या 40 का सदन पटल पर रखा जाना

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2023-24 के पैरा संख्या 40 का अंश सदन के पटल पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष: पढ़ना है?

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): नहीं।

(आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2023-24 के पैरा संख्या 40 के अंश के लिए कृपया परिशिष्ट देखें)

श्री अध्यक्ष: माननीय श्री परसादी लाल जी मीणा।

प्रवर समिति को निर्दिष्ट विधेयक

राजस्थान स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक, 2022 पर गठित प्रवर समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन हेतु नियत समय में वृद्धि

श्री परसादी लाल (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक, 2022 पर गठित प्रवर समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन हेतु नियत समय को वर्तमान सत्र में प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने की दिनांक तक बढ़ा दिया जाय।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि प्रवर समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन हेतु नियत समय को वर्तमान सत्र में प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने की दिनांक तक बढ़ा दिया जाय?

(स्वीकृत)

प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

घोषणा

आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2023-24 हेतु उपलब्ध समय का बंटवारा

मुझे सदन को सूचित करना है कि आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2023-24 पर सामान्य वाद-विवाद के लिये लगभग 16 घंटे उपलब्ध हैं। उपलब्ध समय में सरकार द्वारा उत्तर दिये जाने का समय भी सम्मिलित है। मैं विभिन्न पार्टियों के लिये समय का बंटवारा निम्न प्रकार करता हूं:-

क्र.सं	पार्टी/दल का नाम एवं सदस्य संख्या	आबंटित समय
1	इण्डियन नेशनल कांग्रेस (108)	8 घंटे 36 मिनट
2	भारतीय जनता पार्टी (71)	5 घंटे 41 मिनट
3	राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (03)	15 मिनट
4	कम्युनिस्ट पार्टी आफ इंडिया (मार्क्सिसिस्ट) (02)	10 मिनट
5	भारतीय ट्राइबल पार्टी (02)	10 मिनट
6	राष्ट्रीय लोक दल (01)	5 मिनट
7	निर्दलीय (13)	01 घंटा 03 मिनट

सामान्य वाद-विवाद राजस्थान राज्य के आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2023-24 पर, श्री राजेन्द्र राठौड़।

आय-व्ययक

आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2023-24 पर सामान्य वाद-विवाद

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): अध्यक्ष महोदय, यह सदन, सदन के नेता के तीसरे कार्यकाल के अंतिम बजट भाषण पर चर्चा कर रहा है। अध्यक्ष महोदय, मेरा दीर्घ संसदीय जीवन रहा, इस सदन में कई बजटों की प्रस्तुति का मैं साक्षी

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

रहा, परंतु इस बार बजट प्रस्तुत करने से पूर्व जिस प्रकार प्रस्तुत किये जाने वाले बजट का महिमा मंडन किया गया, राजस्थान का कोई ऐसा हिस्सा नहीं बचा जहां बड़े-बड़े होर्डिंग्स, कोई समाचार पत्र नहीं बचा जहां बड़े-बड़े विज्ञापन मुख्य मंत्री जी के मुस्कराते हुए फोटो, "बचत, राहत और बढ़त" इस थीम के साथ एक तरह से बजट की थीम को भी बजट से पूर्व जनता के सामने लीक करने का काम भी किया। अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में पहली बार 11,500 ग्राम पंचायत, 286 पंचायत समितियां, 200 के लगभग नगर निगम, नगर परिषद, नगरपालिकाएं, 3000 से ज्यादा महाविद्यालयों को सरकारी फरमान के माध्यम से यह बाध्य किया गया कि जब बजट प्रस्तुत हो तो ऑनलाइन उस बजट को सुनें।

अध्यक्ष महोदय, इस बार बजट की प्रस्तुति भी बड़ी बेजोड़ रही, बड़े नायाब तरीके से बजट प्रस्तुत किया गया। पुराने सदन के नेता हैं, पुराने मुख्य मंत्री हैं, अपने पुराने बजट से मोह नहीं छोड़ पाये और उसका परिणाम यह रहा कि इस संसदीय इतिहास में पहली बार पुराना बजट पढ़ा गया। अध्यक्ष महोदय, यह मानवीय भूल हो सकती है, पर बजट एक गोपनीय दस्तावेज है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, जनता के सामने बहुत क्लीयर जाना चाहिये, पुराना बजट नहीं पढ़ा है, बजट में एक पन्ना पुराना था, यह क्लीयर जाना चाहिये। जनता में यह मैसेज नहीं जाना चाहिये कि पुराना बजट पढ़ा। यह मैसेज जाना चाहिये कि नये बजट में एक पेज अलग था।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): अध्यक्ष महोदय, मैं अपने आपको करेक्ट करता हूं, आपने सही फरमाया 7 मिनट तक जो एक पेज पढ़ा गया, वह पुराना था। अध्यक्ष महोदय, बजट की एक सैंक्टिटी है, एक पवित्रता है। मुझे अफसोस इस बात का है कि सदन में बजट की प्रस्तुति से पहले...

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): पूरा नहीं पढ़ा गया, कुछ लाइनें पढ़ी गईं और उसके बाद अपने आपको दुरुस्त कर लिया गया। यह आना चाहिये। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: राजेन्द्र जी को राय देने की जरूरत है? मिस्टर चन्द्रभान सिंह आक्या, आपको अभी ट्रेनिंग लेनी है। राठौड़ साहब इतने कमजोर हो गये कि उनको सपोर्ट की जरूरत पड़े? (व्यवधान) सीनियर मंत्री हैं तो वह भी सीनियर पार्लियामेंटेरियन हैं, जरूरत नहीं उनको। आप अपने आपको अच्छा पार्लियामेंटेरियन बनाने की कोशिश करो। बाकी आप जिस तरह का बिहेवियर कर रहे हो उससे सदन में अच्छी गरिमा नहीं रहती।

(श्री अध्यक्ष)

मान्यवर, मैं बार-बार यह कहता हूं कि हमारे सदन को देश की सारी नौजवान पीढ़ी यू-ट्यूब से देखती है। हम जिस तरह का बिहेवियर करते हैं, उस तरह सदन के प्रति लोगों की रुचि बढ़ती है। मान्यवर, इसलिए मैं आपसे अपेक्षा करूंगा, कृपया अपने टेम्पटेशन को रोकें। माननीय राठौड़ साहब।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): अध्यक्ष महोदय, आपने सही फरमाया, संसदीय कार्य मंत्री जी ने भी सही कहा कि कुछ अंश पढ़े गये। अध्यक्ष महोदय, मुझे एतराज इस बात का है कि जब मुख्य मंत्री जी सदन के वित्त मंत्री के रूप में अपना बजट प्रस्तुत कर रहे थे, इस अधिकारी दीर्घा में बैठे हुए राज्य के प्रमुख वित्त शासन सचिव, जिनके पास बजट की दूसरी कापी थी, वह मिलान कर रहे थे कि मुख्य मंत्री जी क्या बोल रहे हैं। उन्होंने मुख्य सचेतक जी को सचेत किया और उसके बाद इस नजारे को सदन में सभी ने देखा, एक दस्तावेज चलकर मुख्य मंत्री जी के पास आया।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान संविधान के आर्टिकल 202 की ओर आकर्षित करना चाहूंगा, जिसमें लिखा है कि राज्यपाल के संवैधानिक प्रमुख की आज्ञा से निश्चित तिथि को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में आय-व्यय का वित्तीय विवरण वित्त मंत्री सदन में प्रस्तुत करेंगे। अध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही हमारे विधान सभा के नियम और प्रक्रिया के नियम, जो आर्टिकल 208 (1) के तहत बने हैं, उसके रूल 138 में लिखा है कि राज्यपाल महोदय के द्वारा निश्चित तिथि को सदन में बजट प्रस्तुत किया जायेगा।

(समय: 12.58 बजे)

(श्री राजेन्द्र पारीक, सभापति, पदासीन)

सभापति महोदय, उसके लिए राज भवन से राज्य आज्ञा निकलती है और इस बार जो राज्य आज्ञा निकली, वह निकली थी 10 फरवरी को सही 11.00 बजे मुख्य मंत्री जी बजट प्रस्तुत करेंगे। 10 फरवरी को 11.00 बजे मुख्य मंत्री जी के पास जो बजट था, वह काबीना से अनुमोदित 2023-24 का बजट उनकी अटैची में था ही नहीं। मैं समझता हूं कि अगर देखा जाये तो बीएसी की दुबारा बैठक बुलाकर बजट की तारीख पुन: तय की जानी चाहिये थी। सभापति महोदय, बजट प्रस्तुती से पहले बजट किसी दूसरे के हाथ में हो, यह मंजर इस राजस्थान की अवाम ने पहली बार, ऑनलाइन जुड़े हुए लोगों ने देखा।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

(समय: 13.00 बजे)

सभापति महोदय, यह सही है, इस संसदीय लोकतंत्र में वार्षिक वित्तीय विवरण जिसको आम भाषा में हम बजट कहते हैं। बजट, प्रत्येक वित्तीय वर्ष में राज्य के उपलब्ध वित्तीय संसाधनों से जन प्रशासन, जन कल्याण के लिए जो उसी वित्तीय वर्ष में काम किये जाते हैं, यह कामों के लिए जनता से करार है। यह राज धर्म है कि जब बजट प्रस्तुत किया जाये तो बजटीय प्रावधानों में और बजट भाषण में जो उल्लेख किया गया है, वह उसी वित्तीय वर्ष में पूरा हो। मैं समझता हूं, यह मैं नहीं कह रहा हूं, अनेकों अध्यक्षीय व्यवस्थाएं हैं, कौल एंड शकधर भी कहते हैं।

सभापति महोदय, हमारे सदन के नेता कहते हैं कि मैं जनता का ट्रस्टी हूं। जनता के ट्रस्टी ने इन चार वर्षों में जनता के ट्रस्ट को जिस कदर तोड़ा है, आम आदमी का बजटीय घोषणाओं पर से विश्वास उठ गया है।

सभापति महोदय, अभी सदन के नेता ने 2023-24 में जो बजट प्रस्तुत किया, उसके प्रारम्भिक पैरा-2 में कहा कि चार वर्ष में बजटों की घोषणाओं को हमने पूरा किया है। मैं सदन का ध्यान एक प्रमुख समाचार-पत्र राजस्थान पत्रिका के उस सर्वे.. सभापति महोदय, मुझे मालूम था कि जब मैं अख़बार उद्धृत करूंगा तो उसके पीछे बात भी आयेगी, तो मैंने इस बजट का एनालिसिस करने वाले अधिकारी से जब पूछा कि आपने यह कैसे छाप दिया तो कहा कि पिछले चार बजटों में 2 हजार 7 सौ 72 घोषणाओं में से 49 परसेंट पूरी हुईं, 51 परसेंट अधर में लटकी रहीं। 2022-23 में 1029 घोषणाओं में 33 परसेंट पूरी हुईं और 67 परसेंट अधर में लटकी रहीं। उन्होंने कहा कि हर जिले में पांच-पांच लोग गये चारों बजटों में जो बजटीय घोषणा थी, टीम ने जाकर मौके पर फिजिकल वेरिफिकेशन किया और फिजिकल वेरिफिकेशन में जो काम बड़े थे, दीर्घकालीन थे, प्रारम्भ भी हो गये हैं, उनको भी पूरा माना। इसलिए मैं चाहूंगा कि इस बार जब मुख्य मंत्री जी जवाब दें तो उन्होंने जो चार बजट प्रस्तुत किये हैं, उनमें या तो वे एक्शन-टेकन रिपोर्ट प्रस्तुत करें या श्वेत-पत्र जारी करें।

सभापति महोदय, बड़े-बड़े होर्डिंग्स लगा दिये, बचत, बचकर निकल जा इस दुनिया से। यह राजस्थान की जनता इन्तजार कर रही है, इस सरकार से पूरा हिसाब करने के लिए। इन्होंने कहा -'राहत', तो राजस्थान के अवाम को

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

राहत तब मिलेगी जब इस सरकार की विदाई होगी और वह धूमधाम से होगी और बढ़त की बात तो भूल जाओ। बढ़त एक बात में होगी जो सैनिक कल्याण राज्य मंत्री कहते हैं। राजस्थान में, संसदीय मंत्री जी, मैं रहूं या नहीं रहूं राजस्थान का इतिहास देखेगा कि सत्तारूढ़ दल अपनी असत्य बजटीय घोषणाओं के आधार पर, असत्य जन-घोषणा पत्र के आधार उसकी विदाई होगी, जनता इस मंजर को भी देखेगी।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): हम घोषणाओं की क्रियान्विति से ही दुबारा आयेंगे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): सभापति महोदय, मुंगेरीलाल सपने कैसे ही देखे, मेरे मित्र भी हैं, खूब देखें।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): इनका नाम शान्ती धारीवाल है, मुंगेरीलाल नहीं है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): मैं करेक्ट कर लेता हूं।

सभापति महोदय, एक इतिहास जरूर बना। 3 घंटे और 16 मिनट, 270 पैरा एवं 170 पेज, 18 बार पानी पी-पी कर मुख्य मंत्री जी ने अपना भाषण दिया। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि यह बजट अपवित्र हो गया। अगर मैं कहूं कि यह ताबड़तोड़ घोषणाओं के आधार पर यह आभासी बजट है संसदीय कार्य मंत्री जी, यह शैडो बजट है, यह छाया बजट है। बजट के अन्दर जान नहीं है। सभापति महोदय, मुझे बड़ा अफसोस है, बजट की सैंक्टिटी, बजट की पवित्रता, यह पहली बार नहीं। बजट पैरा-5 में मुख्य मंत्री जी ने घोषणा की और हमारे सत्ता पक्ष के लोगों ने जोर-जोर से मेज थपथपाई। घोषणा भी ठीक थी। बीपीएल और पीएम मुद्रा योजना से जुड़े हुए लोगों को 500 रुपये में गैस सिलेण्डर देने की घोषणा बजट के अन्दर रखी गयी, पर मालाखेड़ा में भारत जोड़ो या सिर फोड़ो, उस यात्रा में सदन के नेता ने की। यह सदन की गरिमा के खिलाफ नहीं है?

सभापति महोदय, आज राजस्थान के अन्दर बेरोजगारी से पीड़ित 28.5 फीसदी नौजवान, जिसने डेढ़ साल के अन्दर 16 पेपर लीक का मंजर देखा है, जो सरकारी नौकरियों की लूट को देख रहा है, वह इस सरकार से परेशान है। किसानों के कर्ज माफी की जो बात थी, उससे किसान हैरान है और लचर कानून-व्यवस्था से आम आदमी दहशतगर्दी की जिन्दगी में है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि मंत्री जी ने यह जो मुख्य बजट रखा है..

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

सभापति महोदय, बजट, बजट में फर्क देखें। केन्द्र सरकार का बजट, अमृत काल का पहला बजट, 25 साल, इस हिन्दुस्तान की हालत और नया हिन्दुस्तान बनाने के संकल्प का बजट था। आपके बजट की हवा 25 मिनट में ही निकल गयी।

सभापति महोदय, मैं मेरी बात को आगे बढ़ाऊंगा। निश्चित तौर पर किसी भी बजट के अन्दर जो लोगों को उम्मीद होती है वह होती है आधारभूत संरचनाएं बनेंगी, हमारे विकास के काम होंगे और बजट के अन्दर, उसके लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर और कैपिटल आउटले की बात को लिखा गया है। मैं सदन का ध्यान बजट 2023-24 के पेज नम्बर 166, पैरा 262 की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। सभापति महोदय, इसमें बजट साइज क्या है? मार्गोपाय अग्रिम सहित Ways and Means के साथ 3 लाख 90 हजार 856 करोड़ 48 लाख। बहुत बड़ा साइज है। मैं समझता हूं कि इस बजट साइज के अन्दर, जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, एसेट बनेगा, वह कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना है? मैं सदन का ध्यान Budget at a Glance 2023-24 पर लाना चाहता हूं। आप चाहें तो लिख लें। पेज नंबर 10, उसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर को एक टेबल में 31 हजार 61 करोड़ रुपये बताया है। यानी पूरे बजट साइज का 9.7 फीसदी। यही नहीं, Budget at a Glance में पेज नम्बर 5 पर एक ग्राफ बनाया गया है, Rupee goes to पैसा और रुपया कहां जाता है? उसमें लिखा है कि कैपिटल आउटले में जो पैसों का प्रावधान किया है, वह 9.74 परसेंट यानी 1 रुपये में 9 पैसा। मुझे बड़ा अफसोस है।

सभापति महोदय, एक ओर केन्द्र सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर के अन्दर इस देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए 10 लाख करोड़ के बजट का प्रावधान किया है और पिछली बार से 33 परसेंट बढ़ाया है, दूसरी तरफ, मैं नेता, प्रतिपक्ष को क्या कहूं। मैं महामहिम राज्यपाल के नाम से भी संबोधित भी नहीं कर सकता, चूंकि आज विराजे हैं। मैं आप से ही कहूंगा कि यह जो इन्होंने कैपिटल आउटले लिखा, इनके दस्तावेजों ने कैपिटल एक्सपेंडिचर की राशि तय की। आज अगर मैं पढ़ना चालू करूं, पैरा नम्बर 93 में 6500 करोड़ की सड़कें बनायेंगे। पैरा नम्बर 94 में 3750 की मिसिंग लिंक सड़क बनायेंगे। पैरा 95 और 96 में 1250 करोड़ के राजमार्ग बनायेंगे और 625 करोड़ की गांवों की सड़कें बनायेंगे। पैरा नम्बर 97 में जल जीवन मिशन में जो सड़कें टूट गयीं, उनके लिए 1250 करोड़ का प्रावधान कर दिया। पैरा 98 में इंटरलॉकिंग सड़क

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

के लिए 2 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान कर दिया। पैरा नम्बर 102 में सौन्दर्यीकरण पर 1,800 करोड़ का प्रावधान कर दिया। पैरा 106 में 11 हजार 255 करोड़ की पेयजल की योजना की घोषणा कर दी। पैरा 107 में ईआरसीपी में 13 हजार करोड़ का प्रावधान कर दिया। पैरा 108 में जेजेएम में 1,500 करोड़ का प्रावधान कर दिया। पैरा 110 में पेयजल के लिए 980 करोड़, देवास के लिए 1,500 करोड़, पावर प्लांट के लिए 7 हजार करोड़, किसान कल्याण कोष में साढ़े सात हजार करोड़। मैं पढ़ूं तो मैं पढ़ता जाऊं, पर यह पैसा किस जगह से आयेगा? सवाल इस बात का है। इसलिए मैंने जो बात की है कि यह आभासी बजट है, शैडो बजट है। इस बजट में जान नहीं है, प्राण नहीं है।

सभापति महोदय, सदन के नेता, जो कि आज यहां नहीं हैं, पर मेरे मित्र बैठे हैं। 2019-20 का बजट बन रहा था। जब बजट के पैरा 14 में आपने क्या कहा? हमने अपने पिछले कार्यकाल में कई अहम फैसले किये। एक तरफ प्रदेश में पहली बार मेट्रो, रिफाइनरी, मेमू कोच फैक्टरी, रेलवे लाइन से वंचित तीन जिले बांसवाड़ा, टोंक, करौली की महत्वाकांक्षी योजना लेकर आये। बहुत अच्छा है। आप योजना लेकर आये, केकड़ी से आने वाले माननीय सदस्य से मैं पूछना चाहता हूं कि 2019-20 के अन्दर चार साल पहले आपने घोषणा की, किसने हाथ रोका? मेमू कोच फैक्टरी बनाने के लिए आपने क्या प्रयास किये?

श्री रघु शर्मा (केकड़ी): माननीय सभापति महोदय, माननीय उप नेता, प्रतिपक्ष ने जो मेरा नाम लिया है। मैं बीच में पार्लियामेंट का मेम्बर भी बना था और आपने बहुत अच्छा किया कि मुझे आज मौका दे दिया। माननीय सभापति महोदय, जब 2008 से 2013 में हमारी सरकार थी, माननीय मुख्य मंत्री जी ने केकड़ी के अन्दर वहां घोषणा की थी 857 करोड़ रुपये की, नसीराबाद से लेकर चौथ का बरवाड़ा तक के लिए रेल लाइन की। उन्होंने मुझ से कहा कि आप मांग करो, मैं यहां अनाउंस करूंगा। 50 परसेंट शेयर राजस्थान वहन करेगा और 50 परसेंट भारत सरकार वहन करेगी, क्योंकि उस समय सरकार यूपीए की थी और हमें विश्वास था कि हम इसके लिए भारत सरकार को मना लेंगे और राज्य सरकार अपनी तरफ से लिखकर दे दे।

माननीय सभापति महोदय, इस बीच में 2013 में आप लोग सत्ता में आ गये और 2014 में वहां भी सरकार बदल गयी। 2018 में जब मैं पार्लियामेंट का मेम्बर बनकर गया तब मैंने वहां सवाल लगाया कि ये रेल लाइन जिसकी स्वीकृति ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): साहब, मेरा समय नहीं होगा, आप काट लेना।

श्री रघु शर्मा (केकड़ी): सभापति महोदय, एक मिनट रुकिए, जब आपने रेफरेंस किया है तो मुझे ये चीज कहनी पड़ेगी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): मेरे समय में से नहीं... (व्यवधान)..

श्री चन्द्रभान सिंह आक्या (चित्तौड़गढ़): सभापति महोदय, ये बीच में...

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): सभापति महोदय, ठीक नहीं है।

श्री सभापति: विराजिए आप।

श्री रघु शर्मा (केकड़ी): यह कोई असंसदीय नहीं है। (व्यवधान) माननीय सभापति महोदय, मैंने सवाल लगाया लोक सभा के अंदर, सरकार बीजेपी की थी।

श्री सभापति: अंकित नहीं होगा किसी का भी। केवल रघु शर्मा जी का अंकित होगा।

श्री रघु शर्मा (केकड़ी): मुझे राइटिंग में जो जवाब मिला कि राजस्थान की तत्कालीन मुख्य मंत्री वसुन्धरा राजे ने फिफ्टी परसेंट शेयर देने के लिये मना कर दिया ...(व्यवधान) इसलिए ये रेल लाइन अटकी है। सदन को गुमराह मत कीजिए। धन्यवाद।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजिए आप। एक मिनट विराजिए आप।

श्री चन्द्रभान सिंह आक्या (चित्तौड़गढ़): 000

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): 000

श्री सभापति: प्लीज विराजिए। जब आपने इनको संबोधित किया है तो अपना जवाब दे रहे हैं, इसमें किसी को क्या दिक्कत है? (व्यवधान) आपने संबोधित किया है उनको, आपने इन्वाइट किया है उनको।

श्री चन्द्रभान सिंह आक्या (चित्तौड़गढ़): 000

श्री सभापति: प्लीज, विराजिए आप। मैं अलाउ नहीं करूंगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): सभापति महोदय,...

श्री सभापति: मैं अलाउ नहीं करूंगा। माननीय सदस्य, आप विराजिए। वरिष्ठ सदस्य हैं, आप विराजिए। श्री रघु शर्मा।

श्री रघु शर्मा (केकड़ी): माननीय सभापति महोदय, जब सरकार बदलती है ...(व्यवधान) मुख्य मंत्री ने लिखकर दिया ...(व्यवधान)

श्री सभापति: आप सब विराजिए। (व्यवधान) आप अपनी बात बोलिए।

श्री रघु शर्मा (केकड़ी): सभापति महोदय, मुझे आपका संरक्षण चाहिए। (व्यवधान) माननीय उप नेता, प्रतिपक्ष ने मेरा नाम लिया और रेल लाइन भी मेरे ही क्षेत्र से जाने वाली थी। जिला टोंक, राजस्थान में लंबे समय से इस बात की मांग करता आया ...(व्यवधान) कि ये जिला मुख्यालय रेल लाइन से नहीं जुड़ा। इतनी बड़ी समस्या थी, उसका समाधान हो रहा था, तो इन्होंने कहा किसने रोका? उसका स्पष्टीकरण किया है मैंने।

श्री सभापति: प्लीज, आप सब विराजिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): सभापति महोदय ...(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, एक मिनट विराजिए आप। जब आप किसी को इन्वाइट करेंगे तो अगला जवाब देगा। मेहरबानी होगी आप इन्वाइट नहीं करें, सिर्फ अपनी बात रखें और आसन को संबोधित करें। व्यक्तिश: उंगली करके, कभी तो आप संसदीय कार्य मंत्री जी की तरफ उंगली करके बताते हैं ऐसा है, ऐसा है और कभी आप आसन की ओर उंगली करते हैं ... (व्यवधान) माननीय सदस्य, आप इन्वाइट मत कीजिए। प्लीज, ये क्या हो रहा है? आप आसन को संबोधित कीजिए। किसी को इन्वाइट मत कीजिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): सभापति महोदय, मैं बिलकुल किसी को इन्वाइट नहीं करूंगा। केकड़ी से आने वाले माननीय सदस्य के साथ जीवन के बहुत से बसंत बीते इसलिए पुरानी याद आ गयी।

सभापति महोदय, मैं कह रहा था कि मेमू कोच, मेट्रो फेज सैकण्ड डीपीआर से बाहर नहीं निकला। ये रेलवे के तीनों जिले, चार साल में इन्होंने कह दिया कि हमने नहीं किया। हमने नहीं किया तो हम यहां आकर बैठ गये। अब इस सरकार ने क्या किया, ये तो सामने आये।

एक बात आगे क्या कही इन्होंने, 2019-20 में बजट पैरा 79 में कहलवाया, 2022 तक रिफाइनरी का काम पूरा कर देंगे। घोषणा कर दी इन्होंने। घूम-घूम कर सदन के नेता ने पूर्ववर्ती सरकार पर यह आरोप लगाया था कि 36 हजार 600 करोड़ की लागत से बनने वाली रिफाइनरी, उसमें जब इन्होंने रिफाइनरी दोबारा चालू की तो उसकी लागत हो गयी थी 43 हजार 129 करोड़, आज 75 हजार करोड़ को पार कर गयी।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहता हूं

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

कि क्या हुआ उस घोषणा का, बजटीय घोषणा का? आपने कहा था प्लास्टिक, रबर, डिटर्जेंट, फाइबर, ल्यूब्रिकेंट, पेस्टिसाइड्स, पेंट, कास्मेटिक्स, ये रीको के द्वारा इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल जोन बनाएंगे। ये बजटीय घोषणा 2019-20, 2020-21 में रिफाइनरी का डेडिकेटेड कौशल केन्द्र बनाएंगे। 2020-21 का पैरा 87, 2022-23 पैरा 52, 383 किलोमीटर, यहां से सीकर से भी आगे..., पेट्रोलियम, कैमिकल एंड पेट्रोकैमिकल्स इन्वेस्टमेंट रीजन बनाएंगे और 1 लाख 40 हजार लोगों को रोजगार देंगे। ये घोषणाएं कहां चली गयीं?

सभापति महोदय, मैं सदन का ध्यान इसी बजट 2023-24 के पैरा 5 (1) की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। इन्होंने कहा कि एनएफएसए परिवारों को आगामी वर्ष से राशन के साथ एक किलो दाल, चीनी, तेल देंगे। 3 हजार करोड़ की घोषणा कर दी। मैं पूछना चाहता हूं, क्या यह सही नहीं है कि एनएफएसए परिवार के 01 करोड़ से ज्यादा लोगों को राजस्थान में पिछले दो वर्षों से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल और 1 किलो दाल नहीं मिल रही? घोषणा केन्द्र सरकार की और नाम अपना। मैं समझता हूं कि इस बार भी दो लाख करोड़ का प्रावधान किया है। केन्द्र सरकार की योजनाएं, मैं एक योजना का जिक्र यहां और करूंगा, प्रधानमंत्री आवास योजना। प्रधानमंत्री आवास योजना में 2022-23 के अंदर राजस्थान में 4 लाख 61 हजार 990 मकान बनने थे, इनके दस्तावेज ये कह रहे हैं कि 2 लाख 6 हजार 480 मकान बने, 50 परसेंट से भी कम। इसके साथ 7 लाख लोग वे हैं जो पीएमएवाई प्लस के अंदर जो सिर्फ इसलिए बेघर रह गये कि उनके डाटा जो पोर्टल में दर्ज करने थे, वे डाटा समय पर दर्ज नहीं किये गये, डाटा गलत इन्द्राज किये गये। आज वह गरीब आदमी उस मकान से वंचित है। वहीं दूसरी ओर इस बार केन्द्रीय बजट में 66 परसेंट की बढ़ोतरी की है प्रधानमंत्री आवास योजना में, 79 हजार करोड़ का बजट। सभापति महोदय, यह सही है कि इस बजट के अंदर..., मैं बैठ जाऊं, या तो आप इनको बोलिए।

श्री सभापति: शांत रहिए। आपकी आवाज यहां तक आती है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): सभापति महोदय, मैं सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं 2023-24, पेज नंबर 165, जिसमें बजट अनुमानों का संक्षिप्त विवरण दिया है। इसमें लिखा है, एक टेबल दी है, इसमें कालम (3) में है कि राजस्व घाटा इस बार होगा 24 हजार 895 करोड़ 67 लाख का। निश्चित तौर

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

पर जब चाहे कोई घर हो या सरकार हो, जब घर में आमदनी से ज्यादा खर्च होगा तो वह कंगाली की ओर बढ़ेगा। मैं सदन का ध्यान 2019-20 के बजट पैरा 10 की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। अब आकर्षित मैं करूंगा, नाम ले दूंगा तो आप नाराज। सभापति महोदय, मैं आज बड़ी दुविधा में फंस गया। मेरा जैसा सीधा-सादा आदमी, ये बात इन्होंने भी मान ली। मेरी क्रेडिबिलिटी देखिये आप।

श्री सभापति: आप सिर्फ आसन को कहें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): सभापति महोदय, इन्होंने जो कहा पैरा 10 में, पिछली सरकार के वित्तीय कुप्रबंधन के कारण राजस्थान की वित्तीय स्थिति बहुत खराब हो गयी। हमारे पिछले कार्यकाल में कुशल वित्तीय प्रबंधन के कारण, पिछला कार्यकाल इनका कुशल वित्तीय प्रबंधन के कारण राज्य 2010-11 से रेवेन्यू सरप्लस में पहुंच गया और 2013 तक लगातार रेवेन्यू सरप्लस में रहा। गत सरकार के, हमारी सरकार, अविवेकपूर्ण नीतियों के कारण 2018-19 में रेवेन्यू डेफिसिट 29 हजार करोड़ पहुंच गया। अब तो रेवेन्यू डेफिसिट का बजट पेश ही नहीं होगा, राजस्व हानि का बजट पेश ही नहीं होगा। ये बेलगाम राजस्व घाटा, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि बजट एट ए ग्लांस 2022-23, पेज नंबर 2 एफआरबीएम एक्ट, 2023-24 पेज नंबर 9, उसमें 2020-21 के जो राजस्व घाटे की BE थी, बजट एस्टीमेट थे, वे थे 12 हजार 378 करोड़ रुपये और जब ये RE में आये तो बढ़कर हो गये 41 हजार 721 करोड़, यानी 29 हजार 343 करोड़ बढ़े। 2021-22 में पुन: इन्होंने बजट रखा घाटे का 23 हजार 750 करोड़, RE में आये तो 35 हजार 689 करोड़, 11 हजार 993 करोड़ बजट घाटा फिर बढ़ा। 2022-23 के अंदर फिर इन्होंने 23 हजार 448 करोड़ के घाटे का बजट प्रस्तुत किया। RE में आये तो बढ़कर हो गया 32 हजार 310, 8 हजार 822 करोड़ का और इस बार इन्होंने फिर 24 हजार 895 करोड़ के घाटे का बजट प्रस्तुत किया और इस घाटे के बजट में राजस्व कम करने के लिये एक जगलरी की है। अपने Own Tax Revenue के प्रोजेक्शन को बढ़ा दो, बजट अनुमान है, सरकार पहलवान है। अनुमान चाहे कुछ भी लगा दें, इसीलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा, अब हालत हमारे Own Tax Revenue की क्या है? मैं समझता हूं मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि बजट भाषण के 164 नंबर पैरा में सदन के नेता ने, पुराने बजट से नहीं, नया बजट पढ़ते हुए, सभापति महोदय, मैं बिलकुल नहीं कहूंगा पुराना बजट इन्होंने पढ़ा, मैं क्यों कहूंगा, उसमें 164 पर इन्होंने कहा सरकार के एफिशिएंट प्रबंधन के

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

कारण 2021-22 और 2022-23 में जीएसटी की वृद्धि दर 32.50 और 31.22 परसेंट रही।

मेरी चुनौती है, कोई सुने नहीं सुने। आफिसर दीर्घा के अन्दर जो अधिकारी बैठे हैं, वे कलम उठा लें। यह आंकड़ा कहां से आया? हमारा आन टैक्स रेवेन्यू है, यह जीएसटी का सबसे बड़ा कम्पोनेंट है। मैं सदन का ध्यान बजट एट ए ग्लांस पेज-1 में जो टेबल दिया उसकी तरफ आकर्षित करना चाहूंगा। 2022-23 की बी ई में राज्य का कुल कर राजस्व 98 लाख 29 हजार 364 करोड़ 75 लाख था। 2022-23 में उसी साल, जब इन्होंने आर ई के कागज पेश किये इस बजट एट ए ग्लांस में, तो लिखा है 92 लाख 71 हजार 892, यानी हमारा आन टैक्स रेवेन्यू गिर रहा है। 6 हजार करोड़ से भी कम रहा। अब इन्होंने नये टैक्स, प्रोजेक्शन दिए हैं इस साल के, वह 1 लाख 14 हजार 189 हैं। यह 12-13 हजार करोड़ रुपये कैसे बढ़ जाएंगे, आन टैक्स रेवेन्यू कैसे बढ़ जाएगा? अब तो इनके पास यह बहाना भी नहीं है कि कोरोना काल आ गया। अब तो इन्होंने जो बजट प्रस्तुत किया है, उसमें घोषणा कर दी कि मैंने इतने हजार करोड़ की छूट दे दी, मैं समझना चाहूंगा, मुझे बताएं। एक सबसे बड़ा कम्पोनेंट है वह फिस्कल डेफिसिट। इसी बजट में इन्होंने यह कहा, बजट भाषण के अन्दर कुशल वित्तीय प्रबन्धन की शेखी बघेरी इन्होंने पेज नम्बर 170 में।

मैं सदन का ध्यान 2023 के बजट पैरा 266 में एक टेबल है, उसकी ओर आकर्षित करना चाहूंगा। बजट अनुमानों के अनुसार राजस्व घाटा 62 हजार 771 करोड़ 92 लाख, जो हमारे जीएसडीपी का 3.98 परसेंट है। मैं जानना चाहूंगा 2019-20 के पैरा 11 में पूर्ववर्ती सरकार के बढ़ते फिस्कल डेफिसिट पर चिन्ता की, आलोचना की। अब आपकी हालत क्या है? मैं फिर कोट कर रहा हूं एफ.आर.बी.एम. एक्ट 2022-23 और 23-24, उसकी भी एक तालिका है। 2020-21 में इनकी बी.ई. फिस्कल डेफिसिट की 33 हजार 922 करोड़ रुपये थी, आर ई में बढ़कर 58 हजार 608 करोड़ रुपये हो गया और एक्चुअल आये हैं वह 59 हजार 375 है। 2021-22 में बी.ई. 47 हजार 652 करोड़ रुपये थी, आर.ई. में बढ़कर 62 हजार, 15 करोड़ रुपये हो गये और एक्चुअल में 58 हजार 211 आये। 2022-23 में इनकी बी ई 58 हजार 211 करोड़ रुपये थी, आर.ई. में बढ़कर 61 हजार 263 करोड़ रुपये हो गये, अभी एक्चुअल आएंगे तो और बढ़ेंगे। 2023-24 का 62711 का फिस्कल डेफिसिट

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

का बजट है, मेरा आरोप है कि जब आप आर.ई. में आएंगे, एक्चुअल में आएंगे 70 हजार करोड़ को पार करेगा।

मैं एक और ध्यान दिलाना चाहता हूं। एफआर.बी.एम. एक्ट 2023-24, पेज-19, उसमें 2021-22 में एक्चुअल जीएसडीपी का कितना बजटीय घाटा था, परसेंट था, वह 3.96 था और आर.ई. के अन्दर आ गया यह। यह खुद की किताब कह रही है, मैं नहीं कह रहा। 4.33 एफ.आर.बी.एम. एक्ट सेक्शन-5 इनको परमिसिबल लिमिट 3 परसेंट की है, 5 परसेंट इनको इन्सेंटिव के तौर पर, विद्युत सुधार के नाम पर दिये गये। मैं समझता हूं कि इतना हाई फिस्कल स्ट्रेस के अन्दर हमारा बजट है, उसके अन्दर फिर यह थोथी घोषणाएं नहीं तो क्या है।

सभापति महोदय, मुझे बड़ा अफसोस है, रिजर्व बैंक की एक चेतावनी जो रिजर्व बैंक ने उन पांच राज्यों को दी, जिन राज्यों ने अपनी जीएसडीपी का 25 परसेंट से 40 परसेंट तक लोन ले रखा है, राजस्थान उसमें दूसरे नम्बर पर। जीएसडीपी का 49.8 परसेंट कर्जा इन्होंने ले रखा है। मैं नहीं कह रहा, आरबीआई की रिपोर्ट कह रही है। 2019 में प्रदेश का कर्जा 3 लाख 49 हजार करोड़ था, 2022-23 में 200 परसेंट बढ़कर 5 लाख 59 करोड़ हो गया। आरबीआई की रिपोर्ट और क्या कहती है, उन्होंने कहा कि श्रीलंका की इकॉनोमी धराशायी हो गई, पाकिस्तान की इकॉनोमी ध्वस्त हो गई, क्योंकि पाकिस्तान और श्रीलंका ने, वर्ल्ड बैंक ने जो चेतावनी दी कि आप कर्जा आधारित अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहे हो, उसको नहीं माना, तो आज वहां हाहाकार मचा है।

मैं सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं 2019-20 के बजट पैरा-12 जिसमें इन्होंने लिखा था, पिछली सरकार ने राजस्व घाटे की पूर्ति अत्यधिक ऋण लेकर की, राज्य को कर्ज भार में डुबो दिया। 2018-19 के संशोधित अनुमानों के अनुसार यह कर्ज भार 3 लाख 9 हजार 385 करोड़ हो गया जो जीएसडीपी का 33.4 है। यह मैं नहीं कह रहा, मैंने वह उद्धृत किया है जो 2019-20 में पैरा 12 में इन्होंने कहा। आज हालत क्या है, एफ.आर.बी.एम. एक्ट 2023-24, पेज 24 देखिये, उधार व अन्य दायित्व, 2021-22 के एक्चुअल हैं। महामहिम महोदय, 4 लाख 62 हजार 845, इसी में आर.ई. 2022-23 की 5 लाख 16 हजार 815 आई है। इन्होंने 2023-24 की बी.ई. प्रस्तुत की है, आप

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

राजस्थान की हालत देखिये, राजस्थान पर कर्जा देखिये, 5 लाख 89 हजार 781 है। सभापति महोदय, मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं, जीएसडीपी का भार निकालकर देखा, 44 परसेंट। हम श्रीलंका और पाकिस्तान की इकॉनोमी की तरफ बढ़ रहे हैं। अराजकता का वातावरण नहीं होगा तो क्या होगा?

सभापति महोदय, एफ.आर.बी.एम. एक्ट. 2023-24 पेज-9 में राज्य के वित्तीय संकेतों के रुख में एक टेबल 6.1 की तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। माननीय मंत्री महोदय, आप यह लिखवा लेना, ब्याज का भार, 2021-22 में 28 हजार 100 था, 2022-23 में बढ़कर 30 हजार 733 करोड़ हो गया, 2023-24 में 32 हजार 393 हो गया, आप क्या करेंगे, जिस सरकार को, जिस राज्य को 32 हजार 393 करोड़ रुपये हर वर्ष ब्याज में देने पड़ते हैं।

आपने पेज-4 बजट एट ए ग्लांस का दिया है, उसमें एक ग्राफ दिया है, आमदनी का रुपया जाता कहां है। उसमें लिखा है 23.99 रुपये में से केन्द्रीय ऋणों का पुनर्भुगतान, उसमें जाता है और 8.29 ब्याज भुगतान में। यानी जो कर्जा ले रखा है उसके भुगतान और ब्याज में एक रुपये की आमदनी अगर हमारी है, 32.88 परसेंट जाता है।

सभापति महोदय, वेतन, हमारी पेंशन, कर्जे का भार क्या है। 2021-22 में कुल टैक्स रेवेन्यू, कुल राजस्व का 145 परसेंट था, 2021-22 में 135 और 2022-23 में 125 करोड़ हो गया। एफ.आर.बी.एम. एक्ट, मैं सारे पढ़ूंगा तो टाइम लगेगा। एफ.आर.बी.एम. एक्ट का आपने पेज-9 पर दिया है, उसमें ब्याज इस साल 32 हजार 393 हैं, पेंशन 26 हजार 71 हैं, वेतन 71 हजार 797 हैं, यानी 1 लाख 29 हजार 961 करोड़ रुपये, जो आपके कुल राजस्व का 122 परसेंट हैं, आप सिर्फ वेतन में, भत्तों में, ब्याज अदायगी में देते हो, इस प्रकार की हालत है।

मुख्य मंत्री जी चूकते नहीं, चाहे ईआरसीपी की बात करनी हो, यहां बैठे-बैठे भाषण दे गये। केन्द्र सरकार की केन्द्रीय परिवर्तित योजना में सारा पैसा यह उन योजनाओं के अकाउंट्स में डाल रहे हैं, यह कंसोलिडेटेड फण्ड में नहीं डाल रहे। मतलब, केन्द्र सरकार को कोसने का काम किया। केन्द्रीय करों में हमारा हिस्सा है, बजट एट ए ग्लांस, 23-24 पेज-1 टेबल, कालम नम्बर दो जिसमें करों में हमारा हिस्सा 2022-23 की बी ई में 49 हजार 211 करोड़ 29 लाख रुपये था, 2022-23 की आर.ई. में चला गया 97 हजार 230 करोड़ 78

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

लाख और 2023-24 की बी.ई. में 61 लाख 55 हजार। यानी पिछली बार के बजट अनुमानों से 8 हजार आर.ई. में ज्यादा पैसा दिल्ली से हमें मिल गया। 2023-24 के अन्दर हम लोगों को 12 हजार करोड़ ज्यादा मिलता है। 2021-22 में केन्द्र सरकार से आपको करों व अनुदान में 88 हजार 80 करोड़ मिले हैं। 2022-23 में 94 हजार 458 करोड़ मिले। मैं समझता हूं अब बिना कारण से गाली देने का वक्त नहीं।

सभापति महोदय, ओ.पी.एस. स्कीम के बारे में बजट में पेज 105, पैरा नम्बर 151 में 1 लाख लोगों को मुख्य मंत्री जी, जो विद्युत उत्पादन निगम के थे, रीको के थे, आरटीडीसी के थे, विश्वविद्यालय के थे, आरएसएमएमएल के थे, उनको ओ.पी.एस. के दायरे में लाए। ओ.पी.एस. के खिलाफ मैं और मेरी पार्टी नहीं है। न्यू पेंशन स्कीम में पी.एफ.आर.डी.ए. ट्रस्ट 2010 में बना है, जिसके अन्दर पैसा जमा होना चालू हुआ था कर्मचारी के कंट्रीब्यूशन का 10 परसेंट और 10 परसेंट सरकार का, उस पर दस्तखत महानुभाव ने किये थे वित्त मंत्री के रूप में। जब लोक सभा के अन्दर, केन्द्रीय वित्त मंत्री ने साफ कह दिया कि पी.एफ.आर.डी.ए. फण्ड में आज ब्याज के साथ 42 हजार करोड़ रुपये हैं, यह पैसा नहीं मिलेगा। पी.एफ.आर.डी.ए. एक्ट 2013 में बना है, रूल 2015 में बना है, इसमें कहीं पर यह व्यवस्था नहीं है कि वह पैसा जो जमा हो गया, वह वापस कल राज्य के कंसोलिडेटेड फंड में चला जाये। मुख्य मंत्रीजी ने कैबिनेट की बैठक लेकर प्रेस में क्या कहा, मैं जी.पी.एफ. के अकाउंट में यह सारा पैसा दूंगा। जी.पी.एफ. के अकाउंट का फायदा लेना इस राज्य के कर्मचारी का हक है, जो आज सड़कों पर है।

मैं यह कहना चाहता हूं कि आपकी अर्थव्यवस्था तो धराशायी हो गयी। इस धराशायी अर्थव्यवस्था के अन्दर आप यह 42 हजार करोड़ रुपया और अपने खुद के संसाधनों से डाल देते जी.पी.एफ. में। मैं यह समझता हूं कि बजट की घोषणाओं को तो पूरा न आज कर सकोगे और न कल कर सकोगे, मैं यह समझता हूं कि यह पैसा आप डालते और फिर आप सुप्रीम कोर्ट में लड़ते रहते और यह जो प्रोजेक्शन है, कितना बजट 2024-25 के अंदर, एफ.आर.बी.एम. के पेज 24 में यह कहा है कि 30671 करोड़ रुपया सिर्फ पेंशन पर, सिर्फ पेंशन पर और 2025-26 में 31,485 करोड़ रुपये।

माननीय सभापति महोदय, मैं मेरी बात को आगे बढ़ाऊं, मुख्य मंत्रीजी ने एक बड़ा जोरदार काम किया। कृषि के लिए हमने अलग से बजट

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

प्रस्तुत किया और उन्होंने अपने दूसरे बजट में कहा कि मेरे पहले बजट की किसानों ने, पशुपालकों ने सराहना की और एक वक्तव्य जो डाक्टर स्वामीनाथन, जिनकी रिपोर्ट पर, 2007 में उन्होंने रिपोर्ट दी और 2014 तक वह ठंडे बस्ते में रही और उसको लागू करने का काम 56 इंच सीने वाले प्रधान मंत्री, विश्व के लोकप्रिय नेता श्री नरेंद्र मोदी ने किया, उसका यहां जिक्र कर दिया कि कृषि रोजगार आधारित अर्थव्यवस्था को वह गति दे सकते हैं और कृषक कल्याण कोष में उन्होंने पांच हजार से बढ़ाकर सात हजार पांच सौ रुपये कर दिया। पांच हजार से बढ़ाकर साढ़े सात हजार करोड़ रुपये।

पहले जो ग्यारह मिशन चल रहे थे, इस बजट के अंदर उनको प्रगतिरत रखते हुए, संचालित रखते हुए 12 नये मिशन मतलब, पूर्व में संचालित केन्द्रीय योजना के आगे मिशन का नाम लिख दो। नाखून कटवा लूंगा शहादत में नाम लिख दे मेरा, इस तर्ज पर यह काम हुआ है।

माननीय सभापति महोदय, मैं सदन का ध्यान बजट एट ए ग्लांस, पेज-23-24, योजना का उदव्यय, यह प्लान, यह 1 लाख 84 हजार 311 करोड़ का है, यह किताब कोई मेरी नहीं है, इनकी है और उसमें कृषि सम्बन्धित सेवाओं पर जो आपने प्रस्तावित परिव्यय रखा है वह है 10 हजार 580 करोड़, आप खुद ही यह कह रहे हैं कि यह कुल मिलाकर पूरे प्लान साइज का 5.74 परसेंट है।

माननीय सभापति महोदय, बजट एट ए ग्लांस के पेज-1 में जो टेबल है, उसमें कृषि और सम्बन्धित सेवाओं के अलावा सिर्फ कृषि पर 3,306 करोड़ 87 लाख का प्रावधान किया है और जो आपका बजट प्लान है 1 लाख 84 हजार 311 का, इसका प्रतिशत जब मैं निकालता हूं तो किसान की बात कहने वाली इस सरकार ने पूरे प्लान साइज का 1.79 परसेंट इस पर खर्च किया है, उस कृषि पर जिस पर 67 परसेंट लोग आधारित रहते हैं।

माननीय सभापति महोदय, मैं यह समझता हूं कि अगर ये इस बात को देखें, एक तरफ आप केन्द्र सरकार को देखिये कि 2013-14 में जो बजट था 21 हजार 933 करोड़ का, इस बार देश के किसानों के लिए, किसान की आमदनी दुगुनी हो, इस परिकल्पना को पूरा करने के लिए 1 लाख 25 हजार करोड़ का बजट रखा है जो भूतो न भविष्यति और इसके साथ यह 3,306 के अन्दर, इनकी किताब क्या कहती है? उसमें कौन-कौनसी चीज शामिल है?

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

उसमें प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के 2 हजार करोड़ रुपये, उसमें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के 431 करोड़ रुपये, राष्ट्रीय कृषि विकास निगम के 325 करोड़ रुपये, राष्ट्रीय कृषि विस्तार तकनीकी मिशन के 180 करोड़ रुपये, प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना के 90 करोड़ रुपये, राष्ट्रीय टिकाऊ कृषि मिशन के 17 करोड़ रुपये, प्रधानमंत्री कुसुम योजना के 300 करोड़ रुपये, विश्वविद्यालयों के 494 करोड़ रुपये, मैं यह समझता हूं कि आप किसको गुमराह करना चाहते हो? आप क्या करना चाहते हो? यह मेरे समझ के बाहर की बात है, इसका सरकार उत्तर दे।

माननीय सभापति महोदय, आपने यह कहा कि 2019 में ईज आफ डूइंग बिजनस की तर्ज पर यह जो फार्मिंग का हम लेकर आयेंगे और आपने उसके अंदर यह घोषणा कर दी कि हम किसान कल्याण कोष में यह 7500 करोड़ रुपये, इसमें कुल मिलाकर आपका बजट जो आपने प्रस्तावित कर रखा है, यह बजट है आपका 3,306 करोड़ रुपये, तो यह सात हजार पांच सौ करोड़ रुपये कौनसे मद में लेकर आयेंगे, बतायें आप उत्तर दें तो, परंतु बात करना है।

आपने वर्ष 2022-23 में बजट पैरा 133 में यह कहा कि हम राजस्थान मिलेट्स प्रोत्साहन मिशन 100 करोड़ रुपये का प्रारम्भ करेंगे। इसकी पुनरावृत्ति आपने इस बार भी वर्ष 2023-24 के बजट के पेज 115 में की है।

माननीय सभापति महोदय, यह सही है कि यू.एन.ओ. इंटरनेशनल ईयर आफ मिलेट्स मना रहा है। केन्द्र सरकार ने इस मोटे अनाज को 'श्री अन्न' का दर्जा दिया है और आपने क्या किया? 2022 के अंदर बाजरे की एम.एस.पी. पर खरीद थी 2250 रुपये प्रति क्विंटल, 2022-23 की खरीद में कर दी 2350, केन्द्र सरकार ने दो बार प्रस्ताव मांगे।

यह मेरा आरोप है कि केन्द्र सरकार ने दो बार प्रस्ताव मांगे, मैं आपको तारीख बता रहा हूं, केन्द्र सरकार ने अगस्त, 2021 एवं जुलाई, 2020 को पत्र लिखकर राज्य सरकार को यह कहा कि आप विधिवत रूप से बाजरे के न्यूनतम समर्थन मूल्य में खरीद के लिए प्रस्ताव भेजो, लेकिन आपने यह प्रस्ताव नहीं भेजे और यह ही नहीं, जब यह मामला हाई कोर्ट में गया, राजस्थान किसान वेलफेयर सोसायटी बनाम राज्य सरकार, आपने शपथपूर्वक लिखकर यह कहा कि हम बाजरे की खरीद में असमर्थ हैं और आपने यह स्वीकार किया कि हां, हमें केन्द्र सरकार का यह पत्र मिला। हरियाणा हमारे

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

पड़ोस में है राजगढ़ के बाद, वहां पर 2,350 रुपये प्रति क्विंटल में बाजरा खरीदा गया, वहां पर यह योजना लागू की गयी पर हमारे किसान जो आपके खुद के आंकड़े यह कहते हैं कि 45 लाख 12 हजार हैक्टेयर में बाजरे की बुवाई हुई तो वह मजबूर था 1600-1700 रुपये में बाजरा बेचने के लिए, तो 6 हजार करोड़ रुपये का उसको फटका लगा।

माननीय सभापति महोदय, वर्ष 2019-20 के बजट के बिंदु संख्या 25 में मुख्य मंत्रीजी ने जो कथन कहा, मैं उसको उद्धृत करना चाहूंगा:-

'25. दूसरी तरफ 30 नवम्बर, 2018 तक किसानों के बकाया रहे रुपये 9 हजार 513 करोड़ के अल्पकालीन फसली ऋण भी माफ किये, इससे 20 लाख 46 हजार किसानों को ऋण माफी की राहत मिली। मुझे इस बात की खुशी है कि सरकार द्वारा रुपये 2 लाख के मध्यकालीन एवं दीर्घकालीन कृषि ऋण माफ करने से किसानों की 1 लाख 10 हजार बीघा भूमि रहन मुक्त हो गई है। वाणिज्यिक बैंकों आदि के ऋणी काश्तकारों को ऋण माफी की राहत पहुंचाने के लिए हमारी सरकार ने सम्बन्धित केन्द्रीय मंत्रालय से संवाद प्रारम्भ किया है। हमने बैंकों द्वारा उद्योगपतियों एवं व्यापारियों के साथ किये जाने वाले one time settlement की तर्ज पर किसानों के साथ भी ऐसे settle-ment के जरिए ऋण माफी के लिए आग्रह किया है। मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में हम यह प्रक्रिया अपनाकर पात्र किसानों को लाभ दिलवायेंगे।'

माननीय सभापति महोदय, वर्ष 2021-22 में फिर यही बात कही कि हमने स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी से सम्पर्क करके ऋण माफी के शेष रहे राष्ट्रीयकृत बैंकों, अनुसूचित बैंकों एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के ऋणी कृषकों को वन टाइम सैटलमेंट से इनको माफ करवायेंगे।

माननीय सभापति महोदय, पन्द्रहवीं विधान सभा का यह अंतिम बजट सत्र है। यह चौदहवीं के चांद बने सदन के नेता चौदह बार सदन में आये होंगे और इन्होंने कोई मौका नहीं छोड़ा। जब इस मंच से राजस्थान के नेशनलाइज्ड बैंक, कामर्शियल बैंक और शिड्यूल्ड बैंक से जिन्होंने ऋण लिया, 2019 में फसली ऋण, जो अवधिपार ऋणी हो गया, उसको माफ करने का आश्वासन नहीं दिलवाया। 01 जनवरी, 2019 में कल्लाजी की कमेटी बनी, यह कल्ला कमेटी अल्लाह के पास चली गयी। राजस्थान के किसानों के खाते एन.पी.ए. हो गये और चक्रवर्ती ब्याज करते-करते यह दो लाख रुपये का ऋण आठ लाख

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

रुपये हो गया और अब आप क्या कर रहे हैं? कह रहे हैं कि अब हम यह एक्ट लायेंगे, Rajasthan farmers debt relief act, अभी घोषणा की है।

माननीय सभापति महोदय, मैं यह समझता हूं कि यह जो Rajasthan farmers debt relief act अब लेकर आ रहे हैं, यह वह ही सदन है जिसने सी.पी.सी. के अंदर सेक्शन 60(1) में एक संशोधन किया था कि अगर किसी किसान की कोलेटरल सिक्योरिटी के नाम पर पांच एकड़ तक की जमीन उसकी दर्ज है तो उसकी जमीन नीलाम नहीं होगी, यह सिविल प्रोसीजर कोड का है, यह चूंकि, कान्करेंट लिस्ट का सब्जेक्ट था। आर्टिकल 254 (2) के तहत राज्यपाल महोदय ने राष्ट्रपति महोदय के पास भेज दिया तो सदन के नेता ने यह भाषण दे दिया कि राज्यपाल राजनीति कर रहे हैं। यह मेरे समझ के परे की बात है।

माननीय सभापति महोदय, मैं यह जिम्मेदारी से कह रहा हूं, मैं लॉ का विद्यार्थी रहा हूं। यह जो रोडा एक्ट 1974 बना है, उसके सैक्शन 13 और 14 में यह साफ अधिकार दिया है कि अगर किसान वित्तीय संस्थाओं को अपनी जमीन रहन में रखेगा, खाता उसका कुर्क होगा तो उसकी जमीन नीलाम होगी और यह बात सदन में एक उत्तर में खुद सरकार ने यह कहा है, 01 जनवरी, 2019 से जनवरी, 2022 तक किसान की जमीन के 22,215 प्रकरण कुर्की के हुए और 18,817 किसानों की जमीन नीलाम हो गयी।

माननीय सभापति महोदय, किसान के साथ अन्याय के इस मंजर को हमने देखा है। आज राजस्थान के अन्दर किसान अपनी उपज को जब बेचने जाता है तो सर्वाधिक टैक्स देकर जाता है, सर्वाधिक टैक्स। कृषि उपज मण्डी टैक्स है 1 रुपया 60 पैसे, यह किसान कल्याण सेस 50 पैसे सैकड़ा, यह लगाया था आपने कोरोना महामारी में और उसके साथ आढ़त 2 रुपये 25 पैसे और जी.एस.टी., एस.जी.एस.टी. 2 रुपये 50 पैसे, तो हालत क्या है? मैं यह समझता हूं कि इस सरकार ने यह गुनाह किया और मैंने उस वक्त भी यह विरोध किया था जब आप कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1961 की धारा 17 (ए) में संशोधन लाकर किसान के खेत से लेकर आम कोई भी जगह पर जहां किसान अपनी जिन्स को बेचेगा, उसको आपने कृषि उपज मण्डी की उस परिभाषा में शामिल कर लिया है।

आज हालात क्या हैं? किसान जब अपनी उपज बेचने जाता है तो आज यू.पी. में मंडी टैक्स जीरो, कर्नाटक में पाइंट थ्री फाइव परसेंट, गुजरात

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

में पाइंट फाइव जीरो परसेंट, मध्यप्रदेश में एक परसेंट, महाराष्ट्र में पाइंट ऐट जीरो परसेंट पर हमारे यहां पर 1.60 परसेंट कृषि टैक्स, पचास पैसे सेस, यह कृषि कल्याण कोष के ढाई रुपये, दो रुपये पच्चीस पैसे की आढ़त और ढाई रुपये एस.जी.एस.टी., यह जो आपने झुनझुना अपनाया।

सभापति महोदय, 2023-24 के बजट के समय बड़े जोर से मेजें थपथपायी गयीं। मैं देख रहा था, सत्तारूढ़ दल के एक माननीय सदस्य मेज थपथपा कर हाथों को देख रहे थे कि लाल हुए या नहीं, क्योंकि घोषणा ही ऐसी थी। बजट के पैरा 5 में कहा गया है कि हम 100 यूनिट तक की बिजली मुफ्त करेंगे। बजट के पैरा 167 में कहा कि 2000 यूनिट किसान को प्रतिमाह मुफ्त देंगे और पैरा 168 में कह दिया कि डेढ़ लाख नये कनेक्शन देंगे। बजट के पैरा 114 में कह दिया कि आईटी की विद्युत कम्पनी अलग से खोलेंगे। आपने खोली थी न? 2021-22 के बजट पैरा 75 में कहा गया था कि 'कृषि विद्युत वितरण कम्पनी' 'एग्रीकॉम'। वह किस काम में चली गई, महानुभाव? इसका भी आईटी कम्पनी की तरह ही होगा। 2023-24 के बजट पैरा 113 में, रिन्युअल एनर्जी के क्षेत्र में 21 हजार मेगावाट का उत्पादन करते हुए खुशी है। आपने कहा कि अब हम आत्मनिर्भर हो गये, 23 हजार 309 मेगावाट बिजली हमारे पास है। 'अंधेर नगरी चौपट राजा' राजस्थान के लोगों ने नगरी को अंधेरे में डूबा देखा, शासन चौपट रहा। दो घंटे से सात घंटे तक विद्युत कटौती हुई और दम्भ भर रहे हैं कि हम लोग आत्मनिर्भर हो गये। मैं समझता हूं 100 यूनिट तक फ्री बिजली का लाभ तब मिलेगा जब तार में बिजली दे पाओगे। 200 यूनिट बिजली का लाभ किसान को तब मिलेगा जब उसके तार में करंट आयेगा। इसके अलावा आपने डेढ़ लाख कृषि कनेक्शन की भी बात कही है। 2022-23 के अन्दर भी आपने कहा था 22 फरवरी को कि हम 3 लाख 38 हजार कृषि कनेक्शन देंगे। उसका क्या हुआ? एक कृषि कनेक्शन हुआ हो तो बताओ।

कृषि कनेक्शन नाम पर टर्नकी योजना, भ्रष्टाचार के ताण्डव को राजस्थान का अवाम देख रहा है। 01 लाख 04 हजार कनेक्शन देने की आपने निविदा आमंत्रित की। 6 बार निविदाओं को पोस्टपोन किया 6 मई, 9 मई, 25 मई, 31 मई, 8 जून को, और लिख यह दिया कि पांच साल का अनुभव होना चाहिए। टर्नकी प्रोजेक्ट पहली बार ला रहे हो और पांच साल की शर्त इस कारण से कि राजस्थान की कोई कम्पनी भाग नहीं लेगी। आपने कुछ

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

कम्पनियों को टेलरमेड बनाया। सारी कम्पनियों को बाहर कर दिया। आज हालत यह हो गई कि रिजर्व प्राइस से 82 परसेंट पर इस टर्नकी प्रोजेक्ट को मंजूर किया है जिससे 2300 करोड़ का प्रोजेक्ट 3,900 करोड़ का हो गया। 1600 करोड़ का मेरा आरोप है सरकार पर, सरकार में बैठे बड़े लोगों पर। बड़ी-बड़ी कम्पनियों से 1600 करोड़ का भ्रष्टाचार।

आज ये दावा करते हैं, 2023-24 बजट के पैरा 168 में कहते हैं कि डेढ़ लाख कनेक्शन देंगे। सभापति महोदय, सीकर का वह किसान जिसने बूंद-बूंद योजना में अपना डिमाण्ड नोटिस डेढ़ साल पहले जमा करवा दिया, वह एससी का किसान आज टुकुर-टुकुर देख कर घूम रहा है। इन्होंने कहा कि किसान को अप्रेल, 2023 से पूरे दिन बिजली देंगे। वाह, क्या बात कही। 'क्या अन्दाज है तेरा, सदके जाऊं'।

फर्स्ट फेज में 16 डिस्ट्रिक्ट, सैकण्ड फेज में 5 डिस्ट्रिक्ट और उसके बाद अब तो सारे ही। इन्होंने क्या किया है नौ बार फ्यूल चार्ज बढ़ाये हैं। आज राजस्थान में सर्वाधिक महंगी घरेलू बिजली है और बीजेपी के राज में औसतन फ्यूल चार्ज जो 18 पैसा था उसको बढ़ा कर 64 परसेंट कर दिया। अरबन सेस के 15 पैसे यूनिट, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी के 40 पैसे, जल संरक्षण के 10 पैसे कर दिये। हिंडनबर्ग का बड़ा मामला चल रहा है। कल भी आप धरना दे रहे थे। सभापति महोदय, मैं नाम लूंगा तो ये नाराज हो जाएंगे। मैं समझता हूं कि मेरी रक्षा आपके अलावा कोई कर ही नहीं सकता। हिंडनबर्ग पर प्रदर्शन कर रहे थे न। अडानीजी कौन है? ये वही हैं जिनसे 7 हजार 440 करोड़ रुपये के कोयले में, कवाई के अन्दर कोयला मंगवाया, उन दरों में अन्तर था। आप राजस्थान के 1 लाख 39 हजार उपभोक्ताओं को 2020-21 से 5 पैसे दे रहे हो, जिसको बढ़ा कर आपने कर दिया 7 पैसे पांच साल के। यह अडानीजी वही हैं जिनको आरटीपीपी एक्ट की धज्जियां उड़ाते हुए कोयले का सिंगल टेंडर दिया गया। राजस्थान का अब तक सबसे महंगा कोयला 17 हजार, 18 हजार मीट्रिक टन का 1 हजार 42 करोड़ का इन्होंने बढ़ा दिया। आपकी मजबूरियां हैं। मजबूरी आपकी एआईसीसी है। एआईसीसी है, साहब। मैं इस पर कोई टिप्पणी करूंगा तो फिर से नाराज हो जाएंगे। एआईसीसी में जाने वाला धन।

श्री सभापति: समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): सभापति महोदय, कोयले की धुलाई के नाम पर भ्रष्टाचार का ताण्डव, अतिरिक्त कोयला लिंकेज के नाम पर निजी कोयला उत्पादन कम्पनियों से विद्युत उत्पादन निगम को पूर्व में आबंटित कोल से 40 परसेंट महंगा खरीद रहे हैं।

श्री सभापति: समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): मैं समय पर बैठ जाऊंगा। आपने समाचार पत्रों में पढ़ा होगा। कालीसिंध का पावर प्रोजेक्ट इसलिए बन्द हो गया कि कोयले में मिट्टी थी। ताना-बाना बुन दिया। कम्पनी के साथ टेलरमेड। एक विज्ञापन निकाला और कमाई का जरिया ढूंढ लिया।

सभापति महोदय, मैं एक और रिपोर्ट प्रस्तुत करना चाह रहा हूं इनवेस्टमेंट समिट। 2022-23 के पैरा 17 में कहा गया कि इनवेस्टमेंट समिट 2022 में 10 लाख 41 हजार के 4016 एमओयू/एलओआई हस्ताक्षर हो चुके हैं और उसमें 4 लाख 90 हजार लोगों को रोजगार मिलेगा। उसके एक साल बाद 2023-24 के बजट के पैरा 206 में कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट समिट में 10 लाख 45 हजार के 4192 एमओयू हो गये जिनसे 9 लाख से अधिक व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा। सभापति महोदय, एक इन्वेस्टमेंट धरती पर आया नहीं, रोजगार पाने वालों की संख्या जरूर बढ़ा दी। केन्द्रीय मंत्रालय के उद्योग संवर्द्धन व्यापार विभाग की जनवरी, 2022 की जो रिपोर्ट है, राजस्थान में 2019 में 3958 करोड़ का निवेश आया था, 2020-21 में आया 4992 करोड़ का। यह 10 लाख का आंकडा कैसे पार करेगा?

हिंडनबर्ग वाले को मैं एक बात कहना चाहता हूं। और सब तो ठीक है लेकिन हाथी के दांत खाने के कुछ और दिखाने के कुछ और होते हैं। कुछ करो। जमीन लुटाना बन्द करो। यहां पूर्व राजस्व मंत्रीजी बैठे हैं। अगर ये खड़े हो जाएंगे तो मुश्किल हो जायेगी। आपने अडानीजी को 2019-20 में 9 हजार बीघा जमीन दी फतेहपुर में, 2020-21 में 25 हजार बीघा सिमवाड़ा (जैसलमेर) में, 2022 में 400 बीघा करालिया (जैसलमेर) में, 2022 में 38 हजार बीघा मोहनगढ़ में, फिर 2022 में 13 हजार बीघा फतेहगढ़ में और 75 हजार बीघा जमीन अभी कैबिनेट के अन्दर अप्रूवल में पड़ी है। 74 हजार बीघा मंत्रीजी के पास पड़ी है। मैं समझता हूं कि ये सारी बातें यह सिद्ध कर रही हैं।

सभापति महोदय, आज पता लग गया कि इन्होंने औद्योगिक निवेश के लिए ग्रेटर भिवाड़ी इण्डस्ट्रियल टाउनशिप को एक पैसा भी नहीं दिया।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

इन्होंने एक घोषणा की थी, राजस्थान औद्योगिक सुरक्षा बल का गठन करेंगे 2022-23 में। एक आदमी का भी गठन हुआ तो मुझे बतायें।

सभापति महोदय, मैं अपनी बात को कन्क्लूड करूं उससे पहले एक घोषणा 2019-20 के बजट के पैरा 39 में की गई। आज भी ग्राम पंचायतों में आबादी क्षेत्रों में अच्छी सड़कों का अभाव है। सच्ची बात है, बिलकुल ठीक है। फिर कहा कि सरकार आने वाले पांच वर्ष में समस्त ग्राम पंचायतों में एक विकास पथ बनायेगी। 10 हजार किलोमीटर सड़क नाली सहित वॉल टू वॉल बनायेगी। वाह। बन गयी सड़कें? चार साल गुजर गये, अब तक 8 हजार किलोमीटर बन जानी चाहिए थी। जबाव दो तब बताना तो सही मुझे।

आपने पंचायती राज संस्थाओं को कमजोर करने का काम किया। संविधान के 73वें संशोधन के माध्यम से पंचायती राज को राज्य वित्त आयोग और केन्द्रीय वित्त आयोग से कंसोलिडेटेड फण्ड का एक निश्चित प्रतिशत मिलता है, आपने राजस्थान के अन्दर 5वें वित्त आयोग को जिसका कार्यकाल 31 मार्च, 2020 को समाप्त हो गया, आपने ढाई साल तक बनाया नहीं। मेरा आरोप है कि आज भी राजस्थान की ग्राम पंचायतों में, पंचायत समितियों और जिला परिषदों में राज्य वित्त आयोग के 2870 करोड़ रुपये बकाया पड़े हैं। एक तरफ तो आप यह बात कहते हो, दूसरी तरफ रूरल डवलपमेंट के बारे में एक शब्द भी नहीं है इस पूरे बजट के अन्दर। देखो आप। भारत सरकार ने इस बार 01 लाख 60 हजार करोड़ का प्रावधान किया है।

सभापति महोदय, मैं ईआरसीपी की बात जरूर करूंगा। कल राजस्थान के लिए सोने का सूरज उगा था। देश के प्रधान मंत्रीजी ने ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट को इंटर रिवर लिंक योजना में पार्वती, कालीसिंध, चम्बल लिंक परियोजना के साथ एकीकरण करने का प्रस्ताव जो नदियों से नदियों को जोड़ने की विशेष समिति एससीआईएलआर की 20वीं बैठक में पारित हुआ है, उसके बारे में सूचना दी। उन्होंने कहा कि अब गेंद राजस्थान की सरकार के पाले में है। इंटर लिंक योजना के लिए केन्द्र 90 परसेंट देगा और राजस्थान की सरकार का सिर्फ 10 परसेंट हिस्सा होगा। आज तक मुझे मुख्य मंत्रीजी एक भी योजना बता दें, इस देश के अन्दर 16 राष्ट्रीय योजना/परियोजना बनीं, एक योजना बता दें जो 50 परसेंट वाटर डिपेंडिबिलिटी पर बनी हो और आपने खुद ने, जब आप शासन में थे, आपके योजना आयोग का 11.11.1975 का फैसला, आपके योजना आयोग का 31.07.2003 का फैसला, आपके जल

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

संसाधन मंत्री कार्यालय का 21.09.2004 का फैसला, सबमें यह कहा गया कि 75 प्रतिशत से कम वाटर इंडिपेंडिबिलिटी पर यह योजना नहीं बननी चाहिये।

मंत्रीजी, इस योजना को मैंने पढ़ा। माननीय सभापति महोदय, 13 जिलों के अंदर जीवनदायिनी यह योजना होगी। दो जिले जरूर हैं - धौलपुर में 72,500 और सवाई माधोपुर में 01 लाख 39 हजार हैक्टेयर है। अलवर में इन्होंने भाषण दिया। मेरा आरोप है। कुल मिलाकर अगर ई.आर.सी.पी. योजना को एज-इट-इज लागू कर दिया तो अलवर में जितना सिंचाई के लिये खुलेगा, वह 9,402 हैक्टेयर, भरतपुर में 1,165 हैक्टेयर, दौसा 534 हैक्टेयर, यह आपके गांव का, आपके मोहल्ला है न, उससे भी कम है। करौली में 4,401 हैक्टेयर, बूंदी में 200 हैक्टेयर, जयपुर में 7,738 हैक्टेयर और टोंक में 37 हजार, मतलब आप किसको गुमराह करना चाहते हैं ई.आर.सी.पी. के नाम पर? क्या सब्जबाग दिखा रहे हैं? मैं समझता हूं 08 अप्रैल, 2022 को जल संसाधन मंत्री जयपुर में आये। (व्यवधान)

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): ड्रिंकिंग का भी बता दो। आप सिंचाई का बता रहे हो तो ड्रिंकिंग का भी बता दो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): बता देता हूं न। माननीय सभापति महोदय, मैं इस सदन में कोशिश करता हूं कि जब मैं अपनी बात कहूं तो मैं जिम्मेदारी से कहूं। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त करें प्लीज।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): इस योजना में ड्रिंकिंग वाटर का जितना प्रोजेक्शन लिया गया, वह जो प्रधान मंत्रीजी ने अनाउंस किया, उस योजना के अंदर शामिल है पर ई.आर.सी.पी. के नाम पर आप राजनीति करना बंद कर दीजिये। आप लोगों को जब बतायेंगे कि इन 13 जिलों के अंदर, और आपने अभी क्या कहा? आपने राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में कहा 2051 तक इस योजना को पूरा करेंगे। मतलब इससे बड़ा मजाक कोई हो नहीं सकता।

श्री सभापति: समाप्त करें प्लीज।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): माननीय सभापति महोदय, आप मुझे बिठाना चाहते हैं, पर आज राजस्थान की विधान सभा के बाहर एक अनोखा धरना हो रहा है। राजस्थान के अंदर राजस्थान के मंदिरों के पुजारी-पंडित, धर्मगुरू

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

प्रोटेक्शन बिल के लिये आ रहे हैं। राजस्थान के अंदर जिस प्रकार पुजारियों को जिंदा जलाया गया, राजस्थान का पुजारी उससे आहत है। वह पुजारी जिसने ईश्वर से सीधा सम्पर्क कर रखा है, उसकी डाह लगेगी, उसकी दुराशीष लगेगी और इस सरकार को भस्म कर देगी।

श्री सभापति: समाप्त करें, माननीय।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): माननीय सभापति महोदय, मेरा समय शायद अभी शेष है।

श्री सभापति: आपका समय बहुत ज्यादा हो गया। प्लीज सहयोग करें। प्लीज आप विराजिये। हो गया समय, प्लीज विराजें। समाप्त करें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): माननीय सभापति महोदय, यह 2023-24 में इन्होंने प्रत्येक गांवों में आगामी तीन वर्ष में एक किलोमीटर इंटर-लिंक सड़क की बात की है, दो हजार करोड़ की। (व्यवधान)

श्री सभापति: बहुत मौके आयेंगे आपके बोलने के लिये, प्लीज विराजें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): नरेगा में इसके साथ जोड़ा है। एक मिनट, जवाबदेही कानून का इन्होंने क्या किया? इस बार भी राजस्थान गारंटीड सर्विस डिलीवरी अकाउंटेबिलिटी बिल, 2019-20 में पैरा 180 में, 2020-21 में 164 में, 2022-23 में 168 में, मैं समझता हूं जवाबदेही कानून के लिए 2019 में रामलुभाया कमेटी बनी, 2020 में रामलुभाया कमेटी की रिपोर्ट सरकार के पास आ गयी, पर सरकार इसको लागू नहीं करना चाहती।

श्री सभापति: प्लीज समाप्त करें। श्री बाबूलाल नागर।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): माननीय सभापति महोदय, मैं आपको नाराज नहीं देख सकता। माननीय सभापति महोदय, आपने जो समय दिया और मेरी इनसे रक्षा की, वह पीछे बैठे हैं, माननीय सभापति महोदय, यह मुझे घूरकर देखते हैं न, मैं कांपने लग जाता हूं। यह आप नहीं होते तो मैं आज बोल नहीं सकता। मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं।

श्री रघु शर्मा (केकड़ी): माननीय सभापति महोदय, एक प्रश्न मेरे मन में आ रहा है कि कटारिया साहब तो महामहिम बनकर जा रहे हैं, अब उस वेकेंसी पर इनकी नजर है। लेकिन यह भाषण में अडाणी जी के खिलाफ बोल रहे हैं, भागवत जी के खिलाफ बोल रहे हैं, वह वेकेंसी आप कैसे फिल करोगे?

श्री सभापति: प्लीज बैठें। श्री बाबूलाल नागर।

श्री बाबूलाल नागर (दूदू): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान के लोकप्रिय मुख्य मंत्री, श्री अशोक जी गहलोत ने बजट 2023-24 एक ऐतिहासिक बजट पेश किया है। मुझे आपने उस बजट का अनुमोदन करने का, मुख्य मंत्रीजी का आभार प्रकट करने का मौका दिया, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं।

माननीय सभापति महोदय, प्रदेश के मुख्य मंत्रीजी ने बजट के माध्यम से प्रदेश में खुशहाली लाने और आर्थिक सुरक्षा उपलब्ध कराने, प्रदेश को नये आयाम तक पहुंचाने का प्रयास किया है। मुख्य मंत्रीजी ने कुशल वित्तीय प्रबन्ध कर जन घोषणा की 80 प्रतिशत तक, माननीय सभापति महोदय, चार वर्षों में कुल 2,272 बजट घोषणाएं कीं, इनमें से 80 प्रतिशत तक धरातल पर उतारने में सफल रहे। निश्चित रूप से जब-जब राजस्थान के मुख्य मंत्री अशोक गहलोत बने, सरकार से पहले जब चुनाव घोषणा-पत्र जारी करते हैं, उन्होंने चुनाव घोषणा-पत्र को अपना काम करने का आधार बनाया। आज राजस्थान के लोगों को यह विश्वास है कि प्रदेश के मुख्य मंत्रीजी ने अगर बजट में कोई बात कही है तो निश्चित रूप से वह जमीन पर उतरेगी।

कोरोना का कुशल वित्तीय प्रबन्ध किया। भीलवाड़ा मॉडल की पूरी दुनिया में सराहना हुई। कोई भूखा नहीं सोये, इसलिये 33 लाख परिवारों को पांच किस्तों में, उनको 5,500 रुपये की सहायता उपलब्ध करायी। पांच-पांच महीने तक लॉकडाउन लग गया, लेकिन राजस्थान में कोई गरीब भूखा नहीं सोया। प्रदेश की जनता को महंगाई की मार से बचाने के लिए मुख्य मंत्रीजी ने पेट्रोल, डीजल, वैट, घरेलू बिजली की दरों में कमी करने जैसे कदम उठाये। इससे 13 हजार करोड़ रुपये का वार्षिक वित्तीय भार आया है। महंगाई में उस गरीब को सहारा दिया।

मुख्यमंत्री नि:शुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट देने की घोषणा की। एक करोड़ राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के परिवारों को एक किलो दाल, एक किलो चीनी, नमक, एक लीटर खाद्य तेल, मसाले दिये जायेंगे। इस पर करीब 3 हजार करोड़ रुपये का व्यय होगा।

मुख्य मंत्रीजी ने इस बजट में गरीब को गणेश मानकर पूजने का काम किया है। बी.पी.एल. तथा पी.एम. उज्ज्वला योजना में शामिल 76 लाख परिवारों को 500 रुपये में एल.पी.जी. गैस सिलेण्डर उपलब्ध कराने की मुख्य मंत्रीजी ने घोषणा की है। 500 करोड़ रुपये इसमें व्यय होंगे।

मुख्यमंत्री नि:शुल्क बिजली योजना, पिछले बजट में 50 यूनिट तक

(श्री बाबूलाल नागर)

बिजली फ्री की। गरीब एक लट्टू जलाता है, दो लट्टू जलाता है, मैं मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद दूंगा कि 100 यूनिट तक बिजली फ्री करने की मुख्य मंत्रीजी ने घोषणा की है। राजस्थान के एक करोड़ 19 लाख कुल उपभोक्ता हैं, इनमें से एक लाख 4 लाख उपभोक्ताओं को राजस्थान में नि:शुल्क घरेलू बिजली मिलेगी। मैं समझता हूं वह गरीब जो झोंपड़ी में रहता है, वह भी उजाले में रहेगा। माननीय सभापति महोदय, इतना जबरदस्त तरीके से मुख्य मंत्रीजी ने यह निर्णय लिया है। 15 लाख उपभोक्ता अलग से और बचते हैं, उनके लिए भी स्लैब के अनुसार 300 से 750 रुपये प्रति माह तक की छूट मिलती रहेगी। इस तरह 7 हजार करोड़ रुपये इस घरेलू बिजली में मुख्य मंत्रीजी व्यय करेंगे।

माननीय सभापति महोदय, हमारी सरकार का, चरणबद्ध रूप से लक्ष्य 300 यूनिट प्रतिमाह उपयोग करने वालों को नि:शुल्क बिजली देने का सरकार का लक्ष्य है। इस तरह एल.पी.जी. गैस सिलेण्डर, नि:शुल्क फूड पैकेट, नि:शुल्क घरेलू बिजली 19 हजार करोड़ से अधिक का महंगाई राहत पैकेज दिया जाना सरकार ने प्रस्तावित किया है। यह अपने आप में इस सरकार का एक बहुत बड़ा कदम है। डीजल, पेट्रोल पर जो वैट लागू है, उसको कम किया था। 7 हजार 500 करोड़ रुपये इसमें छूट को आगे बढ़ाने का, इसको जारी रखने का मुख्य मंत्रीजी ने इस बजट में प्रस्ताव किया है। इससे निश्चित रूप से महंगाई पर अंकुश लगेगा।

युवाओं के विकास के लिये 'नवीन युवा नीति' बनाने की घोषणा की है और इसमें 500 करोड़ रुपये का 'युवा विकास कल्याण कोष' का गठन करने का मुख्य मंत्रीजी ने जो प्रस्ताव दिया है, निश्चित रूप से राजस्थान के युवाओं में एक बहुत बड़ी ताकत, बहुत बड़ा जोश उत्पन्न होगा। उन्होंने 200 करोड़ रुपये

(समय 14.00 बजे)

दक्षता विकास, रोजगारोन्मुखी, 100 करोड़ रुपये व्यक्तिगत विकास, 200 करोड़ रुपये शिक्षा, छात्रवृत्ति एवं संबंधित संसाधनों हेतु व्यय किया जाना प्रस्तावित किया है।

सभापति महोदय, युवाओं को रोजगार के लिये कारगर कदम उठाये हैं। 4 वर्ष के कार्यकाल में 1 लाख 42 हजार युवाओं को नौकरी देने का काम प्रक्रियाधीन है। इसी तरह 1 लाख 81 हजार की प्रक्रिया चल रही है। कुल 3 लाख 23 हजार लोगों को नियुक्ति देने का इस सरकार का मकसद है। एनडीए

(श्री बाबूलाल नागर)

सरकार 2014 में जब चुनाव में आयी थी तो प्रति वर्ष 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात की थी। आज 8-8, 9-9 साल हो गये, पूरे हिन्दुस्तान का नौजवान, राजस्थान का नौजवान भटक रहा है, एनडीए सरकार को बद्दुआ दे रहा है। इस प्रदेश के लोकप्रिय मुख्य मंत्री जी की इस 5 साल की अपनी कार्ययोजना में 3 लाख 23 हजार नौजवानों को रोजगार मिला है।

सभापति महोदय, एक बहुत बड़ी चुनौती है पेपर लीक की चुनौती। पेपर लीक से नौजवान बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होता है। मुख्य मंत्री जी ने, सरकार ने पर्याप्त कदम उठाये हैं। राजस्थान में पहली बार पेपर लीक करने वालों को जेल भेजा है। मुख्य मंत्री जी ने राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के लिये अधिनियम, 2022 की बात कही है। निश्चित रूप से यह इस सरकार का कारगर कदम है।

सभापति महोदय, एसओजी, स्पेशल आपरेशन ग्रुप के अधीन आधुनिक संसाधनों से सुसज्जित स्पेशल टास्क फोर्स, एस.टी.एफ. गठित करने की घोषणा की है, इससे निश्चित रूप से पेपर लीक पर अंकुश लगेगा। राजस्थान के नौजवानों के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, उससे बचाने का काम इस सरकार ने किया है।

सभापति महोदय, भर्तियां सुरक्षित और पारदर्शी तरीके से सम्पन्न हों, प्रत्येक जिले में सुविधायुक्त ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेंटर बनाने का प्रस्ताव सरकार ने प्रस्तुत किया है, निश्चित रूप से यह काबिले तारीफ है। इससे भर्ती परीक्षा में 250 करोड़ रुपये का व्यय होगा।

भर्ती परीक्षा में वन टाइम रजिस्ट्रेशन प्रणाली के द्वारा, एक बार रजिस्ट्रेशन हो गया तो किसी भी भर्ती परीक्षा में उसको शुल्क देने की जरूरत नहीं है, वह नि:शुल्क भर्ती परीक्षा में बैठ सकता है। यह भी नौजवानों को ताकत देने का काम प्रदेश के मुख्य मंत्री जी ने किया है।

सभापति महोदय, मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना में विद्यार्थियों को प्रोफेशनल कोर्सेज, प्रतियोगिता परीक्षाओं में पिछले बजट में 15 हजार का प्रावधान किया था, मैं, मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि इस बजट में उन्होंने 30 हजार विद्यार्थियों को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा है।

सभापति महोदय, प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारियों के लिए दिल्ली में आवास सुविधा के लिए नेहरू युवा ट्रांजिट होस्टल फैसिलिटेशन सेंटर बनाया

(श्री बाबूलाल नागर)

जा रहा है। इसका काम चल रहा है। इसी तर्ज पर प्रदेश के मुख्य मंत्री ने राजस्थान के तमाम जिला मुख्यालयों पर 100-100 आवासीय क्षमता के विवेकानंद यूथ होस्टल बनाने की घोषणा की है। राजस्थान में कहीं भी जिला मुख्यालयों पर अगर कोई प्रतियोगिता परीक्षाएं होती हैं तो हमारे उस नौजवान को भटकना नहीं पड़ेगा और प्रत्येक जिले में 100-100 आवासीय क्षमता के विवेकानंद यूथ होस्टल बनाने की घोषणा की है।

सभापति महोदय, इसी तरह बजट में प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी के लिए जिला मुख्यालयों पर सावित्रीबाई फूले वाचनालय राजस्थान में शुरू हुए हैं। मैं धन्यवाद दूंगा कि अब राजस्थान में प्रदेश के मुख्य मंत्री ने राजस्थान के तमाम ब्लाक मुख्यालयों पर सावित्री बाई फूले वाचनालय स्थापित करने का इस बजट में प्रस्ताव दिया है। यह निश्चित रूप से काबिले तारीफ है।

सभापति महोदय, इसी तरह विश्वकर्मा कामगार कल्याण योजना शुरू करने का प्रस्ताव करके महिलाओं, कामगार, हस्तशिल्पी, केश कला, माटी कला, कारीगर, घुमन्तू आदि को रोजगार देने का माननीय मुख्य मंत्री जी ने लोकप्रिय निर्णय किया है।

सभापति महोदय, युवाओं को हैल्थ फार्मेसी, एग्रीकल्चर बायोइनफार्मेटिक से संबंधित हाई रिसर्च एंड डवलपमेंट एवं सर्टिफिकेट कोर्स करने के लिये एपीजे अब्दुल कलाम इंस्टीट्यूट बॉयो टेक्नोलॉजी की स्थापना करने की मुख्य मंत्री जी ने घोषणा की है। इसमें करीब 300 करोड़ रुपये खर्च होंगे।

सभापति महोदय, इसी तरह से युवाओं के विकास के लिए जयपुर में राजीव गांधी सेंटर आफ एडवांस टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी बनाने की घोषणा की। करीब 350 करोड़ रुपये इस यूनिवर्सिटी में व्यय होंगे।

सभापति महोदय, दूदू, फागी दोनों स्थानों पर सरकारी महाविद्यालय खोल दिये मुख्य मंत्री जी ने। मैं आग्रह करूंगा कि हमारे तो डीडीपी ब्लाक है, गरीब क्षेत्र है, दोनों विद्यालयों में आपने सब सब्जेक्ट दे दिये हैं, आर्ट्स, कामर्स, साइंस, इन दोनों सरकारी महाविद्यालयों दूदू एवं फागी को पी.जी. किया जाये जिससे वहां के बच्चों को वहीं उच्च शिक्षा का अध्ययन करने का अवसर मिल सके।

सभापति महोदय, मैं, मुख्य मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि नारेहड़ा,

(श्री बाबूलाल नागर)

फागी में एक ऐसा क्षेत्र है जिसके आसपास 4-5 उपाध्याय संस्कृत विद्यालय हैं, उस क्षेत्र में शास्त्री संस्कृत महाविद्यालय हो जाये। हमारे दूदू में भी नहीं है, फागी में भी नहीं है, चाकसू में भी नहीं है, फुलेरा में भी नहीं है। यहां तक कि किशनगढ़ में भी नहीं है, मालपुरा में भी नहीं है। अगर संस्कृत महाविद्यालय खुल जाती है तो संस्कृत पढ़ने वाले हमारे बच्चों को बहुत बड़ा फायदा हो सकता है।

सभापति महोदय, पिछले बजट में विश्व के जो प्रसिद्ध उच्च शिक्षण संस्थान हैं, वहां अध्ययन के अवसर देने के लिए मुख्य मंत्री जी ने राजीव गांधी स्कालरशिप फोर एकेडमिक एक्सीलेंसी योजना शुरू की थी, उसमें 200 होनहार विद्यार्थियों को वित्तीय सहायता दी जा रही थी। मैं धन्यवाद दूंगा कि इस बार मुख्य मंत्री जी ने 500 विद्यार्थियों को लाभान्वित करने का प्रस्ताव दिया है। इससे निश्चित रूप से जो हमारे राजस्थान के लोग हैं, दुनिया के बड़े-बड़े जो उच्च शिक्षण संस्थान हैं, सरकारी फंड पर उनको वहां अध्ययन करने का मौका मिलेगा।

सभापति महोदय, राजकीय महाविद्यालयों के शिक्षकों को भी, बच्चों को ही नहीं, अब शिक्षकों को भी देश-विदेश के जितने भी प्रतिष्ठित संस्थान हैं, उसमें रिसर्च एंड ट्रेनिंग की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए टीचर्स इंटरफेस फोर एक्सीलेंस, टीआईई कार्यक्रम को प्रारम्भ किये जाने का प्रस्ताव दिया है। इसमें 500 शिक्षकों को देश-विदेश में रिसर्च करने का सरकारी खर्च पर मौका मिलेगा। इससे जो हमारी उच्च शिक्षा है, उसकी गुणवत्ता में सुधार आयेगा। हमारे राजस्थान के बच्चों को इससे फायदा होगा।

सभापति महोदय, इसी तरह मुख्य मंत्री जी ने नवीन आईटीआई खोलने की घोषणा की है। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का ध्यानाकर्षित करना चाहूंगा कि प्रदेश में ऐसे बहुत से उपखण्ड हैं, बहुत से ब्लाक हैं, जहां अभी आईटीआई नहीं है। जहां नये ब्लाक बने हैं, हमारे मौजमाबाद में आईटीआई नहीं है। इसी तरह से हमारे फागी में जो पहले आईटीआई थी, आजकल फागी अलग बन गया, माधोराजपुरा अलग बन गया, फागी ब्लाक में आईटीआई नहीं है। आईटीआई से हमारे बच्चों को रोजगार मिलता है। मैं मुख्य मंत्री जी से चाहूंगा कि जितने भी आपने नये पंचायत समिति ब्लाक खोले हैं, सब जगह

(श्री बाबूलाल नागर)

यह आईटीआई खुले। यह हर उपखण्ड लेवल पर, हर ब्लाक लेवल पर राजस्थान में होने चाहिए। इससे निश्चित रूप से फायदा होगा।

सभापति महोदय, इसी तरह से कालीबाई भील, देवनारायण योजना में स्कूटी की संख्या पहले 20 हजार रखी गयी थी, पिछले बजट में 20 हजार थी। मैं मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि इस बार उन्होंने हमारी बेटियों के लिये 30 हजार करने की घोषणा की है।

सभापति महोदय, इसी तरह से छात्राओं को उच्च शिक्षा संस्थानों में आने-जाने के लिये परिवहन का किराया मिलता था। अब मुख्य मंत्री जी ने जो बच्चियां महाविद्यालयों में पढ़ती हैं, उनके लिए भी ट्रांसपोर्ट वाउचर्स स्कीम लागू करने की घोषणा की है। इससे उन बच्चियों का, छात्राओं का मनोबल बढ़ेगा। उनके पेरेंट्स को भी जो परेशानी आ रही थी, वह दूर होगी।

सभापति महोदय, राइट टू एजुकेशन एक्ट कक्षा 1 से 8 तक विद्यार्थियों को नि:शुल्क शिक्षा देने का काम होता है। पिछले वर्ष बजट में माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने कक्षा 9 ओर 10 तक की हमारी जो बच्चियां हैं उनको नि:शुल्क शिक्षा की घोषणा की थी। अब माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने इस बजट में कक्षा 1 से 12 तक छात्र और छात्राओं, पिछली बार छात्राएं और इस बार सभी, छात्र और छात्राओं दोनों को नि:शुल्क शिक्षा उपलब्ध कराने की घोषणा की है। माननीय सभापति महोदय, इससे निश्चित रूप से हमारे बच्चों को एजुकेशन में एक बहुत बड़ी ताकत मिलेगी।

माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने वैसे तो बहुत स्कूलें क्रमोन्नत की हैं फिर भी 100 नवीन प्राथमिक विद्यालय, 300 प्राथमिक विद्यालयों को क्रमोन्नत करने का, 300 विद्यालयों में नवीन विषय खोले जाने का निर्णय किया है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री महोदय से आग्रह करना चाहूंगा कि हालांकि आपने मेरे यहां कृषि महाविद्यालय खोलने की घोषणा कर दी लेकिन राजस्थान के हर पंचायत मुख्यालय पर एक हायर सैकंडरी विद्यालय में आवश्यक रूप से आपको कृषि का विषय खोलना चाहिए। माननीय सभापति महोदय, हमारा प्रदेश जो कृषि प्रधान है, यहां 60-70 प्रतिशत लोग कृषि पर निर्भर हैं और जब कृषि विषय

(श्री बाबूलाल नागर)

खोलेंगे तो हमारे बच्चों को बहुत बड़ा फायदा होगा।

मानननीय सभापति महोदय, इसी तरह से माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने घोषणा कर दी है कि प्रदेश के प्रत्येक ब्लाक मुख्यालय पर चार संकाय आवश्यक रूप से रहेंगे, कला, विज्ञान, वाणिज्य और कृषि। उन्होंने ब्लाक लेवल पर कहा है। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि पंचायत लेवल पर एक स्कूल में कृषि का विषय आवश्यक रूप से होना चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय, यह इस सरकार का ऐतिहासिक कार्यक्रम है। आज पूरे राजस्थान में ही क्या, पूरे विधान सभा क्षेत्रों में, हर जगह अंग्रेजी माध्यम के स्कूल खुलवाना चाहते हैं। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने विद्यालय खोले ही नहीं हैं, 10 हजार अंग्रेजी माध्यम के अध्यापक इस हेतु भर्ती करने का काम भी शुरू कर दिया है। हमारी सरकार का आज यह बहुत बड़ा प्रयोग है। इसमें इन्होंने एक हजार विद्यालय खोलने की बात की है, ये एक हजार राजस्थान में कम हैं। जब आज लोग समझ गये हैं, अंग्रेजी के महत्व को समझ गये हैं, आज राजस्थान में हर जगह अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों की मांग है, ये एक हजार ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर हैं, सरकार को इनको बढ़ाना चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए राष्ट्रीय और अन्तरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के विजेताओं को राजस्थान के सरकारी विभागों में 229 युवाओं को सरकारी नौकरी मिली है। अब खेलों से भी सरकारी नौकरी मिलती है, यह जागृति जनता में पैदा हो गई है। माननीय सभापति महोदय, राजीव गांधी ग्रामीण ओलम्पिक में मैंने बच्चों का जो रुझान देखा, उनके पैरेंट्स का रुझान देखा, अब लोगों के समझ में आ गया है कि खेल से मान-सम्मान भी मिलता है और खेल से सरकारी नौकरी भी मिलती है। माननीय सभापति महोदय, इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि इनका दायरा और बढ़ाना चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, आप तो सदन के बहुत अनुभवी सदस्य हैं। 1998 में जब पहली बार अशोकजी गहलोत मुख्य मंत्री बने थे तो राजस्थान पहला एक ऐसा राज्य था जहां वे बीपीएल को नि:शुल्क इलाज की योजना लेकर आये थे। एक सोच था मुख्य मंत्रीजी का, बाद में मुख्यमंत्री सहायता कोष से जो नोन बीपीएल थे, उनका भी इलाज करवाने का काम

(श्री बाबूलाल नागर)

करते थे। इस बजट में तो माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने इलाज की सीमा 10 लाख से बढ़ाकर 25 लाख रुपये कर दी है। 25 लाख रुपये तक का इलाज राजस्थान का गरीब, कैसी भी गंभीर से गंभीर बीमारी हो, आज उसको न कर्जा लेने की जरूरत है, न उसको अपना गहना गिरवी रखने की जरूरत है। यह ऐतिहासिक काम करने पर मुख्य मंत्रीजी को राजस्थान का आम गरीब आदमी दुआएं दे रहा है। राजस्थान में गरीब आदमी चाहे कितना ही महंगा से महंगा इलाज हो, इलाज की वजह से मर नहीं सकता, जांच की वजह से मर नहीं सकता, मुख्य मंत्रीजी ने यह एक ऐतिहासिक काम किया है।

माननीय सभापति महोदय, मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना, सरकारी चिकित्सालयों में चाहे ओपीडी हो, आईपीडी हो, पूर्णतया निःशुल्क इलाज कर दिया है। 3 करोड़ 50 लाख लोगों को इससे लाभ हो चुका है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना, यह इतना बड़ा ऐतिहासिक काम है कि किसी गरीब आदमी की किसी दुर्घटना में मृत्यु हो जाए, उसको भी मुख्य मंत्रीजी ने इतना बड़ा सहारा दिया है, 5 लाख रुपये सहायता का पिछले बजट में रखा था, इस बार मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, उसके नाबालिग बच्चों को सहारा देने के लिए, उसमें उन्होंने 5 लाख रुपये की मदद को बढ़ाने का काम किया है। पालनहार योजना में ज्यादा पैसा देने का काम किया है, 5 लाख रुपये के स्थान पर 10 लाख रुपये की दुर्घटना बीमा राशि को बढ़ाने का काम किया है।

माननीय सभापति महोदय, राजस्थान में 30 जिलों में मेडिकल कालेज पहले ही खुल रहे हैं। आप जानते हैं कि मेडिकल कालेज में केन्द्र सरकार और राज्य सरकार, दोनों मद होता है, राजस्थान में तीन जिले ऐसे थे, जालौर, प्रतापगढ़ और राजसमन्द, जहां मेडिकल कालेज शुरू नहीं हुए थे। प्रदेश के मुख्य मंत्रीजी ने, हमारे लोकप्रिय चिकित्सा मंत्रीजी ने बार-बार केन्द्र सरकार को लिखा कि प्रधान मंत्रीजी, आप अपनी घोषणानुसार हर जिले में मेडिकल कालेज खोलना चाहते हैं, हमारे यहां तीन जिले ऐसे हैं जहां पर मेडिकल कालेज नहीं हैं, लेकिन उन्होंने राजस्थान सरकार की, मुख्य मंत्रीजी की नहीं सुनी। खुद मुख्य मंत्रीजी ने अपने राज्य मद से तीन जिलों में मेडिकल कालेज खोलने की जो मंशा जाहिर की है, निश्चित रूप से यह काबिले तारीफ है।

माननीय सभापति महोदय, हमारे यहां पीएचसी को सीएचसी में क्रमोन्नत किया गया है। चिकित्सा मंत्रीजी बैठे हैं। चिकित्सा मंत्रीजी, मेरे यहां फागी में चौरू एक ऐसी पंचायत है, एक ऐसा बड़ा गांव है, सिंगल गांव जो

(श्री बाबूलाल नागर)

फागी के बराबर का है, फागी हमारा उप खण्ड मुख्यालय है, यह उसके बराबर का है और वहां पर पीएचसी भी बहुत पुरानी हुआ करती थी। चौरू के गांव वालों को बड़ी उम्मीद थी कि हमारे यहां सीएचसी बनेगी। मैं आग्रह करूंगा आपसे कि जब मुख्य मंत्रीजी जवाब दें तो हमारे चौरू गांव के लोगों की जो उम्मीद है, वैसे भी दूदू के लोगों को उम्मीद होती है तो मुख्य मंत्रीजी कभी भी उनको हताश नहीं करते हैं इसलिए आप अपने जवाब में एक सीएचसी हमारे यहां चौरू में भी खोलने की घोषणा करें।

माननीय सभापति महोदय, महात्मा गांधी मिनिमम गारंटी योजना लागू करने की जो मुख्य मंत्रीजी ने घोषणा की है, सभी परिवारों को 125 दिवस प्रति वर्ष रोजगार की गारंटी दे रहे हैं, यह भी गरीब को बहुत बड़ी ताकत दी है।

माननीय सभापति महोदय, सामाजिक सुरक्षा पेंशन के समस्त लाभार्थियों, कोई विधवा हो जाती है, कम एज है, 500 रुपये मिलते हैं उसको, मुख्य मंत्रीजी ने तय कर दिया कि राजस्थान में जितनी भी सामाजिक सुरक्षा की योजनाएं हैं उनमें कम से कम एक हजार रुपये आवश्यक रूप से पेंशन मिलेगी। उस गरीब को, चाहे विधवा हो, चाहे कोई और गरीब हो, उसको बहुत बड़ी ताकत दी है मुख्य मंत्रीजी ने।

माननीय सभापति महोदय, हमारे प्रदेश में 75 वर्ष तक की 77 लाख की आबादी है, 75 वर्ष के बाद 750 और 1000 रुपये पेंशन मिलती थी। उन 77 लाख लोगों को एक हजार रुपये प्रति माह पेंशन मिलेगी। इससे हमारे जो बुजुर्ग हैं, जो पेंशन को अपने बुढ़ापे का सहारा समझता है, दुआएं दे रहा है राजस्थान में, सारे राइडर हटाए, पेंशन योजना में और पैसा भी बढ़ा दिया। प्रदेश में मुख्य मंत्रीजी ने यह एक ऐतिहासिक काम किया है।

माननीय सभापति महोदय, मैं धन्यवाद दे रहा हूं, शहरों में इंदिरा रसोई योजना, 8 रुपये में भरपेट थाली। मुख्य मंत्रीजी ने इसको गांवों और कस्बों में भी खोलने की घोषणा की है और इसको 1 हजार से बढ़ाकर 2 हजार करने की घोषणा की है। इसमें 700 करोड़ रुपये का व्यय होगा। इससे निश्चित रूप से गांवों में, मुख्य मंत्रीजी की जो सोच है, कोई व्यक्ति भूखा नहीं सोना चाहिए। जब 8 रुपये में रोटी मिलेगी तो मैं समझता हूं कि राजस्थान का कोई भी गरीब आदमी, भीख मांगने वाला व्यक्ति जो गांवों में रहता है, वो भी भूखा

(श्री बाबूलाल नागर)

नहीं सो सकता। इस प्रदेश के मुख्य मंत्री ने उनके लिए भी सोचा है।

माननीय सभापति महोदय, हमारे एससी और एसटी के विकास कार्यों का जो विकास कोष था, 500 करोड़ रुपये पिछले बजट में था, इस बार मुख्य मंत्रीजी ने एक-एक हजार करोड़ रुपये कर दिया। एससी का भी एक हजार करोड़ कर दिया और एसटी का भी एक हजार करोड़ रुपये कर दिया। इसी तरह से ओबीसी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस, अल्पसंख्यक विकास कोष में, प्रत्येक में 200-200 करोड़ रुपये मुख्य मंत्री महोदय ने प्रदान किये हैं।

माननीय सभापति महोदय, हमारे जो वाल्मीकि कोष है उसमें 20 करोड़ रुपये का प्रोविजन पिछली बार रखा था। इस बार मैं धन्यवाद दूंगा, वाल्मीकि कोष हमारे समाज के पिछड़े हुए लोग हैं, बहुत गरीब लोग हैं, उनके लिए मुख्य मंत्रीजी ने बजट में कोष को 20 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 100 करोड़ रुपये करने का प्रावधान किया है।

माननीय सभापति महोदय, दो वर्षों में लगभग 30 हजार सफाई कर्मचारियों की भर्ती करने की बात की है। जब आप नगरपालिकाएं खोल रहे हैं, मेरे यहां भी आपने नगरपालिकाएं खोली हैं तो आपने सोच बनायी कि इतनी बड़ी संख्या में नगरपालिकाएं खोल रहे हैं तो सफाई कर्मचारी भी होने चाहिए। सभापति महोदय, मैं कहना चाहूंगा, यह जो लाटरी के आधार पर आप सफाई कर्मचारियों की भर्ती करते हैं, इसमें वाल्मीकि समाज के लोगों को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। मैंने देखा है, ये जो अन्य समाजों से आ जाते हैं, वे आफिसों में केवल फाइल्स पकड़ाने में लगे रहते हैं, वहां अपनी सैटिंग करते रहते हैं, किस तरह हम दफ्तरों में आ जाएं, सफाई में इनकी बहुत लापरवाही रहती है। यदि वाल्मीकि समाज के लोगों की इसमें भर्ती की जाती है तो निश्चित रूप से इस भर्ती का मकसद कामयाब होगा।

सभापति महोदय, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। कोरोना में कोई बच्चा जो अनाथ हो गया, जिसके मां और बाप दोनों की डैथ हो गयी, उनके लिए राजस्थान के मुख्य मंत्री बेसहारा के सहारा हैं। उन्होंने ऐसे बच्चों को सरकारी नौकरी देने की बजट घोषणा की। यह काबिल-ए-तारीफ है। जिसके मां-बाप मर गये, जो नौजवान बेसहारा हो गया, जैसे ही वह बालिग होगा उसे सरकारी नौकरी मिलेगी। यह ऐतिहासिक काम प्रदेश के मुख्य मंत्री ने किया। सभापति महोदय, पालनहार योजना में 0 से 6 साल तक के बच्चों को 500 रुपये मिलते हैं।

श्री सभापति: दो मिनट में समाप्त करें।

श्री बाबूलाल नागर (दूदू): सभापति महोदय, दो ही मिनट में समाप्त कर रहा हूं। मैंने तो अभी शुरू ही नहीं किया। मैं आपसे आग्रह करता हूं। सभापति महोदय, मैं शोर्ट करने की कोशिश करता हूं।

पालनहार योजना में इन्होंने पैसा बढ़ाया। पिछली बार तीन-तीन सड़कें थीं, इस बजट में इन्होंने एक-एक जिले में पांच-पांच सड़कें बनाने की बात की। इसी तरह सड़कों के निर्माण, उन्नयन के लिए मुख्य मंत्री जी ने जो घोषणा की है, उसके लिए मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। मेरी एक सड़क है दूदू-फागी रोड से चूरू वाया चूरू नाड़ा से मंडावरा वाया छापरी, यह महत्वपूर्ण सड़क है, 17 किलोमीटर अगर यह बन जाती है तो करीब 50 किलोमीटर घूमकर जाने से लोगों का बचाव हो जायेगा।

सभापति महोदय, 10 करोड़ रुपये के काम की मुख्य मंत्री ने प्रत्येक विधान सभा के लिए घोषणा की है, यह काबिल-ए-तारीफ है। जो लोग सड़कों के लिए तरस रहे थे, आज हम बहुत सड़कें बनाने में कामयाब हुए हैं। इसी तरह यह बहुत बड़ा काम हाथ में लिया है। 6 हजार गांवों में इंटरलाक ब्लाक बनाने की घोषणा की गयी है। एक-एक पंचायत में एक-एक इंटरलाक ब्लाक मुख्य मंत्री जी को करने चाहिए, क्योंकि आज हम बड़ी-बड़ी सीमेंट सड़कें बना रहे हैं, गांव-कस्बों में कीचड़ है। हम कितने ही विकास के काम कर लें, लेकिन वहां हमें उलाहना सुनना पड़ता है। एक-एक किलोमीटर अगर एक-एक पंचायत में मिल जाती है तो मैं समझता हूं बहुत बड़ा काम हो जायेगा।

सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि बिजली में भी बहुत बड़ा काम किया गया है 6600 मेगावाट को 8600 मेगावाट कर दिया गया है। अब तो हमारा राजस्थान पूरे हिन्दुस्तान में प्रथम नम्बर पर आ गया। बोराज में मैंने एक एईएन कार्यालय खोलने का अनुरोध किया था, वह खुल जाता तो बहुत अच्छी बात होती। कानून-व्यवस्था, आपने बहुत से एडीशनल एसपी, डीवाईएसपी बनाये। मेरे दूदू डीवाईएसपी में 6 थाने आते हैं, अब 6 थानों पर एक डीवाईएसपी बहुत मुश्किल से पहुंच पाता है। वहां फागी के लिए हमने उप-तहसील कार्यालय के लिए अनुरोध किया है।

सभापति महोदय, ऐसे ही मोखमपुरा एक जगह है, पिछले साल मुख्य मंत्री जी ने हमारा मौजमाबाद थाना खोला, लेकिन वह बहुत लम्बा एरिया कवर कर रहा है, मोखमपुरा में हमारा एक थाना खुल जाए। इस तरह हमारी जो जेल है, वह साम्भर में है। अब 6 थाने हैं हमारे उस चाकसू वाले एरिया में और 6 न्यायालय हैं, इसके बाद साम्भर में जेल है। दूदू में जेल कारागृह भी

(श्री बाबूलाल नागर)

खोलना चाहिए।

श्री सभापति: समाप्त करें। प्लीज सहयोग करें। विराजें।

श्री बाबूलाल नागर (दूदू): मैं कम्प्लीट कर रहा हूं।

श्री सभापति: नहीं, नहीं, प्लीज सहयोग करें।

श्री बाबूलाल नागर (दूदू): मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, पांच ही मिनट में खतम कर दूंगा।

श्री सभापति: वक्ता बहुत हैं। श्री ज्ञानचंद पारख।

श्री बाबूलाल नागर (दूदू): सभापति महोदय, मैं तो अनुशासन वाला आदमी हूं। आपको धन्यवाद।

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): सभापति महोदय, मुख्य मंत्री जी का जो बजट है, कांग्रेस का जो डीएनए है न कि चुनावी वर्ष हो, प्रलोभन दे दो, घोषणाएं कर दो और वापस सत्ता कैसे हासिल हो, यह डीएनए कांग्रेस में है और यह बजट में साफ झलक रहा है। गरीब की मजबूरी का कैसे फायदा उठाओ वोटों के रूप में, उसकी बेबसी को कैसे अपने पक्ष में लो, यह सारा काम बजट में है। मैं मानता हूं, माननीय मुख्य मंत्री जी खुद बहुत अच्छे हैं दयालु भी हैं, अच्छे जादूगर भी हैं, पर कांग्रेस की जो छवि पूरे देश में बन गयी है न, उस कलंक को मुख्य मंत्री जी कितना भी प्रयास कर लें न तो साफ कर नहीं सकते। उनका जादू भी अब कोई ज्यादा चलने वाला नहीं। मुख्य मंत्री जी अच्छे रफूगर भी हो सकते हैं, पर जो तार-तार कांग्रेस हो गयी न, उसका रफू मुख्य मंत्री जी अब नहीं कर सकते।

माननीय सभापति महोदय, कोई मरणासन्न व्यक्ति होता है, डाक्टर को पता है यह बचने वाला नहीं, पर उसकी ड्यूटी है कि वह उसे लाइफ सेविंग सपोर्ट भी लगायेगा, लाइफ सेविंग ड्रग भी देगा। बजट में यही हुआ। मुख्य मंत्री जी को पता है कि कांग्रेस अब बच नहीं सकती। इस बजट के माध्यम से किस प्रकार लाइफ सेविंग ड्रग और लाइफ सेविंग सपोर्ट लगाकर कांग्रेस को राजस्थान में जिन्दा रखने का प्रयास कर रहे हैं। उसके लिए एक के बाद एक कई घोषणाएं कर दीं। यह जनता अब कोई ज्यादा झांसे में आने वाली नहीं है। आपकी घोषणाएं, आपके कार्यक्रम, आपकी योजनाएं, ये सारी की सारी धराशायी हो जाएंगी और जो भारी भ्रष्टाचार का खेल राजस्थान की धरती पर चल रहा है न, वह आपको सत्ता से दूर कर देगा।

माननीय सभापति महोदय, माननीय प्रधान मंत्री जी ने 15 अगस्त

(श्री ज्ञानचंद पारख)

को लाल किले की प्राचीर से भाषण देते हुए अपनी पीड़ा व्यक्त की थी। देश में संसाधनों की कमी नहीं है, पैसों की कमी नहीं है। जितनी भी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, वे अगर ईमानदारी से लागू हो जाएं तो कोई भी व्यक्ति अभावग्रस्त नहीं रहेगा, पर भारी भ्रष्टाचार के चलते जिस व्यक्ति के लिए वह योजना बनी है, उस तक वह योजना पहुंचती नहीं। उसी का परिणाम है कि कई लोग जो वाकई में पात्रता रखते हैं, उसके बावजूद भी योजना का लाभ उठा नहीं पाते।

माननीय सभापति महोदय, विकास के क्या हालात हैं? भ्रष्टाचार के चलते सारा का सारा विकास कितनी जल्दी धराशायी हो जाता है, सड़कें बनती हैं, टूट जाती हैं, पुलिया बनती है, टूट जाती है। माननीय मुख्य मंत्री जी घोषणाएं अच्छी कर लेते हैं, पर असल में उन घोषणाओं का लाभ जनता को धरातल पर मिल रहा है अथवा नहीं, कभी मुख्य मंत्री जी को झांकने की फुर्सत तक नहीं मिलती। मुख्य मंत्री जी को तो बजट तक देखने की फुरसत नहीं है, गलत पढ़ गये यहां पर। ऐसे में जो घोषणाएं हैं, उनकी क्रियान्विति कैसी हो रही है, उस ओर झांकने का जब तक वे साहस नहीं दिखाएंगे तब तक लाभ मिलने वाला नहीं।

कल माननीय प्रधान मंत्री जी दौसा आये थे। विकास कैसे होता है, कहां होता है और कितने समय में होता है, मुख्य मंत्री जी ने वह नजारा देखा होगा और शायद चकाचौंध हो गये होंगे कि हिन्दुस्तान की धरती पर भी ऐसा विकास हो सकता है। माननीय सभापति महोदय, यह जो भ्रष्टाचार है, मैं पाली का उदाहरण देता हूं आपको। आपने मुख्य मंत्री बजट घोषणा में 25 करोड़ की राशि दी। पाली के महत्व की सड़कें बननी चाहिए थीं। कुछ काम आपने पी डब्ल्यू डी को और कुछ काम नगर परिषद् को दिया। दोनों का अन्तर आप देख लेंगे तो आपके सामने सच्चाई आ जायेगी कि एक तरफ काम अच्छा और समय पर हो गया, दूसरी तरफ काम हुआ भी नहीं और जो भी हुआ घटिया हुआ। आज तक वह काम पूरा नहीं हुआ। उस भ्रष्टाचार के चलते एक ठेकेदार ने सुसाइड तक कर लिया। उसके बाद भी मुख्य मंत्री जी के पास समय नहीं है कि भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई करें। जब तक ये भ्रष्टाचारी खुलेआम घूमेंगे और पद पर बने रहेंगे, मुख्य मंत्री जी, आप कितनी ही घोषणाएं कर लें और कितनी ही जन कल्याणकारी योजनाएं ले आएं, उनका लाभ जनता को नहीं मिलेगा और यह भ्रष्टाचारियों से कैसा रिश्ता आपका? क्यों बचा रहे हैं?

(श्री ज्ञानचंद पारख)

यह रिश्ता क्या कहलाता है? थोड़ा एक बार जवाब दे दें।

माननीय सभापति महोदय, भ्रष्टाचार को लेकर देश की जनता ने जो सज़ा कांग्रेस को दी है उससे अब भी आपको सबक लेने का समय नहीं है। इस भ्रष्टाचार के कारण आपको कहां ले जाकर पटक दिया है। आपने बड़ा काम किया था देश को आजाद कराने का परन्तु उसके बाद में जो भ्रष्टाचार हुआ उसका परिणाम देखो कि देश के किसी भी राज्य में चले जाओ, जनता ने आपको नकार दिया है। माननीय सभापति महोदय, आपने ठान रखा है कि हम नहीं सुधरेंगे। आप नहीं सुधरोगे तो जनता आपको सुधार देगी।

माननीय सभापति महोदय, देश के यशस्वी प्रधान मंत्री पर भी बजट भाषण में मुख्य मंत्री जी कटाक्ष करने से चूके नहीं। जिसका लोहा पूरा विश्व मान रहा है, उस पर भी कटाक्ष किया और जिस नेता को देश की जनता ने नकार दिया, उस शीर्ष नेता की यात्रा की तारीफ भी यहां सदन में कर डाली। क्या हुआ यात्रा में? क्या कहा मुख्य मंत्री जी ने कि हमारे नेता देश में प्रेम बांटने चले थे। कैसा-कैसा प्रेम बांटा, उसके फोटो व्हाट्सएप के जरिये आपने देखे होंगे। यह हमारी संस्कृति हमको कहती है कि ऐसे खुलेआम आप कर सकते हो? उसके बाद भी आपने तारीफ की। (व्यवधान)

श्री सभापति: विराजिये। प्लीज, विराजिये।

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): माननीय सभापति महोदय, योजनाएं आपकी अच्छी हैं, लेकिन उनको पूरा करने के लिए आपने जो कर्ज लिया है उससे राजस्थान देश का पांचवां सबसे बड़ा कर्जदार प्रान्त हो गया। 2018-19 में हमारे ऊपर कर्ज था 3 लाख 11 हजार करोड़ का और चार वर्षों में यह बढ़कर 5 लाख 37 हजार करोड़ हो गया। यानी चार वर्षों में हमने 2 लाख 26 हजार करोड़ कर्जा लिया है। मात्र 4 स्टेट ऐसे हैं जो कर्जा लेने में हमसे ऊपर हैं जो तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल हैं। पर इनकी आबादी आप देखोगे तो किसी की दो गुना है, किसी की तीन गुना है पर कर्ज के मामले में कोई भी डेढ़ गुना से ज्यादा नहीं है और कई बड़े प्रदेश भी हमसे पीछे हैं, जैसे मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, बिहार, उड़ीसा हैं। बीजेपी की एकमात्र उत्तर प्रदेश की सरकार कर्जा लेने के मामले में राजस्थान से ऊपर है, बाकी सारी की सारी सरकारें अन्य पार्टियों की हैं। एक महाराष्ट्र है जो वापस हमको मिला है। माननीय सभापति महोदय, यू.पी. की सरकार ने कर्जा भी लिया है तो उसके ऊपर कर्जा 7 लाख 10 हजार करोड़ का है पर यदि उसका

(श्री ज्ञानचंद पारख)

रेवेन्यू आप देखोगे तो वह 5 लाख करोड़ है। कर्जा हमसे मात्र 2.4 गुना ज्यादा है पर उसकी रेवेन्यू 5 लाख करोड़ है, जो हमसे लगभग ढाई गुना ज्यादा है। महाराष्ट्र की सरकार पर भी कर्जा है वह 6.80 लाख करोड़ है और उसकी रेवेन्यू भी 4.3 लाख करोड़ है और राजस्थान पर कर्जा है वह 5.37 लाख करोड़ का है और हमारी रेवेन्यू मात्र 2.9 लाख करोड़ है। यानी हम जो कर्जा ले रहे हैं वह विकास के कार्यों के बजाय उन कार्यों में लगा रहे हैं जहां से हमें वापस कोई रिटर्न मिलने वाला नहीं है। अगर इस प्रकार से हम कर्जा लेंगे तो हम राजस्थान को डुबोने का काम कर रहे हैं। आप कर्जा लो राजस्थान के विकास के लिए, रोजगार के नये अवसर पैदा करने के लिए, तब तो आने वाले कल में राजस्थान की जनता को फायदा होगा और कर्जा लेकर आपने खैरात बांटने का काम किया तो आने वाले कल में राजस्थान बहुत कुछ खो सकता है। हमको राजस्व बढ़ाना होगा, हमको नयी परिसम्पत्तियां भी खड़ी करनी होंगी पर उस मामले में बिलकुल फिसड्डी साबित हो रहे हैं, हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं।

माननीय सभापति महोदय, यह जो आपका, इस सरकार का बजट बना, उसके लिए मेहरबानी करके थोड़ा यशस्वी प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी को भी धन्यवाद दे दो जिनके जीएसटी और इन्कम टैक्स कलेक्शन, सेंट्रल गवर्नमेंट के टैक्सेज हैं उनकी वजह से आपको ज्यादा आय प्राप्त हुई है आपको ज्यादा रेवेन्यू प्राप्त हुई है। माननीय सभापति महोदय, डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन, सेंट्रल की ग्रांट, जीएसटी, यह 2020-21 में भारत सरकार से मात्र 95 हजार करोड़ मिली थी और 2022-23 में भारत सरकार से आपको 1 लाख 56 हजार करोड़ मिली है, मतलब 64.21 परसेंट आपको भारत सरकार से पैसा ज्यादा मिला है और वाहवाही आप ले रहे हो। 61 हजार करोड़ आपको ज्यादा मिला है। आपकी अपनी इन्कम है उसका भी आप थोड़ा आईना देख लो। 2020-21 में स्टेट का जितना भी रेवेन्यू है वह मात्र 39 हजार करोड़ रुपया था, 2022-23 में यह 20 हजार करोड़ बढ़ा है, जिसमें 58 हजार 800 करोड़ रुपया हो गया। माननीय सभापति महोदय, यह रेवेन्यू आपने कैसे बढ़ाया? आपने दारू की दुकानें खोलकर बढ़ाया। जिस प्रकार से बर्बादी के कगार पर लोगों को पहुंचाकर आय प्राप्त की, इससे प्रदेश का भला होने वाला नहीं है। आपकी स्टेट एक्साइज 2020-21 में 9853 करोड़ थी जो 2022-23 में बढ़कर 15 हजार करोड़ हो गयी, मतलब आपने लगभग साढ़े पांच हजार करोड़ रुपया दारू से प्राप्त किया। यह इन्कम अच्छी इन्कम नहीं है। आपकी जो रेवेन्यू बढ़ी है उसमें

(श्री ज्ञानचंद पारख)

डीजल, पेट्रोल पर जो वैट है उसमें भी दो साल में कुल 7 हजार करोड़ की आय बढ़ी है। मतलब 19 हजार करोड़ की आय में से 12 हजार करोड़ की आय बढ़ने का जो कारण है वह दारू और डीजल-पेट्रोल पर वैट है। बाकी मामलों में चाहे जमीनों का पंजीयन हो, चाहे खनन की रायल्टी हो, चाहे आपका कोई और काम हो जिससे आपको रेवेन्यू प्राप्त हो सकती है, उसमें आप कोई ज्यादा कमाल नहीं कर पाये। यह पैसा तो आपको बिना मेहनत के ही मिल गया, आपने कोई प्रयास ही नहीं किया। अगर वाकई में आप प्रयास करते तो इन्कम बढ़ाने के आपके और भी जरिये थे परन्तु आपने कुछ नहीं किया।

अब आप माननीय मुख्य मंत्री जी की घोषणा देखो। घोषणाएं अच्छी हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मुख्य मंत्री जी ने घोषणा की है अन्नपूर्णा योजना की। जो परिवार खाद्य सुरक्षा योजना से जुड़े हैं उनको आप तेल दोगे, दाल दोगे, शक्कर दोगे, नमक दोगे, मसाले दोगे, बहुत अच्छी बात है। माननीय सभापति महोदय, खाद्य सुरक्षा योजना में नाम जोड़ने के लिए जो पात्र व्यक्ति हैं और जिस पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं उस पोर्टल को आपने चार साल से बन्द कर दिया। जो पात्र व्यक्ति हैं, मेहरबानी करके उनके नाम उस सूची में दर्ज हो जाएं, उसके लिए आप कार्यवाही करो। आपका कहना क्या होता है कि भारत सरकार ने राइडर लगा रखा है कि इससे ज्यादा नहीं हो सकते। अगर भारत सरकार का राइडर है तो जितना भारत सरकार देती है वह भारत सरकार से ले लो और उसके अलावा जो पात्र व्यक्ति बचता है, जो आपने मापदण्ड तय कर रखे हैं, जो आपकी पात्रता में आते हैं और बच गया तो आप राज्य कोष से दे दो। यह अन्नपूर्णा योजना में आप राज्य कोष से दे रहे हो तो उसको भी आप राज्य कोष से, स्टेट फण्ड से कर दो। माननीय सभापति महोदय, जब आप इतना लुटा रहे हो तो इनके ऊपर भी लुटा दो। माननीय सभापति महोदय, आश्चर्य की बात यह है कि कोई परिवार खाद्य सुरक्षा योजना से जुड़ा है, उसकी शादी हो गई, पत्नी आ गई तो उसका नाम नहीं जोड़ रहे हैं। किसी के सन्तान हो गई तो उसका नाम भी नहीं जुड़ रहा, तो उनका नाम भी जोड़ो ताकि उनकी यूनिट बढ़ेगी तो उनको गेहूं ज्यादा मिलेगा। माननीय सभापति महोदय, जब देश का प्रधान मंत्री 80 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत गेहूं और दाल दे सकता है तो राजस्थान का मुख्य मंत्री जो वाकई में पात्रता रखते हैं, उनके लिए यह काम नहीं कर सकता? मैं हजारों लोगों के लिए कह रहा हूं, लाखों की संख्या नहीं है

(श्री ज्ञानचंद पारख)

वह। अगर मान लो आपके पास बजट की कमी है, पैसे की कमी है तो इतना लोन लिया है उसमें थोड़ा बहुत लोन इनके लिए ले लेना ताकि आपकी सूची है वह दुरुस्त हो जाए वरना गरीब तक लाभ पहुंचेगा कैसे? आपने घोषणा कर दी पर उसका नाम नहीं है तो उसको लाभ पहुंचेगा नहीं।

माननीय सभापति महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी का मजाक देखो। घोषणा क्या की? आगामी दो वर्षों में 30 हजार सफाई कर्मचारियों की भर्ती की जाएगी। खुद का 6 महीने बाद का भरोसा नहीं है और घोषणा कर रहे हैं दो साल बाद की। अगर वाकई में सफाई कर्मचारियों के प्रति आपके मन में हमदर्दी है, उनको रोजगार देना चाहते हो तो जिस प्रकार वसुन्धरा जी ने 2013 में, 2018 में घोषणा की थी और चार महीनों के भीतर भर्ती कर उनको नियुक्ति पत्र दे दिया था उसका। आप भी साहस दिखाओ वरना दो साल की भर्ती की घोषणा करके आप उनको झांसा देना चाहते हो, उस झांसे में लोग आने वाले नहीं हैं। माननीय सभापति महोदय, मेरा आग्रह रहेगा, हो सकता है कि हाई कोर्ट का राइडर हो कि आपको इस कैटेगरी के लोगों को लेना है, सरकार को अपील कर हाई कोर्ट के सामने जाना पड़े पर यह सफाई कर्मचारियों की भर्ती मात्र वाल्मीकि समाज के परिवारों को ही अधिकतम संख्या में मिल जाए, उसके लिए सरकार को कहीं न कहीं प्रयास करना चाहिए। मात्र नगर परिषद में ही नहीं, पहले जितने भी आपके सरकारी कार्यालय थे चाहे अस्पताल हो, स्कूल हो, और भी कोई कार्यालय हों, तो वहां भी सफाई कर्मचारियों के पद होते थे पर पिछले कई वर्षों से चाहे हमारी सरकार रही हो या आपकी सरकार रही हो, हमने वहां पद खतम कर दिये और ठेके पर सफाई कार्य दे दिया। ठेके में उस सफाई कर्मचारी का शोषण होता है। जिस सफाईकर्मी ने कोरोना काल में कोरोना के विरुद्ध लड़ाई लड़कर हमें स्वच्छ वातावरण दिया, उसको हम इतना-सा उपहार भी नहीं दे सकते हैं तो हममें कहीं न कहीं कमी है। हमको निश्चित रूप से हमारे वाल्मीकि समाज के जो सफाईकर्मी हैं, उनके कार्यालयों और नगर परिषदों में जितने भी पद रिक्त हैं, चुनाव से पहले-पहले भर दिये जाएं, इसके लिए कार्यवाही करनी चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, पहले स्वच्छकार पुनर्वास रोजगार योजना भी थी। यदि कोई सफाई कर्मचारी सफाई का काम नहीं करना चाहता है, कोई और रोजगार करना चाहता है तो जिला परिषद के माध्यम से उसको लोन मिलता था, पर पिछले कुछ सालों से इसे भी हमने बन्द कर दिया। यदि कोई

(श्री ज्ञानचंद पारख)

दूसरा काम करना चाहे तो वह नहीं कर सकता है।

माननीय सभापति महोदय, जिस एस.सी./एस.टी. के बूते कांग्रेस ने वर्षों तक शासन किया, राज किया, अगर कांग्रेस उनकी सुध ले लेती तो भी मान लेते। मैंने कहा न कि कांग्रेस के डीएनए में नहीं है। उनसे केवल लेना-लेना और जहां तक देने का काम है, वहां कुछ नहीं। 2018-19 में हमारी सरकार 8 महीने और 4 महीने आपकी सरकार थी। हमने एस.सी./एस.टी. की योजनाओं के लिए 5 हजार 293 करोड़ का प्रावधान रखा और खर्चा किया 3 हजार 960 करोड़ रुपया, मतलब 75 परसेंट खर्चा किया। 2019-20 में आपकी सरकार आई। आपने 1 हजार 115 करोड़ की राशि सीधे कम कर दी और प्रावधान किया 4 हजार 178 करोड़ का और खर्चा किया मात्र 3 हजार 194 करोड़ रुपया। मतलब, हमारी सरकार की तुलना में आपने लगभग 800 करोड़ रुपये कम खर्च किये। आपने 2020-21 में प्रावधान बढ़ाया और 4 हजार 655 करोड़ रुपये कर दिया, पर आपने मात्र 2 हजार 681 करोड़ रुपये खर्च किये। मतलब, हमारी सरकार की तुलना में 1300 करोड़ रुपये के एस.सी./एस.टी. के हित में काम होने थे, उनके कल्याण के लिए काम होने थे, प्रावधान होने के बाद भी आपने खर्चा नहीं किया। आपने वर्षों तक उनके वोट लेकर शासन किया है। उसके प्रति भी जवाबदेह नहीं हैं। उसकी जिम्मेदारी भी आप नहीं समझते हैं।

माननीय सभापति महोदय, आपने हर बार बजट प्रावधान भी कम किया। माननीय सभापति महोदय, जो ट्राइबल एरिया डवलपमेंट है, जरा आप उसका भी नजारा देख लें। 2018-19 में हमारी सरकार थी, चार महीने कांग्रेस की सरकार रही, 3682 करोड़ रुपये का प्रावधान था, 2900 करोड़ रुपया खर्च हुआ। 2019-20 में आपकी सरकार ने यह बजट 200 करोड़ रुपया कम कर दिया, 3 हजार 190 का प्रावधान किया। आपने खर्च किया मात्र 2553 करोड़ रुपया और आपने 2020-21 में 3438 करोड़ का प्रावधान किया और आपने मात्र खर्च किये 2169 करोड़, मतलब 2020 की तुलना में भी आपने लगभग 400 करोड़ कम कर दिया। हमारी सरकार की तुलना में आपने 800 करोड़ की राशि एस.टी./एस.सी. के हमारे जो भाई, बन्धु हैं, उनके लिए कम की। जहां आपको बढ़ानी चाहिए, जहां आपका बजट बढ़ रहा है। आपका हर क्षेत्र में काम बढ़ रहा है तो फिर आपने एस.सी./एस.टी. के जो बन्धु हैं, साथी हैं, उनके कल्याण की योजनाएं थीं, उसमें कटौती करके आपने क्या सन्देश दिया है?

(श्री ज्ञानचंद पारख)

मेरा आग्रह है माननीय मुख्य मंत्री जी से कि आपकी जो छवि है, उसके अनुसार आप एस.सी./एस.टी. के जो बन्धु हैं, उनके कल्याण की योजना में बढ़ोतरी करें, समय के अनुसार जितनी बढ़ोतरी कर सकते हैं, आप करें।

माननीय सभापति महोदय, मैंने पहले ही कहा, यदि लोन लेकर हम नई इंडस्ट्री या रोजगार खड़ा नहीं करेंगे तो आने वाले कल में यह लोन हमारे लिए बोझ बन जायेगा।

माननीय सभापति महोदय, राजस्थान को डीएमआईसी के रूप में इतनी बड़ी सौगात मिली थी, पर हमारी नाकामी देखें, इतनी बड़ी सौगात का कोई लाभ हम राजस्थान की जनता को नहीं दिला सकें। इतना बड़ा इंडस्ट्रियल फ्रेट कोरिडोर बनता। भारत सरकार राशि दे रही है, पर हमारी इच्छा नहीं है। हमारी काम करने की इच्छा नहीं है। भारत सरकार ने 2018-19 में, हम जिन किसानों की भूमि अधिग्रहित करने वाले हैं, हमको उन किसानों के लिए 4 हजार 418.64 करोड़ की राशि दी। पूरी राशि भारत सरकार की है। हमको यह पैसा किसानों को देना था, पर हमने उनको पैसा नहीं दिया। आपने मात्र 2 परसेंट दूसरे कामों में खर्च किया और 98 परसेंट राशि खर्च नहीं कर पाये। हमने खर्च नहीं की, उसके बावजूद भी 2019-20 में भारत सरकार ने वापस 85 करोड़ रुपये और दिये। किसानों की भूमि का जो पैसा बनता है, आप उसका आकलन करवाकर किसानों को उनके हक का पैसा दे दें, पर 2019-20 में भी हम वह पैसा खर्च नहीं कर पाये।

माननीय सभापति महोदय, इस 83 करोड़ की राशि का हमने मात्र 21 परसेंट पैसा दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर के कामों में खर्च किया। हमको भारत सरकार ने 2020-21 में वापस 43 करोड़ रुपये दिये, पर हमारी आदत है, हमको तो काम करना ही नहीं है। इतनी बड़ी योजना राजस्थान की धरती पर आ रही है, जिससे राजस्थान को रोजगार के बहुत-बड़े अवसर मिल सकते हैं, पर किसी को रोजगार मिले, हमको इसकी चिन्ता ही नहीं है। हमको तो हमारी कुर्सी सुरक्षित रहे, उसकी चिन्ता है। 2020-21 में 43 करोड़ रुपये मिले, उसमें से दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 24.76 करोड़ रुपये खर्च किये। भारत सरकार ने आपके द्वारा खर्च नहीं करने का कारण पूछा न, तो आपका जवाब क्या है?

माननीय सभापति महोदय, एक बार तो भारत सरकार ने निर्णय ले लिया कि अगर राजस्थान इस योजना में गम्भीरता से काम नहीं करता है तो

(श्री ज्ञानचंद पारख)

इस प्रोजेक्ट से राजस्थान को बाहर निकाल दो। आपके पूर्व उद्योग मंत्री जी इस बात के गवाह हैं। राजस्थान के मंत्री महोदय और अधिकारी वहां गये, वहां मिन्नतें कीं, गिड़गिड़ाये, माफी मांगी और कमिटमेंट किया कि हमको एक और मौका दें, हम राजस्थान की धरती पर यह काम कर देंगे, पर माफी मांगना, वादा करना और उसके बाद मुकर जाना और कुछ करना नहीं, यह हमारे डीएनए में है, कांग्रेस के डीएनए में है। हमने वैसा ही किया, जुलाई-2021 में जवाब दिया कि पटवारी, तहसीलदार के पद खाली होने से, जो किसानों की जमीन का कम्पन्सैशन बनता है, हम उसका निर्धारण नहीं करवा पाये। भारत सरकार को राजस्थान सरकार का यह जवाब है, इसलिए हम उनको कम्पन्सैशन नहीं दे पाये।

माननीय सभापति महोदय, यह मेरे विधान सभा क्षेत्र में आता है। वहां का किसान कितने वर्षों से प्रयास कर रहा है। आपने 2013 में उसकी जमीन पर भूमि रूपान्तरण और भू-उपयोग परिवर्तन पर रोक लगा दी और वह लगातार कह रहा है कि मेहरबानी करके हमारे काम को कर दें। आपको जो जमीन लेनी है, वह पैसा देकर ले लें और जो जमीन आपको नहीं लेनी है, उसकी कम से कम हमको छूट दे दें कि हमको वहां क्या करना है। अब न तो आप उसको पैसा दे रहे हो और न ही उसकी बची हुई जमीन, जो डीएमआईसी में नहीं जा रही है, उसमें कुछ करने का अधिकार आप उसको नहीं दे रहे हो।

माननीय सभापति महोदय, यह मुद्दा मैंने पहले भी उठाया था। आप पैसा देंगे 2013 या 2024 में और जो राशि आप दे रहे हैं वह राशि आज की जो बाजार दर है, उसकी एक चौथाई भी नहीं बन रही है जबकि भारत सरकार ने स्पष्ट प्रावधान कर रखा है कि किसान की कोई भी जमीन यदि हम इंडस्ट्री के लिए उपयोग में लेने के लिए अधिग्रहित करेंगे, तो उस किसान को बाजार मूल्य का चार गुना मुआवजा देंगे, पर यहां उलटा है, चार गुना की बजाय एक चौथाई राशि भी नहीं।

सभापति महोदय, यहां तक कि ऐसी भूमि भी अधिग्रहित कर ली, जहां पचासों वर्षों से किसान पक्के मकान बनाकर निवास कर रहा है, पर आपको मुआवजा देने की चिन्ता नहीं है। किसान परेशान है। मेरा मुख्य मंत्री जी से आग्रह रहेगा, आप हमारे बिलकुल पड़ोस के हैं, जोधपुर से हैं, आपको पाली वालों ने बहुत प्यार दिया है, आप जोधपुर वालों की तो सुध लेते हो,

(श्री ज्ञानचंद पारख)

कभी-कभी पाली की भी ले लिया करें। यह बिलकुल चिपटा हुआ जिला है जहां यह भूमि है, एक तरफ जोधपुर है और एक तरफ पाली है। उन किसानों की जमीन का मुआवजा, जो नियमानुसार बनता है, आज के बाजार मूल्य का चार गुना, वहां एक टीम भेजकर निर्धारण करवा दें और उस राशि का बंटवारा चालू कर दें।

माननीय सभापति महोदय, एक कारण यह भी बताया गया कि कोविड की वजह से हम यह काम नहीं कर पाये। कोविड 2020 में आया और आपको राशि 2018-19 में ही मिल गई। आप कम से कम असत्य भी बोलें तो थोड़ा ढंग से भी बोल लें। 2018-19 में कोविड था ही नहीं और आपने अपने पत्र में लिखा है कि कोविड की वजह से काम नहीं हो सका। इससे ज्यादा शर्मनाक स्थिति राजस्थान की क्या हो सकती है। डीएमआईसी का जो पैसा देना है।

श्री सभापति: आपस में वार्ता नहीं।

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): माननीय सभापति महोदय, अब आपकी जो पिछले वर्ष की घोषणा है मेरे जिले की, पूरे स्टेट की तो हजारों होंगी, मैं मेरे जिले की जो पिछले वर्ष की घोषणाएं हैं उनके हश्र की बात कर रहा हूं। माननीय मुख्य मंत्री जी ने बहुत जोश-खरोश से एक साल पहले घोषणा की थी जवाई पुनर्भरण के काम की। 11 महीने बीत गये न, अब वापस नया बजट आ रहा है तो पता है कि कहीं न कहीं सवाल खड़े होंगे, पूछेंगे तो अब कहीं जाकर टेण्डर जारी किये हैं। अब जाकर टेण्डर जारी किये हैं वह भी 1100 करोड़ रुपये के।

माननीय सभापति महोदय, अब आपका यह काम जिस गति से आप कर रहे हो न, दौसा के काम से आप सबक लेते। कल नजारा देखा न आपने कि भारत सरकार अपना कोई भी काम जो अवधि निर्धारित करती है उससे कम समय में करके उसकी लागत घटाती है और आप उससे दुगुना-तिगुना-चौगुना समय लगाते हो न तो आपकी लागत बढ़ती भी है और जनता को जो राहत आज मिलनी है उसके लिए वह चार साल तक तरसती है।

माननीय सभापति महोदय, मुख्य मंत्री जी की एक और घोषणा थी इसी सदन में कि पाली की पानी की समस्या को राहत देने के लिए उन्होंने कहा था कि कुड़ी से रोहट तक की पाइपलाइन की मैं घोषणा करता हूं। उसके बाद में पाली बहुत बड़े संकट से गुजरा है, पानी के संकट से गुजरा है। एक-

(श्री ज्ञानचंद पारख)

एक मटकी पानी के लिए पाली तरसा है। एक साल होने को आया है, अब कहीं जाकर आपने वर्क आर्डर दिया क्योंकि आपको पता है कि विधान सभा सत्र आयेगा, सवाल होंगे, जवाब देना मुश्किल होगा। एक साल बाद आपने वर्क आर्डर दिया है। जब पता है कि पाली में इतना बड़ा संकट है और आपकी घोषणा थी तो यह काम तो आप पहले भी कर सकते थे। मार्च में आपकी घोषणा और अप्रैल-मई-जून तक यह लाइन बिछा कर रोहट क्षेत्र की जनता को आप पानी के मामले में संकट से उबार सकते थे, पर आपके मन में इच्छा नहीं है काम करने की और आपने क्या किया, जो पुरानी पाइपलाइन थी जो 2002 में बिछी थी और वह भी उतरन थी रणसी गांव से, जो पुरानी पाइप काम

(समय: 14.51 बजे)

(श्री जे.पी. चन्देलिया, सभापति, पदासीन)

नहीं आती, रोहट को पानी देने के लिए यहां वह उतरन हमको खैरात में दी थी आपने, जो कई सालों से काम नहीं आ रही है और अधिकारियों को कह दिया था कि आप इसको दुरुस्त करो। दस महीने तक अधिकारी प्रयास करते रहे, पैसा खर्च करते रहे, पूरी गर्मी बीत गयी, मानसून आ गया, तब तक यह पाइपलाइन ठीक नहीं हुई। इससे ज्यादा आपका काम करने का तरीका क्या हो सकता है कि आप कितना बदतर तरीके से काम करते हो और जो उतरन आपने मजबूरी में दी थी न, उसके लिए आपने करोड़ों रुपये खर्च भी कर दिये और वो ही खैरात आज आप यह जमीन के रूप में हमको दे रहे हो।

जमीन बेशकीमती, जमीन हमारी और पैसा खैरात में जैसे कि अहसान कर रहे हो। हमको आपका अहसान नहीं चाहिये, माननीय मुख्य मंत्री जी, हमको हमारे हक का पैसा चाहिये, उसके लिए आपसे निवेदन कर रहे हैं और आपने तो भगवान भरोसे छोड़ दिया पाली-रोहट की जनता को। मैं धन्यवाद दूंगा पाली की समाजसेवी संस्था को जिन्होंने अपने आर्थिक योगदान से पचासों टैंकर लगाकर कहीं से निजी जो कुएं हैं न वहां से पानी की व्यवस्था करके यह छह महीने का जो संकट का काल था उस काल में पशुधन को भी बचाया और मानव जीवन को बचाया वरना आपके भरोसे यह एक भी पशु नहीं बचता। इसलिये मेरा आग्रह रहेगा कि यह जो आपकी घोषणा की हुई योजना है और उसके लिए जो आपने समय-सीमा निर्धारित कर रखी है कम से कम मेहरबानी करके समय-सीमा पर वह काम हो जाये, उसके लिए आप अपने नीचे का जो सिस्टम है उसको दुरुस्त करो, उनको आप निर्देश दो।

(श्री ज्ञानचंद पारख)

माननीय सभापति जी, मेरा यह भी कहना है कि इस बार जवाई बांध में पानी आया है। इस बार तो हमारे जिला कलेक्टर ने साहस दिखा कर एक सम्मानजनक बंटवारा पेयजल के पानी के लिए करवा दिया। कहीं न कहीं आपको नीति बनानी होगी, कोई पालिसी आपको तय करनी होगी...

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): ...कि जितना पानी आता है उसमें कितना हिस्सा पेयजल के लिए रहेगा, उसके बाद आपका जो पानी बचता है न, हम खुद कहते हैं आप किसानों को पानी दो, हम मना नहीं करते पर पेयजल के लिए पहली प्राथमिकता के लिए कहीं न कहीं नीति बनाने की आवश्यकता है वरना हम जब भी पानी आता है अगर सही तरीके से बंटवारा नहीं होता है तो हमारे क्षेत्र की जनता को बहुत बड़ा संकट झेलना पड़ता है, तो बार-बार ऐसा कलेक्टर नहीं आयेगा जो इतना साहस दिखा कर इतना अच्छा बंटवारा कर देगा। कोई कमजोर कलेक्टर आ गया न तो वापस हमको संकट में डाल देगा। इस नाते आग्रह रहेगा कि आप कोई नीति बना दो और आपकी जो बाकी सड़कों की घोषणा है न, आपने पिछली बार रूपावास से पुख्तारी सीआरएफ की सड़क थी सात मीटर चौड़ी बननी थी, एक साल होने को आ गया मात्र दस परसेंट काम हुआ है, दस परसेंट काम। दस-दस करोड़ की सड़कें आपने विधान सभा क्षेत्र में दीं।

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): बस दो मिनट में। दस-दस करोड़ की सड़कें आपने प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में दीं, उसका भी मात्र कहीं दस परसेंट, कहीं बीस परसेंट, कहीं पच्चीस परसेंट काम हुआ है। जब तक मशीनरी को आप इस बात के लिए पाबन्द नहीं करोगे कि जो समय-सीमा है काम पूर्ण करने की, उसमें पूरा नहीं होता है, मैंने दौसा का उदाहरण दिया है आपको और मुख्य मंत्री जी खुद इस बात के गवाह हैं, वो वहां मौजूद थे कि विकास कैसे होता है। यह वहां सीख कर आ जाते न तो राजस्थान में लागू करते तो हो सकता है मुख्य मंत्री जी की वाहवाही हो जाती। उसमें भी कहीं दस, कहीं बीस परसेंट काम।

नवजीवन योजना में आपने मेरी ही मांग पर अलग से सौ करोड़ रुपये का प्रावधान करने की घोषणा की थी। थोड़ा अधिकारियों से बुला कर पूछ लेना आप कि आपकी अपनी की हुई घोषणा में से कितनी राशि वो खर्च कर पाये,

(श्री ज्ञानचंद पारख)

तो सच्चाई आपके सामने आ जायेगी। मैंने पहले ही कहा न कि मुख्य मंत्री जी के पास समय नहीं है। क्या बजट पढ़ना था, क्या बजट पढ़ गये। उनको बजट तक में झांकने की फुरसत नहीं तो योजना में कहां झांकेंगे, लेकिन उनको झांकना होगा राजस्थान की जनता के हित में।

माननीय सभापति महोदय, स्कूल-कालेज खोल दिये, कहीं भवन का पता नहीं तो कहीं मास्टर का पता नहीं, कहीं व्याख्याता का पता नहीं। यह खोलने से कुछ नहीं होगा।

श्री सभापति: थैंक यू। समाप्त करें।

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): एक मिनट में। कहीं न कहीं आपको खोलने के साथ-साथ वहां शिक्षण व्यवस्था सुचारु हो, वहां कमरे पूरे हों, इसकी व्यवस्था करनी होगी और अन्तिम बात जिसका आग्रह मैंने पहले किया था पाली में कुड़ी के काम की वजह से कहीं सीवर लीक हो गया, कहीं पाइपलाइन लीक हो गई, उससे सैकड़ों मकानों में दरारें आ गईं। कई मकान तो इतने क्षतिग्रस्त हो गये कि उनको पूरा उतारना पड़ा। माननीय जिला कलेक्टर महोदय की जानकारी में यह बात है, उन्होंने प्रस्ताव बना कर राजस्थान सरकार को भिजवा भी दिया कि इस-इस व्यक्ति के मकान की इतनी-इतनी क्षति हुई है। वो परिवार वाले कहीं किराये पर मकान लेकर अपना निवास कर रहे हैं। आपको इनको सहायता देनी है, आप जब इतने दयालु हो तो मेहरबानी करके पूरी सही सूची मंगा कर उनका मुआवजा कितना बनता है उनको मुआवजा दिलवा दें...

श्री सभापति: बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): और यह भी आग्रह रहेगा, प्रभारी मंत्री जी भी हैं, पाली जाते हैं काफी एक्टिव भी हैं। मैंने पहले भी कहा था वो कांग्रेस को दुरुस्त करने में लगे हैं, मेहरबानी करके वहां जो मकान खराब हो गये न, टूट गये न, थोड़ा उनके लिए उनकी दुरुस्ती के लिए भी प्रयास कर लें वहां पर कि वो कैसे दुरुस्त हो सकें, उसमें सरकार का क्या योगदान हो सकता है। कांग्रेस तो दुरुस्त होगी नहीं पर वो प्रयास करेंगे तो मकान जरूर दुरुस्त हो जायेंगे। आपने समय दिया, उसके लिए धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री सभापति: थैंक यू। सुश्री रीटा जी चौधरी।

सुश्री रीटा चौधरी (मण्डावा): सभापति महोदय, आपके साथ मैं सचेतक महोदय का भी धन्यवाद देना चाहती हूं कि उन्होंने बोलने का समय दिया।

(सुश्री रीटा चौधरी)

माननीय मुख्य मंत्री महोदय द्वारा 10 फरवरी को जो बजट प्रस्तुत हुआ वह आम जन का बजट है। बजट में गरीब, अमीर, वृद्ध, युवा, महिला सहित सभी वर्गों का ध्यान दिया गया है। एक पंक्ति में कहा जाये तो यह बजट सामाजिक सुरक्षा का बजट है लेकिन यह बात भी सही है कि एक परम्परा-सी बन गयी है, विपक्ष के हैं वो बजट का मजाक उड़ाते हैं, उसकी बुराई करते हैं, आलोचना करते हैं और जो पक्ष के हैं वो उसकी सराहना करते हैं लेकिन मेरा यह मानना है, सभापति महोदय, कि जब हम बजट पर कुछ बोलते हैं तो उसकी तुलना मैं केन्द्र के बजट से करना चाहूंगी।

एक फरवरी को प्रस्तुत केन्द्रीय बजट से यदि इस बजट की तुलना की जाये तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जायेगा। एक फरवरी का केन्द्रीय बजट हमने सुना, सभापति महोदय, और केन्द्र के बजट के अन्दर प्रथम पांच पृष्ठ के अन्दर केवल यह बताया गया कि अमृत काल क्या है और अमृत पीढ़ी क्या है जबकि माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने जो बजट पढ़ा उसमें जो प्रथम पांच पृष्ठ थे उनमें 19 हजार करोड़ का महंगाई का राहत पैकेज देने की घोषणा मुख्य मंत्री महोदय ने की। खाद्य सुरक्षा के अन्तर्गत आने वाले परिवारों को नि:शुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट वितरण, सस्ते एलपीजी सिलेण्डर, नि:शुल्क बिजली, गरीबों की रसोई तक पहुंचने का काम किया।

अब विपक्ष इसको रेवड़ी बांटने का काम कहते हैं लेकिन मेरा यह मानना है, सभापति महोदय, मैं इसको नि:शुल्क कहूंगी और निशुल्क इसलिये कहूंगी कि सरकार से सुविधा प्राप्त करना नागरिक अधिकार है और जब किसी गरीब को राहत मिलती है तो गरीब की गरिमा को मुफ्त कहकर चोट नहीं पहुंचाना चाहती।

सभापति महोदय, केन्द्र के बजट में एक शब्द नया आया था 2022 में 'अमृत काल' और इस वर्ष 2023 के बजट में फिर से एक नया शब्द आया 'अमृत पीढ़ी'। अमृत काल कोई नया शब्द नहीं है बल्कि 2014 के अन्दर एक जुमला आया था अच्छे दिन का। अब लोग बार-बार अच्छे दिन की बात सुन कर बोर होने लगे तो उन्होंने एक नया शब्द ढूंढा अमृत काल और जब अमृत

(समय: 15.00 बजे)

काल की बात करते हुए साल भर बीत गया तो एक नया शब्द इस बार बजट में हमें सुनाई दिया 'अमृत पीढ़ी' का। मैं समझती हूं 'अमृत पीढ़ी' नया नाम नहीं है, प्रधान मंत्री जी ने बेरोजगार युवाओं के लिये 'अमृत पीढ़ी' शब्द का

(सुश्री रीटा चौधरी)

इस्तेमाल किया। वैसे देखा जाये तो युवाओं को रोजगार और काम तो नहीं दिया लेकिन नया नाम देने की जरूर उन्होंने हिमाकत दिखाई। मैं धन्यवाद देना चाहती हूं माननीय मुख्य मंत्री महोदय को जिन्होंने बजट में युवाओं के विकास पर ध्यान दिया, युवाओं को समर्पित बजट सदन में लेकर आये। सबसे बड़ी बात थी युवाओं के, मध्यम वर्ग पर खास फोकस रखा। युवाओं के विकास के लिए पहली बार युवा नीति लेकर आये। अपने चार साल के कार्यकाल में करीब डेढ़ लाख सरकारी नियुक्तियां दीं और उतनी ही प्रक्रियाधीन हैं। इस बजट में सबसे बड़ी बात यह है कि अगले वर्ष 100 मेगा जॉब फेयर प्रस्तावित हैं। मैं समझती हूं कि इससे प्रदेश के युवाओं को स्टार्टअप स्थापित करने में सहायता मिलेगी। मैचिंग शेयर की सीमा को 25 लाख से बढ़ाकर 01 करोड़ करने की जो घोषणा की है, यह केन्द्र सरकार द्वारा स्टार्टअप में जो राहत दी जाती है, उससे कई गुना बढ़िया योजना है।

सभापति महोदय, अभी चूरू से आने वाले माननीय सदस्य केन्द्र के बजट पर बोल रहे थे और उन्होंने कहा कि रूरल डवलपमेंट में पैसा बढ़ा है, फार्मर वैलफेयर में पैसा बढ़ा है। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं, केन्द्र ने बजट आबंटन में सब्सिडियों में भारी कटौती करी। सभापति महोदय, फूड सब्सिडी में 31.3 प्रतिशत की कमी की, जो सीधा-सीधा गरीब को नुकसान देने का काम किया। फर्टिलाइजर सब्सिडी में 22.3 प्रतिशत की कमी की, जो सीधा-सीधा किसान को नुकसान पहुंचाने का काम किया। पेट्रोलियम सब्सिडी में 75.4 प्रतिशत कमी की जो सीधा-सीधा आम और गरीब लोगों को नुकसान करने का काम किया।

सभापति महोदय, विश्व भुखमरी सूचकांक, 2022 को अगर हम देखें तो 121 देशों की सूची में भारत 107 नंबर पर है और केन्द्र ने फूड सब्सिडी को घटाया है। 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य माननीय प्रधान मंत्री ने रखा। आय तो दोगुनी नहीं हुई लेकिन फर्टिलाइजर की सब्सिडी जरूर घटाने का काम किया।

चूरू से आने वाले माननीय सदस्य जब रूरल डवलपमेंट की बात कर रहे थे और उन्होंने कहा कि रूरल डवलपमेंट में 1964 करोड़ रुपये के बजट की बढ़ोतरी हुई, लेकिन वह आगे पढ़ना भूल गये, रूरल डवलपमेंट में 12.34 करोड़ बजट की कटौती की है।

सभापति महोदय, मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय को धन्यवाद देना

(सुश्री रीटा चौधरी)

चाहती हूं कि वह कृषि के लिये अलग से बजट लेकर आये और जब कृषि के लिये बजट लेकर आये तो उन्होंने किसानों के बारे में सोचा। केन्द्र व राज्य में जब भी कांग्रेस की सरकार आई है, पंचवर्षीय योजना पहले हुआ करती थी, उसमें किसान और मजदूर को मुख्य बिन्दु मानकर उसके इर्द-गिर्द सारी योजनाएं बनाई जाती थीं। इसी प्रकार का बजट पिछली बार और इस बार अलग से कृषि बजट लेकर आये। अन्नदाता जो सभी का पेट भरता है, उसके लिये बहुत-सी योजनाएं लेकर आये, उनके लिये बहुत-सी सब्सिडी दी। इस बजट में किसानों को हर महीने 2000 यूनिट बिजली निःशुल्क दी, इससे 11 लाख किसान लाभान्वित होंगे। किसानों को खेत पर मकान बनाने का अनुदान दिया। एससी, एसटी के लघु-सीमांत किसानों को अतिरिक्त अनुदान मिलेगा। तारबंदी के लिए दो वर्ष में एक लाख किसानों को अनुदान मिलेगा। पांच हजार युवा किसानों को प्रशिक्षण दिया जायेगा। नये कृषि महाविद्यालय खोले जायेंगे। वेटरिनरी यूनिवर्सिटी खोली जायेगी। किसानों को गिरदावरी के लिए राजस्व अधिकारियों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, इसके लिए एक मोबाइल एप किसानों के लिए जारी करने का काम किया है।

सभापति महोदय, केन्द्र में जब यूपीए की सरकार थी तो महानरेगा लेकर आये। रोजगार देने की गारंटी का वादा किया और जब कोविड काल रहा, जब छोटे उद्योगपति घर बैठ गये, व्यापार खतम हो गया, रोजगार खतम हो गया, नौकरियां हाथ से चली गईं तो इस महानरेगा ने लोगों को बहुत बड़ा सहारा दिया और बाजार में वापस से पैसा रोटेट होने का काम हुआ। महिलाएं नरेगा में काम पर जाती थीं, उनको जो पैसा मिलता था, उससे वह बाजार में अपनी रोजमर्रा की आवश्यकता के सामान खरीदती थी, अपने लिये सामान खरीदतीं, अपने बच्चों के लिये, अपने परिवार के लिये खरीदती थी, इससे पैसा रोटेड हुआ। लेकिन इस बार केन्द्रीय सरकार ने साढ़े तैंतीस परसेंट की नरेगा में कटौती की। वहीं पर हमारे माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना चालू की, इसमें 125 दिवस प्रतिवर्ष का रोजगार देने का प्रावधान किया। ऐसे समय में नरेगा के एक मजदूर की एक बात याद आती है

'कुछ तो खासियत है मेरे वोट में,

वोट देता हूं फकीरों को, कमबख्त शहंशाह बन जाते हैं।'

सभापति महोदय, मैं सामाजिक सुरक्षा पर बात करूंगी क्योंकि 2023-24 का बजट सामाजिक सुरक्षा के ऊपर था। सामाजिक सुरक्षा इसलिए भी

(सुश्री रीटा चौधरी)

जरूरी है क्योंकि एक लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा है कि समाज में जो गरीब है, मजदूर है, पिछड़ा हुआ है, उसको किस तरह से राहत दी जाये। सभापति महोदय, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना इसका उदाहरण है। इसके साथ ही पेंशन में वृद्धि करना, इंदिरा रसोई लेकर आना, यह ऐसी कुछ सुरक्षा गारंटी योजनाएं हैं जिससे समाज को संबलता मिलेगी। जब नरेगा में कटौती की तो इससे यह जाहिर होता है कि केन्द्र सरकार की क्या सोच है और राजस्थान सरकार की क्या सोच है। केन्द्र सरकार गरीब को और अधिक गरीब करना चाहती है, अमीर को और अधिक अमीर।

अभी माननीय सदस्य बात कर रहे थे, मुझे एक वाकया याद आया। 9 फरवरी का दिन था, माननीय प्रधान मंत्री महोदय संसद में अभिभाषण पर जवाब दे रहे थे और, सभापति महोदय, वह बड़ा हास्यास्पद समय था, विपक्ष ने उनसे अडानी के बारे में पूछा, देश में रोजगार के बारे में पूछा, युवाओं के लिए पूछा, व्यापारियों के लिए पूछा, महिलाओं के लिए पूछा तो ध्यान भटकाने के अलावा उन्होंने कुछ नहीं किया, वह सीधा नेहरू जी पर आ गये। नेहरू जी, जिनकी शख़्सियत आज हम सोच नहीं सकते। उन्होंने देश आजाद कराने में अपना योगदान दिया। आजादी के बाद नेहरू जी एक बार लंदन गये। वहां मिस्टर चर्चिल से उनकी मुलाकात हुई और मिस्टर विंस्टन चर्चिल ने नेहरू जी से पूछा कि आप हमारी जेलों में कितने समय तक रहे? नेहरू जी ने कहा, मैं 10 साल से अधिक समय तक जेल में रहा। विंस्टन चर्चिल ने कहा कि तब तो आप हमसे नफरत करते होंगे? नेहरू जी ने कहा, नो, मिस्टर चर्चिल, मैंने उस व्यक्ति के नेतृत्व में काम किया है जिसने हमें दो बातें सिखाईं। एक तो कभी किसी से डरना मत और एक कभी किसी से नफरत मत करना। राहुल गांधी जी ने जो भारत जोड़ो यात्रा की, पाली से आने वाले माननीय सदस्य मजाक उड़ा रहे थे, मैंने आब्जेक्शन किया था, उसके पीछे उद्देश्य यही है कि जो देश में डर का माहौल है, नफरत का माहौल है, उसको दूर किया जाये।

सभापति महोदय, आज की हमारी युवा पीढ़ी आरएसएस की विचारधारा वाले व्यक्ति, बीजेपी की विचारधारा वाले व्यक्ति नेहरू को नहीं समझ सकते।

नेहरू के लिए क्या खूब कहा है:-

'देश के आत्मबल और स्वाभिमान के प्रतीक हैं नेहरू,

(सुश्री रीटा चौधरी)

बुद्धिमता की जीती-जागती तस्वीर हैं नेहरू,
अन्धविश्वास, साम्प्रदायिक जातिवाद से लड़ने वाले नेहरू,
क्रान्ति के अग्रदूत नेहरू, पर शान्ति के उपासक नेहरू,
विनोबा भावे के शब्दों में कहें तो लोक देव नेहरू।

सभापति महोदय, राज्य सभा के अन्दर जिस तरीके से प्रदर्शन हुआ। जैसे कौरवों की सभा के अन्दर द्रोपदी का चीरहरण हुआ। देश के प्रधान मंत्री, जिन्हें पूरा देश सुन रहा था, पूरी दुनिया सुन रही थी और मंत्रिमंडल ने ताली बजा-बजाकर और मेज थपथपाकर जिस तरीके से नेहरू का उपहास किया। उनको नहीं पता कि हमारा सामाजिक ताना-बाना क्या है, हमारी परम्पराएं क्या हैं, हमारा पारिवारिक ताना-बाना क्या है? उन्होंने सीधा कह दिया कि नेहरू सरनेम क्यों नहीं लगाते? यहां पर विपक्ष के लोग कहते हैं कि प्रधान मंत्री से सीखो, क्या सीखें कि किस तरह से हमारी परम्पराओं को तोड़ा जाये, किस तरीके से हमारे पारिवारिक रिश्तों और पारिवारिक ताना-बाना का मजाक बनाया जाये? उस पर नहीं बोलते हैं। सभापति महोदय, इनके पास बजट पर बोलने के लिए कुछ नहीं है। इनको ऐसा जोर का झटका लगा है। अभी चूरू से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि मुख्य मंत्री महोदय ने 18 बार पानी पीया है, लेकिन 18 बार पानी पीकर ऐसा पानी पिलाया है कि इनको सांप सूंघ गया है।

सभापति महोदय, गाय के बहुत प्रेमी हैं। गाय के लिए बहुत बड़े प्रेमी हैं। गाय के लिए बहुत बड़ी बातें करते हैं। गाय के नाम पर चुनाव लड़ने आते हैं। भारत सरकार के पशु कल्याण बोर्ड ने एक नोटिस जारी किया कि 14 फरवरी को वेलेंटाइन डे के दिन हम Cow Hug Day मनायेंगे। ऐसी घोषणा कर दी और सबको पाबन्द कर दिया। सभापति महोदय, Cow Hug Day मनाने के लिए गाय तो चाहिये। इस देश का गोवंश जो कि लम्पी में खतम हो गया था, हमारे पशुपालकों और किसानों को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। हमारे केन्द्र के बजट के अन्दर उसकी बात नहीं की, लेकिन राजस्थान ऐसा पहला राज्य है जिसमें लम्पी से मरी गायों के लिए मुआवजा देने की बात की है। इस देश का गोवंश लम्पी नामक महामारी के चलते बर्बाद हो गया। अब राजस्थान के बजट में लम्पी रोग से गोवंश की मौत पर 40 हजार रुपये प्रति गाय क्षतिपूर्ति राशि का ऐलान किया। सभापति महोदय, एक तरफ Cow Hug Day और एक तरफ कामधेनु बीमा योजना। पशुपालकों को दुधारू पशुओं के

(सुश्री रीटा चौधरी)

बीमे की घोषणा करना, लोगों को एक बहुत बड़ी राहत देने का हमारी सरकार ने और हमारे माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने काम किया है। Cow Hug Day के लिए विपक्ष इतना ट्रोल हुआ कि उनको वह घोषणा वापस लेनी पड़ी कि हम इस तरह का कोई Cow Hug Day नहीं मनायेंगे।

सभापति महोदय, ओपीएस, जिस पर हमारे विपक्ष के लोग कहते हैं कि कैसे ओपीएस लागू होगा? इनको क्या फर्क पड़ेगा? आने वाले टाइम में जिसकी भी सरकार रहेगी, उस पर भार पड़ेगा, लेकिन ओपीएस लागू करने के लिए भी सीना चाहिए और देश के प्रधान मंत्री कहते हैं कि मैं अकेला सब पर भारी हूं। इसका मतलब है कि उनके साथ कोई नहीं है। (व्यवधान)

श्री सभापति: प्लीज सुनिये। आप बोलिये।

सुश्री रीटा चौधरी (मण्डावा): सभापति महोदय, मुख्य मंत्री महोदय ने विगत बजट में पुरानी पेंशन योजना की घोषणा की, लेकिन निगम व बोर्ड सहित विश्वविद्यालयों के कर्मचारी इसकी सीमा में नहीं आ पाये थे और इस बात की आवाज समय-समय पर उठती रही है। मुख्य मंत्री महोदय ने सबकी बात और भावनाओं की कद्र करते हुए इन सभी को इसके अन्दर शामिल करने का काम किया है। एक तरह राज्य सरकार सभी को पेंशन के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने का प्रयास कर रही है। वहीं केन्द्र की सरकार अग्निवीर और अग्निपथ के माध्यम से सेना में मिलने वाली पेंशन को भी समाप्त करने का काम कर रही है।

चिरंजीवी योजना, जिसे पूरे देश और देश के बाहर भी काफी प्रसिद्धि मिली है। सभापति महोदय, हम लोग इसको इसलिए अच्छा मानते हैं कि कभी वक्त होता था कि परिवार में अगर बेटा-बेटी है और बेटी बीमार हो जाये तो गरीब मां-बाप कहते थे कि अपने आप ठीक हो जायेगी और बेटा अगर बीमार होता था तो उसका इलाज कराने के लिए जाते थे। जब गरीब व्यक्ति के घर में कोई बीमार हो जाये तो उसका अपना घर गिरवी रखना पड़ता, अपना खेत गिरवी रखना पड़ता या किसी से ब्याज पर रुपया लेना पड़ता था और तब जाकर वह हास्पिटल के अन्दर अपना या अपने बच्चे का या अपने परिवार का इलाज करा पाता था। इस पीड़ा को समझते हुए माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने पिछली बार बजट के अन्दर 10 लाख की बीमा योजना को लागू किया, उसको बढ़ाकर अब 25 लाख रुपये कर दिया है। मैं समझती हूं कि यह बहुत बड़ा सहारा सभी को मिलेगा, क्योंकि कैंसर एक ऐसी बीमारी है, प्रत्यारोपण की

(सुश्री रीटा चौधरी)

ऐसी बीमारी, जिसमें गुर्दा है, लीवर है, उनमें बहुत पैसा लगता है। आम आदमी उसको अफोर्ड नहीं कर सकता है। अब आराम से जाते हैं, अपना इलाज कराकर घर पर आते हैं और बहुत सारी दुआएं माननीय मुख्य मंत्री महोदय और राजस्थान की सरकार को देते हैं।

सभापति महोदय, कर्मचारी वर्ग हो, युवा वर्ग हो, गरीब, मजदूर, व्यापारी हैं, सभी को राहत देने वाला यह बजट है। राजस्थान सरकार के पास कुशल एवं क्वालिटी लीडरशिप है। सरकार के कार्यकाल के इन चार वर्षों की परफोर्मेंस बहुत अच्छी रही है। जनता को जनता का हक डिलीवर करने में सरकार सफल रही है। बजट में यह प्रदर्शित हो रहा है। इसलिए राज्य में कांग्रेस की सरकार को किसी अन्य कार्ड की जरूरत नहीं है। जैसे कि केन्द्र की सरकार और केन्द्र के बीजेपी के नेता करते हैं। कभी टुकड़ा-टुकड़ा गैंग बीच में ले आते हैं, कभी हिजाब की बात करने लगते हैं, कभी हलाला की बात करने लगते हैं। कभी टीपू सुल्तान जैसे कार्ड खेलने लगते हैं। और तो और, हिन्दू मुसीबत के अन्दर मन्दिर को याद करता है, भगवान को याद करता है। मुसलमान मुसीबत के अन्दर अल्लाह को याद करता है और बीजेपी वाले और उनकी केन्द्र की सरकार मुसीबत में पाकिस्तान को याद करती है।

सभापति महोदय, सरकार ने जनता को अच्छे भविष्य की ओर मोड़ा है, इतिहास की ओर नहीं, जो कि केन्द्र की सरकार करती है। दौसा में कल प्रधान मंत्री जी आये थे और उन्होंने कहा कि कांग्रेस काम करने नहीं देती है, लटकाने और भटकाने का काम करती है, लेकिन पिछले इतने सालों से आपकी सरकार है। आप कर रहे हैं, नहीं होता है तो आपके बस की बात नहीं है। इस पर एक बात याद आ गयी। एक पिता ने बेटे से पूछा कि तेरा रिजल्ट कैसा रहा तो बेटे ने कहा कि प्रधान का बेटा फेल हो गया। फिर पिता ने पूछा कि मैं तेरा रिजल्ट पूछ रहा हूं कि तेरा रिजल्ट क्या रहा तो वह बोला कि सरपंच का बेटा फेल हो गया। पिता बोला कि सरपंच और प्रधान का बेटा फेल हो गया, मैं तो तेरा रिजल्ट पूछ रहा हूं तो वह बोला कि चौधरी का बेटा फेल हो गया। पिता ने कहा कि चौधरी का बेटा तो फेल हो गया, पर अपना रिजल्ट बता, तो उसने कहा कि जब प्रधान का बेटा फेल हो गया, सरपंच का बेटा फेल हो गया, चौधरी का बेटा फेल हो गया तो आपका बेटा कहां से पास होता? प्रधान मंत्री जी तो इस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं। जब विपक्ष कुछ पूछता है तो वे बताने में असमर्थ रहते हैं।

(सुश्री रीटा चौधरी)

सभापति महोदय, जो बजट राजस्थान की सरकार और माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने दिया है, वह लाजवाब, कल्याणकारी है, जो कि महिलाओं, किसान, युवा, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, सबको साथ लेकर एमएसएमई की बात करता है। राज्य सरकार का यह बजट जन कल्याणकारी बजट है। जनता ने जिस कार्य के लिए चुनकर भेजा है, उस कार्य को पूरा करता है, उसका पूरा रोडमैप इस बजट के अन्दर है। सभापति महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी के बजट के लिए कुछ इस तरह से कहूंगी-

'ख्वाहिशों का मोहल्ला बहुत बड़ा होता है,
बेहतर यह है कि हम जरूरतों की ओर मुड़ जाएं।'

सभापति महोदय, झुंझुनूं और चिड़ावा से एक कवि और रचनाकार हैं श्री रवि शंकर कांगड़ा। अच्छा लिखते हैं। उनकी कुछ पंक्तियां मैं अन्त में बोलना चाहूंगी-

'राजस्थान के जादूगर का यह बजट देखा,
विरोधी सत्ता पाने का बजट बिगाड़ दिया,
सोच रहे थे, अब की बार सत्ता में हम आयेंगे,
उनके इस सपने को बजट ने उजाड़ दिया,
अब एक-दूसरे की बगले झांक रहे हैं,
देखो विपक्ष का यह कैसा चेहरा बिगाड़ दिया,
बजट से लगता है देखो आज राजस्थान में,
रो रहे हैं विपक्षी, जादूगर ने ऐसा पछाड़ दिया,
जादूगर ने विरोधी का बजट बिगाड़ दिया।'

माननीय सभापति महोदय, मैं अपने विधान सभा क्षेत्र की कुछ मांग रखना चाहूंगी।

श्री सभापति: दो मिनट में समाप्त कीजिए।

सुश्री रीटा चौधरी (मण्डावा): मैंने विपक्ष के बहुत सारे सदस्यों की बात सुनी और एक ही बात जब मुख्य मंत्री महोदय बजट पढ़ रहे थे तो कही जा रही थी कि इतना पैसा आएगा कहां से और इतना कैसे करेंगे? चूरू से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि राजस्थान पत्रिका ने सर्वे करवाया लेकिन शायद मण्डावा को वे भूल गये हैं। पिछले तीन साल में जो बजट आया है

(सुश्री रीटा चौधरी)

मण्डावा के अंदर, वह पूरा का पूरा धरातल के ऊपर है। गलती इनकी नहीं है, मुख्य मंत्री महोदय सिर्फ बजट की घोषणा करते हैं, उसका क्रियान्वयन हमारी भी ड्यूटी होती है। जन-प्रतिनिधि के क्षेत्र में कोई काम आता है, जिसकी घोषणा की जाती है तो उनका भी दायित्व बनता है कि वे भी आफिस में जाकर ब्यूरोक्रेट से मिलकर, मंत्री से मिलकर उसको धरातल पर लेकर आएं।

मैं यहां पर आपके माध्यम से मुख्य मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगी कि हमारी कुछ बहिनें हैं जो नर्सिंग भर्ती, 2013 की बार-बार बात करती हैं। मैं समझती हूं कि उनकी मांग वाजिब है। 2013 के अंदर हमने नर्सिंग भर्तियां निकाली थीं। उसके बाद फिर बीजेपी की सरकार आयी और उन्होंने इसमें पदों के अंदर कटौती कर दी। उस समय और अब के समय में एक तो जो हमारी बहिनें हैं वे ओवरएज हो गयी हैं, कुछ का मेरिट लिस्ट में नंबर नहीं आयेगा। मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि ये 2013 की जो नर्सिंग भर्ती है, उसके लिए कुछ न कुछ रास्ता निकालें ताकि जो वंचित रही हैं, उनको इसके अंदर मौका मिल सके।

सभापति महोदय, अबकी बार फसल के अंदर बहुत ज्यादा खराबा हुआ है। हालांकि मुख्य मंत्री महोदय ने किसान कल्याण निधि की घोषणा की है, बढ़ाया है उन्होंने, लेकिन फिर भी आपके माध्यम से कहना चाहूंगी कि गिरदावरी हुई थी, लेकिन रकबा कम होने की वजह से बहुत जगह फसल बीमा योजना के अंदर नहीं आ रही हैं। सरसों की फसल है, चने की फसल है, सौ प्रतिशत खराबा हुआ है। जब मुख्य मंत्री महोदय यहां पर अपना रिप्लाई दें या कृषि मंत्री जब भी डिमांड पर बोलें तो मैं समझती हूं कि जो फसल खराबा हुआ है, इसके अदंर लोग मुआवजे की जो मांग रख रहे हैं, किसान धरने पर बैठे हैं, इस पर भी हम लोगों को सोचकर उसका बजट अलग से देना चाहिए और मुआवजे की घोषणा यहीं विधान सभा के अंदर करनी चाहिए।

बिसाऊ बड़ी तहसील है, बड़ा कस्बा है, उसके अंदर कालेज की मांग है। मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्री महोदय को कहना चाहूंगी कि बिसाऊ कस्बे के अंदर नगरपालिका के अंदर राजकीय महाविद्यालय खोलने की कृपा करें। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार पुन: आपका धन्यवाद देती हूं आपने मौका दिया।

श्री सभापति: श्री प्रताप सिंह जी।

श्री प्रताप सिंह (छबड़ा): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे लीक हुए बजट पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूं।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): सभापति महोदय, ये क्या बोल रहे हैं? (व्यवधान) बजट लीक हुआ है ये?

श्री प्रताप सिंह (छबड़ा): आप अपने समय पर अपनी बात कह लेना। (व्यवधान) आप अपनी बात कह देना। आप बैठिए।

श्री सभापति: बजट लीक नहीं हुआ। उनका अपना विचार है। बोलिए।

श्री प्रताप सिंह (छबड़ा): सबसे पहले तो मैं हमारे प्रतिपक्ष के नेता को मेरी तरफ से और सदन की तरफ से धन्यवाद ज्ञापित करूंगा और हमारे अध्यक्ष महोदय माननीय सी.पी. जोशी साहब के साथ अपनी भावनाएं जोड़कर उनके बारे में इतना कहूंगा कि जिस प्रकार का जीवन आपने राजस्थान की सेवा में बिताया है, उसी प्रकार का जीवन आप असम की सभा में बिताएंगे और वहां से भी निष्कलंक और निष्कपट होकर वापस राजस्थान आएंगे।

माननीय सभापति महोदय, बजट पर बोलने से पहले मैं दुष्यंत कुमार की दो लाइनें सुनाना चाहता हूं -

"ये रोशनी है हकीकत में एक छल, लोगो

कि जैसे जल में झलकता हुआ महल, लोगो

माननीय सभापति महोदय, मुख्य मंत्री जी का इस कार्यकाल का ये अंतिम बजट है और हो सकता है ये आखिरी बजट हो। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने सपने तो बहुत दिखाए हैं परंतु ये सपने साकार होना असंभव-सा लगता है क्योंकि इसमें समय भी कम है। हमारे अक्टूबर में कोड आफ कंडक्ट लग जाएगा और जो सरकारी साल होता है वह 31 मार्च तक होता है। मुझे लगता है कि जितनी घोषणाएं की हैं, ये पूरी नहीं हो पाएंगी। साधन भी राजस्थान के पास में नहीं हैं कि जिस प्रकार की घोषणाएं की हैं वे पूरी कर पाएंगे।

सभापति महोदय, उन्होंने पिछले बजट में भी काफी लोक-लुभावनी घोषणाएं की थीं। वास्तविकता यह है कि उनमें से कुछ ही धरातल पर उतर पायीं। बाकी का क्या हुआ है? न राजस्थान के लोगों को पता है, न आपको और हमको पता है।

माननीय मुख्य मंत्री जी की सबसे प्रिय योजना है चिरंजीवी योजना। जहां भी जाते हैं चिरंजीवी योजना की जरूर बात करते हैं। इस चिरंजीवी

(श्री प्रताप सिंह)

योजना का भी बहुत बुरा हाल है। मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने इसका दायरा तो बढ़ाया है, 10 लाख से बढ़ाकर 25 लाख रुपये किया है, परंतु जितने भी प्राइवेट हास्पिटल हैं या प्राइवेट डाक्टर हैं, ये ओपीडी में सर्जरी वाले केस तो देखते हैं लेकिन आईपीडी में न तो मरीजों को देखते हैं, न भर्ती करते हैं। यही नहीं इम्प्लांट के काम में आने वाले जो सामान हैं, उनकी क्वालिटी भी निर्धारित नहीं की गयी है कि किस प्रकार का इंस्ट्रूमेंट आदमी के हिप पे लगेगा, नी पे लगेगा या हार्ट पर लगेगा। इसकी क्वालिटी डिफाइन करनी चाहिए। अब किसी के स्टंट लगाते हैं तो 20 हजार का भी आता है और 01 लाख रुपये का भी आता है। अब डाक्टर हमको 20 हजार का भी एक लाख का बता देंगे तो हमको मानना पड़ेगा। जब आदमी टेबल पर लेटा हुआ होता है, उस समय वह कीमत नहीं देखता, रेट नहीं देखता चाहे वह अपने परिवार का जेवर या मकान गिरवी रखे, परंतु उसकी सबसे पहली प्राथमिकता हो जाती है आदमी को बचाना। इसलिए क्वालिटी निर्धारित करें ताकि आम अवाम, गरीब आदमी उसका फायदा ले सके।

अभी बहिन जी कह रही थीं कि जो भी बजट दिया है, पूरा पास किया है, जो भी घोषणाएं हैं, सब धरातल पर उतरी हैं। मैं आपको बता देता हूं आरयूएचएस के लिए पिछले बजट में 100 करोड़ रुपये की घोषणा की थी, 100 करोड़ रुपये आज तक धरातल पर नहीं उतरे हैं। यदि उतरे हैं तो कोई भी कांग्रेस का प्रतिनिधि बता दे या माननीय मुख्य मंत्री जी जब बजट भाषण का रिप्लाई करें तो बता दें। माननीय सभापति महोदय, आरयूएचएस में अगर 100 करोड़ रुपये लग जाते, आज एसएमएस की हालत ये है कि वह ओवर क्राउडेड है। ओवर क्राउडेड होने के बाद भी हमको एसएमएस की तरफ देखना पड़ता है। वहां पेशेंट इतने हैं, इतना भारी रश है कि डाक्टर्स पेशेंट को ढंग से देख भी नहीं पाते। इसलिए मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि ये जो 100 करोड़ रुपये की पिछले बजट में घोषणा की थी, निश्चित रूप से इसको पूरा करेंगे और आरयूएचएस में 100 करोड़ रुपये लगवाएंगे ताकि राजस्थान की जनता को फायदा मिल सके।

माननीय सभापति महोदय, जगह-जगह होर्डिंग्स लगाए गए, जगह-जगह टीवी लगाए गए, जितना प्रचार हो सकता था उतना प्रचार हुआ, यहां तक कि ट्विटर का जो बैंगलोर में हैडक्वार्टर है, उसमें भी कहा, यहां से निर्देश गए कि हमको स्पेस ज्यादा मिलना चाहिए इस बजट भाषण पर।

(श्री प्रताप सिंह)

मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा कि बजट भाषण में युवाओं की बात तो की गई परंतु युवाओं को तुरंत क्या लाभ हुआ? मुझे अगर कांग्रेस के मित्र बता दें कि तुरंत ही बजट के बाद एक अप्रैल को फलां युवा को ये बेनेफिट मिल जाएगा तो मैं मान सकता हूं कि इनकी कथनी और करनी में फर्क नहीं है।

सभापति महोदय, जो पेपर लीक हुए हैं, लाखों बच्चों का जीवन इन्होंने उजाड़ दिया और यह युवाओं के उत्थान की बात करते हैं। यह किस मुंह से यह बात करते हैं? यूनिवर्सिटी खोलने की बात करते हैं पर कहीं अमेरिका सिंह जैसे वी.सी. लग जाते हैं, कहीं पर प्रोफेसर्स की कमी है, यूनिवर्सिटीज चल रही हैं, इस ओर ध्यान नहीं है। जब तक हम अच्छी क्वालिटी एजुकेशन नहीं देंगे तब तक हमारे प्रदेश के नौजवानों को, युवाओं को न तो अच्छा रोजगार दे सकते हैं न उनको अच्छा नागरिक बना सकते हैं।

माननीय मुख्य मंत्री महोदय रोजगार की बात करते हैं। पिछले 2-3 बजट में लगातार यह कहते आ रहे हैं कि हम नये औद्योगिक क्षेत्र बनाएंगे। इन्होंने जितनी घोषणा की उसके आधे ही अब तक बना पाये हैं, शुरू में 62 की थी, उसमें से आधे ही बना पाये हैं। एनसीआर रीजन के ज़िले जैसे भरतपुर, अलवर, उनमें आज दिन तक जगह भी चिह्नित नहीं की गई है, जहां सबसे ज्यादा प्रेशर है। अलवर व भरतपुर में आदमी इण्डस्ट्री लगाना इसलिए पसंद करता है क्योंकि उधर मार्केट की प्रोब्लम नहीं है। दिल्ली राजधानी है। आबादी के हिसाब से हिन्दुस्तान का सबसे बड़ा शहर है। डीएमआईसी के बारे में अभी ज्ञान जी कह रहे थे। डीएमआईसी के बारे में पूरे बजट में कोई घोषणा नहीं की है। थोड़े दिनों में लोग डीएमआईसी का नाम तक भूल जाएंगे, इस प्रकार की स्थिति हो रही है।

माननीय सभापति महोदय, यहां भ्रष्टाचार की बात भी की जाती है। कहते हैं कि भ्रष्टाचार के मामले में हमारी सरकार की पालिसी जीरो टोलरेंस की है। मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा अभी रामगंज मण्डी में स्टिंग आपरेशन हुआ। स्टिंग आपरेशन में आंगनबाड़ी केन्द्रों में जो पोषाहार दिया जाता है, दाल, गेहूं, चावल, जितनी मात्रा में मिलना चाहिए था, उससे आधी मात्रा में आपूर्ति हो रही है।

पोषाहार का कॉनफैड के माध्यम से इन्होंने 25 हजार या 5 हजार करोड़ या 2500 करोड़ रुपये का टेण्डर किया, उसमें भारी अनियमितता हुई।

(श्री प्रताप सिंह)

माननीय मुख्य मंत्री जी को मैंने पत्र लिखा, सहकारिता मंत्री को पत्र लिखा, अधिकारियों को पत्र लिखा। पत्र लिखकर अवगत कराया कि कॉनफैड द्वारा क्रमांक आरएससी/सी 26/42244-1 से आंगनबाड़ी केन्द्रों पर प्रोसेस्ड फूड सप्लाई करने का टेण्डर जारी किया है, जिसे टेण्डर कार्टेल बनाकर रविवार को खोलकर, तीन गुना अधिक दर पर स्वीकृत कर दिया है। सभापति महोदय, मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि ऐसी क्या मजबूरी थी कि आपको रविवार के दिन टेण्डर खोलना पड़ा, उसको मंजूर करना पड़ा, वह भी बाजार भाव से तीन गुना रेट में? माननीय सभापति महोदय, इसमें पूरे हिन्दुस्तान में इस प्रकार का काम करने वाले लाखों लोग होंगे, परन्तु टेण्डर प्रोसेस ही इस प्रकार किया कि इसमें 5 फर्म ही एलिजिबल हुईं। उसमें भी दो को आउट कर दिया गया और तीन का कार्टेल बनाकर, तीन गुना रेट में यह टेण्डर दे दिया गया। इसमें राजस्थान की जनता के खून पसीने का करीब एक-डेढ़ हजार करोड़ रुपये का भ्रष्टाचार हुआ है। इसलिए मांग करता हूं कि आप इसकी एसओजी से या एसीबी से जांच करवाएं ताकि हकीकत सामने आ सके। राजस्थान की जनता की गाढ़ी कमाई, राजस्थान के गरीब का हक जिन लोगों ने मारा है, उनको सज़ा मिल सके।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान एक और गम्भीर विषय की ओर दिलाना चाहता हूं। कोटा में कोचिंग का बहुत बड़ा सेंटर है। वहां आये दिन आत्महत्याएं हो रही हैं। कोटा में कोचिंग सेंटर्स में संचालक, होस्टल मालिकों व स्थानीय प्रशासन को मिलाकर इस प्रकार की योजना बनाई जानी चाहिए कि बच्चा आत्महत्या के बारे में विचार तक नहीं कर सके। वहां बच्चों का शारीरिक शोषण होता है। शारीरिक शोषण लड़के का हो या लड़की का हो, एकाएक वह शर्म के कारण कह नहीं पाता। या तो अपने मां-बाप से डरता है या समाज से डरता है।

सभापति महोदय, कोटा में ड्रग्स की मात्रा भी बढ़ती जा रही है। लड़के ड्रग्स के आदी होते जा रहे हैं, आप सुनोगे और देखोगे तो ताज्जुब करोगे। जहां कोचिंग के बच्चे ज्यादा रहते हैं वहां चलते-चलते मोबाइल छीनना, पैन छीनना, किताब छीनना, चश्मा छीनकर ले जाना, यह तो हंसी मजाक हो गया है। मुझे उम्मीद है सरकार इस ड्रग के मामले को बहुत ही गम्भीरता से लेगी। यह हमारे नौजवानों से जुड़ा हुआ मामला है और बजट भी माननीय मुख्य मंत्री जी ने युवाओं को समर्पित किया है, इसलिए इस पर विशेष रूप से ध्यान देंगे। ड्रग्स के मामले में जितना कंट्रोल कर सकेंगे, उतना ही हम हमारी युवा पीढ़ी

(श्री प्रताप सिंह)

का बचा सकेंगे वरना पंजाब, हरियाणा जैसी हालत हो जाएगी। बाड़मेर, जैसलमेर जैसी हालत हो जाएगी, जहां 10 हजार, 15 हजार रुपये किलो में पॉपी हश्क बिक रहा है, डोडा चूरा बिक रहा है, इस प्रकार की स्थिति हो जाएगी। इसलिए मेरा निवेदन है कि अभी तो शुरुआत है, अगर अभी से हमने रोक लगाने का प्रयास किया तो ठीक रहेगा। छात्र-छात्राओं का शारीरिक शोषण हो रहा है, कई प्रकार की गुण्डागर्दी हो रही है, इनको अगर आपने रोका तो निश्चित रूप से मैं समझता हूं कि युवाओं के बारे में आप अच्छे विचार रखते हो।

माननीय मुख्य मंत्री जी, मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं, भ्रष्टाचार के मामले की बात करते हो, जे.डी.ए. का ही मामला ले लो। एक वरिष्ठ सहायक भ्रष्टाचार के मामले में पकड़ा गया और उसको दो साल की सज़ा हुई। दो साल की सज़ा होने के बाद भी वह चार साल तक जे.डी.ए. में नौकरी करता रहा। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? मुझे इसका भी जवाब चाहिए। माननीय मुख्य मंत्री जी इसका जवाब दें। राजस्व विभाग के पटवारी को सज़ा सुनाई जाने के बाद भी बर्खास्त नहीं किया गया, फिर से दोबारा रिश्वत लेते हुए पकड़े जाने पर उसको नौकरी से हटाया गया।

प्रदेश की कानून स्थिति किस प्रकार की है? अभी 11 फरवरी की बात है, मेरे खुद के गांव की बात है, दो-ढाई करोड़ रुपये की डकैती हुई। बंदूक, तमंचों के दम पर बीच बाजार में, बाजार भी हमारा कोई ज्यादा चौड़ा नहीं है, 10 फुट चौड़ा बाजार है, ढाई करोड़ रुपये की डकैती हुई श्रीकिशन जी गोयल सर्राफ के यहां। मेरा निवेदन है कि इस डकैती के मामले में आप टीम गठित करें और टीम गठित करके इस डकैती को उजागर करें, मुलजिमों को पकड़ें, ताकि कानून का इकबाल भी बना रहे और पुलिस का भरोसा भी लोगों में बना रहे।

माननीय सभापति महोदय, मैं मेरे क्षेत्र के बारे में आपको निवेदन करना चाहूंगा। पूरे राजस्थान में जमीन नापने का जरिया एक तरह का कर दिया है। हमारे यहां छबड़ा टोंक स्टेट में आता है और छीपाबड़ौद कोटा स्टेट में आता है, वहां 13 बिस्वा का बीघा था, वहां 20 बिस्वा का बीघा था। अब इनको मिलाकर, आप कलेक्टर रहे हैं, आप ज्यादा जानते होंगे, पर मिलाकर उनको हैक्टेयर और एकड़ में कर दिया है। ऑनलाइन करने की वजह से राजस्थान के कई गांवों में लोगों को कहीं जमाबंदी नहीं मिली, कहीं और काम नहीं हुआ। एक-एक, डेढ़-डेढ़ साल हो गए। मेरा निवेदन है कि छीपाबड़ौद को

(श्री प्रताप सिंह)

तो ऑनलाइन कर दिया गया है पर मिस्टेक की वजह से कहीं गलत नाम दर्ज हो गया, कहीं गलत जमीन चढ़ गई, इस प्रकार की कई गलतियां हैं। इस कारण से किसानों को परेशानी आ रही है। राजस्व मंत्री यहां बैठे हैं, सरकार इसको संज्ञान में ले। छबड़ा दो साल से ऑनलाइन नहीं हुआ है, उसको तुरन्त ऑनलाइन कराएं ताकि वहां के लोगों की परेशानी भी मिटे। आज बेटा बाप के नाम जमीन नहीं कर सकता, बाप बेटे के नाम जमीन नहीं कर सकता, इस प्रकार की स्थिति बनी हुई है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, लैंड रिकार्ड तो सारा हैक्टयर में ही है।

श्री प्रताप सिंह (छबड़ा): नहीं साहब, हैक्टेयर और एकड़ कर दिया न। बिस्वा खतम कर दिया।

श्री सभापति: हां, तो वह समानता ही है।

श्री प्रताप सिंह (छबड़ा): नहीं, हमारे यहां बीघा चलता है, साहब।

श्री सभापति: अभी भी?

श्री प्रताप सिंह (छबड़ा): हां, अभी भी। अभी भी बीघा, हैक्टेयर और एकड़ चलता है।

श्री सभापति: माननीय मंत्री महोदय बैठे हैं, देख लें।

श्री प्रताप सिंह (छबड़ा): आप खुद ही दिखवा लेना, माननीय मंत्री जी भी देख लेंगे। तहसील का राजस्व रिकार्ड ऑनलाइन किया गया और छबड़ा का शीघ्र करवाया जाए। इसके अलावा मेरे क्षेत्र से करीब डेढ़ सौ किलोमीटर मध्यप्रदेश की सीमा लगती है, मध्यप्रदेश में भी वह सम्भाग जो शुरू से ही चोरी-डकैती के मामले में बदनाम है। चाहे ग्वालियर का हिस्सा हो, चाहे चम्बल सम्भाग हो, चाहे ग्वालियर सम्भाग हो। मेरा यह भिंड, मुरैना, एटा, इटावा, आगरा, दतिया वगैरह यह पूरा इलाका लगता है इसलिए यहां पर एक एडिशनल एस.पी. की पोस्ट, क्योंकि मेरे एरिया में सात थाने पड़ते हैं, तो एक एडिशनल एस.पी. की पोस्ट और एक ए.डी.एम. कार्यालय वहां पर खोलें, क्योंकि हमारे यहां पर दो सब-डिविजन हैं और केस भी पर्याप्त हैं इसलिए वहां पर यह खुलना अत्यन्त आवश्यक है।

मेरे फादर के नाम से मैंने एक कालेज बनाया है। मैं मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने उसको राजकीय घोषित कर दिया। श्री प्रेमसिंह सिंघवी राजकीय महाविद्यालय छीपाबड़ौद, उसको राजकीय तो घोषित कर

(श्री प्रताप सिंह)

दिया पर उसके बाद आज तक, करीबन डेढ़, पौने दो साल हो गये, पिछले बजट में घोषणा की थी पर आज तक उनको तनख्वाह का एक धेला भी नहीं मिला है, लोग नौकरियां छोड़कर जा रहे हैं, कई जगह पर उनका जेवर गिरवी रख रहे हैं, इस प्रकार की स्थिति है।

दूसरा, मैं एक निवेदन यह करना चाहूंगा कि हमारे छबड़ा में सीएच.सी. है, ओ.पी.डी. बारां जिले से भी ज्यादा है क्योंकि मध्यप्रदेश लगा हुआ है छबड़ा से छह किलोमीटर पर ही मध्यप्रदेश है तो वहां पर मध्यप्रदेश के पेशेंट भी बहुत आते हैं, इसलिए वहां पर उप जिला चिकित्सालय तो कम से कम बनायें।

मैं तो यहां तक भी मांग करूंगा कि छबड़ा को जिला बना दें तो मुख्य मंत्रीजी की बहुत कृपा होगी।

एक हरनावदा शाहजी उप तहसील है, उसको तहसील स्तर पर क्रमोन्नत किया जाये। छीपाबड़ौद में एक डीवाई.एस.पी. कार्यालय खोला जाये और ल्हासी पेयजल योजना से 20 गांवों की एक स्कीम बनी है। ल्हासी अभी चल रही है, एग्जिस्टिंग स्कीम है, उससे 20 गांवों की एक स्कीम और बनी है। मैंने यह जानकारी की तो मुझे यह पता चला है कि इसका टेंडर एक बार निरस्त हो गया है, दुबारा टेण्डर लगेगा, तो इसकी प्रोसेस को थोड़ा जल्दी करवा दें ताकि इसका काम शीघ्र चालू हो सके।

श्री सभापति: कृपया, दो मिनट में समाप्त करें।

श्री प्रताप सिंह (छबड़ा): 15 मिनट में। बाकी है, साहब, अभी तो।

श्री सभापति: दो मिनट में।

श्री प्रताप सिंह (छबड़ा): दो मिनट आपकी तरफ से और, साहब।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपको एक बहुत बड़ा घोटाला आपके सामने निवेदन करूंगा कि हमारे यहां छबड़ा में वन विभाग की भूमि बहुत है वन विभाग में अतिक्रमण हो रहे हैं। रेंज छबड़ा के राजस्व गांव अल्लाहपुरा में करीब पचास बीघा वन भूमि में ट्यूबवैल लगाकर खेती की जा रही है, लेकिन वन विभाग कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। इसी प्रकार ककरवा गांव में जो भी छबड़ा रेंज में आता है, 120 बीघा भूमि में से सागवान काटा और मध्यप्रदेश की सीमा होने के बाद जैसा कि लोग कहते हैं और सुनते हैं कि गुना, मध्यप्रदेश में क्योंकि वहां पर पारदी, सांसी, कंजर यहीं ज्यादा रहते हैं, इधर से वे इलेक्ट्रिक आरी से पेड़ काटते हैं, नदी में डाल देते हैं और वे ले जाते हैं।

(श्री प्रताप सिंह)

120 बीघा भूमि में दो-दो, तीन-तीन फीट मोटा सागवान का ओरिजिनल पेड़ काट देना, इससे करीब पांच करोड़ रुपये का उन्होंने घपला करके, चोरी करके यह सागवान बेचा है और 120 बीघा जमीन में खेती की जा रही है। मैं समझता हूं कि यह भी बहुत बड़ा घपला है कि आंख के नीचे छबड़ा से पांच किलोमीटर दूर जहां पर रेंज आफिसर बैठता है, साठ किलोमीटर दूर जहां पर डी.एफ.ओ. बैठता है, छीपाबड़ौद में ए.सी.एफ. बैठता है तो फिर इस प्रकार से फोरेस्ट में चोरी किस प्रकार से हो रही है? फोरेस्ट किस प्रकार से कट रहा है?

यहां पर आये दिन हम पर्यावरण की बात कहते हैं पर...(व्यवधान)

श्री सभापति: थैंक यू।

श्री प्रताप सिंह (छबड़ा): हम आये दिन दूसरी बात करते हैं कि पर्यावरण बचाओ, यह करो, वह करो, इससे विश्व के लोग चिंतित हैं कि पर्यावरण के लिए यह होना चाहिए।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, धन्यवाद, थैंक यू।

श्री प्रताप सिंह (छबड़ा): पर पर्यावरण के नाम पर यह जो घपले हो रहे हैं, मैं समझता हूं कि आप इनको शीघ्रता से रोकेंगे और इनसे जो मिले हुए लोग हैं, मुझे यह जानकारी मिली है कि इनको बचाया जा रहा है, तो इनको बचाया नहीं जाये, इनको सज़ा दी जाये ताकि दूसरा कोई हिम्मत नहीं कर सके।

श्री सभापति: बहुत-बहुत धन्यवाद, माननीय सदस्य।

श्री प्रताप सिंह (छबड़ा): अच्छा, एक और बात है। एक मिनट और दे दो, साहब। एक हमारे यहां पर पूरे राजस्थान में दो बिरादरी है, एक तो कंघीसाज और दूसरी चांडाल। यह बहुत ही बुरा शब्द लगता है बोलने में और इस समाज के लोग यह मांग करते हैं कि कंघीसाज की जगह तो हमको ग्वारिया लिख दिया जाये और चांडाल की जगह चिड़ार लिख दिया जाये। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, नोटिफिकेशन जारी करना पड़ेगा और यह काम हो जायेगा तो उनको जो शर्मिंदगी महसूस होती है, जो उनकी जाति का नाम पूछते हैं कि कौन बिरादरी के हैं तो वे कहते हैं चांडालान का हूं, तो हमारी बोली में बोलते हैं तो अब चांडाल कहते ही बुरा सा लगता है। इसलिए मेरा यह निवेदन है कि कंघीसाज है, जो कंघियां औरतें पहले जूं निकालती थीं, वह जरा-जरा सी कंघी होती थी, उसको कंघीसाज बोलते हैं, ऐसे ही उसको ग्वारिया बोल दो, ग्वारिया कर दो और चांडाल को चिड़ार कर दो। इतना ही कहते हुए ...(व्यवधान)

श्री सभापति: बहुत-बहुत धन्यवाद आपको।

श्री प्रताप सिंह (छबड़ा): जैसा मैंने पहले कहा था दुष्यंत कुमारजी का शेर सुनाते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। उससे पहले एक निवेदन और करना चाहूंगा माननीय मुख्य मंत्रीजी से और सत्ता पक्ष के सब नेता लोगों से यह कहना चाहूंगा कि वसुन्धराजी के समय जो काम के वर्क आर्डर चालू हो गये थे, वर्क आर्डर दे दिये थे, टेंडर लग गये थे, प्रोसेस शुरू हो गया था तो उनको ऐसी क्या जिद पड़ी है, वे काम भी राजस्थान में ही होंगे, यदि आप उनको चालू करवा देंगे तो आपका क्या बिगड़ेगा? वे काम आपके इलाके में भी होंगे, हमारे इलाके में भी होंगे।

श्री सभापति: बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री प्रताप सिंह (छबड़ा): मैं इतना ही कहते हुए आपसे यह निवेदन करना चाहूंगा कि एक तो कंघीसाज और चांडालों की यह जो मांग है इसको निश्चित रूप से पूरी करें और यह दुष्यंत कुमार का शेर है-

"आज सड़कों पर लिखे हुए, सैकड़ों नारे न देख।
तू घर का अंधेरा देख, तू आकाश के तारे न देख।"

धन्यवाद।

श्री सभापति: थैंक यू। श्री संयम लोढ़ा।

श्री प्रताप सिंह (छबड़ा): तंबाकू का और कहना चाहता था, साहब, तंबाकू और बीड़ी-सिगरेट पर टैक्स बढ़ा दो और पेट्रोल और डीजल पर घटा दो।

सूचना

आबूरोड में श्री मनीष शर्मा की जारी सीवरेज कार्यों के कारण मृत्यु

श्री जगसी राम (रेवदर): माननीय सभापति महोदय, मेरा पाइंट आफ इन्फोर्मेशन है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आपका टर्न आये जब बोलना। क्या?

श्री जगसी राम (रेवदर): मेरा पाइंट आफ इन्फोर्मेशन है। सर, आबूरोड के अन्दर जो यह रूडीप एवं एल. एण्ड टी. का जो काम चालू हुआ है सीवरेज वाला, उसमें मनीष शर्मा की रात को गड्ढे में गिरने से मृत्यु हो गयी है। (व्यवधान)

श्री सभापति: आप ऐसा करिये कि आप अपना पाइंट आफ इन्फोर्मेशन स्पीकर साहब के सामने बता देना।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): दो मिनट।

श्री जगसी राम (रेवदर): उसकी वजह से पूरे आबूरोड के व्यापारी सहित सभी वर्ग के लोग वहां पर धरने पर बैठे हैं। मैंने पिछली बार भी इस विषय को विधान सभा में उठाया था। लगातार उठाने के बाद में भी विभाग ने किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की। इस वजह से रात को यह युवा मनीष शर्मा की जो गड्ढे में गिरने से मृत्यु हुई है, इसको सरकार संज्ञान में ले, यह मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं। विशेष तौर से, बार-बार कहने के बाद में भी विभागीय अधिकारियों ने आज तक उसकी सुध नहीं ली, इस वजह से ही उनकी मृत्यु हुई है।

श्री सभापति: नोट कर लिया गया है। श्री संयम लोढ़ा।

आय-व्ययक

आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2023-24 पर सामान्य वाद-विवाद

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय सभापति महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने बजट की चर्चा में मुझे भाग लेने का मौका दिया।

माननीय सभापति महोदय, मेरे मन में एक कसक हमेशा से रही है कि संस्कृत को मुझे जिस रूप में अपने विद्यार्थी जीवन में पढ़ना चाहिए था, मैं पढ़ नहीं सका और उस कारण से वह सारा अथाह ज्ञान जो हमारे ऋषि मुनियों ने अपने ग्रंथों में लिखा है, पर उस भाषा की कम जानकारी होने के कारण मूल भाषा में पढ़ने का सौभाग्य मुझे प्राप्त नहीं हुआ।

मैं आज राजस्थान के माननीय मुख्य मंत्री को यह धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने जिला मुख्यालयों पर संस्कृत महाविद्यालय खोलने का निर्णय किया और इतना ही नहीं, वेद विद्यालय खोलने का निर्णय किया जिसके माध्यम से हमारी नई पीढ़ी, हमारे बच्चे उस अथाह ज्ञान से रूबरू हो सकें।

माननीय सभापति महोदय, मुझे यह याद आता है कि जब देश में कांग्रेस की पहली सरकार थी और वह ऐतिहासिक सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ था, पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधान मंत्री होते थे और उस सोमनाथ मंदिर की प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में देश के तत्कालीन महामहिम राष्ट्रपति डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद स्वयं जाकर उपस्थित हुए थे।

सनातन धर्म जिसने पूरी दुनिया का मार्गदर्शन किया है, अनादिकाल से लेकर आज तक जिसने पूरी मनुष्य जाति को ध्यान और तत्व के माध्यम से आत्मा, मोक्ष और ईश्वर का रास्ता दिखाने का काम किया है, राजस्थान के

(श्री संयम लोढ़ा)

मुख्य मंत्री ने इस वेद विद्यालय और संस्कृत महाविद्यालय के जरिये उस सनातन संस्कृति की अप्रतिम और अद्भुत सेवा की है जिसके लिए मैं राजस्थान के आठ करोड़ नागरिकों की तरफ से उनका हृदय के अंतरतम-तल से आभार प्रकट करता हूं।

माननीय सभापति महोदय, इतना ही नहीं संविधान की जो मूल प्रति जो कि हस्तलिखित है, उसमें भी राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर और सारे महा-मानवों का चित्र सहित वर्णन है और यह सब इसीलिए है कि हम देशवासियों को उन अप्रतिम मूल्यों से जोड़ सकें।

माननीय सभापति महोदय, हमारी संस्कृति में गाय को पूजनीय माना गया है, पवित्र माना गया है। मैं जब बच्चा था तो मां रोज शाम को कहती थी कि जाओ, गाय को रोटी देकर आओ, तो हमारी मां ने हम सबको उस गाय की सेवा से जोड़ा है। हिन्दुस्तान के इतिहास में राजस्थान की सरकार पहली सरकार है जिसने गौ सेवा और संरक्षण का अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत किया है। मैं भारतीय जनता पार्टी के उन सारे मित्रों से पूछना चाहता हूं कि क्या देश में ऐसी दूसरी कोई सरकार है जो गोशालाओं में रहने वाले हमारे उस गोवंश को बारह महीने का अनुदान देती हो? क्या देश में ऐसी कोई सरकार है जो गोशालाओं में रहने वाली उन अपाहिज, निर्बल और बीमार गायों का बारह महीने का खर्चा उठा रही है?

सभापति महोदय, मैं बीजेपी के उन मित्रों से जो धर्म का नाम लेकर देश की भोली-भाली जनता को गुमराह करने का काम करते हैं, मैं पूछना चाहता हूं, मेरे बाद जब कोई भी माननीय सदस्य खड़े हों या प्रतिपक्ष के नेता बात रखें, तब बताना कि गायों की सेवा के लिए 2014 से 2018 तक आपकी सरकार थी, वर्षवार इस सदन में विवरण प्रस्तुत करना कि आपने कितना खर्चा किया और उन गोशालाओं को कितने महीने का अनुदान दिया? मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं। 2018 में इनकी सरकार ने मात्र 305 करोड़ रुपये राजस्थान की गोशालाओं पर अनुदान के रूप में खर्च किये थे और यह सरकार, 2021-22 में 876 करोड़ रुपये, 2022-23 के अन्दर 1518 करोड़ रुपये और 2023-24 के अन्दर 1787 करोड़ रुपये का प्रावधान राजस्थान की गौ माता की सेवा के लिए सरकार ने रखा है। 2018 की सरकार की तुलना में 6 गुना ज्यादा। क्या भारतीय जनता पार्टी के तमाम साथियों का यह फर्ज नहीं बनता कि अगर गौ माता की सेवा में वास्ता रखते हैं तो एक स्वर से, संवेग

(श्री संयम लोढ़ा)

स्वर से राजस्थान के मुख्य मंत्री अशोक गहलोत का इस अनुपम, अद्वितीय और मानवीय कार्य के लिए उनका आभार व्यक्त करें, उनका अभिनन्दन करें? (व्यवधान)

श्री सभापति: सुनिए प्लीज। जब आपका टर्न हो तब बोलना।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): अब अगर आपने प्रश्न खड़ा किया है तो देश की जनता को इस बात का जवाब देना। करपात्री जी महाराज जिन्होंने संसद भवन पर प्रदर्शन किया था। आज मोदीजी की सरकार को आये हुए दस साल हो गये। क्या गौ माता को आपको राष्ट्रीय पशु घोषित नहीं करना चाहिए? क्या गौ माता की हत्या की रोक के लिए आपको राष्ट्रीय कानून नहीं लाना चाहिए? लेकिन नहीं, आप राजस्थान में गौ माता की रक्षा की बात करेंगे और गोवा में जाकर गौ माता को काटने की वकालत कर देंगे। आपको इस बात के लिए शर्मिन्दा होना चाहिए कि आपकी सरकार आने के बाद गौ मांस का निर्यात हिन्दुस्तान के अन्दर बढ़ा है, दुनिया के अन्दर बढ़ा है।

सभापति महोदय, मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा। हमारे मित्रों ने, प्रतिपक्ष के साथियों ने इस पवित्र सदन के माध्यम से इस तरह के गलत आंकड़े, गलत तथ्य और गलत तस्वीर राजस्थान की रखने की कोशिश की जिससे राजस्थान की जनता का मनोबल गिरे, लेकिन मैं निवेदन करूंगा कि राजस्थान देश का आगे बढ़ता हुआ राज्य है। इस सरकार ने जो यह बजट पेश किया है, मखदूम मुहिउद्दीन जी का एक शेर इस पर बहुत माफिक है कि-

'हयात ले के चलो, हयात ले के चलो,
कायनात ले के चलो,
चलो तो सारे जमाने को साथ ले के चलो।'

और यही अशोक गहलोत का यह बजट कहता है, माननीय सभापति महोदय।

सभापति महोदय, ऋण दायित्वों को लेकर बहुत गलत तस्वीर प्रस्तुत करने की कोशिश की गई। मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा 2019-20 में राजस्थान का आउटस्टैण्डिंग डैट और दूसरी लायबिलिटी जो थीं, 03 लाख 52 हजार 701 करोड़ रुपये। उस साल में कर्जा कितना लिया, 41 हजार 328 करोड़ रुपये और जीएसडीपी था राजस्थान का 9 लाख 98 हजार 679 करोड़ और यह डैट था 35.32 परसेंट। जब यह मौजूदा सरकार आयी, तब का स्टेटस

(श्री संयम लोढ़ा)

है यह पहले साल का। उसके बाद 57 हजार करोड़ का अगले साल लोन हुआ। 52 हजार करोड़ का उसके अगले साल हुआ। 53 हजार करोड़ का उसके अगले साल हुआ और 62 हजार करोड़ का इस साल के बजट एस्टीमेट के अन्दर प्रस्तावित किया गया और वह होता है जीएसडीपी 15 लाख 76 हजार 186 करोड़ का 36.78 परसेंट।

मैं प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों से यह पूछना चाहता हूं कि राजस्थान में एफआरबीएम एक्ट कब आया था? किसकी सरकार थी? कौन लाया था? वसुन्धरा राजे की सरकार एफआरबीएम एक्ट लेकर आयी थी और उसमें क्या प्रस्तावित किया था? 2025-26 तक जीएसडीपी का 38.2 परसेंट डेट और दूसरी लायबिलिटीज होना चाहिए। आप ही की सरकार थी। आपका एक्ट प्रोविजन था 2025-26 तक लाने का, लेकिन राजस्थान की सरकार ने 2021-22 में ही इस लक्ष्य को प्राप्त कर लिया और जो 2021-22 के एक्चुअल हैं 37.99 पर खड़े हैं हम। अभी तीन दिन पहले ट्विटर पर राजस्थान की पूर्व मुख्य मंत्री वसुन्धरा राजे ने ट्वीट कर दिया कि राजस्थान का 07 लाख करोड़ रुपये कर्जा बता दिया, जो पूरी तरह से तथ्यात्मक रूप से गलत है। उन्होंने उसमें वीडियो भी डाला जिसमें खुद की सरकार का गुणगान किया, इस सरकार की आलोचना की। उसी ट्विट पर कमेन्ट करते हुए मैंने लिखा कि मैं आपको चुनौती देता हूं आपकी सरकार के पांच साल और इस सरकार के चार साल के कामकाज पर राजस्थान में किसी भी जगह पर बहस रख दीजिए। समय, तिथि और स्थान आप तय करके बता दीजिए। सभापति महोदय, असत्य आंकड़ों के आधार पर, गलत सूचना के आधार पर, गलत जानकारी के आधार पर सिर्फ सत्ता के लिए राजस्थान की जनता के मनोबल को कमजोर करने की कुचेष्टा कर रहे हैं।

सभापति महोदय, भारत सरकार का भी आपको निवेदन करना चाहूंगा कि जीडीपी का डैट परसेंटेज क्या है? कम से कम अपने गिरेबान में तो झांको। 56 इंच की छाती वाले उस महान आत्मा से भी तो कभी सवाल किया करो। 2019-20 में भारत सरकार का आउटस्टैण्डिंग डैट जीडीपी का 50.90 परसेंट। आपकी सरकार को आये हुए पांच साल हो चुके थे। 2020-21 में 61.01 परसेंट, 2021-22 में 57.33 परसेंट, 2022-23 के रिवाइज एस्टीमेट में 55.89 परसेंट और इस साल का बढ़ कर 56.16 परसेंट हो गया। अब श्रीलंका का उदाहरण देश के माननीय प्रधान मंत्रीजी को जाकर के दो कि राजस्थान तो ठीक मुकाम पर खड़ा है, वित्तीय अनुशासन की पालना कर रहा है,

(श्री संयम लोढ़ा)

एफआरबीएम एक्ट की पालना कर रहा है, लेकिन देश की सरकार कहां जाकर खड़ी हुई है? डूबेंगे तो श्रीलंका के करीब जाकर हम सबको भी लेकर डूबेंगे।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि इस सरकार ने लगातार प्रावधानों के अन्दर जन आकांक्षाओं के अनुरूप इजाफा किया है। इस साल का 2023-24 का बजट प्रस्तुत किया है, 2022-23 के रिवाइज एस्टीमेट से अगर तुलना करेंगे तो एजुकेशन, स्पोर्ट्स, आर्ट्स और कल्चर में 09 परसेंट की बढ़ोतरी है। हैल्थ एण्ड फैमिली वेलफेयर में 10 परसेंट की बढ़ोतरी है। सोशल वेलफेयर में एक परसेंट की बढ़ोतरी है। अरबन डवलपमेंट में 23 परसेंट की बढ़ोतरी है। एग्रीकल्चर में 10 परसेंट की बढ़ोतरी है। ट्रांसपोर्ट में 42 परसेंट की बढ़ोतरी है। वाटर सप्लाई और सेनिटेशन में 43 परसेंट की बढ़ोतरी पिछले साल की तुलना में है। फिर किस आधार पर हम इस बजट की आलोचना करने की चेष्टा करते हैं?

सभापति महोदय, इतना ही नहीं, मैं आपके सामने यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि किस-किस हैड में देश का राष्ट्रीय औसत क्या है और राजस्थान कहां पर खड़ा है, कितना परसेंट पूरे देश के राज्य मिलकर एवरेज खर्चा कर रहे हैं और राजस्थान उस हैड में कितना खर्चा कर रहा है?

(समय: 16.00 बजे)

माननीय सभापति महोदय, हैल्थ में पूरे देश के राज्यों का औसत है 6.3 प्रतिशत और राजस्थान का है 7.4 प्रतिशत, एजुकेशन में पूरे देश के राज्यों का औसत है 14.8 प्रतिशत और राजस्थान का एवरेज है 19.5 प्रतिशत। माननीय सभापति महोदय, इतना ही नहीं, अरबन डवलपमेंट में देश के राज्यों का औसत है 3.5 प्रतिशत और राजस्थान का औसत है 4.7 प्रतिशत तो इस तरीके से जो बहुत बुनियादी विषय हैं, जो जनोपयोगी विषय हैं, जो जनहित के विषय हैं, उन सबमें राजस्थान कहीं ज्यादा बेहतर स्थिति में खड़ा हुआ है।

माननीय सभापति महोदय, इसके अलावा मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा। एनर्जी में राजस्थान 9.8 प्रतिशत पर खड़ा है, जबकि राष्ट्रीय औसत है देश के राज्यों का 4.8 प्रतिशत। इसी तरीके से इर्रिगेशन के अंदर भी राजस्थान राष्ट्रीय औसत के आस-पास खड़ा है। वाटर सप्लाई और सेनिटेशन का, जैसे मैंने निवेदन किया कि राष्ट्रीय औसत 3 प्रतिशत है और राजस्थान 4 प्रतिशत पर खड़ा है।

(श्री संयम लोढ़ा)

माननीय सभापति महोदय, महंगाई को मुद्दा बनाकर देश में सरकार बदली गयी थी। स्मृति ईरानी जब सिलेण्डर पर 50 रुपये बढ़ते थे और अपनी गोद में सिलेण्डर को लेकर बैठ जाती थीं। 2014 की वह चुनावी सभायें इस सदन के सारे माननीय सदस्यों को याद होंगी जब देश के प्रधान मंत्रीजी ने भाषण दिया था, किसान भाइयों, जो यह कर्जा आपका है, यह नरेन्द्र मोदी की सरकार आने के बाद यह नरेन्द्र मोदी का कर्जा हो जायेगा और उस भाषण का वह वीडियो कोई भी जाकर मेरे फेसबुक पर देख सकता है। माननीय सभापति महोदय, आज 09 साल हो गये देश की सत्ता में नरेन्द्र मोदी को आये हुए, लाखों-करोड़ों रुपये देश के पूंजीपतियों के माफ कर दिये। 10 लाख करोड़ रुपयों का पूंजीपति फ्रॉड करके चले गये, लेकिन किसानों के हितैषी बनने वाले किसान सम्मान निधि पर रोज के 16 रुपये देश के किसान को देने वाले, एक रुपया नेशनलाइज बैंक के किसानों का माफ नहीं कर सके।

माननीय सभापति महोदय, इतना ही नहीं, अन्तरराष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल की कीमत 124 डॉलर प्रति बैरल से घटकर 75 डॉलर हो गयी, 40 प्रतिशत की कमी हो गयी, लेकिन क्या इसका लाभ देश की जनता को मिला? क्या इसके भाव उसके अनुरूप जो कम होने चाहिये थे, वह हुए क्या? सेस बढ़ाते रहे, स्पेशल एक्साइज ड्यूटी लगाते रहे और वह लाखों-करोड़ रुपया, जो हिन्दुस्तान की जनता से इकट्ठा हुआ, वह स्टेट के साथ शेयर नहीं किया जाता है। वह सारा पैसा भारत सरकार के खजाने में पड़ा रहता है और इस तरीके से राज्यों को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं और वह सारी योजनाएं, माननीय सभापति महोदय, जो कभी 10:90 पर चलती थीं, 30:70 पर चलती थीं, 60:40 पर चलती थीं, उन सारी योजनाओं के नियम बदल दिये और उनको 50:50 और 40:60 पर लाकर खड़ा कर दिया, जिसके कारण कई योजनाएं, कई घोषित परियोजनाएं बंद हो गयीं।

अब आप राजस्थान सरकार की आलोचना करते हैं। आप ऐसा चित्र प्रस्तुत करने की कोशिश करते हैं जैसे चार साल में राजस्थान की सरकार ने प्रदेश का भट्ठा बैठा दिया हो, लेकिन मैं आपके माध्यम से, माननीय सभापति महोदय, सवाल करना चाहूंगा कि क्या 2022-23 में राजस्थान में प्रति व्यक्ति आय कांस्टेंट प्राइस पर 86 हजार 134 रुपये नहीं हुई? क्या करेंट प्राइस पर एक लाख 56 हजार 149 रुपये नहीं हुई? यह वृद्धि दर 14.85 प्रतिशत है प्रति व्यक्ति आय में। माननीय सभापति महोदय, राष्ट्रीय औसत क्या है 13.07

(श्री संयम लोढ़ा)

प्रतिशत, मतलब पूरे देश की तुलना में राजस्थान में प्रति व्यक्ति आय बढ़ने का स्तर कहीं बेहतर है। माननीय सभापति महोदय, इतना ही नहीं, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि फिस्कल डेफिसिट है, फिस्कल डेफिसिट में भी राजस्थान ने FRBM एक्ट और नीति आयोग की गाइडलाइन की पालना की है, उसके दायरे में रहे हैं। राजस्थान तो रहा है 3.96 प्रतिशत और भारत सरकार 6.7 प्रतिशत, तो यह वित्तीय अनुशासन किसको सिखाने की जरूरत है? यह अच्छे से विचार कर लिया जाना चाहिये।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा, जैसा मैंने पहले भी कहा है, भारतीय जनता पार्टी के पांच साल में कितने किसानों को कनेक्शन मिले? 01 लाख 77 हजार 226 और इस सरकार ने चार साल में कितने कनेक्शन दिये, 3 लाख 27 हजार 459, क्या तुलना है? इतना ही नहीं, माननीय सभापति महोदय, मुख्य मंत्रीजी ने ऐलान किया है कि इस साल में भी हम और डेढ़ लाख किसानों को बिजली के कनेक्शन देंगे।

माननीय सभापति महोदय, बीजेपी के पांच साल के कार्यकाल में मात्र 5 हजार 842 करोड़ रुपये फसल मुआवजे पर खर्च किये गये और इस सरकार के कार्यकाल में 18 हजार 177 करोड़ रुपये खर्च किये गये, जो तीन गुना से भी ज्यादा है। क्या राजस्थान का किसान इस वास्तविकता को नहीं समझता? विद्युत अनुदान, जो किसानों को दिया गया, बीजेपी ने पांच साल में दिया 31 हजार 940 करोड़ रुपये और इस सरकार ने दिया 60 हजार 754 करोड़ रुपये और इस बजट में तो माननीय मुख्य मंत्रीजी ने 2 हजार यूनिट को नि:शुल्क करने का एलान किया। आंकड़े गवाह हैं, हाथ कंगन को आरसी क्या?

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा, महंगाई किस कदर बढ़ी है, किस कदर भाव बढ़े हैं, यह हम सब लोग समझ सकते हैं। क्या गेहूं की कीमत, क्या जौ की कीमत, और इन सारे लोगों को महंगाई से बचाने के लिए राजस्थान के मुख्य मंत्री ने एक करोड़ परिवारों को अन्नपूर्णा फूड पैकेट देने की घोषणा की। 3 हजार करोड़ रुपये इस पर खर्च होंगे।

माननीय सभापति महोदय, इसके साथ-साथ जब कोरोना का समय था तो मैंने प्रधान मंत्रीजी को सात पत्र लिखे। लोक सभा के अध्यक्ष, जो इस सदन के सदस्य रहे हैं, उनको भी पत्र लिखा कि जो शहर में रहने वाला गरीब वर्ग है, उसकी हालत बहुत खराब हो चुकी है काम-धंधे नहीं होने से उसकी

(श्री संयम लोढ़ा)

सारी बचत खतम हो चुकी है। वह एक हताशा के माहौल में है। केन्द्र सरकार को शहरी रोजगार गारंटी योजना लानी चाहिये। हर परिवार के खाते में जो नोन इनकम टैक्स पेयर है, 10 हजार रुपये हर परिवार के खाते में डालना चाहिये, पर हमारी नहीं सुनी गयी। मैं धन्यवाद दूंगा अशोक जी गहलोत को कि 33 लाख परिवारों के खातों के अंदर साढ़े 5 हजार रुपये कोरोना के टाइम में डीबीटी के जरिये उन्होंने ट्रांसफर किये। मैं धन्यवाद दूंगा कि हमारी अन्तर्मन की उस पीड़ा को उन्होंने महसूस किया और राजस्थान के अंदर शहरी रोजगार गारंटी योजना शुरू की। इतना ही नहीं, चाहे एक तरफ भारत सरकार मनरेगा में पैसा घटा रही है, अशोक गहलोत गांवों के लोगों को 25 दिन का खुद के खर्चे पर दे रहे हैं और इस साल शहर के लोगों को भी 25 दिन देने की उन्होंने घोषणा की।

माननीय सभापति महोदय, हमारे बहुत-से किसान नेता इस सदन में बैठे हुए हैं, उनको मालूम होगा कि यूरिया सब्सिडी के अंदर किस रूप में लगातार कटौती हुई है और इतना ही नहीं, कृषि मंत्रीजी अभी सदन में नहीं हैं, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में भी 2022-23 की तुलना में भारत सरकार ने इस साल 32 प्रतिशत की कटौती की है।

माननीय सभापति महोदय, अशोक जी गहलोत सामाजिक सुरक्षा के मसीहा हैं। यह वही व्यक्ति हैं जिसके दिमाग में पिछली सरकार के वक्त यह आया था कि हमारे बुजुर्गों को पेंशन देनी चाहिये, विकलांगों को पेंशन देनी चाहिये, विधवाओं को पेंशन देनी चाहिये। तब भी यह दुष्प्रचार किया गया कि रेवड़ियां बांटी जा रही हैं। आज फिर जब यह सरकार सामाजिक सुरक्षा का एक नया स्वरूप लेकर, नया कलेवर लेकर इस सदन के माध्यम से उपस्थित हुई है तो हमारे बीजेपी के दोस्त फिर यही बातें करते हैं कि रेवड़ियां हैं, लेकिन यह पूछना चाहूंगा, क्या गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों को फूड पैकेट देना रेवड़ी है? मैं पूछना चाहूंगा कि क्या वृद्धजनों की सामाजिक पेंशन बढ़ाना क्या रेवड़ी है? क्या विधवा महिला को सामाजिक सुरक्षा पेंशन में पैसा बढ़ाना रेवड़ी है? क्या कोरोना में अनाथ हुए बच्चों को पालनहार योजना के अंतर्गत भरण-पोषण करना और वयस्क होने पर नौकरी देने का फैसला करना एक क्रांतिकारी कदम है या रेवड़ी है? यह अपने गिरेबान में झांककर देखें।

माननीय सभापति महोदय, 30-35 साल तक सरकारी आदमी नौकरी

(श्री संयम लोढ़ा)

करता है। सबसे बड़ा सरकारी नौकरी में आने का कारण होता है पोस्ट रिटायरमेंट सिक्योरिटी लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी दिल्ली में और हमेशा से भारतीय जनता पार्टी कर्मचारी विरोधी पार्टी रही है। जब-जब भी कर्मचारियों के हित के कोई निर्णय हुए, फैसले हुए तो वह कांग्रेस की सरकारों ने किये।

अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने फैसला किया कि न्यू पेंशन स्कीम लेकर आयेंगे। राजस्थान में बीजेपी की सरकार थी, न्यू पेंशन स्कीम लागू की। इस सदन में 2019 में सबसे पहले मैंने सवाल लगाया था, मेरा प्रश्न लगा था। मैंने तब पूछा था कि आप ओल्ड पेंशन स्कीम की तरफ जाना चाहते हैं कि नहीं जाना चाहते हैं? मुझे खुशी है कि राजस्थान के मुख्य मंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश के लाखों कर्मचारियों की पीड़ा को समझा, उनकी चिंता को समझा और हिम्मत करके ओल्ड पेंशन स्कीम न केवल लेकर के आये, बल्कि पूरे देश में कांग्रेस पार्टी को यह समझ दी कि ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करना देश के और कर्मचारियों के हित में है। राजस्थान के बाद अनेक राज्यों के अंदर ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की गयी। इतना ही नहीं, आप पार्टी की सरकार जो पंजाब में है, उसने भी राजस्थान के मुख्य मंत्री की सोच के साथ चलते हुए वहां भी ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने का निर्णय किया। हजारों की तादाद में हमारे कर्मचारी जो अलग-अलग विद्युत कंपनियों में हैं, कारपोरेशन में हैं, स्थानीय निकायों में हैं, लगातार हम लोगों को ज्ञापन देते थे, प्रदर्शन करते थे कि हमें भी ओल्ड पेंशन स्कीम में शामिल करो। हमने मुख्य मंत्री जी से निवेदन किया कि जब आप राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिये ओल्ड पेंशन स्कीम लाये हैं तो समानता के अधिकार पर चलते हुए हमें कंपनीज को और दूसरे एम्प्लाइज को भी इसका लाभ देना चाहिए। उदार दिल मुख्य मंत्री ने फिर फैसला किया कि ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ उनको भी दिया जायेगा।

देश के प्रधान मंत्री ने अभी अभिभाषण पर रिप्लाई देते हुए जब भाषण दिया तो यह कहा कि यह ओल्ड पेंशन स्कीम जो लागू कर रहे हैं, यह पाप है। आज इस सदन के माध्यम से मैं भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूं कि आप स्पष्ट बताइये कि आप कर्मचारियों के लिये ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं? करना चाहते हैं तो जिन-जिन राज्यों में आपकी सरकार है, देश में आपकी सरकार है, वहां आप ओल्ड

(श्री संयम लोढ़ा)

पेंशन स्कीम लेकर के क्यों नहीं आ रहे हैं? यह प्रमाणित करता है कि इतने महीने बाद भी ओल्ड पेंशन स्कीम को नहीं लाकर के आपका मत, आपकी पार्टी का मत लोगों के सामने आ रहा है कि आप कर्मचारी विरोधी हैं।

माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं, पिछले बजट से पहले जब महेन्द्रजीत सिंह जी मालविया सिरोही जिले में दौरे पर आये थे तो पब्लिक मीटिंग में मैंने ही उनसे विनती की थी कि आप हर परिवार को घरेलू बिजली 200 यूनिट मुफ्त दीजिये। पिछली सरकार में तो फैसला हुआ 50 यूनिट मुफ्त देने का। अब जो जन समर्थन मिला, जनता ने इसको पसंद किया, जनता ने इसकी मांग की, उसको देखते हुए मुख्य मंत्री जी ने निर्णय किया कि हम हर परिवार को 100 यूनिट बिजली मुफ्त देंगे। एक गरीब परिवार को 100 यूनिट बिजली मुफ्त देना क्या रेवड़ी है? क्या भारतीय जनता पार्टी इसके खिलाफ है?

माननीय सभापति महोदय, 'इंदिरा रसोई', यह सरकार का सबसे बेहतरीन कार्यक्रम है। 8 रुपये के अंदर इतना स्वादिष्ट भोजन मिलता है। महेन्द्र चौधरी साहब, हमारे प्रभारी मंत्री बैठे हुए हैं, हमने भी उनके साथ सिरोही में अनेक बार भोजन किया। भरपेट भोजन किया। ऐसा भोजन किया कि पूरी तरह तृप्त हो गये।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): बिसलेरी मिली कि नहीं मिली?

श्री महेन्द्र चौधरी (सरकारी उप मुख्य सचेतक): आप खाना खाकर गये थे न तब रखी थी वहां।

श्री सभापति: बोलिये, प्लीज बोलिये।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): इतना पापुलर कार्यक्रम हुआ कि लगातार इसकी संख्या में इजाफा करना पड़ा।

माननीय सभापति महोदय, इतना ही नहीं, इस बार जब हम हमारे प्रभारी मंत्री के साथ मीटिंग में बैठे थे तो यह मांग आयी कि जो गांव कस्बे का रूप ले चुके हैं, उनके अंदर भी इंदिरा रसोई शुरू करनी चाहिए। राजस्थान के सदाशय मुख्य मंत्री अशोक गहलोत ने इस बजट में ऐलान किया कि हम उन गांवों में भी यह चालू करेंगे जो कि कस्बे का रूप ले चुके हैं।

माननीय सभापति महोदय, चिरंजीवी बीमा के अंदर जो राशि बढ़ा दी,

(श्री संयम लोढ़ा)

दुर्घटना बीमा का प्रावधान कर दिया, क्या यह रेवड़ी है? मुझे याद है, 2007-08 में मैं एमएलए होता था। मैं वेलांगरी में मौत पर एक जगह बैठने गया। कैंसर से मौत हो गयी थी। उसके परिवार ने मुझे बताया कि 12 लाख रुपये का कर्जा लिया, लेकिन उस आदमी को हम बचा नहीं सके। तब अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का दिल्ली में अधिवेशन था, प्रधान मंत्री बैठे हुए थे, सोनिया गांधी जी बैठी हुई थीं। राजस्थान के प्रभारी मुकुल वासनिक ने मुझे राजस्थान की तरफ से बोलने के लिए कहा। मैंने प्रधान मंत्री जी से विनती की कि कैंसर, हार्ट, लीवर, किडनी इन बीमारियों का इलाज सरकार के खर्चे पर होना चाहिए। मेरे दिमाग में वेलांगरी का वह परिवार था जो 12 लाख के कर्जे में डूब गया।

माननीय सभापति महोदय, उस यात्रा में 15 साल लग गये। हमारा यह सपना, हिन्दुस्तान के लोगों का सपना 15 साल बाद राजस्थान के यशस्वी मुख्य मंत्री ने पूरा किया। आज 88 फीसदी राजस्थान की आबादी उस बीमे से कवर है, जो हिन्दुस्तान का एक रिकार्ड है। हिन्दुस्तान की सिर्फ 41 फीसदी आबादी कवर है। राजस्थान की 88 फीसदी आबादी कवर है। 01 करोड़ 38 लाख परिवार इसके जरिये लाभान्वित हो रहे हैं। आप गांव-गांव में जहां-जहां जायेंगे, जिन परिवारों ने इसका लाभ लिया है, जाकर के, उनके आगे माइक लगाकर पूछिये, उनकी आंखों में अशोक गहलोत के प्रति कृतज्ञता के आंसू आ जाते हैं जिन्होंने इसका लाभ उठाया है।

श्री सभापति: प्लीज, समाप्त करिये।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय सभापति महोदय, अभी तो मैंने शुरू किया है।

श्री सभापति: एक मिनट, एक मिनट।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय सभापति महोदय, अब आप समाप्त कर रहे हो तो फिर मैं मुख्य चीजों पर आ जाता हूं। कृपा रखना थोड़ी सी।

श्री सभापति: 2 मिनट में समाप्त कर दीजिये आप, प्लीज।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय सभापति महोदय, मैं आपको निवेदन करूंगा, जब मुख्य मंत्री जी ने इस बार बजट पढ़ा, मानवीय भूल से एक पेज उसमें तीसरे नंबर पर लग गया और एक मिनट, उन्होंने चंद लाइनें पढ़ी होंगी।

(श्री संयम लोढ़ा)

माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इसी सदन में 2014-15 में जब वसुन्धरा राजे ने अपना लिखित बजट भाषण पढ़ा था, तब भी गलत पढ़ दिया था, और कहां तक पढ़ा था, मैं बता रहा हूं आपको, मैं उनका वह वक्तव्य सुना रहा हूं आपको 'माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे सदन को निवेदन करना है कि दिनांक 14 जुलाई, 2014 को जब मैं परिवर्तित बजट वर्ष 2014-15 का सदन में उपस्थापन कर रही थी, तत्समय बोलते समय कुछ आंकड़ों में निम्न अशुद्धियां रह गयीं'। लिखे हुए भाषण को पढ़ने में अशुद्धियां रह गयीं। लिखे हुए को पढ़ने में 8 स्थानों पर तब संशोधन करवाया गया।

एक कागज जिसको पढ़ा गया, उसमें देश के प्रधान मंत्री टिप्पणी कर रहे हैं। भारत की पार्लियामेंट में देश की वित्त मंत्री टिप्पणी कर रही हैं।

श्री सभापति: कृपया समाप्त करिये ...(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): कम से कम इस सदन का, राजस्थान के इस सर्वोच्च सदन का इतिहास तो पढ़ लेते।

श्री सभापति: कृपया समाप्त करिये। समाप्त करिये।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): दो मिनट।

श्री सभापति: बोलिये।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय सभापति महोदय, मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा।

श्री सभापति: सुनिये प्लीज।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय सभापति महोदय, मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा कि आदर्श सोसायटी का और संजीवनी सोसायटी का इतना बड़ा घोटाला हुआ। लाखों परिवारों के पैसे उसमें फंसे हुए हैं। आज सहकारिता मंत्री के पद पर भारत सरकार के गृह मंत्री अमित शाह हैं। यह मल्टी स्टेट सोसायटी है। मैं आपके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के इन मित्रों से सवाल करना चाहता हूं कि आपके 25 सांसद राजस्थान की जनता ने जिताकर भेजे, उनके पैसे का क्या होगा? उन 21 लाख लोगों के पैसे का क्या होगा?

श्री सभापति: कृपया समाप्त करिये।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): सिर्फ इसलिए उसको बचा रहे हो कि वह आरएसएस से संबंधित है। उसके घर में आरएसएस का कार्यालय चलता था। आरएसएस के सारे प्रचारकों का खर्चा वह उठाता था।

श्री सभापति: कृपया समाप्त करिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): सभापति महोदय, इस प्रकार से किसी संगठन का नाम लेना, फिर हम बोलेंगे ...(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): यह तो सत्य है ...(व्यवधान) यह तो सत्य है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): यह क्या बोल रहे हैं? किसने अधिकार दिया इनको?

श्री सभापति: श्री अविनाश गहलोत।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): किसने अधिकार दिया इनको? बात कर रहे हैं, इतनी देर से सुन रहे हैं हम। मजाक बना रखा है।

श्री सभापति: बैठिये प्लीज। प्लीज बैठिये। हो गया।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय सभापति महोदय, इतना ही नहीं उनकी डायरी में एंट्री मिली है जिसमें बीजेपी को खर्चे के लिये पैसा दिया गया उसका भी वर्णन है।

श्री सभापति: श्री अविनाश गहलोत। आप बोलिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): सभापति महोदय, एक्सपंज कराइये आप। यह क्या मतलब है? (व्यवधान)

श्री सभापति: बैठिये प्लीज, अंकित नहीं होगा ...(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): 000

श्री सभापति: बैठिये प्लीज।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): 000

श्री सभापति: बंद हो गया। आप बोलिये। आप शुरू करिये (व्यवधान) हो गया। बैठिये, प्लीज बैठिये।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): 000

श्री सभापति: बैठिये। प्लीज बैठिये। आप बैठिये ...(व्यवधान) हां, आप बोलिये। मिस्टर अविनाश, शुरू करिये।

श्री सभापति: बैठिए। माननीय सदस्य। आपका हो गया। (व्यवधान) आप आपस में बात न करें। प्रतिपक्ष के माननीय उप नेता महोदय, बैठिये प्लीज। (व्यवधान) आप शुरू कीजिए। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): 000

श्री सभापति: नोट अलाउड, बैठिए प्लीज। (व्यवधान) आप बोलिए, आप शुरू कीजिए। (व्यवधान) नोट अलाउड, हो गया आपका समय।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): 000

श्री सभापति: थैंक यू वेरी मच। (व्यवधान) बहुत-बहुत धन्यवाद। (व्यवधान) प्लीज लेट हिम स्पीक। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): 000

श्री सभापति: उनका टर्न है, उनको बोलने दीजिये। (व्यवधान) कोई अंकित नहीं होगा। (व्यवधान) बोलिए आप।

श्री अविनाश (जैतारण): माननीय सभापति महोदय, आसन पैरों पर था, मैं आपका सम्मान कर रहा था इसलिए मैं उस समय बोल नहीं रहा था।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने मुझे बजट 2023-24 पर बोलने का अवसर दिया।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): 000

श्री सभापति: बैठिये प्लीज।

श्री अविनाश (जैतारण): माननीय सभापति महोदय, मैं अपनी बात शुरू करूं उससे पहले मैंने अपने भी कागज को ठीक तरीके से देखा।

माननीय सभापति महोदय, वर्ष 2023-24 के जिस बजट को माननीय मुख्य मंत्रीजी ने प्रस्तुत किया, बजट प्रस्तुत करते-करते जो नजारा हमने राजस्थान की विधान सभा में देखा, यह इसलिए ऐतिहासिक हो गया कि 10 तारीख को राजस्थान का जो बजट पेश किया जाना था, राजस्थान की प्रत्येक स्कूल, कालेज, ग्राम पंचायतों में लगभग 15 हजार एलईडी लगाकर उसको लाइव दिखाने का बंदोबस्त किया गया था। जब आज मैं इस बजट पर बोलने के लिए मेरे डाक्यूमेंट लेकर आया हूं तो मेरे साथ भी कहीं ऐसी घटना नहीं हो जाए कि मेरा सहयोगी कहीं पुराने पेपर डाल दे और मैं पहले वाला बजट पढ़ लूं, इसलिए मैंने सोच-समझ कर दो-तीन घंटे से तैयार करके मेरे इस बजट भाषण को तैयार किया है। जब सरकार की इतनी बड़ी किरकिरी हुई उस बजट के बाद में जब मैं गांवों में गया, 80 साल के वृद्ध लोगों से भी मिला तो उन्होंने कहा कि हमें जबरदस्ती ग्राम पंचायत में ले जाया गया, एलईडी के सामने बैठाया गया और डेढ घंटे तक राजस्थान की विधान सभा का तमाशा हमने देखा कि जब राजस्थान के मुखिया इस बजट को पढ़ने के लिए आये तो उन्हें पता भी नहीं था कि जो बजट मैं पढ़ रहा हूं वह 2023-24 का है या 2022-23 का है।

(श्री अविनाश)

माननीय सभापति महोदय, इससे पहले सरकारी नौकरियों में भर्तियों के जो पेपर लीक हुए, उससे राजस्थान शर्मसार तो हुआ ही था, लेकिन यह बजट किस तरीके से लीक हो गया या पढ़ने में कोई मिस्टेक हो गई, उससे भी राजस्थान की 08 करोड़ जनता ने नीचा देखा है। मुझे लगता है कि राजस्थान में ऐसा पहली बार हुआ जब बजट पढ़ते कहां से कहां चले गए, यह भी बड़ी शर्मनाक स्थिति पैदा हो गई।

माननीय सभापति महोदय, मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, मैं सिर्फ इस बात के लिए कि अभी सदन में कांग्रेस और बीजेपी के बारे में बहुत सारी बातें हुईं, मैं मानता हूं कि कांग्रेस में कुछ कमियां थीं।

माननीय सदस्य, संयम लोढ़ाजी, आप जाएं नहीं, कृपया मेरी बात को सुनकर जाएंगे तो अच्छा लगेगा। आप थोड़ी देर विराजें। मैं आऊंगा उस बात पर जो आपने अभी इंगित की थी। बैठिये, आप बहुत वरिष्ठ साथी हैं।

माननीय सभापति महोदय, मैं मानता हूं कि कांग्रेस में कुछ कमियां थीं। यह सच है कि 24 लाख करोड़ रुपये के घोटाले हुए। यह सच है कि हिन्दुओं की नहीं सुनी जाती थी। ठीक है, मैं मानता हूं कि महंगाई बढ़ते-बढ़ते बारह परसेंट से ऊपर चली गई थी। मैं मानता हूं कि आतंकवादी मजबूत थे। मैं मानता हूं कि पाकिस्तान और चीन हम पर हावी थे। मैं मानता हूं कि अलगाववादियों की चलती थी। मैं मानता हूं कि विकास दर एक बार तो चार परसेंट से भी नीचे आ गई थी। मैं मानता हूं कि भगवा आतंकवाद को असत्य प्रचार मिला था। चलो मैं यह भी मान लेता हूं कि विदेशों से परमाणु और सैन्य सौदों में दिक्कत थी, दस साल तक बड़े हथियार नहीं खरीदे गये। मानता हूं कि काले धन की एक पैरेलल व्यवस्था से प्रोपर्टी डीलर खुश थे। माना कि चीन कभी-कभार हमारे यहां घुस आता था, सेना का मनोबल कम था। मानता हूं सेना को ओआरओपी नहीं दे पाये। माना कि अठारह हजार गांवों में बिजली नहीं थी। मानता हूं कि लोग खुले में शौच जाते थे। आज की तरह 28 किलोमीटर की तरह प्रतिदिन 12 किलोमीटर हाईवे ही बनते थे। माना कि पीएम की नहीं सुनी जाती थी। मानता हूं व्यापार घाटा ज्यादा था। कोयला, टू-जी, कॉमनवेल्थ गेम्स में थोड़ा-बहुत देश का नुकसान हुआ होगा। माना कि देश के ढाई करोड़ घरों में बिजली नहीं थी। मैं मानता हूं कि फसल बीमा नहीं था। मैं मानता हूं बड़े उद्योगपतियों को 34 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा के लोन दे दिये गये। माना कि होम लोन 11 परसेंट ब्याज पर थे। माना कि मकान

(श्री अविनाश)

बनवाना महंगा था। माना कि रेलवे स्टेशन पर गंदगी थी, सुविधाएं नहीं थीं। माना कि रेस्टोरेंट में खाना महंगा था, वैट 28 परसेंट के करीब था। हम मानते हैं कि गो हत्या आसान था। अवैध बूचड़खानों पर कोई लगाम नहीं थी। यह भी सही है जाकिर नाईक बदमाशी करता था। बुखारी के अनुसार काम होता रहा होगा। लोग कभी-कभी देश विरोधी नारे भी लगा लेते थे। देशद्रोही कभी-कभी भारत का तिरंगा भी जला देते थे। माना कांग्रेस राम मंदिर और हिन्दू विरोधी थी। माना कि आतंकवादी हमलों के जवाब में सर्जिकल स्ट्राइक नहीं की जाती थी।

माननीय सभापति महोदय, लेकिन यह तो मानना पड़ेगा कि कांग्रेस के टाइम पर रेलवे स्टेशन पर प्लेटफार्म टिकट 5 रुपये का था। यह तो मानना पड़ेगा। आइये, उससे आगे चलते हैं। आप और हम यह विधान सभा का सारा सदन देश पर कांग्रेस के किये हुए उपकार को भूल नहीं सकता।

माननीय सभापति महोदय, सुनियेगा। देश पर कांग्रेस के जितने जुल्म हैं उनको भूल नहीं पाएंगे। चीन से पिटे, उसने हमारी जमीन पर कब्जा कर लिया। कश्मीरी ब्राह्मणों को दिल्ली में सैटल किया। 02 करोड़ बांग्लादेशियों को देश में रोजगार दिया। कश्मीर में आतंकवादियों का शासन स्थापित किया। अमन की आशा का संदेश देते हुए आतंकवादी छोड़ दिए। सरदारों की संख्या नियंत्रित की। सिन्धु नदी के पानी से पाकिस्तान की फसल लहलहायी। अफजल गुरु और कसाब को इज्जत बख्शी। उर्दू को द्वितीय राजभाषा बनाया। पंचशील सिद्धांत से चीन को काबू में रखा। शिमला समझौते से पाकिस्तान को पराजित किया। दामादों को हमेशा सम्मान दिया। सबसे बड़ा अहसान तो कांग्रेस ने यह किया कि गांधी वंश की परम्परा को आज दिन तक मरने नहीं दिया, आज दिन तक जीवित रखा है।

माननीय सभापति महोदय, और तो और 1952 के आम चुनाव, 1957 के आम चुनाव, 1962 के चुनाव, 1967 के चुनाव, 1971 के चुनाव, 1977 के चुनाव, 1980 के चुनाव, 1984 के चुनाव, 1991 के चुनाव, 2004 के चुनाव और 2009 के चुनाव, इन चुनावों में देश की जनता ने कांग्रेस को बहुमत दिया और लगभग यह शासन 55 साल का था। इस 55 साल के शासन में भी वो कहते रहे, हमें और मौका दो, 55 साल के शासन के बाद भी कहते रहे, हमें और मौका दो, हम इस देश की दशा और दिशा को बदल देंगे। मैं याद करना चाहूंगा, देश के प्रथम प्रधान मंत्री जवाहर लाल नेहरू से लेकर

(श्री अविनाश)

देश की प्रधान मंत्री इंदिरा गांधी, देश के प्रधान मंत्री राजीव गांधीजी और कांग्रेसी +++ सोनिया गांधीजी, कांग्रेस के +++ राहुल गांधीजी, इतनी लम्बी चौड़ी पीढ़ी ने उस दिन से लेकर आज दिन तक बेरोजगारी हटाने का, गरीबी हटाने का नारा दिया। 55 साल शासन करने के बाद थोड़ी-सी भी शर्म नहीं आई कि जो देश का पहला प्रधान मंत्री बना और 2014 तक आपने शासन किया, उसके बाद भी आप एक ही नारा देते रहे, गरीबी हटाएंगे, गरीबी हटाएंगे लेकिन गरीबी हटी नहीं। माननीय सभापति महोदय, ये आपकी उपलब्धियां हैं, जिसे पूरा देश देख रहा है।

माननीय सभापति महोदय, इससे आगे मैं निवेदन करूंगा कि अभी मोदी-मोदी के बारे में माननीय संयम लोढ़ाजी बहुत बोल रहे थे। मैं कुछ बातें बताऊंगा, उनमें सच बात हो तो, अगर कोई असत्य बात हो तो भी बता सकते हैं।

माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि अगर मोदी राम मंदिर बनवाता है, जिससे आपको बहुत तकलीफ है, तो मोदी आईआईटी, आईआईएम और एम्स भी बनवाता है। मोदी अगर लॉकडाउन लगाता है तो मोदी 80 करोड़ परिवारों को फ्री राशन देता है, 20 लाख करोड़ रुपये का आर्थिक पैकेज भी घोषित करता है। मोदी ताली-थाली बजवाता है तो मोदी वैक्सीन भी बनवाता है। मोदी दीये-मोमबत्ती जलवाता है तो मोदी 18 हजार गांवों में बिजली भी पहुंचाता है। मोदी अगर स्टेच्यू आफ यूनिटी बनवाता है तो मोदी वार मेमोरियल भी बनवाता है। मोदी अगर भाजपा कार्यालय बनवाता है तो मोदी नया संसद भवन भी बनवाता है। मोदी अगर रोहिंग्याओं को भगाता है तो मोदी कश्मीरी पंडितों को भी बसाता है। मोदी अगर 10 लाख का सूट-बूट पहनता है तो उसकी नीलामी करके उसका सारा पैसा चैरिटी में दान करता है। ये नरेन्द्र मोदी ही है।

माननीय सभापति महोदय, मोदी अगर राफेल खरीदता है तो मोदी अपना ब्रह्मोस भी बेचता है। मोदी तेजस को पीपीपी मॉडल पर चलाता है तो मोदी गतिमान और बुलेट ट्रेन भी चलाने को बोलता है। मोदी कुछ स्टेशन पीपीपी मोड पर करता है तो डेडिकेटेड फ्रेट कोरिडोर भी बनवाता है। मोदी अगर टोल टैक्स वसूल करता है तो मोदी 14 लेन हाईवे, ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे, अटल टनल, बोगीबील ब्रिज और कल परसों आपने देखा होगा दौसा में, दिल्ली-मुम्बई एक्सप्रेस वे का लोकार्पण भी इसी मोदीजी ने किया है।

माननीय सभापति महोदय, और तो और, अगर आप बात करें कि पेट्रोल और डीजल मोदीजी महंगा करते हैं तो मोदीजी ईरान का 45 हजार

(श्री अविनाश)

करोड़ रुपये चुकाता है, जो कांग्रेस की सरकार के समय में भारत पर कर्जा था, उसको चुकाने का काम मोदीजी करते हैं। अगर खुदा न खास्ता आपात स्थिति आ गई तो फ्यूल को रिजर्व रखने का पैसा भी मोदीजी अपने यहां से ही देते हैं। आप कहते हैं कि मोदीजी गैस सिलेंडर महंगा करते हैं, तो मोदीजी देश के लगभग 08 करोड़ परिवारों को उज्ज्वला योजना के माध्यम से मुफ्त में सिलेंडर भी देते हैं। मोदीजी स्वच्छ भारत मिशन अगर चलाते हैं तो 12 करोड़ शौचालय बनवाकर देश के गरीबों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का काम करते हैं। मोदी अगर सीएए, एनआरसी लेकर आते हैं तो मोदी पाकिस्तान विस्थापितों को भारत में बसाने का काम करते हैं।

श्री सभापति: राजस्थान के बजट के बारे में भी कुछ बोलिए।

श्री अविनाश (जैतारण): माननीय सभापति महोदय, एक मिनट।

माननीय सभापति महोदय, मोदी चाइना की कम्पनियों को भगाता है तो मोदी आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया भी लेकर आता है। मोदी नोटबंदी करता है तो मोदी डिजिटल पेमेंट के लिए नई करेंसी लेकर आता है। मोदी चाइना के एप्स बंद करता है तो स्वदेशी 'नाविक' सैटेलाइट लेकर आता है, सैटेलाइट लेकर आता है। (व्यवधान)

मोदी चाइना-पाकिस्तान को आंख दिखाता है तो मोदी डोकलाम-सर्जिकल स्ट्राइक भी करता है। मोदी अगर खुद को हिन्दू कहता है तो आप जैसे कांग्रेसियों को घर-घर, घाट-घाट मन्दिर घुमाने का काम भी यही नरेन्द्र मोदी करता है। (व्यवधान) इसलिए, माननीय सभापति महोदय, ये जो लम्बी चौड़ी बातें कर रहे थे ...(व्यवधान) मैंने पहले भी कहा था, थोड़ी देर के लिए रुकिये, सुनिये तो सही एक बार आप।

माननीय सभापति महोदय, जिस राजस्थान सरकार के बजट पर जो आपने केन्द्र और राज्य सरकार की तुलना की, मैं इस शेर के साथ राजस्थान सरकार के चार साल के कार्यकाल की तुलना करूंगा, आने वाले समय में बताऊंगा-

"दुर्योधन कितने दिन मौज करेगा,
दुर्योधन कितने दिन मौज करेगा,
समय अश्वारूढ़ है, जनता कृष्ण है,
कल अज्ञातवास पूरा होगा,
कल अज्ञातवास पूरा होगा,

(श्री अविनाश)

फिर रण बड़ा भयंकर होगा,
तेरे ही पासों से तेरा संहार होगा,
तेरे ही पासों से तेरा संहार होगा,
मैं बना अभिमन्यु, पर चक्रव्यूह पार होगा।।

इसी कांग्रेस के चक्रव्यूह में अभिमन्यु बनकर 2023 के आने वाले चुनाव में सूपड़ा साफ यहां कांग्रेस का होगा।"

जिन नीतियों के आधार पर कांग्रेस ने पिछले चार सालों में राजस्थान की जनता के साथ अन्याय किया है, उसके बारे में मैं आपको कहता हूं। कल परसों हमने देश की संसद में माननीय प्रधान मंत्री का भाषण सुना होगा, मैं अभी बोल रहा था और आप सारे लोग भी कह रहे थे, मोदी ने इसीलिए ठीक कहा था कि एक अकेला इसीलिए भारी है। मोदी जी ने ठीक कहा था कि जब देश के चिन्तन की, राष्ट्र के विकास की बात आती है, तब सारे के सारे राष्ट्रद्रोही एक साथ इकट्ठा होकर उस बात का विरोध करते हैं। उसे इस बात का भी पता नहीं कि जब देश का मुखिया प्रधान मंत्री विकास की बात करता है, उसे सुनने की हिम्मत हम में नहीं हो तो फिर किस बात की।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि उन्होंने अभिभाषण में कहा कि 2004 से लेकर 2014 तक यूपीए का जो कार्यकाल था, वह इतिहास में घोटालों के कारण याद रहेगा। याद कीजिये, 2008 से लेकर 2013 के इतिहास को, राजस्थान की राज्य सरकार को सबसे भ्रष्ट सरकार के रूप में जाना जायेगा, इस बात को भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा।

माननीय सभापति महोदय, इस बजट में मैं बिंदुवार कुछ प्रमुख बातों की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। आपने बिन्दु संख्या 2 में लिखा कि कुशल वित्तीय प्रबन्धन के कारण 80 परसेंट से अधिक बजट घोषणाएं हमने धरातल पर आज दिन तक पूरी कर ली हैं। मैं निवेदन करूंगा कि 2013 में जब आपने अपनी पिछली सरकार का अंतिम बजट प्रस्तुत किया था, उसमें भी आपने ऐसी ही लोक-लुभावनी घोषणाएं की थीं। नतीजा क्या रहा था, 2013 के चुनाव में मात्र 21 सीटों के साथ में आपको विपक्ष का नेता भी नहीं मिला था। ऐसी की ऐसी घोषणाएं आपने इस बार की हैं। आपके पास वक्त बचा है 6 महीनों का। ये बजट घोषणाएं अच्छी हो सकती हैं, माननीय मुख्य मंत्री का दिल बड़ा है, लेकिन ये चुनाव से पहले पूरी होंगी भी कि नहीं, इसका भगवान ही मालिक है, राम जी ही जानते हैं।

(श्री अविनाश)

मेरे विधान सभा क्षेत्र में पिछले चार सालों में आपने जो दिया, मैं निवेदन करूंगा। उप-परिवहन कार्यालय जैतारण में, उप-तहसील कार्यालय आनन्दपुर कालू, गिरी-सुमेल ऐतिहासिक युद्ध की पेनोरमा बनाने के लिए गिरी में 50 लाख रुपये, सीएचसी जैतारण को 50 से 100 बेड में क्रमोन्नति, जैतारण-निम्बोल की सड़क, पीएचसी से सीएचसी में क्रमोन्नत किया बर सीएचसी को, पुलिस चौकी बर को पुलिस थाना में क्रमोन्नत किया और टुकड़ा में नयी पुलिस चौकी लगायी।

यह पिछले चार वर्ष के बजट में मेरे विधान सभा क्षेत्र को दिया गया। अब इसमें देखिये। उप-परिवहन कार्यालय किराये की दुकान में चल रहा है। उप-तहसील एक पुराने पंचायत के किसी भवन के स्कूल की छोटी-सी बिल्डिंग में चल रही है। गिरी-सुमेल पेनोरमा के लिए जो 50 लाख दिये थे, उसमें कितनी राशि लगी, कितना क्या हुआ, सरकार की तरफ से कोई अता-पता नहीं। सीएचसी जैतारण में 50 से 100 बेड की स्वीकृति आज दिन तक, मैं चिकित्सा मंत्री महोदय को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने काफी डाक्टर तो लगाये, लेकिन अभी भी जरूरत है कि वहां जैसा आदर्श सीएचसी है, जो हमने अपने विधायक कोटे से कोरोना काल में माननीय मुख्य मंत्री जी के निवेदन पर दो-दो करोड़ रुपये के इक्विपमेंट्स दिये, आज भी चिकित्सा स्टाफ नहीं होने के कारण, स्पेशलिस्ट डाक्टर नहीं होने के कारण, मेडिकल स्टाफ नहीं होने के कारण वे इक्विपमेंट्स काम नहीं आ रहे।

आपने पिछले बजट में घोषणा की थी कि प्रत्येक सीएचसी पर डायलिसिस मशीन शुरू करेंगे। मैंने दो साल पहले मेरी जैतारण सीएचसी पर डायलिसिस की मशीन दे दी, लेकिन बड़े ताज्जुब के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि दो साल में उस डायलिसिस मशीन को शुरू नहीं कर पाये। मैंने कहा था कि मैं इसके आपरेटर के लिए मेरी एक फाउंडेशन के माध्यम से पैसे दे दूंगा, आप गरीबों के इलाज हेतु डायलिसिस मशीन शुरू करवा दीजिये, लेकिन प्रशासनिक विफलता और सरकार के फेल्योर के कारण वह मशीन शुरू नहीं हो पायी है। पूरे राजस्थान में किसी सीएचसी पर अगर कोई डायलिसिस मशीन शुरू हुई हो तो माननीय मुख्य मंत्री जी अपने जवाब में बताएं।

इस बार आपने इस बजट में जैतारण विधान सभा क्षेत्र में मेरी जो मांग थी खेल स्टेडियम की, उसे स्वीकार किया। लाम्बिया से पुष्कर सीमा पर कुड़की

(श्री अविनाश)

तक 20 किलोमीटर 15 करोड़ रुपये की, झाला की चौकी से जलसा खेड़ा वाया बगड़ी कलाड़ तक 40 किलोमीटर, फालका से कोडाया 8 किलोमीटर 6 करोड़ रुपये, आनन्दपुर कालू पीएचसी को सीएचसी में क्रमोन्नत कर दिया। मेरा माननीय मुख्य मंत्री महोदय से निवेदन रहेगा, ये घोषणाएं तो आपने कर दीं, लेकिन जब नया वित्तीय वर्ष लगेगा, इनके शीघ्रातिशीघ्र एफ.एस. निकाल कर ये काम अगर धरातल पर लग जाएं, टेंडर लग जाएं और वित्तीय स्वीकृति होने के बाद ये काम शुरू हो जाएं, तब इन घोषणाओं की जनता के बीच महत्ता रहेगी।

माननीय सभापति महोदय, इसके साथ ही मैं निवेदन करूंगा, हमारी कुछ मांगें रह गयी हैं। हमारी बार काउंसिल, बर के अधिवक्ता पिछले काफी दिनों से हड़ताल पर हैं। उनकी डिमांड है कि एडीजे कोर्ट बर में खोला जाये। मेरी सरकार से मांग है कि एडीजे कोर्ट बर में खोला जाये। एक कन्या महाविद्यालय। बर क्षेत्र में लगभग आधी से अधिक संख्या में स्कूल-कालेजों में हमारी बहनें पढ़ती हैं, उन्हें सुविधा हो, इसलिए एक कन्या महाविद्यालय की घोषणा भी बर या जैतारण के आस-पास कहीं करें तो बड़ी मेहरबानी होगी। सेंदड़ा उप-तहसील बहुत बरसों से एक उपतहसील के रूप में काम कर रही है, मेरा निवेदन रहेगा कि सेंदड़ा उप-तहसील को अगर तहसील में क्रमोन्नत कर दें तो मगरा क्षेत्र के लोगों को फायदा होगा।

जैतारण में टाउन हाल नगरपालिका क्षेत्र के लिए निवेदन है। एक जैतारण एडिशनल एसपी कार्यालय के लिए निवेदन है कि यहां से जिला मुख्यालय लगभग 100-125 किलोमीटर पड़ता है। पुलिस, कर्मचारियों, अधिकारियों को बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है, इसलिए एडिशनल एसपी कार्यालय जैतारण में खोला जाये। एक सहायक खनिज अभियन्ता कार्यालय अगर जैतारण में हो जाये, यहां चार बड़े सीमेंट के प्लांट्स हैं, मिनरल्स हैं, स्टोन क्रेशर्स हैं...

श्री सभापति: थैंक यू।

श्री अविनाश (जैतारण): बस दो मिनट में खतम कर रहा हूं। मेरा पंद्रह मिनट का समय है, उसमें खतम कर रहा हूं।

श्री सभापति: नहीं, आपका पंद्रह मिनट का समय हो गया है। एक मिनट में समाप्त करें।

श्री अविनाश (जैतारण): पिछली बार आपने जो मिसिंग लिंक नोन-पेचेबल

(श्री अविनाश)

सड़कें दी थीं 10 करोड़ की, मुझे लगता है एक वर्ष बीत जाने के बाद अभी तक एक भी सड़क शुरू नहीं हुई है। इस बार भी आपने घोषणा की है। मेरा सदन के माध्यम से निवेदन रहेगा, पिछली बार भी आपने कहा था कि प्रत्येक विधायक की अनुशंसा पर 10 करोड़ की मिसिंग लिंक नोन-पेचेबल सड़कें देंगे, इस बार भी आप विधायकों की अनुशंसा के आधार पर इन सड़कों को स्वीकृत करें।

माननीय सभापति महोदय, काणुजा के लिए मैंने पहले भी निवेदन किया था, जिस आसन पर आप विराजमान हैं, इसी आसन पर कभी स्व. हीरासिंह जी चौहान साहब विराजते थे, तीन बार रायपुर से विधायक रहे। हमारी पार्टी भाजपा से विधायक रहे। विधान सभा के उपाध्यक्ष भी रहे। उनकी स्मृति में अगर उनके पैतृक गांव काणुजा के उच्च माध्यमिक विद्यालय का नामकरण उनके नाम से हो जाये, इससे बड़ी श्रद्धांजलि और कोई नहीं हो सकती, क्योंकि वे रावत समाज का एक बहुत बड़ा नाम हैं, जिन्हें शेर-ए-मगरा कहा जाता है, रावत रत्न कहा जाता है।

सभापति महोदय, एक महत्वपूर्ण बात और। सैटलमेंट के बाद में जो मेरा क्षेत्र है मगरा, मगरा की रायपुर पंचायत समिति, उसके अन्दर एक कमेटी बनी हुई है। उसमें पांच बीघा से कम जो सरकारी जमीन है, वहां लोगों के पास खुद की खातेदारी जमीन नहीं है। एक कमेटी बनी हुई है उसमें एक नियम भी बना हुआ है, हमारी बीजेपी की सरकार वसुन्धरा जी के समय कि पांच बीघा से कम जमीन जिनके पास सरकारी अतिक्रमण है, उसमें जो पक्का मकान बना हुआ है उन्हें पट्टे दें। जो कृषि भूमि है, उसे नियमन खातेदारी अधिकार देकर उन्हें राहत देने का काम भी करें। मैं पिछले तीन सालों से काम कर रहा हूं लेकिन सरकार, जिसमें कमेटी का मेम्बर मैं भी हूं, उप-खण्ड अधिकारी भी है, तहसीलदार भी है, बीडीओ भी है, तो ऐसा एक आदेश पारित करें जिससे उन्हें फायदा मिले।

माननीय सभापति महोदय, जो जंगलिया जाति है, वह आज की तारीख में जनरल कैटेगरी में है। वह इतना तो पिछड़ा हुआ वर्ग है, जिन्हें कुछ पता ही नहीं चलता, शैक्षणिक सुविधा उन्हें नहीं मिलती, आर्थिक आधार पर भी कमजोर हैं, उन्हें कम से कम एसटी या एससी में अगर ले लें तो जंगलिया जाति के जितने भी लोग हैं, उन्हें फायदा मिलेगा।

रायपुर पंचायत समिति में जो शहीद परिवार हैं, जो शहीद हुए हैं उनके नाम से स्कूलों का नामकरण हो और उनकी मूर्तियां यदि नहीं लगी हैं तो उस गांव में उनकी मूर्तियां लगाएं।

(श्री अविनाश)

मैं प्रेम सिंह जी बाजोर साहब को धन्यवाद दूंगा, जो सैनिक कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष थे, उन्होंने अपने खर्चे से पूरे राजस्थान में शहीदों की मूर्तियां लगायी हैं। कम से कम राजस्थान सरकार ऐसा नियम बनाये। हम एमएलए कोटे से पैसा देना चाहते हैं, लेकिन सरकारी योजना में जिला प्रशासन से अनुमति नहीं होने के कारण वे मूर्तियां नहीं लग पाती हैं और शहीदों का सम्मान नहीं हो पाता है इसलिए, माननीय सभापति महोदय, आपसे निवेदन है कि आप कम से कम ऐसा काम करें जिससे शहीदों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित हो सके। मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। धन्यवाद। जय हिन्द। जय भारत। जय जय जैतारण।

श्री सभापति: श्री जगदीश चन्द्र।

श्री जगदीश चन्द्र (सादुलशहर): माननीय सभापति महोदय, आपने बजट पर चर्चा करने के लिए समय दिया, उसके लिए धन्यवाद। मैं काफी देर से हमारे जैतारण से आने वाले साथी का भाषण सुन रहा था। एक शेर मुझे उन पर याद आ रहा है-

"एक रास्ता यह भी है मंजिलों को पाने का,
सीख लो हुनर हां में हां मिलाने का।"

यह पार्लियामेंट हाउस है कि राजस्थान की विधान सभा, मैं समझ ही नहीं पा रहा था काफी देर तक। चर्चा करनी थी राजस्थान सरकार के बजट पर। जिस सरकार ने चार साल में जो बेहतरीन प्रबन्धन हो सकता है फाइनेंस का और जो विकास के काम हैं, जो जन घोषणा पत्र में जनता के सामने 2018 में पेश किये, हमने बेहतरीन तरीके से करे। किसी साथी ने बजट को लेकर कहा कि बजट लीक हो गया, किसी साथी ने आंकड़ों के हिसाब से अपना वक्तव्य प्रस्तुत किया, लेकिन मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं कि आप भारत सरकार के बजट से राजस्थान सरकार के बजट की तुलना नहीं कर सकते। भारत सरकार का जो हाईएस्ट रेवेन्यू कलेक्शन है वह सेंट्रल एक्साइज और कस्टम्स से आता है और करीब-करीब उससे सरकार चलती है। राजस्थान सरकार के पास में बजट के सीमित सोर्सेज हैं। उसके बावजूद भी हर क्षेत्र में जो विकास के आयाम स्थापित किये हैं, इसके लिए राजस्थान सरकार के मुखिया धन्यवाद के पात्र हैं और राजस्थान की जनता के आशा के अनुरूप हमने जो काम किये हैं, इतिहास इस बात का साक्षी रहेगा और निश्चित तौर पर आने वाला समय आपको इस बात को बतायेगा।

(श्री जगदीश चन्द्र)

किस तरीके से देश में महंगाई बढ़ रही है, किस तरीके से देश के हालात हैं वे भी आपके सामने हैं। महंगाई के बावजूद भी, स्टेट की आर्थिक स्थिति के कमजोर होते हुए भी वैट कम करके करीब 13 हजार करोड़ रुपये का जो वार्षिक वित्तीय घाटा था, नुकसान था वह भी सरकार ने झेला और महंगाई को कंट्रोल करने का प्रयास किया। किन्तु केन्द्र सरकार की नीतियों के कारण महंगाई से जो आमजन ग्रस्त थे और जो खाद्य सुरक्षा का कानून था, जो भारत सरकार और राज्य सरकार की साझा में स्कीम थी उसमें मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जो 10 किलो अनाज की व्यवस्था की गई थी, वहां देश में एक तरफ तो महंगाई की मार थी, कोई चूल्हा नहीं जल रहा था, रोजी-रोटी की कोई व्यवस्था नहीं है और उस समय आपने 10 किलो से 5 किलो अनाज कर दिया। यह सीधा-सीधा एग्जाम्पल आपने दिया है कि यह वही दिल्ली की सरकार है जिस सरकार में हर चीज में महंगाई बढ़ी है। घी लो, आटा-तेल लो या दूसरे इन्फ्रास्ट्रक्चर लो, हर चीज में महंगाई बढ़ी है और महंगाई का आलम इतना है कि शब्दों में व्याख्या नहीं की जा सकती और लोग इस चीज को महसूस कर रहे हैं। लेकिन राजस्थान के मुख्य मंत्री ने मानवता के आधार पर महंगाई के लिए जो नि:शुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट देने का फैसला किया है वह स्वागत योग्य फैसला है। यह कम से कम एक करोड़ परिवारों के लिए फैसला किया गया है, जिसमें 03 हजार करोड़ के लगभग का खर्चा होगा।

माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाह रहा हूं कि 76 लाख परिवार हैं जो उज्ज्वला गैस का इस्तेमाल करते हैं। जब उज्ज्वला गैस स्कीम भारत सरकार ने चालू की थी तब तो लोगों ने वे सिलेंडर भरवाये थे और उसके बाद 8-9 महीनों से वे सिलेंडर खाली पड़े हुए हैं। वह भारत सरकार द्वारा एक रणनीति के तहत किया गया था क्योंकि लोक सभा का चुनाव था। लेकिन आज स्थिति यह हो गई कि गैस की टंकी खाली हुए तीन साल हो गये हैं और एक हजार पचास रुपये से ऊपर गैस सिलेंडर के हो गये हैं। राजस्थान के मुख्य मंत्री जी ने जो फैसला किया है उससे 76 लाख परिवारों को 500 रुपये में गैस का सिलेंडर मिलेगा। यह अपने आप में कम बात नहीं है, यह बहुत बड़ी बात है और इस बात का भी स्वागत किया जाना चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं कि इस सरकार ने न तो कोई नया टैक्स लगाया, न ही पुराने टैक्स को बहाल

(श्री जगदीश चन्द्र)

किया। हमने जो पिछला बजट पेश किया उसमें भी टैक्स नहीं था और यह भी बगैर टैक्स का बजट है और उसके बावजूद भी समाज के हर वर्ग को हमने रियायत देने का प्रयास किया गया है, जो एक ऐतिहासिक बजट है।

चिरंजीवी योजना की बात सारे साथी कर रहे थे। अगर प्राइवेट अस्पताल में जाओ तो मरीज को देखने के 500 रुपये लगते हैं। मुख्य मंत्री जी ने मानवता के आधार पर फैसला किया है, फैसला राजस्थान में ही है और दुनिया के किसी भी मुल्क में नहीं है। मैं 28-30 कंट्रीज में गया हूं और कोई मुल्क नहीं है जहां 25 लाख रुपये तक का इलाज किसी मुल्क में फ्री में होता हो। यह राजस्थान सरकार का ही फैसला है, राजस्थान सरकार के मुखिया की दरियादिली थी कि मानवता के आधार पर स्वस्थ राजस्थान का संकल्प जो 2020 में इसी विधान सभा में लिया था, उसी दृष्टिकोण को आगे बढ़ाते हुए यह फैसला किया गया है, जो स्वागत योग्य है। 05 लाख से 10 लाख की दुर्घटना बीमा योजना भी आपने चालू की है।

मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं कि हमने किसान का बजट पेश किया। चूरू से आने वाले हमारे साथी ने किसानों की बात की कि भारत सरकार ने किसानों के बारे में बड़े फैसले किये हैं और राजस्थान सरकार ने किसानों के बारे में कोई अच्छा फैसला नहीं किया। हमने 11 मिशन के साथ में कृषि का बजट पेश किया था और यह राजस्थान सरकार का एक एग्जाम्पल था कि किसानों के लिए अलग से बजट पेश किया ताकि देख सकें कि किसानों के लिए हमने कितना-कितना पैसा खर्च किया है। इसके अलावा अबकी बार 12वां मिशन उसमें हमने शामिल किया है। यही सरकार है जो किसानों की सरकार है। मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं, आप स्वामीनाथन कमेटी की बात कर रहे थे। पहली बार डाक्टर मनमोहन सिंह जी ने स्वामीनाथन कमेटी बनायी थी, वह इस आधार पर बनायी थी कि देश के किसान के हालात खराब हैं और उस किसान के हालात ठीक करने के लिए, उसकी फसल की जितनी कीमत है उससे उसको डबल मिलना चाहिए और इसी आधार पर यह फैसला किया गया था। हमारी सरकार ने उस कमेटी की रिपोर्ट को लागू करने का फैसला किया और कोशिश की तथा उसी के तहत 72 हजार करोड़ का कर्जा माफ किया था किसान को सम्बल प्रदान करने के लिए तो वह सरदार मनमोहन सिंह जी ने किया था। सरदार मनमोहन सिंह जी ने 72 हजार करोड़ का कर्जा माफ किया था कि हिन्दुस्तान का किसान जो

(श्री जगदीश चन्द्र)

आत्महत्या कर रहा था, उसको थोड़ा बहुत सम्बल प्रदान हो। अगर मैं स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट निवेदन करूं तो आप ही की सरकार थी, आप ही के प्रधान मंत्री थे और 2014 में उन्होंने 2022 में किसान की आमदनी को दुगुनी करने की बात की थी पर आपने आज हिन्दुस्तान के किसान की हैसियत 6 हजार रुपये मानी है। मात्र 6 हजार रुपये मानी है। जो अन्नदाता है, जो जमीन का मालिक है, उसकी हैसियत को आपने 6 हजार माना, तो आप किसानों की पार्टी कैसे हो सकते हो?

1958 के अन्दर कांग्रेस की सरकार थी, देश के अन्दर पहली बार जमीन का अधिकार किसी ने दिया था तो कांग्रेस पार्टी ने दिया था और पण्डित नेहरू जी ने दिया था। हम लोग जमीन नहीं खरीद सकते थे। आज काश्तकार साथी बैठे हैं, किसान बैठे हुए हैं आप जमीन के मालिक नहीं हो सकते थे। अगर जमीन खरीदने का अधिकार दिया था तो वह कांग्रेस पार्टी ने इस देश में पहली दफा दिया था। गरीब को मकान दिया तो कांग्रेस पार्टी ने दिया, गरीब को जमीन दी तो कांग्रेस पार्टी ने दी थी, खातेदारी राइट्स दिये तो कांग्रेस पार्टी ने दिये थे। अगर सही मायने में किसान की कोई पार्टी है तो वह कांग्रेस पार्टी है।

मैं निवेदन करना चाह रहा हूं कि अगर भारत सरकार किसानों की इतनी ही हितैषी है, जब पार्लियामेंट का सेशन नहीं चल रहा था, देश में 2020 में लॉकडाउन था तब आपने इमरजेंसी में दो दिन का सेशन बुलाया और बगैर चर्चा के खेतीबाड़ी के तीन कानून पास किये, वह एमएसपी का इश्यू आज तक पैंडिंग है। पहली दफा पण्डित नेहरू इस देश में एमएसपी का इश्यू लेकर आये थे कि किसान को उसकी फसल का मुआवजा मिले, उसकी फसल का दाम मिले जबकि आपकी सरकार एमएसपी खतम करना चाह रही है, आपकी सरकार एफसीआई को भी खतम करना चाह रही है और आपकी सरकार की मन्शा है कि इस देश में एमएसपी का इश्यू है वह खतम हो जाए। मैं निवेदन करना चाह रहा हूं कि राजस्थान की सरकार के मुख्य मंत्री ने कहा है कि हम एमएसपी के आधार पर किसान की सारी फसल खरीदेंगे जो राजस्थान में फसल पैदा होती है, यह हमारी सरकार का फैसला है।

इस देश में पहली बार किसान के लिए सिंचाई की परियोजनाएं बनी हैं। भाखड़ा नांगल बांध बना था वह पण्डित नेहरू की देखरेख में बना था। उस बांध की वजह से पूरे हनुमानगढ़ और गंगानगर दोनों जिलों में अगर खेती हो रही है तो वह भाखड़ा नांगल बांध की वजह से हो रही है और वह कांग्रेस पार्टी

(श्री जगदीश चन्द्र)

का दिया हुआ था। मैं निवेदन करना चाह रहा हूं कि हिन्दुस्तान में आपकी सरकार है, देश में सिंचाई के मंत्री हैं वह राजस्थान से हैं लेकिन आज तक राजस्थान का जो पानी का मसला है वह पैंडिंग पड़ा हुआ है और उस पर सरकार कोई फैसला नहीं कर रही है। मैं आपसे यह भी आग्रह करना चाह रहा हूं कि बीबीएमबी की सदस्यता की बात है, उसमें आपने बोर्ड को भंग तो कर दिया लेकिन आज तक उसमें सदस्य अपाइंट नहीं हो पाया। मैं आपके माध्यम से आग्रह करना चाहूंगा कि राजस्थान का सदस्य उसमें बैठे ताकि हमें हमारे पानी का हिस्सा मिले।

माननीय सभापति महोदय, पहली बार सरकार ने किसान का ख्याल किया और किसान को 2000 यूनिट बिजली मुफ्त देने का जो फैसला किया वह हमारी सरकार ने किया। सबसे बड़ी समस्या राजस्थान के किसान की बिजली की थी, जिसको हमारी सरकार ने सोर्ट आउट करने का प्रावधान किया। पूरी रात सर्दी में लोग मरते थे और बिजली की कोई व्यवस्था थी ही नहीं। हमारी सरकार ने जनरेशन को भी ठीक किया। जब 2018 में सरकार मिली तब राजस्थान में 14 हजार मेगावाट के आसपास बिजली का जनरेशन था, हमारी सरकार ने उसको 23 हजार मेगावाट किया और किसान के साथ 100 यूनिट का घरेलू उपभोक्ता है उसको भी फ्री में बिजली देने का प्रावधान राजस्थान की सरकार ने किया, जो एक ऐतिहासिक फैसला है। इस फैसले को देखकर हमारे साथी घबरा रहे हैं कि चुनाव की नैया पलट न जाए, चुनाव का रिजल्ट उलटा नहीं हो जाए, इसलिए ये बहुत ज्यादा चिंतित हैं।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाह रहा हूं कि हमारे जो गांवों में आंगनबाड़ी सेंटर हैं उनकी हालत खराब थी। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि 2019 से लेकर आज तक और 2013 से लेकर 2019 तक के भारत सरकार बताये कि राजस्थान में कितने आंगनबाड़ी सेंटर दिये हैं? हमारे मुख्य मंत्री जी ने 08 हजार सेंटर खोलने की घोषणा की है, 02 हजार मिनी सेंटर खोलने की भी घोषणा की है और यह भी तय किया है कि आंगनबाड़ी में पढ़ने वाला जो बच्चा है उसको दो-दो वर्दी देने की भी बात की गई है क्योंकि आंगनबाड़ी में गरीब के बच्चे पढ़ते हैं, सरकार की स्कीम गरीब के लिए होती है, किसी बड़े आदमी के बच्चे आंगनबाड़ी सेंटर में नहीं जाते, गरीब के बच्चे जाते हैं इसलिए सरकार ने प्राथमिकता के आधार पर यह फैसला किया है कि आंगनबाड़ी सेंटर्स को बढ़ावा दिया जाए ताकि गांवों में शिक्षा का वातावरण बने।

(श्री जगदीश चन्द्र)

यह जो बजट है यह युवाओं का बजट है, यह किसानों का बजट है और हमारी सरकार ने युवाओं का खासकर ख्याल रखा है। सरकार ने यह तय किया है कि नौजवान साथी जो हमारा एग्जाम देने के लिए जाता है, उसका एक दफा रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद किसी एग्जाम का कोई पैसा नहीं लगेगा, उसका बस में किराया-भाड़ा नहीं लगेगा। दूसरी व्यवस्था सरकार ने की है उसमें उसको सम्बल प्रदान करने का प्रयास किया है और यही राजस्थान की सरकार है जिसने एक नहीं डेढ़ लाख से ऊपर नौकरियों में भर्ती की है। सभापति महोदय, मैं अगर भारत सरकार की बात करूं तो पिछले तीन साल से केन्द्र सरकार में कोई नौकरी यूपीएससी के अलावा नहीं निकली है। तीन साल से केन्द्र सरकार की भर्ती बन्द है और अगर है तो वह फौज की है, जिसको भी चार साल का कर दिया। ये किस आधार पर नौकरी दे सकते हैं? अगर आप केन्द्र सरकार का, यूनियन बजट देखें तो नौकरी का प्रावधान किया है क्या? पिछले 7-8 साल का अगर डेटा देखो तो भारत सरकार में नौकरी की व्यवस्था खतम कर दी गई है। आने वाले समय में जो बाकी नौकरियां हैं वे भी दस-दस साल की करने का प्रयास किया जा रहा है इसलिए इस सरकार से उम्मीद नहीं करनी चाहिए। ये वही प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी हैं जिन्होंने दो करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात की थी 2019 में पर आज क्या बात हो गई है? आज सारी नौकरियां गायब हो गई हैं। आपने ओपीएस भी बन्द कर दी, आपने दूसरे भी बन्द कर दिये, नौकरी देना तो बहुत दूर की बात है। सरकारी कर्मचारी काम कर रहा था, आपने ओपीएस को भी बन्द कर दिया। भारत सरकार ने 2004 में फैसला किया था। मैं मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि आपने मानवता के आधार पर सरकार के कर्मचारियों को ओपीएस देने का फैसला किया है, यह ऐतिहासिक फैसला होगा। इसका इतिहास में नाम होगा, आने वाली पीढ़ियां आपको दुआएं देंगी कि उनके भविष्य को सुरक्षित करने के लिए आपने फैसला लिया है। निश्चित तौर पर यह ऐतिहासिक फैसला है।

सभापति महोदय, अभी तीन दिन पहले राज्य सभा में प्रधान मंत्री जी का रिप्लाई था। उन्होंने इंडिकेट किया कि जिस स्टेट ने ओपीएस को लागू किया है, प्रधान मंत्री जी द्वारा टोंट किया गया, क्या देश के प्रधान मंत्री का यह काम है? यह सरकार का नीतिगत फैसला है, कोई सरकार कर सकती है, उसने किया, जो नहीं कर सकती है, नहीं किया।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री महेन्द्र चौधरी (सरकारी उप मुख्य सचेतक): माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय डेढ़ घंटा बढ़ाकर साढ़े 6 बजे तक कर दिया जाए।

श्री सभापति: सदन का समय बढ़ाया जाए?

(स्वीकृत)

सदन का समय साढ़े 6 बजे तक के लिए बढ़ाया गया।

आय-व्ययक

आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2023-24 पर सामान्य वाद-विवाद

श्री जगदीश चन्द्र (सादुलशहर): सभापति महोदय, यह सरकार का नीतिगत फैसला है। कोई सरकार ओपीएस लागू कर रही है, कोई नहीं कर रही है। हमने फैसला किया, यह हमारे स्टेट का आर्थिक भार है। हमने स्टेट कर्मचारियों को, कारपोरेशन के कर्मचारियों को, यूनिवर्सिटीज के कर्मचारियों को, बाकी सभी कर्मचारियों को ओपीएस दी है, तो इसमें बुराई की क्या बात है? सवाल इस बात का है कि इनके हाथ से समय निकल गया है। आज सरकारी कर्मचारियों में इस बात का प्रचार है। यह अशोक गहलोत की लोकप्रियता है कि आने वाले 2023 के चुनाव में निश्चित तौर पर कांग्रेस के पक्ष में वोट पड़ रहे हैं। इस बात की चिन्ता सताई जा रही है, क्योंकि ये लोग यह एग्जाम्पल हिमाचल प्रदेश में देख चुके हैं, हिमाचल में यह एक्सपेरिमेंट हो चुका है।

मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, ये लोग बार-बार श्रीलंका की बात करते हैं। आप बार-बार पाकिस्तान की बात क्यों नहीं करते? पाकिस्तान और हिन्दुस्तान साथ-साथ आजाद हुए थे। वह हमारी कंट्री का हिस्सा था। पाकिस्तान का आधार क्या था? जात और धर्म पाकिस्तान का आधार था, वह मुल्क बर्बाद हो गया। उस मुल्क की इकोनोमी बर्बाद हो गई। यहां सेकुलर विचारधार के लोग थे, यह सेकुलर कंट्री है, इसलिए आज हमारा मुल्क दुनिया की पांचवीं बड़ी इकोनोमी है, न कि इनकी वजह से है। अगर धर्म के आधार पर मुल्क होता तो आज स्थिति ज्यादा खराब हो सकती थी। इसलिए धर्म और जात के आधार पर देश नहीं चलते हैं। देश संविधान के हिसाब से चलता है। मुल्क संविधान की मर्यादा के हिसाब से चलता है।

(श्री जगदीश चन्द्र)

सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं कि राजस्थान की सरकार ने स्टार्ट-अप के लिए ढाई सौ करोड़ का बजट में प्रावधान किया है। 500 करोड़ रुपये के युवा कल्याण कोष की स्थापना की गई है। पहली बार डिस्ट्रिक्ट लेवल पर विवेकानन्द होस्टल की स्थापना करना मुख्य मंत्री जी का महत्वपूर्ण कदम है। जिस विवेकानन्द की ये बात करते नहीं थकते हैं, उनके नाम से होस्टल की स्थापना का फैसला तो हमारी सरकार ने लिया है। इन लोगों को इसकी तारीफ करनी चाहिए। ये तारीफ क्यों नहीं कर रहे हैं?

सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं कि जो युवा नीति प्रस्तावित है, जिसमें 500 करोड़ का युवा विकास एवं कल्याण कोष का गठन किया जाना प्रस्तावित है, यह ऐतिहासिक फैसला है। 100 मेगा फेयर लगेंगे, जिनके माध्यम से बच्चों को नौकरी दी जायेगी और ब्लाक हैडक्वार्टर पर सावित्री बाई फुले वाचनालय बनाये गये हैं। यह भी एक हिस्टोरिकल फैसला है।

सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं कि भारत सरकार के केन्द्रीय बजट के जो फैसले थे, अभी यूनियन बजट आया, उसमें किस तरह से नरेगा के पैसे को घटाया गया। जो 2021-22 का बजट था, उसमें 25 परसेंट नरेगा का पैसा घटा दिया गया था। इस सरकार ने 33 परसेंट घटा दिया और इसी सरकार के मुखिया और इसी सरकार के कर्ता-धर्ता, जिन्होंने लोक सभा में बयान दिया था, जब 2005 में नरेगा आई थी, कि हिन्दुस्तान में यह योजना गड्ढ़ा साबित होगी। आज इस योजना को बन्द नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सेन्ट्रल लॉ है। सेन्ट्रल लॉ के लिए आपको पार्लियामेंट में बिल लेकर आना पड़ेगा। आपने इस स्कीम का पैसा कम कर दिया ताकि यह स्कीम फेल हो जाये, लेकिन मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं कि राजस्थान की सरकार के मुखिया ने 125 दिन का काम देकर ऐतिहासिक फैसला किया है। खासकर शहरों में भी रोजगार गारंटी का कानून दिया है। यह हिस्टोरिकल फैसला है। इससे आम आदमी को सम्बल मिला है, उस गरीब को सम्बल मिला है जिसके पास रोजगार नहीं था। मुख्य मंत्री जी इस बात के लिए धन्यवाद के पात्र हैं।

सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि पहली बार सरकार ने, जो हमारे वाल्मीकि समाज के लोग हैं, समाज का सबसे कमजोर तबका है, उस कमजोर तबके का भी ख्याल रखा गया है। सामाजिक दृष्टिकोण के हिसाब से तीस हजार कर्मचारियों की भर्ती करनी है। यह छोटी बात नहीं है,

(श्री जगदीश चन्द्र)

यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तीस हजार की भर्ती करना, नौकरी देना, यह बहुत बड़ा फैसला है। उनके कोष के अन्दर मात्र 20 हजार करोड़ का प्रावधान था, हमने उसे भी बढ़ाकर 100 करोड़ कर दिया है। पहली दफा सरकार ने नौजवानों का ख्याल रखते हुए 250 पद फूड सेफ्टी अफसर के सृजित किये थे। इसके साथ-साथ 100 नये पद भी हम जनरेट कर रहे हैं, ताकि नौकरी का अवसर मिले। सरकार की मंशा है कि आने वाले समय में नौजवान को वे सारे साधन सरकार उपलब्ध कराये। इस बजट के माध्यम से सरकार ने वही करने का प्रयास किया है।

सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाह रहा हूं कि हमारे जो संविदा के कर्मचारी थे, जिनको नौकरी की कभी उम्मीद ही नहीं थी, जिनको यह लगता था कि पूरी जिन्दगी कच्चे में रहेंगे, प्राइवेट एजेंसी के माध्यम से नौकरी करते थे, सरकार ने उस ठेका प्रथा को खतम किया और सरकार ने संविदा के आधार पर सरकारी कम्पनियों के माध्यम से नौकरी देने का फैसला किया है। यह स्वाग्य योग्य फैसला है।

सभापति महोदय, मैं आपसे यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार ने प्रमोशन में भी दो साल की छूट दी है। सरकार के कर्मचारियों को दिक्कत थी, उनका प्रमोशन नहीं हो पा रहा था। उसमें भी दो साल का ध्यान रखा गया है, ताकि उनको फायदा हो।

श्री सभापति: कृपया दो मिनट में समाप्त करें।

श्री जगदीश चन्द्र (सादुलशहर): सभापति महोदय, सचिवालय के कर्मचारियों पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। सरकार ने उनका भी ख्याल रखा है। खासकर जो हमारी बालिकाएं हैं, हमारी महिलाएं हैं, उनको राजस्थान सरकार की बसों में किराये में 50 परसेंट की छूट दी गई है। यह कल्पना कोई कर सकता था कि हमने महिलाओं के सम्मान के लिए राजस्थान सरकार की सारी रोडवेज बसों में किराये में 50 प्रतिशत छूट का प्रावधान किया है? इसके साथ ही साथ 50 किलोमीटर से जो विद्यार्थी रोजाना अप-डाउन करता था, उसको भी 75 किलोमीटर किया गया है। जो विद्यार्थी एग्जाम देने के लिए जाता है, उसको बिलकुल फ्री कर दिया गया है। यह छोटा फैसला नहीं है। इसके साथ-साथ सरकार ने 1000 नई बसें चलाने का फैसला किया है, यह भी ऐतिहासिक फैसला है, इसका स्वागत किया जाना चाहिए।

(श्री जगदीश चन्द्र)

माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से निवेदन करना चाह रहा हूं कि इस सरकार का बजट खासकर एजुकेशन के लिए समर्पित बजट है। पहली बार इतने कालेज खोले गये हैं। हमने महिला कालेज खोले हैं, हमने कन्या महाविद्यालय खोले हैं, हमने आईटीआई कालेज खोले हैं। हमने ट्रांसपोर्ट वाउचर की व्यवस्था की है। इसके साथ ही साथ मैं निवेदन करूं कि शिक्षा के क्षेत्र में राजस्थान के मुख्य मंत्री ने नवाचार स्टार्ट किया है।

सभापति महोदय, इस पूरे बजट के अन्दर जो महत्वपूर्ण बात है वह राजस्थान के किसान की और सिंचाई की बात है, क्योंकि बगैर सिंचाई के किसान की खेती पक नहीं सकती है।

श्री सभापति: थैंक यू।

श्री जगदीश चन्द्र (सादुलशहर): पहली बार सरकार ने सरहिन्द फीडर, हमारी इन्दिरा गांधी कैनाल और दूसरी परियोजनाओं के लिए पैसे का प्रावधान किया है और खासकर के हनुमानगढ़, गंगानगर में भाखड़ा के जो खाले थे, जहां करीब-करीब 01 लाख 32 हजार हैक्टेयर कमांड एरिया है, जहां सिंचाई नहीं हो पा रही थी, वहां पानी कम था, मुख्य मंत्रीजी ने 500 करोड़ रुपये का प्रबन्ध करके उन खालों की व्यवस्था की है।

माननीय सभापति महोदय, हमने पिछले बजट में सिंचाई के लिए 14 हजार 860 करोड़ रुपये का प्रावधान किया था, जिसमें से 11 हजार करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। इस साल 3600 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। जिसमें हमारी अलग-अलग सिंचाई परियोजनाएं हैं।

श्री सभापति: कृपया समाप्त करिये। श्री नरेन्द्र नागर।

श्री जगदीश चन्द्र (सादुलशहर): सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं, राजस्थान के फीडर पंजाब क्षेत्र में 34 किलोमीटर लम्बाई में री-लाइन के काम के लिए मुख्य मंत्री जी ने 500 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है।

श्री सभापति: कृपया समाप्त करें। नरेन्द्र नागर जी, आप बोलिये। आप बैठिये।

श्री जगदीश चन्द्र (सादुलशहर): माननीय सभापति महोदय, गांव और देहात का बच्चा अंग्रेजी पढ़ना चाह रहा था। जिसकी अंग्रेजी पढ़ने की मंशा थी, उसके लिए एक-एक हजार अंग्रेजी मीडियम के स्कूल ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में

(श्री जगदीश चन्द्र)

खोल रहे हैं ताकि भविष्य में उसे इस बात का मलाल नहीं रहे, मुझे आगे पढ़ने का मौका मिला। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री नरेन्द्र नागर। आप शुरू करें।

श्री नरेन्द्र नागर (खानपुर): माननीय सभापति महोदय, माननीय मुख्य मंत्री द्वारा जो बजट भाषण पेश किया गया है, उस पर आपने बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं।

माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा 2022-23, 2023-24 का बजट पेश किया। 2022-23 का भी 7 मिनट के लिए पेश किया था। उसमें मुख्य मंत्री जी ने विशेष रूप से किसानों को मुफ्त में बिजली देने घोषणा की है। पूरे सदन को पता है कि पिछली सरकार के द्वारा भी, पूर्व मुख्य मंत्री वसुन्धराजी ने हर साल 10 हजार रुपये तक 833 रुपये प्रतिमाह के हिसाब से घोषणा की थी। उस घोषणा का लाभ किसानों को मिलना भी शुरू हो गया था, पर सरकार बदलने के बाद वर्तमान सरकार ने उस योजना को लगभग 2 साल तक बन्द रखा। जब उन्होंने दो साल तक बन्द रखा तो किसानों का लगभग बीस हजार रुपये का नुकसान हुआ और दो साल के बाद उस योजना में 2000 हजार रुपये बढ़ाकर 12,000 रुपये और किसानों को मुफ्त में बिजली देने का वादा किया। मैं मानता हूं आपने 2000 रुपये बढ़ाये हैं, पर आपने दो साल तक कम किया, उससे नुकसान ही हुआ है।

आने वाले समय में आपने अधिक की घोषणा की है, उसके लिए मैं वास्तव में सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं और साथ ही वर्तमान में बिजली का जो तंत्र है, उसकी जो हालत है, सभापति महोदय, आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

(समय: 17.00 बजे)

अभी वर्तमान में, पिछले समय में जो हालात रहे कि हर किसान दिन में मेहनत और मजदूरी करके जब शाम को घर पहुंचता था, घर पहुंचने के बाद उसको अन्धेरा मिलता था और जब तक वह सोता था तब तक अन्धेरा, रात में कब बिजली आती है और सुबह जब उठता था तो उसको अन्धेरा नजर आता। आप उसमें पचास यूनिट से बढ़ा कर सौ यूनिट बिजली मुफ्त में देने की बात कर रहे हैं, पर बिजली आती ही नहीं है। किसान तो यही कहते हैं और उपभोक्ता भी यही कहते हैं कि बिजली आती ही नहीं है फिर आप पचास से सौ

(श्री नरेन्द्र नागर)

करो या पूरी मुफ्त करो, उससे क्या फायदा। कोई भी किसान हो, मजदूर हो, हर आदमी स्वाभिमान से जीना चाहता है, भले ही पैसे खर्च हों। अच्छी गुणवत्ता की बिजली मिले, नियमित बिजली मिले, एक जमाना था वसुन्धरा जी का जब 22-22 घंटे सिंगल फेज बिजली आती थी और थ्री फेज जो बिजली आती थी, वह नियमित 6-7 घंटे आती थी, ऐसे हालात हमने देखे हैं।

वर्तमान स्थिति यह है कि जब सरकार ने घोषणा की, राजस्थान में कुछ जिलों को चिह्नित किया और उसमें घोषणा की कि इन जिलों में निश्चित रूप से दिन में बिजली आयेगी। हमारा झालावाड़ जिला भी दिन में बिजली आने वाला जिला था और वर्तमान में, पिछले समय में यह जो स्थिति बनी, उसमें जो दो फीडर 6 से 11 और 12 से 6 जो आने चाहिये थे, 6 घंटे जो बिजली देने की घोषणा सरकार कर रही थी, स्थिति यह बनी कि दो फीडरों की जगह आपने एक फीडर बनाया 9 से 3 बजे तक का और उसमें इतनी ट्रिपिंग, सभापति महोदय, आती थी वास्तव में जो 6 घंटे की जगह 3 घंटे मुश्किल से उसको बिजली मिलती थी और 3 घंटे में भी कितने घंटे उसको बिजली मिलती थी, आप और हम सब समझते हैं कि जब नियमित बिजली नहीं आती है तो कितना नुकसान किसानों का होता है, आप भलीभांति समझ सकते हो और जो लोग मजदूरों से अपनी सिंचाई करवाते हैं, उनको कितना पैसा उनको देना पड़ता था। ऐसे ढाई सौ-तीन सौ रुपये में वह 6 घंटे मजदूरी करता था, पर सुबह से शाम तक के लिए उसको तीन सौ की जगह उसको छह सौ रुपये मजदूरी देनी पड़ती थी। कितना नुकसान हुआ, शुक्र करें यह तो ईश्वर का जो बरसात हो गई, नहीं तो कितना नुकसान होता। हम किसान हैं, जो वास्तव में अपनी फसल को पानी नहीं पिला पाते, ऐसे हालात हो गये।

सभापति महोदय, दूसरी बात करें जो 33 केवी बने हुए हैं उनकी स्थिति यह है, मैंने पूर्व में भी कहा था कि उसके जीएसएस के ठेके हुए हैं उसके ठेकेदार के पूरा जिला है या कहीं-कहीं पूरी तहसील है या कहीं 10 जीएसएस, 6 जीएसएस, सरकार की तरफ से उसको 3,400 रुपये प्रति महीने के हिसाब से पैसा मिलता है, जो उस पर कर्मचारी रखता है वह आईटीआई होल्डर उसको रखना चाहिये, वह उसको भी नहीं रखता, उसके अलावा दूसरे कर्मचारी को रखता है। उसके बाद भी स्थिति यह है कि जिन कर्मचारियों को वह रखता है वह कर्मचारी अनट्रेन्ड होते हैं या ट्रेन्ड कर्मचारी होते हैं तो प्राइवेट कहीं काम करके अपना जीवनयापन कर लेते हैं, पर जो ऐसे कर्मचारी हैं,

(श्री नरेन्द्र नागर)

उनको जो 8-9 हजार तनख्वाह मिलनी चाहिये, उनको 4-5 हजार रुपये दिये जाते हैं वह भी 4-5 महीने में दिये जाते हैं। उनको जिन सामानों की आवश्यकता होती है कि कहीं न कहीं उसका नुकसान न हो, उसकी जानमाल का खतरा न हो, उसके लिए सीढ़ियां भी, दस्ताने भी, बहुत सारे सामान उसको उपलब्ध कराने चाहिये, ठेकेदार की तरफ से वह भी उपलब्ध नहीं कराये जाते और इसीलिये कितने एक्सीडेंट वास्तव में होते हैं, वह आपने-हमने देखे हैं। मैं यही निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार इस प्रकार की व्यवस्था करे कि वह ऐसे टेक्निकल हैल्परों को लगाये जो समय पर बिजली चालू करें, समय पर बिजली बन्द करें, उनको पर्याप्त तनख्वाह मिले, ऐसी सरकार को व्यवस्था करनी चाहिये।

हालात ये हैं कि सरकार के द्वारा हर साल बरसात में सुदृढ़ीकरण के नाम से, कहीं न कहीं पेड़-पौधों की टहनियों से बिजली प्रभावित होती है उसको काटने का ठेका होता है, उसकी खानापूर्ति होती है। जो तार खराब होते हैं उनको भी बदलने का काम हर साल सरकार करती है। उसको हर साल टेन्डर देने का काम करती है, पर वह कागजों में ही पूरा होता है, वे तार बदले नहीं जाते हैं और बार-बार तार टूटने की वजह से कितना नुकसान जान-माल का भी होता है, कितना नुकसान किसानों को भी होता है। सरकार को विशेष रूप से इस पर ध्यान देना चाहिये।

सभापति महोदय, साथ ही मैं कहना चाहता हूं कि विधान सभा क्षेत्र खानपुर का बहुत बड़ा कस्बा है खानपुर। पूरे विधान सभा क्षेत्र में नगरपालिका नहीं है, खानपुर ही सबसे बड़ा क्षेत्र है। वहां की आबादी लगभग 25-30 हजार है, 15 से 17 हजार वोटर हैं। पिछली सरकार के द्वारा भी जाते-जाते प्रस्ताव तैयार किये थे, पर सरकार बदल गयी तो नगरपालिका की घोषणा नहीं हो पायी, पर वह प्रस्ताव अभी भी लम्बित है और जहां-जहां मैंने अभी वर्तमान में जो नगरपालिका की घोषणा देखी और उनकी स्थिति मैंने देखी तो उनसे बहुत बड़ी पंचायत खानपुर की है, तो नगरपालिका की घोषणा निश्चित रूप से होनी चाहिये थी।

सभापति महोदय, खानपुर कस्बे में हमेशा बरसात के समय में स्थिति यह होती है कि वह टापू बन जाता है, बाढ़ का पानी वहां आता है। पिछले 2008 में वहां मेगा हाईवे बना। मेगा हाईवे बनने के बाद जो पानी आया, उसमें रोड की वजह से जो ड्रेनेज सिस्टम है उसमें रोड से जो पानी निकलना चाहिये वह पर्याप्त पानी निकल नहीं पाता और जब-जब भी बाढ़ आती है तो

(श्री नरेन्द्र नागर)

सरकारी अधिकारी, सरकार के मंत्री वहां पहुंचते हैं और पहुंचने के बाद यह तय किया जाता है कि आगे आनी वाली बरसात के पहले इस पानी की पर्याप्त निकासी की व्यवस्था हम करेंगे, इसकी चौड़ाई बढ़ाने का काम हम करेंगे, इसकी पानी की निकासी का काम हम करेंगे पर उसके बाद कुछ होता नहीं, फिर वापस बरसात आती है और बरसात में यही स्थिति होती है।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जो वास्तव में खानपुर कस्बे की मांग है वह पूरी होनी चाहिये ताकि बाढ़ से उस खानपुर कस्बे का बचाव किया जा सके, क्योंकि उससे जानमाल का भी खतरा है, व्यापारियों का भी बहुत बड़ा नुकसान होता है व्यापारियों की भी आधी-आधी दुकानें उसमें डूब जाती हैं तो इसके लिए विशेष पैकेज देकर, क्योंकि खानपुर विधान सभा क्षेत्र का सबसे बड़ा कस्बा है खानपुर और विधान सभा क्षेत्र का नाम भी खानपुर है, उस पर विशेष रूप से सरकार को ध्यान देना चाहिये।

सभापति महोदय, साथ ही, पानी के लिए पूरे खानपुर में परवन सिंचाई परियोजना से पानी के लिए योजना बनाई जा रही है, पानी जल्दी हर गांव तक पहुंचे, ऐसा प्रयास विशेष रूप से सरकार के द्वारा किया जाना चाहिये और वर्तमान के हालात ये हैं कि फ्लोराइड युक्त पानी लोगों को मिल रहा है। वर्तमान में सरकार की जो योजना चल रही है जल जीवन मिशन, उसके तहत बहुत सारे गांवों में काम चल रहा है। जल जीवन मिशन में जो मेन ठेकेदार होता है, मैं जहां तक समझता हूं कि शायद सैकंड पार्टी और थर्ड पार्टी को उसका ठेका दे दिया जाता है और किस प्रकार का काम हो रहा है।

सभापति महोदय, पिछली सरकार के द्वारा मुख्यालय पर गौरव पथ बनाये थे, उस गौरव पथ को किस प्रकार से उस ठेकेदार के द्वारा खराब किया जा रहा है और उसके बाद में उसके रिपेयर का काम भी जो हो रहा है, वह ऐसा हो रहा है कि चार से छह महीने के बाद में उसकी बुरी स्थिति हो जाती है। ठेकेदार काम करता है, दस जगह का उसका ठेका होता है तो यह सरकार को निश्चित करना चाहिये कि एक गांव का वह काम करे तो जब तक उस गांव का काम पूरा नहीं हो तब तक उसको पूरा काम वहीं पर करना चाहिये। उसको वहां की खुदाई, लाइन बिछाई, टेस्टिंग करने के बाद ही दूसरे गांव में आगे बढ़ना चाहिये, ताकि गांव के लोगों को दिक्कत न हो, गांव के लोगों को परेशानी न हो।

सभापति महोदय, माननीय मुख्य मंत्री महोदय द्वारा पिछले साल भी विशेष रूप से दस करोड़ की घोषणा की गयी थी, उसके पहले पांच करोड़ की

(श्री नरेन्द्र नागर)

घोषणा की थी। मैं कहना चाहता हूं कि पांच करोड़ की जब सरकार ने घोषणा की थी तब एमएलए की अनुशंसा से आपने रोड बनायी थी और पिछले साल दस करोड़ की अनुशंसा की है तो जहां तक सत्ताधारी पार्टी के एमएलए हैं, उनसे पूछ कर आपने रोड नोन-पेचेबल बनाये, पर विपक्ष के एमएलए जहां हैं वहां आपने उनसे नहीं पूछा और उसका नुकसान, सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूं आपसे कि अधिकारियों ने मिल कर नोन-पेचेबल सड़कें ऐसी सड़कें बनाई हैं जो वास्तव में आगे आने वाले तीन साल तक भी उन सड़कों का कुछ बिगड़ भी नहीं रहा था और अच्छी चमचमाती सड़कों को नोन-पेचेबल में इन्होंने उखाड़ कर फेंक दिया। जब सैंक्शन की कापी आयी तो मैं वहां के जिला कलेक्टर को भी लड़ा, वहां के अधिकारियों को भी लड़ा। यह वास्तव में एक जांच का विषय है कि आपने जो सड़कें जिनके गिट्टी है, नामोनिशान नहीं है उनको तो आपने नोन-पेचेबल में नहीं किया, जो अच्छी सड़कें हैं उनको आपने नोन-पेचेबल में करके सरकार के पैसे का दुरुपयोग किया है।

सभापति महोदय, एमएलए से पूछते हैं तो हम उनको सड़कें बताते हैं, खराब सड़कों की स्थिति चूंकि क्षेत्र में हम जाते हैं हमें पता होती है, अधिकारी टेबल पर बैठ कर काम करता है, तो ऐसे हालात हैं। वास्तव में जो जन प्रतिनिधि हैं उनसे पूछ कर आपको करना चाहिये, ताकि कम से कम सही काम हो सके। ऐसे हालात वास्तव में हैं।

सड़कों के लिए मैं कहना चाहता हूं कि पिछले दो साल से जो मेरे विधान सभा क्षेत्र में फ्लड आ रहा है उसमें इतनी पुलिया हैं वो सारी टूटी पड़ी हैं। दो साल में कहीं पुलिया के नाम से पैसा नहीं है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में पीपलिया नग्गा एक उजाड़ नदी है, वहां एक रपट जो बिलकुल खराब है उससे लोगों को काफी दिक्कत आती है। रतनपुरा एक गांव है, उसकी पुलिया हर बरसात में टूट जाती है, मिट्टी हम डालते हैं उसके बाद फिर खतम हो जाती है, उस पुलिया की भी सरकार को नयी स्वीकृति जारी करनी चाहिये। ऐसे ही मरायता गांव है जो बरसात में कट जाता है।

सभापति महोदय, साथ ही, दरा अरनिया रोड जो सैंक्शन हुआ था उसमें जो गांव-कस्बे के मध्य की सड़कें हैं उसी ठेकेदार को उनको बनानी थी पर वे सड़कें उसने बनायी नहीं, उसकी वजह से कितने लोगों को दिक्कत आ रही है, उसको भी उस ठेकेदार के द्वारा ठीक किया जाना चाहिये।

सभापति महोदय, चूंकि झालावाड़ जिले के पास ही बारां जिला है,

(श्री नरेन्द्र नागर)

बारां जिले में भी बहुत-सी बार जाने का नम्बर आता है। चूंकि बारां जिले के ज्यादातर विधायक सत्ताधारी हैं, वे बोलते नहीं हैं पर मैंने हालात देखे हैं कि आज के समय में बारां से अटरू जाने के लिए जो तीस किलोमीटर का रास्ता है, उस तीस किलोमीटर में आपको लगभग तीन घंटे लगे, ऐसे हालात हैं। उसमें आदमी पैदल नहीं चल सकता, ऐसे हालात हैं। चूंकि यह एनएच का रोड है, एनएच की रोड की जानकारी की है, एनएच से सैंक्शन हो गया। यहां पर पहले ठेका हुआ, ठेकेदार के द्वारा फिर उसका काम शुरू नहीं किया गया। यह स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती है कि काम क्यों नहीं हो रहा है, क्या कारण है। ठेकेदार को काम क्यों नहीं करने दिया जा रहा है, यह इनको देखने की आवश्यकता है ताकि जनता को उसका लाभ मिल सके, समय पर काम पूरा हो सके, ऐसा प्रयास निश्चित रूप से सरकार को करना चाहिये।

साथ ही नोन-पेचेबल सड़कों की वर्तमान में यह स्थिति है, मेरे गुआडी, कोरपुरा, बड़ची की बहुत बुरी स्थिति है, रुपाड़ा की है...

श्री सभापति: दो मिनट में समाप्त करें।

श्री नरेन्द्र नागर (खानपुर): हां, दो मिनट में मैं पूरा कर दूंगा।

देवली, रीछवा की बुरी स्थिति है।

सभापति महोदय, चिकित्सा विभाग की मैं बात करूं, मेरे विधान सभा क्षेत्र में बकानी बहुत बड़ा कस्बा है, जहां 30 बेड का अस्पताल है, मैं सरकार से मांग करता हूं कि उसे 30 बेड से बढ़ाकर 50 बेड का किया जाये, ताकि लोगों को लाभ मिल सके, वह तहसील हैडक्वाटर है।

इसी प्रकार से पंचायती राज में जो हालात हैं, अभी जो 2870 करोड़ रुपये जिला परिषद, पंचायत समितियों को सरकार की तरफ से मिलना चाहिये, वह पैसा मिल नहीं पा रहा है, विकास रुका पड़ा है। साथ ही पहली बार जो पंचायत समिति के सदस्य हैं, जिला परिषद सदस्य हैं, सभापति महोदय, इन्होंने बार-बार सब जनप्रतिनिधियों को ज्ञापन दिया है कि या तो इस पद को खतम कर दिया जाये, पहले सरपंच के जो चुनाव होते हैं, ऐसे सरपंचों के चुनाव किये जायें। पहले सरपंचों से प्रमुख बनाया जाता था, ऐसे बनाया जाये या वर्तमान में उनकी कोई ऐसी व्यवस्था करें कि जिस प्रकार से प्रमुख के पास पैसा आता है, प्रधान के पास आता है, ऐसे ही कहीं न कहीं उनको अधिकार दिये जायें, नहीं तो यहां से कोई चुनाव लड़ने वाला भी नहीं मिलेगा, ऐसे हालात वास्तव में पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद के सदस्यों के हैं। इनको निश्चित रूप से कुछ अधिकार मिलने चाहिये।

(श्री नरेन्द्र नागर)

उच्च शिक्षा में मेरे बकानी में महाविद्यालय की लंबे समय से मांग थी। असनावर में, मेरे साथी एमएलए साहब बैठे हैं, जहां किसी ने महाविद्यालय मांगा नहीं, जिनके महाविद्यालय 15 किलोमीटर पर पड़ता था, जिन लोगों की मांग थी, वहां महाविद्यालय नहीं खोला, जो वर्षों से मांग कर रहे हैं, वहां निश्चित रूप से महाविद्यालय खुलना चाहिये। साथ ही बकानी में उप खण्ड कार्यालय राजस्व की मांग है ताकि लोगों को 50 किलोमीटर दूर झालावाड़ न जाना पड़े।

पिछली सरकार में भी मैं एमएलए था, हमने बस स्टैण्ड बनाया, 20 लाख मैंने दिये और 20-25 लाख सांसद महोदय ने दिये, लगभग 45 लाख लगाकर बाउंड्री वाल होकर बस स्टैण्ड पड़ा है, लेकिन विभाग द्वारा उस पर कुछ नहीं किया जा रहा, सरकार को उस पर ध्यान देना चाहिये ताकि लोगों को उसका लाभ मिल सके। माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे अवसर दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, आभार, जय हिन्द।

श्री सभापति: बहुत-बहुत धन्यवाद। श्री रफीक खान।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): सभापति महोदय, आपने मुझे 2023-24 के बजट पर बोलने का मौका दिया, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं, धन्यवाद देता हूं। हिन्दुस्तान के सबसे बड़े राज्य के मुख्य मंत्री ने एक ऐसा बजट पेश किया, राजस्थान भौगोलिक स्थिति के हिसाब से देश का सबसे बड़ा राज्य है। राजस्थान का बहुत बड़ा इतिहास रहा है, चाहे आजादी का समय हो, चाहे दुश्मनों से लड़ाई का जब-जब मौका पड़ा, राजस्थान के शूरवीरों ने आगे होकर अपना नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज किया है। पिछले चार साल में दो साल कोविड जैसी गम्भीर महामारी से लड़ते-लड़ते गुजर गये, बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ा, फिर भी मैं आप सबको यह कह सकता हूं कि ये जितनी भी बातें कह रहे हैं, इन सब बातों पर एक जवाब भारी है कि पूरे हिन्दुस्तान की जीडीपी की जब बात होती है तो राजस्थान राज्य की जीडीपी पूरे देश में दूसरे नंबर पर आती है। बीजेपी शासित बहुत सारे प्रदेश हैं, एक प्रदेश यहां से आगे नहीं है। बजट पर जितना भी डिस्कशन कर लें, जितनी भी क्रिटिसिज्म कर लें, लेकिन इस बात का कोई जवाब नहीं है कि अकेला आंध्र प्रदेश हमसे आगे है। राजस्थान जीडीपी के मामले में पूरे हिन्दुस्तान में दूसरे नंबर पर है। यह एक मुख्य मंत्री के कुशल प्रबंधन और

(श्री रफीक खान)

मुख्य मंत्री की दूरगामी सोच का नतीजा है। मैं यहां एक शेर भी मुख्य मंत्री जी के लिए बोल देता हूं-

'यह कैसा असर है तेरे जज्बा ए खामोश में,
हर शख्स खिंचा चला आता है तेरे आगोश में।'

बजट के लिए भी एक शेर कह देता हूं, जैतारण से आने वाले माननीय सदस्य, कविता पढ़ दी थी आपने, मेरा शेर भी सुन लो।

'चन्द खुशबू के दीये साथ में ले आये हैं,
गुलों से भरा दामन ए सौगात ले आये हैं।'

ऐसा बजट दिया है मुख्य मंत्री अशोक गहलोत जी ने। यह बजट नहीं है, यह सौग़ातों का पिटारा है जो मुख्य मंत्री जी ने यहां दिया है और एक एक बात के लिए आपको हां कराऊंगा कि क्या यह देना चाहिये था या नहीं देना चाहिये था? शुरुआत करता हूं 100 यूनिट बिजली से ...(व्यवधान) आप बोलोगे कि फ्री देनी चाहिये या नहीं देनी चाहिये? कोविड जैसे कठिन समय में आप सब लोगों ने और हम सबने मिलकर मुख्य मंत्रीजी से रिक्वेस्ट की कि, मुख्य मंत्रीजी, बिजली में राहत दो। दो महीने का बिल कम कर दो, तीन महीने का बिल कम कर दो। कोविड लंबा चला गया, छह महीने का बिल कम कर दो। मुख्य मंत्री जी ने सबकी सुनी और खाली 2-4 महीने का बिल कम नहीं किया, राजस्थान के हर कंज्यूमर को 50 यूनिट फ्री कर दी और मुझे यह कहने में गर्व है कि उससे खाली एक आम आदमी लाभान्वित नहीं है, जो इस हाउस में बैठे हैं, वे सब आदमी और राजस्थान का हर बाशिंदा उस स्कीम से लाभान्वित है। (व्यवधान) आपको मिला या नहीं मिला 50 यूनिट का फायदा, मिला ... (व्यवधान) अविनाश जी हां बोल रहे हैं।

श्री सभापति: आपस में बात नहीं।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): अब तो 100 यूनिट बिजली का वादा कर दिया। सभापति महोदय, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जब 50 यूनिट कम की गई तो उससे 38 लाख कंज्यूमर का बिल जीरो हो गया। 50 यूनिट का फायदा आम आदमी को जो हुआ वह तो हुआ ही, लेकिन 38 लाख कंज्यूमर का बिल जीरो हो गया और अब 100 यूनिट बिजली से क्या होने जा रहा है, उसके बारे में भी थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहता हूं। 100 यूनिट बिजली से राजस्थान की इकोनोमी पर और राजस्थान के आम आदमी पर

(श्री रफीक खान)

क्या प्रभाव पड़ेगा? यंग बच्चे सुन रहे हैं, इनको भी पता लगना चाहिये कि मुख्य मंत्री जी सोशल सिक्योरिटी की तरफ ध्यान देते हैं। मुख्य मंत्री जी ने युवाओं का, बुजुर्गों का, गृहिणियों का, बच्चों का, बेरोजगारों का ध्यान रखकर, सोशल सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए यह बजट प्रस्तुत किया।

100 यूनिट बिजली का क्या प्रभाव पड़ रहा है, सभापति महोदय, जब 100 यूनिट बिजली फ्री हो जायेगी तो एक करोड़ चार लाख परिवारों को फायदा मिलेगा और उनका बिल जीरो हो जायेगा। क्या इस बात में आप एग्री नहीं कर सकते? आप हां नहीं भर सकते हैं कि मुख्य मंत्री जी ने यह एक जोरदार काम किया? इस महंगाई के समय में, बेरोजगारी के समय में आम आदमी को जब जरूरत है, उस वक्त एक शख्स ने सोचा और सोच समझकर यह फैसला लिया कि मैं आम आदमी के साथ खड़ा हूं और मैं राजस्थान के रहने वाले हर परिवार को 100 यूनिट का फायदा दूंगा। फायदा हर एक आदमी को होगा लेकिन एक करोड़ चार लाख से ज्यादा कंज्यूमर राजस्थान में फ्री हो जायेंगे और कोई बड़ी बात नहीं कि जो 100 यूनिट बिजली से ऊपर जा रहे हैं, वह भी दो कनेक्शन लेकर या मितव्ययता बरत कर फ्री के दायरे में आने की कोशिश करेंगे। मैं धन्यवाद दूंगा मुख्य मंत्रीजी को कि इस समय अगर किसी ने आम आदमी की सोची तो वह मुख्य मंत्री अशोक गहलोत जी ने सोची। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप अपना चालू रखें।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): सभापति महोदय, चिरंजीवी योजना राजस्थान की ऐसी स्कीम है, यह सारे के सारे क्रिटिसिज्म तो कर रहे हैं, इनकी जुबान, दिमाग और दिल साथ नहीं दे रहा है। चिरंजीवी का नाम लेते हुए जुबान लड़खड़ा रही है। चिरंजीवी योजना राजस्थान की वह योजना है जिसको अगर ये लोग चाहें तो पूरे देश में लागू कर सकते हैं, हर आदमी को फायदा दे सकते हैं। चिरंजीवी की कापी करो और सीखो ...(व्यवधान) बैठो, बैठो, बहुत देर सुना है आपको, मैं आपकी सारी बात सुनूंगा बाद में, एक-एक बात का जवाब दूंगा, बीच में नहीं। (व्यवधान)

श्री सभापति: एक दूसरे का जवाब देने की बात नहीं है ...(व्यवधान) माननीय सदस्य, यह गलत है। (व्यवधान) मेरी बात सुनिए। माननीय सदस्य, सुनिए आप, यह परम्परा गलत है।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): चिरंजीवी योजना का क्रिटिसिज्म करोगे तो क्षेत्र में जनता मारेगी। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, यह परम्परा ठीक नहीं है। (व्यवधान)

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): चिरंजीवी योजना के बारे में मत बोल देना, चिरंजीवी का विरोध कर दिया तो पब्लिक पकड़ कर मारेगी।

श्री सभापति: आप इधर देख कर बात कीजिए।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): इनको भी बताना जरूरी है, इन्होंने बहुत सारा काव्य पाठ कर दिया है।

श्री सभापति: वह मेरे माध्यम से ही सुनेंगे।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): सभापति महोदय, चिरंजीवी योजना वह योजना है, 2018 से पहले मैंने देखा है और आप सबने देखा होगा जब किसी परिवार में कोई आदमी गंभीर बीमारी से त्रस्त हो जाता था तो वह परिवार जमीन, जायदाद, दुकान, मकान बेच देता था, यहां तक कि औरतें जेवर बेच देती हैं, दर्शक दीर्घा में जो बच्चे बैठे हैं, ये इसके गवाह हैं, जेवर बेच देती हैं कि मैं मेरे परिवार के आदमी का इलाज कराऊंगी।

श्री सभापति: वे माननीय सदस्य हैं, बच्चे मत बोलिये।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): मैं दर्शक दीर्घा के स्टूडेंट्स की बोल रहा हूं।

सभापति महोदय, इलाज कराने के नाम पर सम्पत्ति और जायदाद बिक जाती थी। मुख्य मंत्री अशोक गहलोत ने इस बात के मर्म को समझा और समझकर यह फैसला किया और ऐसी योजना लेकर आये जो राजस्थान के हर घर को फायदा देकर गयी। पिछले साल चिरंजीवी योजना में 30 लाख परिवारों ने फ्री इलाज कराया है। साढ़े आठ सौ रुपये दें। जो आदमी बीपीएल में रजिस्टर्ड है, उसे एक रुपये देने की जरूरत नहीं है, जिसके पास राजस्थान का जन आधार है, राजस्थान का आवास-प्रमाण पत्र है, उसको सरकारी हास्पिटल में एक पैसा देने की जरूरत नहीं है और अवाम जिसने प्रीमियम देकर चिरंजीवी योजना में अपना रजिस्ट्रेशन करा रखा है, राजस्थान के 90 प्रतिशत लोग इस स्कीम का फायदा उठा रहे हैं। इसमें पहले 10 लाख तक की बीमारी का इलाज फ्री था। मेरे मित्र के यहां पर एक आदमी काम करता था। अभी बजट से पांच-सात दिन पहले की बात है। किसी कारण से मेरे घर आये थे, वे बोले कि मेरा एक मजदूर है, उसको अस्पताल से छुट्टी दे दी। उसका प्राइवेट अस्पताल में इलाज हो रहा था और वे बोले कि उसके कैंसर था। 10 लाख रुपये तक का तो उसका इलाज हो गया और वे कह रहे हैं कि इससे ऊपर का कोटा वह पूरा नहीं कर सकता।

(श्री रफीक खान)

मुझे लगता है कि वही बात मुख्य मंत्री जी ने सुन ली और इस दस लाख को 25 लाख रुपये कर दिया। राजस्थान की धरती पर इससे बड़ा काम कुछ नहीं हो सकता। आम आदमी की आवाज को पहचाना और चिरंजीवी योजना में यह बढ़ोतरी, इससे बड़ी बात राजस्थान के इतिहास में न कभी हुई और न कभी होगी। जितने भी साथी यहां बैठे हैं, 25 सांसद राजस्थान की जनता ने चुनकर भेजे हैं, आप सबका दायित्व बनता है कि केन्द्र में आवाज उठायें कि चिरंजीवी योजना को नेशनल लेवल पर लागू करें। मुख्य मंत्री अशोक गहलोत को कापी करें और उन्हें धन्यवाद दें।

उज्ज्वला योजना, इन्होंने अभी उज्ज्वला योजना के बारे में बहुत बात की, इतने कनेक्शन दे दिये। प्रधान मंत्री जी ने कितने कनेक्शन दे दिये? वे सारे चूल्हे लटाणो पर पड़े थे। 400 रुपये का सिलेण्डर 1100 रुपये का हो गया। जिसको भी सिलेण्डर दिया, यह तो वैसे कर दिया जैसे रिलायंस ने जिओ का कनेक्शन बांटा कि फ्री कनेक्शन, फ्री कनेक्शन और बाद में एकदम से बिल चालू कर दिये। ऐसे मार्केटिंग की, कनेक्शन तो दे दिये, लेकिन गैस कहां से आयेगी, इसका इन्तजाम नहीं किया। इस बात को अगर किसी ने समझा तो मुख्य मंत्री अशोक गहलोत ने समझा और कहा कि प्रधान मंत्री दें या नहीं दें, मैं उज्ज्वला योजना के लाभार्थी को 500 रुपये में सिलेण्डर दूंगा। आप लोग जो कनेक्शन देने की बात करते हैं, इन 500 रुपये से सहमत हैं, तो जायें और केन्द्र सरकार से मांग करें कि उज्ज्वला योजना में पूरे हिन्दुस्तान में 500 रुपये में सिलेण्डर दें। अगर आम आदमी के प्रति आपके अन्दर जरा-सी भी मानवता है और जरा-सी भी जागरूकता है, आम आदमी का भला करना चाहते हैं तो यह बात उठायें कि उज्ज्वला योजना के कन्ज़ूमर को पूरे हिन्दुस्तान में 500 रुपये में सिलेण्डर दो। इसको बुलन्द आवाज में उठाओ।

किसानों की बात करते हैं। सभापति महोदय, इन्होंने किसानों का तो बजट काट दिया। मैं अभी उसकी डिटेल दूंगा कि कितने पैसे काट दिये? मुख्य मंत्री जी ने समझा, पहली बार यहां सत्ता में आये, पहला बजट। सभापति महोदय, मैं पहली बार का विधायक हूं, जब मैं आया तो मुझे बहुत सारी बातों का पता नहीं था। मुख्य मंत्री जी ने अनाउंसमेंट किया कि जब तक मैं राज में हूं, इन पांच सालों में एक रुपये की बढ़ोतरी नहीं करेंगे और फिर एक हजार यूनिट प्रतिमाह उनको फ्री दी, अब इस बजट में उसको दो हजार यूनिट कर दिया। किसानों के लिए इससे ज्यादा बड़ा काम नहीं हो सकता, बिजली की राहत।

(श्री रफीक खान)

ओल्ड पेंशन स्कीम। कर्मचारी बाहर बोलते हैं, अगर बीजेपी आ गयी तो ओल्ड पेंशन स्कीम खतम हो जायेगी। उनको डर है, भय है। एक आदमी जिसने पूरा जीवन नौकरी में लगा दिया और रिटायरमेंट के बाद उसको पता लगे कि उसके भविष्य का कोई पता नहीं है। मुख्य मंत्री ने इस मर्म को समझा और इस मर्म को समझकर ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की। इस बजट में उन लोगों के लिए भी कर दी जो कि बोर्ड और दूसरे निगमों के कर्मचारी हैं। आज मैं यह कह सकता हूं कि साढ़े पांच लाख से ज्यादा लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं और उनको इस बात का फायदा मिल रहा है।

श्री सभापति: कृपया तीन मिनट में बात समाप्त कीजिये।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): अभी तो बहुत सारी चीजें हैं। मैं एक स्कीम और बता देता हूं। कोविड के अन्दर जितने भी आदमी मारे गये हैं, वह आदमी किसी भी पार्टी का हो सकता है। मुख्य मंत्री जी ने कहा कि उसके आश्रितों को नौकरी दूंगा। अगर वह अनाथ है तो मैं नौकरी दूंगा, मैं उस आदमी का ख्याल रखूंगा और मुख्य मंत्री ने नौकरी देने का वादा किया।

मैं आपको एक बात और बता दूं। एजुकेशन का मसला, वह गरीब आदमी जिसके बच्चे में बहुत टैलेंट है, वह बहुत मेधावी है और बाहर पढ़ना चाहता है, जेब के अन्दर पैसे नहीं हैं। बाहर की यूनिवर्सिटीज का जब खर्चा पता करता है तो पता लगता है कि तीन साल में एक करोड़ रुपये चाहिए। मुख्य मंत्री जी ने इस बात को समझा और राजीव गांधी स्कालरशिप के नाम से एक नयी योजना शुरू की और 200 स्टूडेंट्स को, जिनका अगर अपनी प्रतिभा के आधार पर सलेक्शन बाहर के किसी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन में हो जाता है तो हम उसको 80 लाख रुपये से लेकर 01 करोड़ रुपये तक का अनुदान देंगे। उस गरीब आदमी की सुनने वाला कोई नहीं था और 200 स्टूडेंट्स उसमें पूरे नहीं हुए तो आठ लाख से ऊपर वालों को भी देंगे। मुझे खुशी है कि इस बजट में उन्होंने यह संख्या बढ़ाकर 500 कर दी है। आम आदमी की अगर इस समय कोई सोचने वाला है तो वह मुख्य मंत्री अशोक गहलोत है।

बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे लोगों ने कह दीं, लेकिन कुछ बातें रह जायेंगी। इसलिए मैं बीच में दूसरी बात और करना चाहता हूं। आपने अडानी जी की बात बहुत की। आपने अडानी जी की बातें बहुत जोरदार ठोकीं। मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूं कि अडानी जी के 64 हजार करोड़ किसके माफ

(श्री रफीक खान)

किये, इसकी तो इनक्वायरी कर लें। किसी ने किसानों के तो माफ नहीं किये। अडानी के 64 हजार करोड़ रुपये कैसे माफ हुए? पूरे व्यापारियों के 11 लाख करोड़ रुपये माफ कर दिये, किसानों और गरीब आदमी का कर्जा माफ नहीं हो रहा है लेकिन कारपोरेट घरानों के 11 लाख करोड़ माफ कर दिये। 64 हजार करोड़ अकेले अडानी के माफ कर दिये, फिर अगले साल 84 हजार करोड़ माफ कर दिये। मैं पूछना चाहता हूं कि कैसे माफ कर दिये? (व्यवधान) इसकी जांच करायी जाये।

श्री सभापति: प्लीज सुनिये।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): किस वजह से माफ कर दिये? जनता माफ नहीं करेगी।

श्री सभापति: प्लीज बैठिये। जब आपका टर्न आये तो बोल देना। आप एक मिनट में अपनी बात समाप्त कीजिये।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): प्रधान मंत्री जी ने दुष्यंत कुमार की एक गजल की एक पंक्ति पढ़ दी और भारत जोड़ो के नाम पर पढ़ दी। आप भी आ गये, बहुत देर से आये, मैं आपका इन्तजार कर रहा था। दुष्यंत कुमार की है। सात शेरों की गजल है। प्रधान मंत्री जी ने एक शेर पढ़ दिया। मैं उसके कुछ और शेर पढ़ना चाहता हूं।

'तुम्हारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं,
कमाल ये है कि फिर भी तुम्हें यक़ीन नहीं'

यह बड़ा ठहाके लगा के कहा है। मैं आपको अगला मिसरा बताता हूं। उसी गजल का अगला मिसरा।

'मैं बे-पनाह अंधेरों को सुबह कैसे कहूं,
इस काली रात को सुबह कैसे बता दूं,
मैं इन नज़ारों का अंधा तमाशबीन नहीं।'

मैं अंधा नहीं हूं कि मुझे ये नजारे भी नहीं दिखें जो बाजार में सच्चाई चल रही है।

तेरी ज़बान है झूठी जम्हूरियत की तरह।

झूठी जुम्हूरियत का मतलब है कि असत्य लोकतंत्र। असत्य लोकतंत्र जहां ईडी का भय, जहां इनकम टैक्स का भय, जहां सीआईडी का भय, हर चीज का खौफ। लोकतंत्र में आदमी है नहीं।

(श्री रफीक खान)

'तेरी ज़बान है झूठी जम्हूरियत की तरह,
तू इक ज़लील सी गाली से बेहतरीन नहीं।'

यह उसी का तीसरा शेर है।

तुम्हीं से प्यार जताएं तुम्हीं को खा जाएं।

आडवाणी जी की तरह।

'तुम्हीं से प्यार जताएं तुम्हीं को खा जाएं।
अदीब यूं तो सियासी हैं पर डैश-डैश नहीं।'

मैं नाम नहीं लेना चाहता। कई जनों ने नाम लिया था। ये उसका फायदा उठायेंगे। आप दुष्यंत कुमार का पढ़ना और पत्रकारों से भी गुजारिश करता हूं कि पूरी गजल पढ़ना। (व्यवधान) यह इसी का है।

'तुझे क़सम है ख़ुद को बहुत हलाक न कर,
तू इस मशीन का पुर्ज़ा है तू मशीन नहीं।'

सिस्टम का पुर्जा है, आती-जाती सरकारें हैं, परमानेंट नहीं है। प्रधान मंत्री परमानेंट नहीं टिकेंगे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): सभापति महोदय, शायरी का एक घंटा तय कर लीजिये। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय, जो आया है बीच में ...(व्यवधान) उसका जवाब दे रहे हैं।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): जैतारण वाले सारी कविता बोल सकते हैं। मैं नहीं बोल सकता?

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): ये शायर कहां से आ गये?

श्री सभापति: मैं बता रहा हूं, सुनिये। माननीय सदस्य, आपका समय हो गया है। आप सुनिये। माननीय उप नेता, प्रतिपक्ष, आप बाहर थे तो इन्होंने लिंक किया माननीय प्रधान मंत्री जी ने जो गजल का एक मिसरा पढ़ा, उसके साथ लिंक किया।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): पूरी गजल नहीं पढ़ी है मैंने।

श्री सभापति: आप खतम कीजिए। समाप्त कीजिए।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): पूरी गजल मैंने अभी भी नहीं पढ़ी है। (व्यवधान) आप कहते हैं तो बंद कर देता हूं। इतना नाराज मत होइए। प्रधान

(श्री रफीक खान)

मंत्री जी न ज्ञान कोनी हो कि आगे की पंक्तियां के हैं? म्हे थोड़ो साहित्य से जुड़योड़ो आदमी हूं। म्हे कहयो बहुत अच्छो शेर है पूरी गजल तो पढ़नी चाहिजे। आगे नहीं पढ़ूंगा। आगे पढ़ूंगा तो और बहुत सारी बात हो जाएगी। कांट्रेक्चुअल लेबर...(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आपका टाइम हो गया प्लीज।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): मेरी कांस्टीट्यूएंसी की दो-तीन बातें और कर लेता हूं। छोटी-सी डिमांड्स हैं, वह सुन लीजिए। मुख्य मंत्री जी ने सब कुछ दिया और इतना अच्छा बजट, जो देश व दुनिया को नई दिशा देगा। मैं पूरे दावे के साथ में यह कह सकता हूं कि पूरे देश के राज्यों को इस बजट का स्मरण करना चाहिए।

सभापति महोदय, मेरे पास में दूर-दूर से विधायकों के फोन आये हैं कि इंग्लिश ट्रांसलेट करके हमें दे दीजिए, इस बजट को हम देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं। लोग इस बजट को रिलिजियस किताब की तरह पढ़ना चाहते हैं।

मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि यूनानी डाक्टर के लिए हमने भर्ती की जगह नहीं निकाली। मैं यह एक डिमांड करना चाहता हूं कि हमने सबमें कुछ न कुछ दिया है तो मेरी आपके माध्यम से गुजारिश है कि यूनानी डाक्टर की 350 पोस्टें हैं, वे भी निकाली जाएं ताकि जो लोग आलरेडी लगे हुए हैं, उनको अपनी नौकरी मिल सके।

एक मदरसा पैरा टीचर्स के बारे में भी मैं आवाज उठाना चाहता हूं। मदरसा पैरा टीचर्स के लिए भी कोई न कोई परमानेंसी का जरिया ढूंढा जाए और उनको परमानेंट किया जाए।

एक मेरी कांस्टीट्यूएंसी का बहुत ज्वलंत मुद्दा है आगरा रोड पर। आगरा रोड पर बहुत-सी कालोनियां बस चुकी हैं। राजस्थान पत्रिका और एक केस की वजह से इकोलोजिकल की उसमें अटकी हुई है। मैं सदन के माध्यम से गुजारिश करना चाहता हूं कि इसको इकोलोजिकल से जल्दी से जल्दी निकाला जाए, ताकि वहां पर हजारों की तादाद में लोगों ने मकान बना लिए हैं और लाखों की तादाद में लोग रह रहे हैं, वे बेघर नहीं हों। आज पोजिशन ये है कि जेडीए का अधिकारी जाता है और एक बनते हुए मकान को जो बहुत छोटी सी अपनी पूंजी के साथ मकान बनाना चाहता है, उसका मकान तोड़ देता है। मेरी गुजारिश है कि वहां कोई तोड़फोड़ नहीं की जानी चाहिए। उन लोगों को

(श्री रफीक खान)

किसी तरीके से रेगुलराइज करने की छूट दी जानी चाहिए। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: धन्यवाद। श्री बलवान पूनियां।

श्री बलवान पूनियां (भादरा): सभापति महोदय, पांचवां बजट हमने देखा। हमारे विधान सभा क्षेत्र के लिए काफी सारी घोषणाएं हुईं। जनता ने जिस उम्मीद के साथ हमें राजस्थान की विधान सभा में भेजा, उनमें से बहुत सारे काम इस पांचवें बजट में हुए लेकिन अभी-भी बहुत सारी हमारी मांगें किसानों की पेंडिंग हैं। उनको किये बगैर, किसानों के खाले अगर नहीं बने तो अमरसिंह ब्रांच, सिद्धमुख नहर, नोहर फीडर के किसान बर्बाद हो जाएंगे। इसलिए मेरी इल्तजा है कि हमारे पूरे टूटे हुए खाले जो 2004, 2005, 2006 में बने, उनको दोबारा बनाया जाए।

भादरा शहर के चारों तरफ घनी आबादी की वजह से कोई आदमी भीतर से ढंग से क्रोस नहीं कर सकता। भारी वाहन भी नहीं जा सकता। पराली के ट्रेक्टर भी नहीं जा सकते। आये दिन पंजाब से पराली के ट्रैक्टर साहवा के लिए निकलते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे भादरा के चारों तरफ रिंग रोड बने। डूंगराना से भाड़ी मोड़ की सड़क है जो काफी गांवों को जोड़ती है। वह सड़क भी अभी तक नहीं बनी है, उस सड़क को भी सरकार जोड़ने का काम करे। उसका सुदृढ़ीकरण व चौड़ाईकरण करे। गोगामेडी जो धार्मिक स्थल है, पांचों पीरों की धरती में गोगामेडी भी एक ऐसी जगह है जहां साम्प्रदायिक सद्भाव का मेला लगता है, लाखों-लाख लोग आते हैं। पहले ददरेवा जाते हैं, फिर गोगामेड़ी जाते हैं। इसलिए मेरी सरकार से मांग रहेगी कि वाया हुणतपुरा होते हुए गोगामेड़ी से सीधी ददरेवा सड़क जोड़ी जाए।

सभापति महोदय, भादरा में एक कन्या महाविद्यालय चल रहा है। संस्था ने उसको खड़ा किया और अब संस्था के लोग बुजुर्ग हो गए। उनमें अध्यक्ष पिछले दिनों चल बसे। इसलिए हमारी मांग है और समाज की मांग है कि इसका सरकारीकरण हो जाए। मुख्य मंत्री जी ने 300 के करीब कालेज खोले हैं तो इस ग्रामीण कन्या महाविद्यालय को भी गवर्नमेंट कालेज में तब्दील कर दिया जाए।

मेरे विधान सभा क्षेत्र के दो बड़े गांव हैं घेऊ और मलसीसर, जिसके पास पाइप लाइन भी है और वाटर वर्क्स भी दोनों के एक हैं। मैं चाहता हूं कि

(श्री बलवान पूनियां)

उसकी सड़क भी बन जाए। हमारी यह भी मांग रहेगी कि जिस तरह से हरियाणा हमारे नजदीक है और हरियाणा से आये दिन आपराधिक गतिविधियां बढ़ रही हैं, इसलिए गांधी बड़ी में, सोनी मार्केट, भादरा और ड्ंगराना उप-तहसील में चौकी भी खोली जाए, जिससे कानून व्यवस्था का पैरा ठीक रहे। चलते-चलते हम यह चाहते हैं कि जो मुख्य मंत्री महोदय ने घोषणा की है कि एक नशा मुक्ति केन्द्र हर जिले में बनेगा, मैं समझता हूं कि वह नशा मुक्ति केन्द्र भादरा में खोला जाए ताकि नौजवान जो नशे की लत से मशगूल हो गए हैं, उनको उसमें एडमिट कराया जा सके।

सभापति महोदय, खूब दिया खेल पर, लेकिन खेल पर पिछले चार साल में मैं भी ज्यादा ध्यान कंसंट्रेट नहीं कर पाया। राजस्थान सरकार से हमें विधान सभा क्षेत्र के लिए कुछ नहीं मिला। मेरी मांग है कि सलीम दुर्रानी आवासीय स्पोर्ट्स स्कूल भादरा में खोला जाए, जिससे खेल की गतिविधियां भी नौजवानों के लिए बढ़ें।

सामाजिक सुरक्षा में जिस तरीके से मुख्य मंत्री जी ने घोषणा की, मैं समझता हूं कि अभी-भी एक वर्ग अछूता है, वह है जिनके बेटे व बेटियां सरकारी नौकरी में हैं, अभी उन बुजुर्गों को पेंशन नहीं मिल रही। इस पूंजीवादी युग में, इस भौतिकतावादी युग में ये चीज कतई ठीक नहीं है कि बेटे-बेटी नौकरी में है, उसके मां-बाप को पेंशन नहीं दी जाए। उन बुजुर्गों को भी पेंशन दी जाए। मैंने पहले भी मांग की है और अब मैं फिर मेरी मांग को दोहरा रहा हूं। पुरजोर तरीके से सरकार इसको पूरी करे।

ड्ंगराना, सेरड़ा, भरवाना और मलखेड़ा चार ऐसे बड़े गांव हैं, ड्ंगराना में तो उप-तहसील है, इन गांवों में पीएचसी खोली जाए ताकि आने वाले समय में राइट टू हैल्थ जो कानून आ रहा है, उस कानून का पालन ढंग से हो सके।

सभापति महोदय, मैं मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने पूरी की पूरी प्लेसमेंट एजेंसियों को खतम किया। मेरी मांग रही थी 2019 के पहले सदन में कि ये प्लेसमेंट एजेंसी वाला बीच में दलाल कौन है, जो पैसे खा जाता है, नौजवान का शोषण करता है, प्लेसमेंट एजेंसी खतम कीजिए। मैं मुख्य मंत्री से चाहता हूं कि प्लेसमेंट एजेंसी के लिए शर्त नहीं लगाएं कि 31 दिसम्बर, 2021, उसके बाद भी अगर कोई प्लेसमेंट एजेंसी के जरिये नौकरी लगा है तो उसकी एजेंसी भी खतम करके सीधा सरकारी सुविधा

(श्री बलवान पूनियां)

पर उसको रखा जाए। इसलिए मेरी मांग है कि सन् 2000 में जब आप मुख्य मंत्री थे, उस समय हमारे नहरी क्षेत्र में ठेका प्रथा शुरू हुई थी उस ठेका प्रथा को आप ही खतम कीजिए ताकि जो उपभोक्ता संगम के चुनाव हैं, वह चुनाव बंद हों और बेलदार, चौकीदार की नियुक्ति हो। यह मेरे विधान सभा क्षेत्र की मांगें हैं, जो अभी तक पूरी नहीं हुई। मैं कोशिश करूंगा और मांग करूंगा कि सरकार इन क्षेत्रों को आज भी सफल बनाने का काम करे। मेरी मांग पूरी करे।

सभापति महोदय, बिजली की बात आई। साथियों ने चर्चा की कि दो हजार यूनिट बिजली फ्री होगी किसान की। नि:संदेह किसान को फायदा होगा, लेकिन हम मांग करते हैं कि जिस तरीके से पिछले बजट में घोषणा की थी कि आपको जल्दी से जल्दी कनेक्शन मिलेगा, उस कनेक्शन की कछुआ स्पीड है, उस स्पीड को बढ़ाने की जरूरत है। ट्रांसफार्मर आज भी समय पर नहीं मिल रहे हैं, तार आज भी समय पर नहीं मिल रहे हैं, पोल आज भी समय पर नहीं मिल रहे, वह समय पर मिले, यह हमारी मांग है। हमारी मांग है कि जीएसएस की संख्या बढ़ाई जाए। हमारी मांग है कि जिस तरीके से आप बार-बार चर्चा कर रहे हैं कि हम राजस्थान में बिजली उत्पादन में एक नंबर पर हो गए, वह बिजली हमें मिले, उत्पादन का फायदा राजस्थान की जनता को मिले। घरेलू बिजली में जो आपने 50 से 100 यूनिट किया, इस बात के लिए धन्यवाद। हम चाहते हैं कि घरेलू बिजली के लिए हमारे पास फोन नहीं आये कि बिजली चली गयी, बिजली आयी नहीं। आप कोयले का प्रबन्ध कहीं से भी कीजिए, कैसे भी कीजिए, कोयले का प्रबन्ध करके बिजली उत्पादन का काम सरकार मजबूती के साथ करें।

(समय: 17.58 बजे)

(श्री राजेन्द्र पारीक, सभापति, पदासीन)

सभापति महोदय, मैं यह भी चाहता हूं कि जो ऋण की बात आपने की। आपने कहा कि राजस्थान में डैट रिलीफ एक्ट लेकर आएंगे और एक्ट आने के बाद एक कमीशन नियुक्त होगा और कमीशन का अध्यक्ष रिटायर्ड जज होगा। मैं बिलकुल नहीं चाहता कि रिटायर्ड जज कमीशन का अध्यक्ष हो। कमीशन का अध्यक्ष हो कोई प्रगतिशील किसान, कमीशन का अध्यक्ष हो कोई युवा नेता, कमीशन का अध्यक्ष हो कोई एमएलए और कोई एमपी, कमीशन का अध्यक्ष कतई रिटायर्ड जज नहीं होना चाहिए। कमीशन का अध्यक्ष, अगर

(श्री बलवान पूनियां)

राजस्थान के किसान को कर्ज मुक्ति की बात से आगे लेकर के जाना है, उसकी जमीनों की कुर्की नहीं रुके तो कोई ऐसा जन-प्रतिनिधि हो जो किसान का यह दर्द महसूस करे कि ये किसान बर्बाद हो रहे हैं, इनकी जमीनें कुर्क हो जाती हैं। मैं चाहता हूं कि राजस्थान में रोडा एक्ट को पूर्ण रूप से बंद किया जाए। जिक्र बार-बार सुनते हैं। जहां मजबूत जन-प्रतिनिधि नहीं है, वहां आज भी रोडा एक्ट के तहत कुर्कियां निकल रही हैं। उन कुर्कियों को रोका जाए।

मेरी मांग है कि जिस तरीके से आपने चिकित्सा पर जिक्र किया, मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना का दायरा बढ़ाया, इस बात के लिए तो धन्यवाद, लेकिन मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना में जो दुकानें लगाई हुई हैं डाक्टर्स ने उन दुकानों को भी हमें चिह्नित करना है। मैंने पिछली बार भी जिक्र किया था, पीयूष हास्पिटल सांगानेर में, मेरे विधान सभा क्षेत्र का आदमी, उसने खुद ने महसूस किया है, उसको 99 हजार रुपये का बिल बनाकर दे दिया, जबकि उसका हास्पिटल चिरंजीवी योजना से जुड़ा हुआ था। चिरंजीवी योजना का नाजायज फायदा उठाने वाले ऐसे लोग भी बैठे हैं। आदमी के सिर में दर्द है तो उसकी जांच करा लेंगे और जांच कराकर कहेंगे कि आपके सिरदर्द का इसलिए पता कर रहे थे कि आपके टखने में भी तो दर्द नहीं है, उसकी वजह से सिर दर्द हो। सारी जांच कराकर, उसके पैसे खाते में डलवा लेते हैं। इन चीजों को दुरुस्त करने की जरूरत है। बाकी मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना और मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना में राजस्थान की जनता को जो फायदा हो रहा है वह वास्तव में ही काबिले-तारीफ है।

मेरे विधान सभा क्षेत्र में दीपलाना, घेहूं और शेरपुरा तीन पीएचसी ऐसी बनी थीं, दीपलाना तो दस साल पहले बनी थी, लेकिन वह अटक गई। मैं चाहता हूं कि चिकित्सा विभाग के सारे काम एनएच.एम. से करवाने के बजाय पीडब्ल्यूडी से करवाइये, ताकि जनप्रतिनिधियों का कंट्रोल रहे, प्रशासन का कंट्रोल रहे। एन.एच.एम. का कोई एक्स ईएन, ए ईएन नहीं मिलता है, आप किसको अपनी बात बताएंगे। आज उप स्वास्थ्य केन्द्र बन रहे हैं, सीएचसी बन रही है, पीएचसी बन रही है, डायरेक्ट बजट उनके वहां गया है, तो उसका कोई धणी-धोरी नहीं है। ठेकेदार बीच में काम छोड़कर भाग जाता है।

सरकार ने शुद्ध के लिए युद्ध की घोषणा की, लेकिन दूध नहीं जहर पीता है इंडिया, उत्पादन 14 करोड़ लीटर, लेकिन खपत 64 करोड़ लीटर।

(श्री बलवान पूनियां)

मुख्य मंत्री जी ने पहले दो दिन के लिए घोषणा की थी बच्चों को स्कूल में दूध पिलाने की। मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र के गांव छावनी बड़ी स्कूल में शुरुआत भी करके आया था। सभापति महोदय, योजना जोरदार है। गरीब के बच्चे ने दूध देखा है, पूरे राजस्थान में देखेगा, पर दूध की जगह पिलायेंगे क्या, यह चीज सुनिश्चित करनी है। जिस तरीके से डब्ल्यूएचओ की चेतावनी है कि मिलावट बंद नहीं हुई तो 87 प्रतिशत भारतीय 2025 कैंसर में डूब जाएंगे, आज भी एक-एक गांव में 10-10, 20-20, 30-30 लोग कैंसर से पीड़ित हैं। इसलिए इन मिलावट खोर लोगों के खिलाफ मजबूती से कार्रवाई करनी है।

आपने गरीब का जिक्र किया। आप देखेंगे, गांव के चारों तरफ गरीब बसा हुआ है। 1982 में हमारा गंगानगर-हनुमानगढ़ एक जिला था। उस समय के तत्कालीन कलेक्टर ने यह घोषणा कर दी कि यह सारा क्षेत्र वन विभाग है। सभापति महोदय, 1982 में वन विभाग गलत दर्ज किया गया। आज भादरा विधान सभा क्षेत्र के बहुत सारे गांव ऐसे हैं, जिनकी बस्ती वन विभाग में घुस गई। लोग जमीन पर बसेंगे।

श्री सभापति: एक मिनट में समाप्त करें।

श्री बलवान पूनियां (भादरा): सभापति महोदय, आप आये, उससे एक मिनट पहले ही मैं बोलना शुरू हुआ था। मेरे 15 मिनट हैं। अगर 2 मिनट आज तो फालतू भी दो तो, यह लास्ट भाषण है, इसके बाद तो भाषण होने ही नहीं। अब तो दुबारा जीतकर आएंगे तब भाषण देंगे।

वन क्षेत्र में बसे लोगों के लिए श्रीगंगानगर के कलेक्टर ने जो फैसला किया था, राज्य सरकार से हम चाहते हैं देर आये दुरुस्त आये, उस फ़ैसले को देखो, उस फ़ैसले का परीक्षण कराओ। आज स्थिति कब्रिस्तान की, श्मशान भूमि की। पीएचसी खोल रहे हैं, सीएचसी खोल रहे हैं, उप स्वास्थ्य केन्द्र खोल रहे हैं, स्कूल खोल रहे हैं, महात्मा गांधी अंग्रेजी विद्यालय खोल रहे हैं, जगह ही नहीं है। वन विभाग को ऐसी जगह ले जाइये जहां वन विभाग ठीक लगे, वहां वन उगे तो सही। यहां तो सारी घुण्ढल की, कीकर खड़ी है। उन कीकरों को हटाओ और जनता को बसने के लिए, सरकारी मकान बनाने के लिए जगह दें।

सभापति महोदय, मैं कृषि की बात करूं। कृषि के लिए अलग से बजट दिया, इस बात के लिए धन्यवाद। हम चाहते हैं कि प्रधानमंत्री फसल

(श्री बलवान पूनियां)

बीमा योजना में जो लोचा आ रहा है, राजस्थान की सरकार आने वाले समय में मुख्यमंत्री फसल बीमा योजना लेकर आये, ताकि सैटेलाइट का लफड़ा और बीमा न देने का लफड़ा न हो। बीमा कम्पनियां, कि हम चले जाएंगे, बीमा कम्पनी हमारे लिए नहीं आई है, सभापति महोदय। बीमा कम्पनी तो पैसा कमाने के लिए आई हैं। बीमा कम्पनी, जहां हाथ लगेगा वहां लूटेगी। यह बात तो ठीक है 2018 रबी से लेकर अब तक 3100 करोड़ रुपये फसल बीमा क्लेम आया है मेरे ज़िले में, उसमें मेरी अकेली विधान सभा में 1266 करोड़ आया है। फिर भी कहीं न कहीं गड़बड़ कर जाते हैं। 2021 में सैटेलाइट का लफड़ा लेकर आ गए। आज मेरे सैकड़ों पटवार मण्डल ऐसे हैं, दर्जनों पटवार मण्डल ऐसे हैं जहां सैटेलाइट की बजाय क्रॉप कटिंग से बीमा मिलना चाहिए। आपने घोषणा तो करी है कि हम 150 करोड़ रुपये के प्लांट लगायेंगे और रोजाना 500 मैट्रिक टन यूरिया और डीएपी पैदा करेंगे। जब तक यह प्लांट लग जाए, यूरिया व डीएपी बढ़नी शुरू न हो जाए, किसान को यूरिया व डीएपी के लिए लाइन में नहीं लगना पड़े, सरकार यह सुनिश्चित करे।

सभापति महोदय, हम चाहते हैं कि राजस्थान कृषि सम्बल मिशन के अंतर्गत 5 लाख भूमिहीन श्रमिकों को हस्तचालित कृषि यंत्र खरीदने के लिए 5 हजार रुपये प्रति परिवार, 250 करोड़ रुपये व्यय होगा, किस आधार पर हम तय करेंगे उन 5 लाख परिवारों को। यह पारदर्शिता होनी चाहिए। ऐसी-ऐसी जोरदार योजनाएं जो नाम से बहुत अच्छी लगती हैं। यह बात सही है कि खेतिहर मजदूर के पास खुद के यंत्र नहीं हों, सरकार उसको उपलब्ध कराये, लेकिन इसके लिए पारदर्शिता और गाइडलाइन तय हो कि किस तरह से उन परिवारों को चिह्नित किया जाए।

सभापति महोदय, हम चाहते हैं कि बीज के किट बांटे जाएंगे, मिनी किट्स बांटे जाते हैं बीज के। कहते हैं कि भूमिहीन लोगों को दे दिए। भूमिहीन किसमें बोयेंगे? सरकार पहले या तो उन्हें जमीन दे। किट उन किसानों को दिए जाएं जो वास्तव में खेती करते हैं। यह मेरा राजस्थान सरकार को सुझाव है।

सभापति महोदय, डिग्गी के लिए खूब पैसा दिया है। अभी कृषि बजट में घोषणा की है कि हम डिग्गी के लिए 500 करोड़ रुपये और देंगे, पर डिग्गियां हम किसको दे रहे हैं, लाटरी से। जिन लोगों ने डिग्गी बना ली, जिन लोगों ने फार्म लगा दिया, दो साल पहले यह था कि पहले आओ, पहले पाओ।

श्री सभापति: समाप्त करें, प्लीज।

श्री बलवान पूनियां (भादरा): तीन मिनट और देनी पड़ेगी। मेरे चार-पांच कागज ही बचे हैं।

श्री सभापति: बोलने वाले बहुत हैं, एक मिनट में समाप्त करें।

श्री बलवान पूनियां (भादरा): यह राठौड़ साहब आंगली कर रहे हैं, मेरे 12 मिनट ही हुए हैं, 3 मिनट और पड़े हैं। राठौड़ साहब, मैं तो आपकी कितनी इज्जत करता हूं, आप ही घोंचे कर रहे हो। (व्यवधान) मेरे से नाराजगी लोगे तो कोई नेता, प्रतिपक्ष नहीं बनाएगा। (व्यवधान) आपको कौन पूछे, मोदी जी बनाएंगे। कासनिया जी, आप भी बीच में पंगा ले लेते हो यूं ही। सभापति महोदय, किसी का फार्म है, उसकी वरीयता तय की जाए, डिग्गी बनाई जाए।

सभापति महोदय, मधुमक्खी पालन में हनुमानगढ़ ज़िले को शामिल किया जाए। मिड-डे मील की मैं बात करूंगा। मिड-डे मील, आंगनबाड़ी, स्कूल, अंग्रेज़ी माध्यम स्कूल, सब जगह जोरदार तरीके से बांटा जा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं कई ज़िलों में गया हूं, जिस भी ज़िले में जाता हूं मिड्डे मील चैक करता हूं, स्कूलों में मेरी रुचि है। मैं मुख्य मंत्री जी से एक बात कहना चाहता हूं, आपके रहते सामाजिक न्याय की अवधारणा गलत हो जाए, हो ही नहीं सकता। जालौर, पाली, गोडवार, कहीं भी मिड-डे मील बनाने वाली महिला एससी की नहीं है। आपके मार्फत मेरी मांग है सदन से कि आप न्याय करिये, आपसे न्याय की उम्मीद करते हैं। मैं चाहता हूं कि स्कूलों में रिक्त पद हैं उनको भरा जाए। 2 लाख अध्यापकों की...

श्री सभापति: श्री अमृतलाल।

श्री बलवान पूनियां (भादरा): सभापति महोदय, दो मिनट में मेरी बात पूरी कर देता हूं।

श्री सभापति: समाप्त करें। प्लीज, सहयोग करें।

श्री बलवान पूनियां (भादरा): जल जीवन मिशन, 2 लाख अध्यापकों की नियुक्ति की जाए। आपने युवाओं को बजट समर्पित करने की बात कही है। आपने स्कूल खोले, कालेज खोले। 2 लाख भर्तियां और निकालेंगे तब स्कूल व कालेज का काम आगे बढ़ेगा। आपने जल जीवन मिशन दिए। आपने मेरे विधान सभा क्षेत्र में 350 करोड़ रुपये दिए। एचडीपीई पाइपलाइन को अगर काम में नहीं लेंगे, डीआई पाइपलाइन के इंतजार में रहेंगे तो जल जीवन मिशन तेजी से आगे नहीं बढ़ेगा। काम स्लो चल रहा है। डीआई पाइपलाइन के

(श्री बलवान पूनियां)

लिए लाइन लगी हुई है। पूरे देश भर में काम चल रहा है। मेरा सुझाव है कि एचडीपीई पाइपलाइन को आगे बढ़ाया जाए।

श्री अमृतलाल मीणा (सलूम्बर): माननीय सभापति महोदय...

श्री बलवान पूनियां (भादरा): ठेकेदारों को वो ही काम दिए जाएं जिन कामों में प्रगति है। सभापति महोदय, एएनएम भर्ती 2013 पूरी करने की मैं मांग करता हूं। प्रयोगशाला सहायक भर्ती 2018 जो लम्बित है, उसको पूरा करने की मांग करता हूं।

श्री अमृतलाल मीणा (सलूम्बर): सभापति महोदय, आपके आदेश की पालना नहीं हो रही है।

श्री बलवान पूनियां (भादरा): एल.डी.सी. 2013 से वंचित रहे।

श्री सभापति: विराजिए।

श्री बलवान पूनियां (भादरा): 6029 पदों की भर्ती की जाए।

श्री सभापति: अंकित नहीं होगा।

श्री बलवान पूनियां (भादरा): 000

श्री सभापति: अंकित नहीं होगा। विराजिए आप।

श्री बलवान पूनियां (भादरा): 000

श्री अमृतलाल मीणा (सलूम्बर): सभापति महोदय, 2023-24 के हवा-हवाई बजट के बारे में मैं बोलना चाहूंगा..

श्री बलवान पूनियां (भादरा): 000

श्री सभापति: प्लीज।

श्री अमृतलाल मीणा (सलूम्बर): हवा-हवाई बजट के बारे में मैं बोलना चाहूंगा। हमारे राजस्थान के मुख्य मंत्री जी बहुत संजीदा हैं।5 बार सांसद भी रहे, 5 बार विधायक भी रहे। कांग्रेस पार्टी में, हाई कमान में कई निर्णय लेने वाले और वे यह कहें कि बजट में एक पन्ना एक्स्ट्रा लग गया, कहां तक सत्य है। पूरे भारत, पूरे राजस्थान में जनता को भ्रमित करने वाला बजट पेश किया है।

सभापति महोदय, मैं कहना चाहूंगा, आपने खाद्य सुरक्षा की बात की, गैस की बात की, 100 यूनिट बिजली की बात की, युवाओं को रोजगार देने की बात की, नवीन नीति बनाने की बात की। सभी भर्तियों को नि:शुल्क करने की बात की।

(श्री अमृतलाल मीणा)

सभापति महोदय, मैं आपको यह याद दिलाना चाहूंगा कि बजट 2019-20 में आपने क्या कहा था? 10 जुलाई, 2019 को बजट पेश हुआ, आपने क्या कहा। उसमें पैरा संख्या-31 में आपने कहा था कि जो आवारा पशु हैं, रोड पर घूमते रहते हैं, प्रत्येक पंचायत मुख्यालय पर नंदीशाला बनाने की घोषणा की थी। आज पांच साल बीत जाने के बाद भी पूरी नहीं हुई।

माननीय सभापति महोदय, आपने पैरा नम्बर-32 में यह भी कहा था कि सार्वजनिक निर्माण विभाग में आने वाले सालों में सड़क का तंत्र, 35 हजार किलोमीटर से ज्यादा सड़कें बनाएंगे लेकिन आप भी ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, आज आपकी क्या स्थिति है, यह आप भी जानते होंगे।

पैरा 39 में भी पांच वर्षों में समस्त ग्राम पंचायत में विकास पथ का निर्माण करवाया जायेगा, तो वह एक में भी नहीं हुआ। गौरव पथ की जगह आपने नाम चेंज कर दिया, कोई बात नहीं। विकास पथ का, माननीय सभापति महोदय, आपके विधान सभा क्षेत्र में भी नहीं हुआ होगा।

पैरा नम्बर 41 में भी, यह मैं वर्ष 2019-20 की बात कर रहा हूं, 2019-20 में आपने राज्य विद्युत उत्पादन को सरप्लस कर देंगे, पर आज क्या स्थिति है? किसानों की हालत खराब है, लाइट गायब, लट्टू नहीं जल रहा है। खाने के समय, सुबह नहाने के समय लाइट नहीं है।

पैरा नम्बर-44 के बारे में मैं यही कहना चाहूंगा कि प्रदेश के सभी घरों की छतों पर सोलर लगायेंगे, माननीय सभापति महोदय, यह मैं बजट के किताब की बात कह रहा हूं, हमारे माननीय मुख्य मंत्रीजी ने यह कहा था।

पैरा नम्बर-47 में आपने यह कहा था कि 132 के.वी. जी.एस.एस. का निर्माण करेंगे। यह वर्ष 2019-20 में मेरे विधान सभा क्षेत्र में 132 के.वी. जी.एस.एस. में ओनली बाउंड्री बनवायी है, बाउंड्री।

पैरा नम्बर-49 में किसानों को कुसुम योजना के तहत सोलर पम्प आबंटन करेंगे, यह नहीं हुआ।

पैरा नम्बर- 51 में किसानों को रात्रि के स्थान पर हम दिन में लाइट देंगे, यह नहीं हुआ। ईमानदारी से अगर अपन सदन में इसको पढ़कर बात करेंगे तो सच्चाई सामने आयेगी।

वर्ष 2020 में आपने कहा कि गली-गली में जनता क्लिनिक खोलेंगे। (व्यवधान)

श्री सभापति: आपस में वार्ता नहीं।

श्री अमृतलाल मीणा (सलूम्बर): सर, मैं 15 मिनट में पूरा बोलूंगा। जनता क्लिनिक का कहा, इसके अलावा पैरा नम्बर-106 में गांवों में मास्टर प्लान बनाएंगे, जिसमें नाली सहित सारा व्यवस्थित होगा एवं नवीन आवासीय छात्रावास की स्थापना करेंगे, वह नहीं हुआ।

माननीय सभापति महोदय, भिक्षावृत्ति की बात है। आप जब भी आते हैं, सुबह आते हैं तो चौराहे पर, उस समय आपने यह एक प्रण किया था वर्ष 2019-20 में कि हम जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर, कोटा जैसे शहरों में भिक्षावृत्ति की जो समस्या है, लोग भिक्षा मांगते रहते हैं, उनके लिए हम व्यवस्था करेंगे, लेकिन अभी तक भी आपने उसके लिए व्यवस्था नहीं की है।

शिक्षा के लिए आपने कहा कि 14 हजार से ज्यादा हम कमरे बनाएंगे, प्रयोगशाला का करेंगे, यह करेंगे, लेकिन अभी तक भी कुछ नहीं हुआ है। वर्ष 2019-20 में आपने यह भी बात कही थी कि एक नवाचार एक कार्ड, एक पहचान। खाद्य सुरक्षा की तो स्थिति बहुत खराब है। चार साल से जो एस.डी.ओ. कार्यालय में सारे फार्म पड़े हुए हैं अभी तक भी, मैं सबसे बड़ी बात यह कहूंगा कि कोरोना काल में हमारे में से सात-आठ विधायक चले गये, उनको नहीं जाना चाहिए था। उनके नाम, अपने-अपने क्षेत्रों में नाम रख दिया, लेकिन हमारे गौतमलालजी, विधायक, धरियावद के थे जो कि एक एस.टी. के विधायक थे, अनुसूचित जनजाति के विधायक थे और हमारे बार-बार लिखने के बाद भी उनके नामकरण का, कोई भी स्कूल, कालेज नहीं रखा, इसके लिए हमें खेद है। मेरा आपसे यह भी निवेदन है कि ...(व्यवधान)

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सात-आठ विधायक, पूर्व विधायकों की बात कही है, यह आंकड़ा ...(व्यवधान)

श्री सभापति: विराजिये-विराजिये। अंकित नहीं होगा।

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): 000

श्री अमृतलाल मीणा (सलूम्बर): मैं कोविड की बात कर रहा हूं।

श्री सभापति: अंकित नहीं होगा। माननीय सदस्य, प्लीज विराजिये। अंकित नहीं होगा किसी का भी।

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): 000

श्री अमृतलाल मीणा (सलूम्बर): सुनिये, मैं बोल रहा हूं। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप एक मिनट विराजिये। माननीय सदस्य, यह क्या हो रहा है? कृपया, शांत रहें। बाकी वक्ता बोल नहीं पायेंगे, आप कृपया इंटरवीन नहीं करें। (व्यवधान)

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): 000

श्री अमृतलाल मीणा (सलूम्बर): मैं बता रहा हूं।

श्री सभापति: विराजिये-विराजिये। आपका मौका आये, तब आप अपनी बात बताना। आप बीच में इंटरवीन नहीं करें। किसी का अंकित नहीं होगा। माननीय मीणाजी।

श्री अमृतलाल मीणा (सलूम्बर): माननीय सभापति महोदय, घोषणा नम्बर 49 में साथी विधायकों के कोविड में बिछड़ जाने के बाद उनकी याद में, स्मृति में कन्या महाविद्यालय का नाम उनके नाम से करने की घोषणा माननीय मुख्य मंत्रीजी ने की थी, जिसमें से हमारे कुंवारिया-राजसमन्द में किरण माहेश्वरी राजकीय कन्या महाविद्यालय, भीण्डर-उदयपुर में गजेन्द्र सिंह शक्तावत कन्या राजकीय महाविद्यालय, सुजानगढ़-चूरू में मास्टर भंवरलाल राजकीय कन्या महाविद्यालय व गंगापुर-भीलवाड़ा में कैलाश त्रिवेदी राजकीय कन्या महाविद्यालय खोले जाने की घोषणा की थी। यह जो हमारे एक मात्र विधायक जनजाति के थे गोतमलालजी मीणा, धरियावद, उनके लिए बार-बार निवेदन करने के बाद भी नहीं हुआ, इसका हमें खेद है।

माननीय सभापति महोदय, पिछले चार साल के बजट में किसानों को छह घंटे थ्री फेज बिजली देने की बात कही थी, वह भी नहीं हुआ। किसानों के बिजली बिल की राशि को निर्धारित समय पर जमा नहीं करवाने पर, अब आपने दो हजार यूनिट का कहा है, लेकिन मुझे शंका है कि इसमें सम्भावना कतई नहीं है। जिस प्रकार 2013 में आपने बहुत हवाई बजट पेश किया था इस राजस्थान के सदन में वह ही स्थिति आपकी 2023 में होने वाली है। उस समय आप 21 जने आये थे अबकी बार 11 जने आने की सम्भावना है।

वर्ष 2020-21 में आपने यह भी कहा था, घोषणा 45 में सभी ग्राम पंचायत में सहकारी समितियों को सौर ऊर्जा से जोड़ने वाली घोषणा की, लेकिन वह अभी तक भी नहीं हुई।

जो हमारे उदयपुर जिले और पूरे मेवाड़ सम्भाग में बच्चे-बच्चियों की तस्करी हो रही है, उसके लिए आपने यह 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है, लेकिन अभी तक इस पर कोई कार्य नहीं हुआ।

वर्ष 2020-21 में आपने घोषणा 47 में प्रत्येक सरकारी विद्यालय में कम्प्यूटर शिक्षक कैडर का सपना दिखाया था, लेकिन अभी तक वह काम नहीं हुआ।

(श्री अमृतलाल मीणा)

आपने पूर्ववर्ती सरकार के प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय में सी.सी. सड़क का कहा, वर्ष 2020-21 में आपने यह भी घोषणा की, बांधों का निर्माण करने का कहा, 503 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया, 18 बांध हैं जिनमें हमारा सोम-कमला-अम्बा डैम भी है, आज तक उसमें कोई काम शुरू नहीं हुआ।

आपने 2020-21 में, घोषणा नम्बर 181 पर भी जंगलों में लगने वाली आग के बारे में कहा, उसके लिए भी अभी तक आपकी कोई व्यवस्था नहीं हुई है।

मैं यह भी कहना चाहूंगा, माननीय सभापति महोदय, 2021-22 में भी आपने घोषणा नम्बर-6 में महात्मा गांधी नरेगा योजना में सहरिया, कथौड़ी और जनजाति के लोगों को 100 दिन की जगह 200 दिन का रोजगार उपलब्ध करवाएंगे, वह की वह बात अभी बजट में आपने कही।

श्री सभापति: आप अपनी बात को दो मिनट में समाप्त करें।

श्री अमृतलाल मीणा (सलूम्बर): मैं कर रहा हूं, साहब।

माननीय सभापति महोदय, मैं यह मांग करना चाहूंगा, आपका थोड़ा प्यार तो हमारे प्रति है ही है, मेरे विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर में जयसमंद, गींगला को तहसील का दर्जा दिया जाये। सराड़ा, चावण्ड, केजड़ को नगरपालिका का दर्जा दिया जाये। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र जावरमाइन्स में तो नया खोला जाये। ईडाणा, खरका और गांवड़ापाल और टोडा और राठौड़ा में पी.एच.सी. खोली जाये। हमारे पी.एच.सी. सुरखण्ड का खेड़ा में स्वीकृत है 2018 से, उसके लिए बजट जारी किया जाये।

माननीय सभापति महोदय, जो दस-दस करोड़ रुपये की पिछली बार भी माननीय मुख्य मंत्रीजी ने घोषणा की और दिये भी, लेकिन अभी तक भी उनके काम शुरू नहीं हुए हैं और काम अपनी मर्जी से स्वीकृत कर दिये। पेवर रोड थी, उसकी जगह पर मिसिंग रोड कर दी और मिसिंग रोड की जगह पर पेवर रोड कर दिया, तो इस प्रकार का अंधाधुंध कार्य किया है। उस क्षेत्र में हमारा पूरा जंगलात का एरिया है। वहां के निवासी वहां पर वर्षों से निवास कर रहे हैं, उनको वनाधिकार का पट्टा दिया जाये। सी.एच.सी., सराड़ा को 100 बेड का हास्पिटल किया जाये और 132 जी.एस.एस. हमारे सराड़ा में है, उसका बजट आबंटित नहीं हुआ है, उसको भी किया जाये।

माननीय सभापति महोदय, इन चार सालों में पेपर लीक को लेकर,

(श्री अमृतलाल मीणा)

पेपर आउट को लेकर, निर्दोष लोगों की हत्या को लेकर, किसानों की लाइट को लेकर और साइबर क्राइम को लेकर, बिजली को लेकर, पेट्रोल-डीजल के जो भाव हैं, पूरे देश में सबसे ज्यादा राजस्थान में वैट लगने से हैं। आप यह देखिये कि इन परीक्षाओं का पेपर, बच्चों ने क्या सोचा होगा, इस प्रकार से यह पेपर आउट हो जाना, यह कलंक है और हमारे मुख्य मंत्रीजी जिस प्रकार से सोच रहे हैं, उनको यह चलने नहीं दे रहे हैं दूसरे नीचे वाले, सेकंड लाइन वाले जो लोग हैं और अधिकारी जिन्होंने जिस प्रकार का पर्चा दूसरा डाल दिया...(व्यवधान)

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री अमृतलाल मीणा (सलूम्बर): आपने समय दिया, धन्यवाद। जय हिन्द।

(समय: 18.00 बजे)

श्री सभापति: श्री पदमाराम। (व्यवधान)

माननीय सदस्य, यदि आप गम्भीर नहीं हैं तो मैं स्थगित करूं? आप बहुत ज्यादा बोल रहे हैं। कृपया शांत रहें। वक्ता को अपनी बात कहने दें। हर माननीय सदस्य अपनी सीट पर जाकर बैठें। आप जो भी बात कर रहे हैं, यहां तक आसन को सुनाई दे रहा है। प्लीज जाइये अपनी सीटों पर। सदन को गम्भीरता से लें। यदि आपकी मंशा नहीं है तो मैं सदन स्थगित करता हूं। प्लीज। क्या हो रहा है? शांत रहें। श्री पदमाराम।

श्री पदमाराम (चौहटन): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान सरकार के जन कल्याणकारी मुख्य मंत्रीजी ने 10 तारीख को जो बजट पेश किया है उसके पक्ष में मुझे बोलने का मौका दिया, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं।

माननीय सभापति महोदय, आज सुबह से ही बजट पर चर्चा हो रही है और राजस्थान की आठ करोड़ जनता ने हम सबको चुन कर भेजा है वह टीवी चैनल पर, सोशल मीड़िया पर यह देख रही है कि हमारे सेवक जो चुन कर भेजे, वह हमारे क्षेत्र के विकास के लिए, जनता के कल्याण के लिए क्या-क्या वक्तव्य दे रहे हैं और जनता की उनको कितनी चिन्ता है, उसके बारे में देख रही है।

माननीय सभापति महोदय, राजस्थान के लोकप्रिय मुख्य मंत्रीजी ने राजस्थान का विकास कैसे हो, राजस्थान के युवाओं को रोजगार कैसे मिले, राजस्थान के किसानों को मजबूती कैसे मिले, राजस्थान के असहाय लोगों को

(श्री पदमाराम)

मजबूती कैसे मिले और गरीब तबके के लोग जो महंगाई की मार झेल रहे हैं, उसको राहत कैसे दें, उसको ध्यान में रखते हुए जो यह शानदार बजट पेश किया है वह एक साल का एक विजन है, एक आईना है। मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहूंगा।

आज विषम परिस्थितियां हैं। दो साल कोरोना काल था, उस दौरान राज्य का रेवेन्यू घटा। लोगों के धंधे बन्द हो गये। लोग बेरोजगार हो गये। उनके खाने-पीने की समस्या हो गयी। मजदूरों की मजदूरी खतम हो गयी। उस विषम परिस्थिति के अन्दर उन्होंने राजस्थान की जनता की सेवा की। उस विषम परिस्थिति के अन्दर लोगों को सम्बल देने का काम किया, इसलिए माननीय मुख्य मंत्री महोदय को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। उन विषम परिस्थितियों के उपरान्त भी राजस्थान का विकास करने के लिए आज कल्याणकारी योजनाएं लागू की हैं। आजादी के बाद आज दिन तक किसी ने न तो की है और न ही करने वाले हैं। पूरे देश के अन्दर वाहवाही सब लेना चाहते हैं परन्तु जनता, युवाओं, किसानों और असहायों को सम्बल देने का काम वही कर सकता है जो जनता का सेवक है। हमारी भावना जनता की सेवा करना और जनता को आगे बढ़ाना है। जनता को मजबूती देने के लिए जो काम किये हैं, उसके लिए माननीय मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहता हूं।

माननीय सभापति महोदय, एससी, एसटी के कोष को 500 करोड़ से बढ़ाकर 01 हजार करोड़ किया, इसके लिए भी मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहूंगा। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप अपने स्थान पर बैठिये जाकर। कृपया आप अपनी सीट पर जाइये। काफी देर से आप आसन की तरफ पीठ करके खड़े हो रहे हैं। जाइये अपनी सीट पर।

श्री पदमाराम (चौहटन): आज टीएसपी और टाडा माडा क्षेत्र के अन्दर हमारे एसटी के भाइयों को जो सुविधा मिल रही है उसकी हमें खुशी है। आदिवासी लोग जो पहाड़ों में रह रहे हैं उनके विकास के लिए माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जो योजना लागू की, उनको शिक्षा के अन्दर अग्रसर मूल धारा में जोड़ने के लिए योजना लागू की, उसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहता हूं।

साथ ही यह निवेदन करना चाहता हूं कि बाड़मेर जिला सीमावर्ती जिला है, हमारे जिले में रहने वाले हमारे एसटी के भाई शिक्षा की मूल धारा से

(श्री पदमाराम)

वंचित हैं, उनका रहन सहन अच्छा नहीं है। उनको शिक्षा की मूल धारा से जोड़ने के लिए, उनके जीवन का उत्थान करने के लिए ऐसी कोई नयी योजना लागू करें जिससे टाडा और माडा के तहत उनको भी लाभ मिल सके और कृषि कनेक्शनों में भी उनको प्राथमिकता के आधार पर कनेक्शन दिए जाएं। नौकरी के अन्दर एसटी वर्ग में जो आरक्षण दिया जा रहा है, उसमें भी सीमावर्ती क्षेत्र को विशेष मानते हुए उनको विशेष प्राथमिकता दी जाए।

हमारे माननीय मुख्य मंत्रीजी ने मरु विकास बोर्ड का गठन किया था, इसलिए भी मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। उसके अन्दर एक नयी योजना लागू करनी चाहिए जिससे आदिवासी क्षेत्रों में रहने वाले हमारे एसटी भाइयों को मजबूती मिले, उनको सम्बल मिले और वह मूल धारा के अन्दर आयें और अपना विकास करें।

माननीय सभापति महोदय, हमारे राजस्थान के लोकप्रिय मुख्य मंत्रीजी ने सोशल वर्ग को मजबूती देने के लिए, गरीब का उत्थान करने के लिए, जो आजीविका कमा कर अपना भरण पोषण कर रहा है उनको सम्बल देने के लिए शानदार योजना लागू की। 76 लाख लोगों को 500 रुपये में गैस का सिलेण्डर देना बहुत बड़ी बात है। बात करना बहुत आसान है बात हर आदमी कर सकता है परन्तु करके दिखाना बहुत मुश्किल काम है। विपक्ष के साथियों का कर्तव्य है कि राजस्थान की अच्छाइयों का गुणगान करना चाहिए। सच्चाई जो धरातल पर है उसके बारे में जरूर बात करनी चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, 2014 के अन्दर भारत के लोकप्रिय प्रधान मंत्रीजी जब चुनाव में आये उनका पहला फोकस युवाओं पर था। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पिछले नौ साल से युवाओं का सोशल मीडिया के अन्दर आकर्षित करके उन्होंने वोट तो ले लिए परन्तु पिछले नौ साल से युवाओं को कितना रोजगार दिया, कितनी नौकरियां दीं, किस-किस क्षेत्र में नौकरियां दीं, कौन-कौनसी नौकरियां बन्द कीं, उसके बारे में तो थोड़ा वे बतायें। पिछले तीन महीनों में राजस्थान के अन्दर हमारे प्रधान मंत्रीजी दो बार पधारे। हम उनका स्वागत करते हैं परन्तु यहां आकर उन्होंने ऐसी कौनसी घोषणा कर दी? राजस्थान की जनता ने 25 एम पी चुन कर भेजे। सबसे ज्यादा रेवेन्यू राजस्थान से जीएसटी के मार्फत जा रहा है। मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसी कौनसी घोषणा कर दी?

(श्री पदमाराम)

हमारे साथी बजट की चर्चा करते हुए हंसी मजाक कर रहे हैं, बोल रहे हैं। बजट पर बोल रहे हैं और पीछे से हंसी कर रहे हैं। गम्भीरता को समझो। यह जनता जर्नादन है, प्रजातंत्र के अन्दर जनता माई बाप होती है और जनता का फैसला अपन सबको मानना पड़ेगा। जनता की आवाज मानो। हंसी करने का टाइम नहीं है। आज से पहले ऐसी कौनसी बजट की घोषणा होगी जो 101 परसेंट हो गयी? हमारे माननीय मुख्य मंत्रीजी ने पिछले चार साल के अन्दर 2722 घोषणा कीं, 80 परसेंट पूरी कर दीं। (व्यवधान)

आपके यहां नहीं तो आप चिन्ता करो। हमारे यहां तो हो गयी। आपके यहां नहीं हुई तो सोच करो। कल प्रधान मंत्रीजी आये थे तो आपको मांग करनी चाहिए थी कि हमारे यहां योजना लागू नहीं हुई, लागू करो, तो हो जाती लागू। ऐसी कौनसी बात है? बात तो बताओ।

आप अभी शान से कह रहे थे कि हमने पाकिस्तान को जवाब दे दिया है, हमने चीन को जवाब दे दिया, हमने हिन्दू मुसलमान के दंगे बन्द करवा दिये। आप बात तो हिन्दुत्व की करते हो और पांच-पांच मिनट में आपके आदमी हिन्दू मुसलमान की बात नहीं करे तो आपको खाना नहीं पचता है। आप कौनसे हिन्दुत्व की बात कर रहे हो? आप तो जनता को गुमराह करने के लिए और राज प्राप्त करने की बात करते हो और कुछ नहीं करते हो। आप कह रहे हो कि घोटालों की सरकार है। आप बताओ तो सही आपने 9 साल के अन्दर कांग्रेस के कितने नेताओं को जेल में डाला? बताओ तो सही। आपकी ई.डी. और सी.बी.आई. कहां गयी? अडानी की बात करते ही आपको बुखार क्यों आ गया? आपको चर्चा करनी चाहिये। बात करो और उसके खिलाफ जांच कराओ न। कांग्रेस के फण्ड के अंदर... (व्यवधान)

श्री सभापति: दो मिनट में समाप्त करें अपनी बात।

श्री पदमाराम (चौहटन): माननीय सभापति महोदय, अभी तो शुरू किया है। कांग्रेस की सरकार खाद्य सुरक्षा कानून लेकर आयी, नरेगा लेकर आयी, सूचना का अधिकार दिया, भूमि अधिग्रहण बिल लायी। आपने कौनसा काम किया? आपने एल.आई.सी. को बेचा, रेलवे को बेचा और एयरपोर्ट को बेचा और इन सबको बेचकर कौनसी योजना लाये? देश में महंगाई की मार है, बेरोजगारी की मार है और आपने ऐसा कौनसा काम कर दिया? आप तो एक्साइज ड्यूटी बढ़ा रहे हो, स्पेशल एक्साइज ड्यूटी लगा रहे हो, सेस लगा रहे हो। वह धन कहां खर्च हो रहा है, उसका जनता जवाब मांगेगी।

(श्री पदमाराम)

माननीय मुख्य मंत्रीजी ने सोशल सिक्योरिटी का कहा था, ओ.पी.एस. लागू किया, साढ़े तीन लाख बेरोजगारों को रोजगार दिया, नौकरियां दीं। संविदाकर्मियों को परमानेंट करने की कल घोषणा की और इसके साथ ही यह प्रावधान किया कि जितने साल आपने नौकरी की है, वह उसको साथ में जोड़ देंगे। कर्मचारियों के वेतन के अंदर जो विसंगतियां थीं, उनको दूर करने का काम किया।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके मार्फत निवेदन करना चाहता हूं कि 2013 के अंदर जो ए.एन.एम. की भर्ती हुई, उसके अंदर 2018 में उनको वंचित रखा गया था, उनकी नियुक्ति करने की कोशिश करें। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जो किसानों को मजबूती देने के लिए पहले प्रतिमाह हजार रुपये देने का काम किया, अब दो हजार यूनिट बिजली देने की बात कही। पशुओं को मजबूती देने के लिए लम्पी के अंदर जो गायें खतम हो गयी थीं, उनको अनुदान देने का काम किया। किसानों को मजबूत करने के लिए, युवाओं को मजबूती प्रदान करने के लिए, असहाय लोगों का सहारा बनने के लिए और सबकी मजबूती के लिए शानदार बजट दिया। मैं इनकी प्रशंसा करता हूं और आने वाला समय कांग्रेस का होगा। 2023 के अंदर वापस कांग्रेस जीतकर आयेगी और कांग्रेस का झंडा 2023 में फहराएगा।

श्री सभापति: श्री बाबुलाल खराड़ी।

श्री बाबुलाल (झाडोल): माननीय सभापति महोदय, इस राज्य की सरकार का अंतिम और पांचवां बजट है, आपने इस पर बोलने का मुझे अवसर दिया, इसके लिए आपका आभारी हूं।

माननीय सभापति महोदय, काफी माननीय सदस्यों ने अपनी-अपनी बात कही है। आज यहां पर जिस प्रकार की चर्चा हो रही है, सत्ता पक्ष के लोगों ने अपनी सरकार का गुणगान किया है। इस सरकार ने चार साल से जनता को आईना बताने का काम किया है। घोषणा पर घोषणाएं और उन घोषणाओं का क्या हुआ, यह हमारे सलूम्बर से आने वाले माननीय सदस्य ने और हमारे प्रतिपक्ष के उप-नेता महोदय ने भी जिक्र किया था।

माननीय सभापति महोदय, मैं ज्यादा कुछ जिक्र करूंगा तो लम्बा समय हो जायेगा, लेकिन कुछ बातें कहनी भी आवश्यक हैं। अभी सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य कुछ आंकड़ों को कोट करके गये थे। मैंने भी थोड़ी-सी नजर बजट पर डाली है, मैं वह आपके सामने निवेदन करना चाहता हूं। हमारी सरकार ने जिस प्रकार से कुछ मदों में काम किया है, मैं उनको कोट करना चाहता हूं। हमारे यहां एग्रीकल्चर एक्सपेंडिचर में 2023-24 में 4.3 व्यय

(श्री बाबुलाल)

किया है, यह अन्य राज्यों से बहुत ही कम है। इसी के साथ में, रोड एण्ड ब्रिज में 2023-24 में 3.6 प्रतिशत, अन्य राज्यों से यहां पर भी हमारा प्रदेश पिछड़ा है। माननीय सभापति महोदय, आगे हम देखें तो हैल्थ एण्ड फैमिली वेलफेयर, अब इसमें आप देखेंगे तो माइनस 10 प्रतिशत, जितना बजट हमारा था, उसमें इतना खर्चा किया है। इसी प्रकार, एग्रीकल्चर का हम देखेंगे तो इसमें भी माइनस 10 प्रतिशत, आगे हम रूरल डवलपमेंट, ग्रामीण एरिये की हम बात करें, यह सब कहते हैं कि हमने गांवों का विकास कर दिया, क्या किया, माइनस 8 प्रतिशत। अब हम क्या अपेक्षा करें इस सरकार से कि इस सरकार ने अभी जो सपने दिखाये हैं, वह पूरे होंगे क्या? मुझे लगता नहीं है।

माननीय सभापति महोदय, अब मैं कुछ घोषणाओं की ओर जिक्र करूंगा। बाहर की बातें तो सब लोगों ने कह दीं, लेकिन मेरे विधान सभा क्षेत्र की मैं बात कहूंगा। आपने घोषणा की थी कि हम प्रत्येक पंचायत में खेल मैदान बनायेंगे। मेरे विधान सभा क्षेत्र में तो एक भी नहीं बना। आपने क्या किया? हम सरकार से क्या अपेक्षा रखें? अभी एक पूर्व वक्ता बोल रहे थे कि हमारे यहां सारा काम हो गया। यह तो कांग्रेस की पुरानी परिपाटी है, शक्लें देखकर तिलक निकालती है, क्योंकि इनका सब काम किया और हम लोगों को केवल घोषणा करके छोड़ दिया और हमारे यहां एक भी काम नहीं हुआ।

इसी प्रकार आपने कहा था कि ग्राम पंचायतों की जो सड़कें रह गयीं, उनको हम डामर की सड़कों से जोड़ेंगे। मेरे विधान सभा क्षेत्र में उमरिया और बेड़दा, दो पंचायतों का मैं बार-बार कह रहा हूं, क्या हुआ उस घोषणा का? आपने पूरा कर दिया क्या? हम आपसे क्या अपेक्षा रखें कि आपने जो यह घोषणाएं कीं, सपने दिखाये, यह पूरे करोगे? इसी प्रकार कोटड़ा में 132 केवी जीएसएस की घोषणा की थी। अभी सलूम्बर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि केवल बाउण्ड्री बनी है, आगे मामला ठप है।

माननीय सभापति महोदय, आपने पेयजल के लिए बहुत बड़ी-बड़ी बातें कही हैं कि हम नल योजना से घर-घर जल पहुंचा देंगे। आप दो साल से तो जल पहुंचा रहे हो। केन्द्र सरकार ने आपको पैसा दे दिया, लेकिन वह पैसा लेकर भी आपने काम पूरा नहीं किया। हमारे कोटड़ा में पेयजल के लिए दो बांधों की मुख्य मंत्रीजी ने पिछली बार घोषणा की थी। मुख्य मंत्रीजी वहां पर मानव जीवन के मूल्यों पर पानी पिलाना चाहते हैं। उन लोगों का क्या होगा? जो गांव का गरीब आदमी है, आप गांव और गरीब की बातें करते हैं, वह विस्थापित होंगे, तो उनका पुनर्वास कहां करोगे? उस व्यक्ति के मन में, वहां का रहने वाला जनमानस

(श्री बाबुलाल)

त्राहिमाम-त्राहिमाम कर रहा है कि हम जायेंगे कहां? माननीय सभापति महोदय, मैं सरकार को कहना चाहूंगा कि हमें इस बांध के लिए पुनर्विचार करना चाहिये जिससे आम अवाम और गरीब को कोई तकलीफ न हो।

माननीय सभापति महोदय, आपने काफी बातें कहीं। शिक्षा के क्षेत्र में, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि शिक्षा के क्षेत्र में आपने पहले भी कहा था कि हम विद्यालयों के भवन बना देंगे, मास्टर लगा देंगे। आपने युवाओं की बात कही है न, आज युवाओं की परीक्षाओं के 16 बार पेपर लीक हुए। जिस बच्चे ने परीक्षा के लिए तैयारी की, अपना पैसा खर्च किया, कोचिंग की और उसकी इच्छा थी कि मैं एग्जाम देकर पास होऊंगा और नौकरी लग जाऊंगा, लेकिन उसके बाद में आज भी वह नौकरी का इंतजार कर रहा है। आप कह रहे हैं न हमने सब युवाओं को रोजगार दे दिया। आपने कहा केन्द्र ने रोजगार नहीं दिया, आप तो अपनी बताओ न कि आपने कितने लोगों को नौकरी दी? आप फालतू ही केन्द्र सरकार को कोस रहे हो। यह तो कोई सही तरीका नहीं हो सकता है।

माननीय सभापति महोदय, मैं महाविद्यालय की बात करूंगा। महाविद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों को गाड़ी किराया मिलता है। एक साल से वहां के विद्यार्थियों को गाड़ी किराया नहीं मिला है। वह दूर-दूर से आता है तो अपनी जेब से पैसा देकर आता है। हम लोग क्या करेंगे? आपने पहले भी कहा था कि हम 10 हजार अंग्रेजी माध्यम के शिक्षक लेंगे, आपने लिये क्या? आपने एक भी शिक्षक नहीं लिया। आपने अभी बजट में और कहा है कि हम और शिक्षक भर्ती करेंगे, और लेंगे, अब क्या गारंटी है कि इसको आप पूरा करोगे? हमें तो लगता नहीं कि आप ऐसा वादा पूरा करोगे।

आपने कहा कि पहली से लेकर आठवीं तक हम यूनिफार्म फ्री देंगे और उनकी सिलाई का पैसा उनके खाते में डालेंगे। 20 प्रतिशत बच्चों का, आज भी उस यूनिफार्म का पैसा उन तक नहीं पहुंचा है, वह बच्चे क्या अपेक्षा रखेंगे?

माननीय सभापति महोदय, हमारे यहां कुछ और बातें आपने कही हैं, मैं ज्यादा जिक्र तो नहीं करूंगा। मैं उनका जिक्र करूंगा तो बहुत समय हो जायेगा, लेकिन आपने कहा था न हमारे यहां मुख्यमंत्री नि:शुल्क अन्नपूर्णा योजना का, अन्नपूर्णा योजना का आपने देखा न, जब कोरोना आया था तब हिन्दुस्तान के प्रधान मंत्रीजी ने कहा कि आप सब लोग घरों में रहिये, घर से बाहर न निकलें। यह बीमारी ऐसी है, अगर बीमारी लग जायेगी तो आप भी मरेंगे, औरों को भी मारेंगे। लोगों ने घरों से निकलना बंद कर दिया। उनकी

(श्री बाबुलाल)

मजदूरी बंद हो गयी। बाजार बंद हो गये। उनके मन में कल्पना थी कि गांव का आदमी, गरीब का बच्चा भोजन कैसे करेगा? उन्होंने 5 किलो गेहूं और दाल उनके घर तक पहुंचाने की व्यवस्था की थी। आपने भी किया, क्योंकि प्रधान मंत्रीजी ने किया तो हम भी करेंगे। आपने भी किया, लेकिन कोरोना जब उतार पर आया था, तब आपने तो बंद कर दिया था न? उसके बाद में अब तक तो दिया नहीं। आज मुख्य मंत्रीजी कह रहे हैं कि हम गेहूं भी मुफ्त देंगे, तेल भी देंगे, दाल भी देंगे। सारी चीज दोगे क्योंकि आपको वापस सत्ता में आना है। सत्ता में आने के बाद आप फिर से भूल जाओगे। जनता जनार्दन आपको देख रही है। यह सपने दिखाने से आप सत्ता में वापस आओगे, यह अपेक्षा करना बंद करें। जिस प्रकार की घोषणाएं की हैं, अब गांवों में हम जाते हैं तो लोग पूछते हैं कि पहले की बातें तो पूरी की नहीं हैं, लेकिन अब क्या यह पूरी होंगी? उनको शंका है, इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि इस पर बहुत ज्यादा कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है।

चिकित्सा के क्षेत्र में आपने कहा था कि हम चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत कुछ कर देंगे। अब चिकित्सा के क्षेत्र में आपकी क्या स्थिति है? चिरंजीवी योजना की बात आपने बहुत बढ़चढ़कर की। थोड़ी बहुत चर्चा उस बात की भी करते कि पूर्व मुख्य मंत्री वसुन्धरा राजे ने 30 हजार से लगाकर 3 लाख तक की भामाशाह योजना बनाकर के इलाज मुफ्त करने का काम किया। उसी को लेकर हिन्दुस्तान के प्रधान मंत्री ने आयुष्मान भारत योजना बनाकर के कहा कि 5 लाख तक का इलाज मुफ्त कराइये। उसी का आपने नाम बदलकर के चिरंजीवी योजना लाये तो कौनसा बड़ा काम कर दिया? मुझे लगता नहीं है कि आप बहुत कुछ कर जाओगे। लेकिन आज हास्पिटल की स्थिति क्या है? हास्पिटलों में पर्ची लिखने वाला डाक्टर नहीं है। डाक्टर की भर्ती आप कर नहीं रहे हो तो मरीज कहां जायेगा?

लाइट के क्षेत्र में आपने कहा कि हम उनको अनुदान भी देंगे, सारा कुछ करेंगे। उन तारों में बिजली आती है क्या? क्या उन बल्बों की आरती उतारें? लगता नहीं है कि आप कुछ करोगे। आज गांव का आदमी लाइट का इंतजार करता है। उसके पास लाइट ही नहीं आयेगी, यूनिट नहीं जलेगी तो आप कहां से उनको लाभ दोगे? आप बताने की कृपा करें, जब भी होगा तब।

मैं इसलिए कहना चाहूंगा कि आप अपनी बात कहते समय कम से कम केन्द्र की योजना का भी जिक्र करें। आपने बहुत कहा कि किसान का

(श्री बाबुलाल)

आपने भला किया, किसान की हितैषी कांग्रेस है। कांग्रेस का हाथ किसान के साथ में है। क्या कर दिया?

किसान सम्मान निधि योजना में पहली बार हिन्दुस्तान के प्रधान मंत्री जी ने गांव के गरीब आदमी, किसान को रोकड़, पैसा देने का काम किया। तीन किस्तों में 2-2 हजार रुपये, 6 हजार रुपये देने का काम किया। यह पहली बार हुआ है। आपने कभी सोचा था कि किसान की हम मदद करेंगे? आपने मदद नहीं की। आपके मन में ही नहीं है। आपको केवल लुभावनी बातें करके, घोषणा करके, हमें सत्ता में आना है।

आपने तो कहा न कि हम सम्पूर्ण कर्जा माफ कर देंगे। कर दिया न? क्या कर दिया? आपने कर दिया हो तो बताओ न। फिर आपने कहा कि हम कामर्शियल बैंकों का तो नहीं करेगे, सहकारी बैंकों का करेंगे। उसमें भी कितना किया, बता देना। तब पता लगेगा।

सभापति महोदय, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यह जितनी भी घोषणाएं हुई हैं, इन पर भरोसा नहीं है कि यह घोषणाएं पूरी होंगी।

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री बाबुलाल (झाडोल): सभापति महोदय, मैं आपसे यह कहना चाहूंगा, कई बार होता है कि बोलने की गति आती है तो आप रोकने का प्रयास करते हो तो हम रुक जाते हैं। इसलिए बहुत ज्यादा नहीं बोलकर के अपनी बात यहीं खतम करता हूं। जय भारत। धन्यवाद।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री महेन्द्र चौधरी (सरकारी उप मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय एक घंटा बढ़ाकर साढ़े 7 बजे तक कर दिया जाये।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि सदन का समय साढ़े 7 बजे तक बढ़ा दिया जाए?

(स्वीकृत)

समय का समय साढ़े 7 बजे तक बढ़ाया गया।

श्री मदन प्रजापत।

आय-व्ययक

आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2023-24 पर सामान्य वाद-विवाद

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): माननीय सभापति महोदय, बहुत-बहुत आभार। माननीय लोकप्रिय मुख्य मंत्री जी ने गरीब के हित में, किसान के हित में जन कल्याणकारी एवं शानदार बजट दिया है। इसके लिए मैं जितना धन्यवाद दूं, उतना कम है। मैं दिल से धन्यवाद देता हूं।

जब 10 तारीख को माननीय मुख्य मंत्री जी बजट पढ़ रहे थे तो इतना हल्ला मचाया कि देश की संसद में भी बात उठी। मानवीय भूल हो जाती है, लेकिन प्रधान मंत्री जी भी कहानी और किस्से के माध्यम से बजट के ऊपर, इस घटना की बात कहने को मजबूर हो गये। वित्त मंत्री जी कह रही हैं। ऐसा कौनसा पहाड़ टूट गया। हां, मान लेते हैं कि विरोध आपका धर्म है, लेकिन यह मानवीय भूल है। इससे ऐसा कौनसा जनता को नुकसान हो गया, जो इतना ड्रामा और हाहाकार मचा है? यह लोक कल्याणकारी बजट आपको हजम नहीं हुआ। आपके पेट में दर्द हो रहा है। लाइव था इसलिए आपने जोरदार नाटक का मंचन किया। लेकिन जनता समझती है कि आपके पेट में दर्द क्यों है?

आज इन जन कल्याणकारी योजनाओं के कारण राजस्थान की जनता में वह मैसेज गया है कि 2024 में वापस कांग्रेस आ रही है। प्रधान मंत्री जी को एक महीने में 2 बार राजस्थान आने के लिए अगर मजबूर किसी ने किया है तो अशोक गहलोत जी की शानदार योजनाओं ने किया है।

माननीय सभापति महोदय, बार-बार पुरानी और फालतू बातें कई बार की। जैतारण से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे, मैं आपको कह रहा हूं कि आपको इतने कशीदे पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप बुजुर्ग नहीं हो, आप जवान हो इसलिए आपकी टिकट नहीं कटेगी। बुजुर्गों की टिकट कटने वाली है। आपको कशीदे पढ़ने की जरूरत नहीं है।

माननीय सभापति महोदय, गरीब हित में फायदा होता है तो यह नाखुश होते हैं। गरीब और किसान का भला होता है तो इनके पेट में दर्द होता है। अगर बजट में कोई कमी है तो वह कमी बतायें कि इस योजना में यह फर्क है, यह गड़बड़ है, तो हम आपको धन्यवाद देते।

माननीय सभापति महोदय, कोई 2013 की बात कर रहा है। कोई नेहरू जी की बात कर रहा है। मुझे तो लग रहा है कि अगर इनको बुखार भी

(श्री मदन प्रजापत)

आता है तो वह नेहरू जी के कारण आता है। कभी भूख नहीं लगती है तो उसका कारण भी नेहरू जी बन जाते हैं। थोड़ी बहुत तो शर्म होती है।

भाजपा को चिंता इसलिए है कि इस शानदार बजट के कारण राजस्थान में कैसे चुनाव लड़ेंगे। एक तरफ आवाज आ रही थी कि घोषणाएं करो, वोट लो, वापस सत्ता बनाओ। सच्चाई वास्तव में आ ही जाती है। बीजेपी के एमएलए ने स्वीकार किया है कि राजस्थान में वापस कांग्रेस रिपीट हो रही है। मैं दावे और विश्वास के साथ कह सकता हूं कि 2024 में हम आयेंगे और सामने बैठना आपकी मजबूरी होगी।

माननीय सभापति महोदय, गत बजट में भी कहा कि धरातल पर कैसे आयेगा? पैसा कहां से आयेगा? बजट शानदार है, लेकिन धरातल पर उतरे तब। धरातल पर पहले वाला भी उतरा और यह भी उतरेगा। यह चिंता आपकी नहीं है। इनको मैं कहना चाहता हूं कि यह चिंता लोकप्रिय मुख्य मंत्री अशोक गहलोत जी की है, उनकी जादूगरी है। आपकी समझ के ऊपर होकर जा रही है। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। 2024 में सरकार आ रही है।

आज बहस राजस्थान के बजट पर है और कई अंधभक्त पुरानी कैसेट्स पढ़ रहे हैं। मैं कह सकता हूं कि आप फर्जी गौ भक्त हैं। अनुदान उन्होंने बढ़ाया। बीफ का निर्यात हिन्दुस्तान से बढ़ा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बढ़ा है। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या गुजरात और यूपी में कत्लखाने बंद हो गये? क्या बूचड़खाने बंद हो गये? उस समय आपकी बोलती बंद क्यों है? योगी जी के चुनाव में बड़े-बड़े नारे लगे थे। आज गूंगे की तरह चुप क्यों हैं? यहां से 25 सांसद जनता ने भेजे थे तो क्या एक ने भी बूचड़खाने की बात कही।

माननीय सभापति महोदय, आज बातें मैं भी कह सकता हूं लेकिन मैं यह नहीं कहूंगा। क्या काला धन आ गया? 15 लाख मिल गये? अच्छे दिन आ गये? बजट राजस्थान का और श्रीलंका की तुलना राजस्थान से कर रहे हैं। केन्द्र की वकालत की बजाय आपको जनता ने भेजा है तो किसानों की वकालत करो, जनता की वकालत करो। आप सिर्फ चमचागीरी और उनको राज़ी करने के लिए कर रहे हैं।

माननीय सभापति महोदय, एक सब पर भारी, यह लोकतंत्र है, यह राजा-महाराजा नहीं हैं। एक सब पर भारी, अडानी जी को कह सकते हैं कि हिन्दुस्तान में सब पर अडानी भारी है। अडानी जी कह सकते हैं। मोदी जी

(श्री मदन प्रजापत)

लोकतंत्र में प्रधान मंत्री हैं, राजा-महाराजा नहीं हैं। डबल इंजन की सरकार, मैं तो महापुरुष मानता हूं, प्रधान मंत्री जी को मानता हूं, लेकिन डबल इंजन, इंजन तो लोहे का होता है। यह तो सज्जन महापुरुष हैं, इंसान हैं। क्या इंसान भी लोहे का इंजन बन जाता है? समझ में नहीं आया कि यह डबल है या सिंगल है?

कभी 56 इंच का सीने का नारा देना। विजन नाम की चीज नहीं है। फील गुड, शाइनिंग इंडिया, अच्छे दिन, अमृत काल, भाइयों और बहनों, महंगाई से लोग मर रहे हैं, बेरोजगार रोड पर घूम रहे हैं। इनको अमृत काल की पड़ी है। दो जून की रोटी नहीं है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने बजट में गरीब के लिये किया है। आप वकालत अडानी जी की कर रहे हैं। आप चमचागीरी केन्द्र सरकार की कर रहे हो। क्या आपने धन्यवाद दिया है कि 25 लाख तक का गरीब का बीमा, 10 लाख दुर्घटना बीमा, खेत बेचने को मजबूर नहीं होना पड़ेगा। 25 लाख रुपये तक हिन्दुस्तान में कोई इलाज फ्री होता है तो राजस्थान में और अशोक गहलोतजी के राज में होता है।

माननीय सभापति महोदय, समय कम है। कभी प्रधान मंत्रीजी प्रेस के सामने नहीं गए लेकिन अडानी लूटे तो देश कंगाल नहीं और गरीब को राहत दे दी, देश कंगाल हो जाएगा, जैसे अर्थशास्त्री भाषण दे रहा है और ऐसे नाटक कर रहे हैं जैसे भगवान के नाम पर, गम्भीरता से कह रहा हूं, ईमानदारी से, किस बात की ईमानदारी की आप बात कर रहे हैं और किस मुंह से किसान का नाम ले रहे हैं? किसानों ने आपको मजबूर किया और मुंह की खानी पड़ी और तीनों बिल वापस लेने पड़े। मैं पूछना चाहता हूं कि 2022 में आय दुगुनी हो गई? काला धन आ गया? आप वाली कोई बात नहीं, 'के' फोर कोयला, 'ए' फोर आदर्श। दस सालों से शासन में हो, आपको किसने रोका? आपके एक भी आरोप सिद्ध हुए? असत्य बोलने से, जनता समझ गई है, यह एक्टिंग, दारू, शराब, क्या गुजरात में बंद हो गई? मुंह सूख गया है, इसलिए कभी श्रीलंका से तुलना करते हैं, हम गरीब की भलाई के लिए बात करते हैं।

माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से दो मांग करते हुए मैं स्थान ग्रहण करूंगा। मैं आपसे निवेदन करता हूं और मुझे मुख्य मंत्रीजी से उम्मीद है और भरोसा है कि भगवान श्रीकृष्ण ने कहा है,

"बस कर्म तुम्हारा कल होगा,
कर्म में अगर सच्चाई हो तो,
कर्म कहां निष्फल होगा,

(श्री मदन प्रजापत)

हर बार संकट का हल होगा,
आज नहीं तो कल होगा,
आज नहीं तो कल होगा।''

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि बालोतरा जिले के लिए जरूर हमें थोड़ी निराशा होगी लेकिन उम्मीद अभी बाकी है। (व्यवधान)

''ना हारेंगे हम हौसला, इस बात की तसल्ली रख,
जो यूं ही मिट जाना होता तो कब के ही मिट गए होते,
कब के ही मिट गए होते।
इसलिए हारें न हौसला हम,
इस बात की तसल्ली रख।''

माननीय सभापति महोदय, मुझे भरोसा है कि माननीय लोकप्रिय मुख्य मंत्रीजी ने छप्पर फाड़ कर दिया है। हर वर्ग के लिए दिया है। पेंशन हो, दवाई हो, हर वर्ग के लिए दिया है। आपके श्रीमुख से 16 तारीख को अगर घोषणा होती है कि बालोतरा जिला बन गया तो मैं आपका दिल से आभार व्यक्त करता हूं। पूर्व मंत्रीजी कह रहे थे कि ढोंग है, जब बनेगा तब बन जाएगा। आपकी गलती नहीं है, आपकी उम्र है, 80 साल की उम्र है, उनकी गलती है। जब बन जाएगा, तब बन जाएगा। मेहमान घर पर आ गए, जब खाना बनेगा तब खिला देंगे, भूख अभी लगी। आपने कभी एक बार भी मांग नहीं की, आप कह रहे हो कि बन जाएगा बालोतरा में बैठे-बैठे। इसलिए यह जनता के साथ कुठाराघात है।

माननीय सभापति महोदय, जिले के अलावा एक हमारी प्रमुख मांग है, बालोतरा बड़ा है, रिफाइनरी की वजह से आबादी बढ़ गई है, बाहर से हजारों-लाखों लोग आ गये हैं, पानी स्टोरेज के बिना पानी सप्लाई सम्भव नहीं है, इसलिए बालोतरा में पन्द्रह दिन का पानी स्टोरेज बनाना अति जरूरी है क्योंकि रिफाइनरी के कारण अतिरिक्त भार पड़ गया है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि रिफाइनरी के कारण बढ़ी आबादी के कारण पानी स्टोरेज की बात हो, सीनियर हायर सैकंडरी स्कूल की बात हो, पीएचसी हो, सड़क और टाउन हाल, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के नाम से पुराना है ओर उनके लिए बजट दिया जाए। माननीय स्वायत्त शासन मंत्रीजी भी विराजमान हैं, दो बार आपने हमारे

(श्री मदन प्रजापत)

सीवरेज के लिए 190 करोड़ रुपये पास कर दिए, मैं आपका दिल से आभार व्यक्त करता हूं। इसका थर्ड पार्ट है, ड्रेनेज सिस्टम, पानी निकासी का 56 करोड़ रुपये का, वो पेंडिंग है। इसलिए मैं करबद्ध निवेदन करता हूं कि आप उसमें जल्दी थर्ड पार्ट स्वीकृत करें ताकि 232 करोड़ रुपये की योजना पूरी हो सके।

माननीय सभापति महोदय, माननीय राठौड़ साहब एक बात कर रहे थे कि रिफाइनरी, रिफाइनरी की लागत बढ़ना और देर होना और सात साल लेट होना, इसका श्रेय यदि किसी को जाता है तो आपको जाता है। आपकी हठधर्मिता के कारण सात साल तक बंद रखा और हमने जन आंदोलन के माध्यम से वसुन्धराजी की सरकार को मजबूर कर दिया, चाहे सौ किलोमीटर हजारों लोग पैदल चले कि रिफाइनरी हमारा हक है और इसे हम लेकर रहेंगे, यह कोई भीख नहीं है और मजबूर होकर मारवाड़ी में कहावत है कि परणिज्योड़ी पाछी कदै नीं परणीजे।

माननीय सभापति महोदय, माननीय मनमोहन सिंह जी, सोनिया गांधी जी और लोकप्रिय मुख्य मंत्री, अशोक गहलोत जी ने शिलान्यास किया सितम्बर 2013 में और कलियुग के कारण वापस उनका शिलान्यास, हमने विरोध किया, तो कार्य शुभारम्भ हो रहा है। कान इधर से पकड़ो या उधर से पकड़ो, सात साल के कारण जो बर्बादी हुई है और करोड़ों रुपये ज्यादा लागत लगी, इसलिए इसका कोई गुनाहगार है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है।

माननीय सभापति महोदय, शर्म कई लोगों को आती है, कई को नहीं आती है लेकिन थोड़ी-बहुत तो होनी चाहिए। किस भाषा में कह रहे हैं? जीरो, डबल जीरो करे, बजट हवा में है। कोई कह रहा है, बजट 2022-23 का पढ़ा जा रहा है। एक कागज, दो शब्द पढ़कर कौनसा पहाड़ टूट गया? इसका मतलब यह है कि यह गरीब, किसान, युवा, मजदूर और छत्तीस कौम के हित में बजट था। आपको डर लगा, मुकाबला कैसे करेंगे? राजस्थान के इस जादूगर का मुकाबला कैसे करेंगे, चुनाव में जनता के बीच में कैसे जाएंगे? यह डर आपके मन में पैदा हो गया, इसलिए मुझे विश्वास है और आपके मन में भी है कि जगह परिवर्तन होने वाली नहीं है, जो भले लोग हैं, मैं चाहता हूं कि वे वापस आएं और माननीय सभी मुखिया, यथा स्थिति में उन्हीं सीट पर बैठे रहें।

माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय कटारियाजी को बधाई देता हूं कि आज विधान सभा के प्रतिपक्ष के नेता राज्यपाल के रूप में जो बनाये गये हैं, यह अपने लिए एक बहुत बड़ी बात है। मैं इनका आदस्सत्कार करता हूं,

(श्री मदन प्रजापत)

बधाई देता हूं। कई इनके लेन में लगे हैं यह आपका अंदरूनी मामला है लेकिन मैं आप सबके लिए पुन: कामना करता हूं कि आप पुन: इन्हीं सीटों पर विराजे रहें और 2024 में हम शानदार, 2023 में, 2024 भी आ रहा है। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): माननीय सभापति महोदय, इसका मतलब 2023 और 2024, दोनों में हमारी सरकार बन रही है। असत्य का पुलिंदा खुल गया है। भाइयों और बहनों, काला धन, धोळा धन, अब लोग बहकावे में आने वाले नहीं हैं हिन्दू-मुस्लिम के, इसलिए आज वर्तमान आर्थिक स्थिति, अडानीजी के कारण एलआईसी की क्या स्थिति हो गई? देश के आर्थिक हालात खराब हो रहे हैं।

श्री सभापति: समाप्त करें। श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी।

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): आप श्रीलंका की बातें कर रहे हैं, मैं पूछना चाहता हूं कि चाइना को एक बार भी लाल आंख दिखाई होती तब आप बोलने के हकदार हो, अन्यथा इनके असत्यों को जनता समझ गई है। धन्यवाद। आपका बहुत-बहुत आभार। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, कृपया इन्टरवीन न करें, ...(व्यवधान) बाकी वक्ता बोलने से रह जाएंगे। (व्यवधान) माननीय सदस्य, आप गम्भीर नहीं हैं तो मैं सदन स्थगित करूं? बाकी वक्ता रह जाएंगे, आपके बोलने से। श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी।

श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): आदरणीय सभापति महोदय, आपने बजट पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय सभापति महोदय, मेरा यह दूसरा बजट सेशन है और कहीं न कहीं सुबह से जो चर्चा चल रही है वह मुझे कंफ्यूज कर रही है कि राजस्थान के बजट पर चर्चा कर रहे है या केन्द्र सरकार के बजट पर चर्चा कर रहे हैं? केन्द्र सरकार के बारे में चर्चा करने के लिए वैसे तो योग्य नहीं हैं यहां पर बैठे हुए सभी विधायक, क्योंकि 25 के 25 हमारे सांसद गये हुए हैं। केन्द्र के बारे में आपको इतनी चर्चा करनी है तो उसका प्लेटफार्म अलग है। यह राजस्थान विधान सभा है और हमें यहां पर जो बजट दिया गया है उसके बारे में चर्चा करनी चाहिए।

(श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी)

माननीय सभापति महोदय, मेरे से पूर्व वक्ता ने इतनी बातें बोलीं कि केन्द्र सरकार ने क्या किया है और क्या नहीं किया है। कहीं न कहीं इतने बड़े 176 पेज के बजट में वो यह नहीं ढूंढ पाए कि उनकी सरकार ने कितनी अच्छी उपलब्धियां की हैं। शायद नहीं है, वो भी इस बात को जानते हैं और मानते हैं कि यह बजट सिर्फ एक घोषणा के रूप में रह जाएगा और धरातल पर नहीं उतरने वाला है।

माननीय सभापति महोदय, केन्द्र सरकार के बारे में इतनी बुरी, इतनी गलतफहमियां, इतनी असत्य बातें करने की जो प्रवृत्ति है, वह बहुत ही गलत है। पूरे विश्व ने इस बात को माना है कि कोरोना काल में अगर कोई अच्छे से मैनेज हो पाया है तो वो हमारी केन्द्र सरकार ने पूरे देश को इसकी व्यवस्था को बहुत अच्छा किया है। वैक्सीन बनाकर पूरे देश में उपलब्ध कराया है और पूरे विश्व ने इस बात को माना है। राजस्थान सरकार के राजस्व में जो टैक्स रेवेन्यू बढ़ा है, जो कि 927 अरब रुपये था, वह बढ़कर 1142 अरब रुपये हो गया है। यह अपने आप में यह दिखाता है कि केन्द्र सरकार की उपलब्धियां बहुत अच्छी हैं। रेवेन्यू बहुत अच्छे से जनरेट हो रहा है और राज्य सरकार को भी मिल रहा है। बार-बार केन्द्र सरकार के बारे में यह बात बोलना और आदरणीय प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी के बारे में यह बात बोलना कि बजट का बस एक पन्ना ही पलट गया था, एक पन्ना कहीं न कहीं मिस हो गया था, तो जब यह बजट मैं पढ़ रही थी, इसके दूसरे पन्ने पर ही यह कोटेशन इन्होंने लिखी है। मुझे लगता है यही पन्ना रह गया था और इस कोटेशन को भी इन्होंने इसमें पूरा नहीं लिखा है, तो मैं यह बात पूरी आप लोगों के सामने बोलना चाहूंगी-

"बस कर्म तुम्हारा कल होगा,
कर्म में अगर सच्चाई है तो कर्म कहां निष्फल होगा,
हर एक संकट का हल होगा,
वह आज नहीं तो 2023 के बाद होगा।"

इस बात का मुझे यकीन है, पूरे राजस्थान को यकीन है। बार-बार असत्य बातें करना, असत्य घोषणाएं करना। इस बात को मेरे विधान सभा क्षेत्र राजसमन्द के सभी लोगों से अच्छा और बेहतर कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि उप-चुनाव के दौरान बहुत सारे मंत्रीगण पधारे थे। उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी घोषणाएं की थीं, जो बड़े-बड़े अखबारों की हैडलाइंस बनी थीं, जिसमें से

(श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी)

एक हैडलाइन 8 फरवरी को दैनिक भास्कर में छपी थी। उसमें यह कहा गया था कि राजसमन्द विधान सभा क्षेत्र में हम मेडिकल कालेज खोलेंगे। दो साल पहले ही वह घोषणा हो जानी चाहिए थी, पर अब चूंकि याद आ रहा है कि वापस से चुनाव आ रहे हैं तो एक घोषणा और होनी चाहिए और उस घोषणा को बहुत अच्छी तरह से ट्वीट करते हुए यह बात बोली गयी कि राजसमन्द विधान सभा क्षेत्र नहीं, राजसमन्द जिले में यह मेडिकल कालेज खोला जायेगा।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह मांग रखना चाहूंगी कि राजसमन्द जिला मुख्यालय, जहां से मैं विधायक हूं, अगर यह मेडिकल कालेज खुले तो हमारे विधान सभा क्षेत्र में खुले, और इसलिए नहीं खुले कि यह सही है अथवा गलत, उसमें तो मैं नहीं जा रही हूं, लेकिन भौगोलिक दृष्टि से राजसमन्द सेंटर में पड़ता है, इस वजह से वह जिला मुख्यालय है। अगर यहां पर खुलता है तो चारों विधान सभा क्षेत्रों के लोगों को बहुत अच्छी तरह से सुविधा मिलेगी।

आदरणीय सभापति महोदय, इतना बड़ा भाषण, इतना बड़ा बजट जो पेश किया गया है, उसके बारे में इतनी माइक्रो डिटेलिंग कि इस विधान सभा क्षेत्र में यह पीएचसी खोलेंगे, इस विधान सभा क्षेत्र में यह कन्या महाविद्यालय खोलेंगे। सबसे पहले तो इतना ज्यादा भेद-भाव कि कांग्रेस के जहां विधायक हैं वहां तो बहुत अच्छे-से घोषणाएं हों ताकि वे वापस आएं और बीजेपी के विधायकों को कुछ न मिले। लेकिन जहां तक मेरी थोड़ी-बहुत समझ है, बजट मैक्रो डिसिजंस पर होना चाहिए कि हम कौन-सी ऐसी नीतियां ला रहे हैं जिससे कि राजस्थान की इस जनता को सुरक्षा मिले, फायदा मिले। उसकी जगह हम माइक्रो डिटेलिंग में गये कि हमारे विधायकों को कैसे सुविधा मिले, कैसे उन्हें फायदा हो।

मुझसे पहले अपना वक्तव्य देने वाले माननीय सदस्य से मैं कहना चाहूंगी, अभी तक आपका जिला नहीं हो पाया तो हम क्या उम्मीद रखें आपकी इस सरकार से? हमारा क्या होगा, जब आपकी ही वे नहीं सुन रहे हैं।

आदरणीय सभापति महोदय, बहुत बड़े-बड़े होर्डिंग्स लगे थे, बहुत बड़ी-बड़ी बातें कही गयी थीं इस बजट के आने से पहले कि यह बजट बचत, राहत और बढ़त की कसौटी लायेगा और इस बजट में सबको बहुत सारी चीजें मिलेंगी, लेकिन इस बजट में कहीं भी इस बारे में चर्चा नहीं की गयी है कि ग्रॉस इनकम राजस्थान की जनता की कैसे बढ़ा रहे हैं, उस विषय में क्या कर रहे हैं।

(श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी)

कहीं भी यह बात नहीं कही गयी बजट में कि एम्प्लायमेंट जनरेट करने के लिए क्या कर रहे हैं, लाभदायक रोजगार के लिए क्या कर रहे हैं। बार-बार बेरोजगारी की बात आती है। बेरोजगारों के लिए इसमें एक राजीव गांधी नेशनल यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम के बारे में भी लिखा है और ऐसी कितनी सारी चीजें लिखी हैं कि हम यूथ के लिए यह करेंगे, लेकिन आज का यूथ, आज का युवा, आज का नौजवान यह नहीं चाहता है कि उसे मुफ्त में रोटी मिले, वह सैल्फ रेस्पेक्ट से दो रोटी कमाना चाहता है और अपने परिवार को खिलाना चाहता है। एमओयूज साइन किये गये, पर इस बजट में उस बारे में कोई बात नहीं रखी गयी कि किस तरीके से इन एमओयूज को धरातल पर लाया जायेगा, कहां पर रोजगार बढ़ रहा है, कौन-सी इंडस्ट्री आ रही है।

आदरणीय सभापति महोदय, बहुत सारी इंडस्ट्रीज के बारे में यहां पर लिखा गया है कि हम जोधपुर और जयपुर में हाट के माध्यम से, ब्लू पोटरी के माध्यम से वह बढ़ाएंगे। मैं जिस जगह से आती हूं राजसमन्द, वहां पर मार्बल एक मेजर प्रोडक्ट है, उसके बारे में कहीं कुछ नहीं लिखा गया। उन स्माल बिजनसमैन के लिए, व्यापारियों के लिए कहीं नहीं लिखा गया कि उनके लिए क्या सुविधाएं प्रोवाइड होंगी। मार्बल इंडस्ट्री एक है और मार्बल हैंडीक्राफ्ट दूसरी चीज है, लेकिन उसे तो हम इस बजट में कहीं भी देख ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि कहीं न कहीं इन्हें सिर्फ यही लगता है कि सिर्फ जयपुर और जोधपुर ही राजस्थान बनाते हैं, मेवाड़ में तो कोई जरूरत ही नहीं है किसी को किसी चीज की। कहीं न कहीं वह भी गलत नहीं हैं, क्योंकि उन्हें जोधपुर तो बचाना ही है और जयपुर में भी वापस आना है तो इसलिए उनका पूरा फोकस वहीं पर बना हुआ है। (व्यवधान) आएंगे हम लोग, आएंगे, कोई बात नहीं सफिया जी, ...(व्यवधान) आप लोग फॉर्च्यूनर की बात न ही करें तो अच्छा है, कहीं आप लोगों की इलेक्ट्रिक स्कूटी, ईवी व्हीकल की हालत न हो, आप लोग तो बस यह मनाएं। जो चर्चा हुई है अभी यहां पर, वह सिर्फ यह बता रही है कि केन्द्र सरकार ने क्या किया। आप लोगों ने अभी तक तो यह बताया ही नहीं कि राज्य सरकार ने क्या किया है, तो कहीं न कहीं आप सबसे पहले यह सोचिये, क्योंकि आपके पास कुछ है नहीं बताने के लिए। हमारी तो जिम्मेदारी है कि हम राजस्थान की जनता को यह बताएं कि यह सरकार किस तरह से निष्फल हुई है।

बेरोजगारों की बात हो रही थी, युवाओं की बात हो रही थी। इतनी सारी बातें की गयीं कि इंग्लिश मीडियम में हम यह विंग चालू करेंगे। जिन स्कूल्स में

(श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी)

200 बच्चे हैं, वहां पर हम इंग्लिश मीडियम की एक विंग रखेंगे। अभी तक जो इंग्लिश मीडियम स्कूल्स हुए हैं उनमें अब तक इंग्लिश टीचर्स नहीं आये हैं। बार-बार यह जो फोकस है इंग्लिश के ऊपर, राजस्थान के युवाओं को, बच्चों को इंग्लिश सीखने से नौकरी नहीं मिलेगी। उन्हें नौकरी तब मिलेगी, जब हम उनकी स्किल्स को डवलप करने की कोशिश करेंगे। (व्यवधान)

आदरणीय सभापति महोदय, नयी विधायक हूं, नयी वक्ता हूं, अगर सभी इतनी बात करेंगे तो मेरा भी थॉट प्रोसेस कहीं न कहीं ब्रेक होता है। आप प्लीज सबसे बोलें कि वे मुझे बोलने का मौका दें।

आदरणीय सभापति महोदय, स्किल इंडिया, जो कि हमारे प्रधान मंत्री जी ने न सिर्फ एक सपना देखा, बल्कि उसे लागू करने की पूरी कोशिश की, राजस्थान में अभी तक स्किल डवलपमेंट पर कोई बात नहीं हुई। इस बजट में थोड़ी-थोड़ी बातें रखी हैं कि हम स्किल डवलपमेंट पर बात करेंगे, लेकिन मेरी समस्या यह है...

श्री सभापति: दो मिनट में समाप्त करें।

श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): सभापति महोदय, मैं आपसे फिर वही निवेदन करूंगी कि आप मुझे 5 मिनट दें। मुझे 10 मिनट का बोला गया था, मैं अपने समय से पहले ही समाप्त करूंगी।

सभापति महोदय, स्किल डवलपमेंट, इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट की बार-बार बातें की जाती हैं, लेकिन कहीं भी यह बात नहीं कही जाती कि ह्यूमन रिसोर्सेज कहां से लाएंगे। इंग्लिश मीडियम स्कूल्स बढ़ा देंगे, लेकिन टीचर्स नहीं हैं। स्किल के लिए हम कुछ प्रयास करेंगे, लेकिन करेगा कौन, स्किल डवलपर्स कौन होंगे? जब आप किसी छोटे फैक्टरी ओनर से, स्माल स्केल इंडस्ट्री बिजनसमैन से बात करेंगे तो आप यह पाएंगे कि वे लोग हमेशा यह बात रखते हैं कि हमारे पास स्किलफुल लेबर नहीं है, हमारे पास टैक्निशियंस नहीं हैं, हमारे पास लाइनमैन नहीं हैं, हमारे पास इलेक्ट्रिशियंस नहीं हैं। ये स्किल्स हमारे बेरोजगारों को मिल सकती हैं, ताकि उन्हें डिफरेंट जॉब आपर्चुनिटीज मिलें। उसके बारे में इस बजट में कहीं भी कोई बात नहीं कही गयी।

चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना, इतनी बड़ी बातें आप सब लोग कहते हैं कि चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना में यह हुआ, वह हुआ। मैं आपका एक छोटी-सी बात पर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी कि पिछले बीस दिनों से इस योजना

(श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी)

का सर्वर काम नहीं कर रहा है, इसकी वजह से प्राइवेट हास्पिटल, जो पेशेंट्स ठीक हो गये हैं, उन्हें भी रिलीव नहीं कर पा रहे हैं और इसके कारण से नये पेशेंट्स भी नहीं आ पा रहे हैं। एक लम्बी क्यू हो गयी है। आप चिरंजीवी योजना में क्या करेंगे, क्या करते हैं, वह तो आप बाद में देखिये, पहले इस सर्वर सिस्टम को ठीक करें, जो कि अभी की प्रोब्लम है। चिरंजीवी योजना में यहां बैठे हुए सभी विधायक जानते हैं कि अगर इतनी अच्छी यह योजना चल रही होती तो आप ही की एक विधायक को धरना नहीं देना पड़ता इस योजना के खिलाफ। इसमें तो मुझे ज्यादा कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लोग खुद अपनी बात को कोन्ट्राडिक्ट करने के लिए तैयार रहते हैं।

पूरे बजट में और पूरे चार साल में सिर्फ और सिर्फ आत्म मुग्धता, narcissism, self-praise, इसके अलावा आप लोगों ने कुछ नहीं किया है। पूरे प्रदेश में क्या नया करेंगे, क्या अच्छी चीजें लायेंगे, उस बारे में बातें न करके हम अपनी कुर्सी कैसे बचायेंगे, जब इस पर कंसंट्रेशन होगा, तो डेफिनेटली राजस्थान की जनता कहीं न कहीं तो सफर करेगी।

हमारे यहां एक वाकया हुआ। एक मंत्री महोदय ने उपचुनाव में आकर कहा था कि अगर आपने हमें सपोर्ट नहीं किया तो आप आपके घर और हम हमारे घर, आगे भी वही होने वाला है। यदि यह बजट राजस्थान की जनता को एक छोटी-सी, जिसको कहते हैं, धमकी के रूप में दिया गया है कि अगर हमें सपोर्ट नहीं किया तो ये जितनी भी घोषणाएं हैं, घोषणाएं बनकर रह जायेंगी। इस तरह की आप लोगों की जो परम्परा है, इसको आपको थोड़ा-सा बदलने की जरूरत है।

मुख्य मंत्रीजी ने बजट भाषण में अल्पसंख्यक समुदायों के लिए विशेष योजनाओं की घोषणा की, अल्पसंख्यक कार्यक्रमों के लिए अलग से ही बहुत सारी चीजें बनी हुई हैं। वित्त निगम बना हुआ है।

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): उनके कार्यों के लिए आयोग बना हुआ है। हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है। संविधान में यह क्लीयरली लिखा हुआ है कि धर्म के आधार पर हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए। सभापति महोदय, इसलिए मैं आपके माध्यम से यह बात रखना चाहूंगी कि इससे अच्छा होगा कि हम एक मानव अधिकार मंत्रालय बनायें,

(श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी)

जिसके अन्दर सभी धर्मों के निर्धन, वंचित एवं पिछड़े व्यक्ति अपनी बात रख सकें। अपनी कोई भी मजबूरी हो, अपनी कोई भी शिक्षा, स्वास्थ्य की उपलब्धियां हों, वह अच्छे से पा सकें।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): सभापति महोदय, प्लीज मुझे बोलने के लिए दो मिनट और दीजिए, क्योंकि एक बहुत ही इम्पोंटेंट पाइंट पर बोलना चाहूंगी। अभी तक राजसमन्द के अन्दर जितनी भी घोषणाएं हुई हैं।

श्री सभापति: आप विराजिये।

श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): दो मिनट। प्लीज, दो मिनट।

श्री सभापति: श्री रूपाराम।

श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): डीएमएफटी के बारे में...

श्री सभापति: अंकित नहीं होगा। माननीय सदस्य, सहयोग करें। प्लीज विराजिए। आपने कहा, मैंने समय दे दिया।

श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): 000

श्री सभापति: श्री रूपाराम।

श्री रूपाराम (जैसलमेर): सभापति महोदय, आपने बजट 2023-24 पर बोलने का मौका दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद। आज सुबह से ही बजट पर चर्चा हो रही है। पक्ष और विपक्ष सब अपनी-अपनी बात बता रहे हैं। मैं इस मौके पर कहना चाहूंगा, राजस्थान और पूरा देश सैकड़ों वर्ष तक गुलाम रहा...

श्री सभापति: माननीय सदस्य, एक बार आप विराजिए। श्री महेन्द्र चौधरी।

समिति प्रतिवेदन

कार्य सलाहकार समिति का प्रतिवेदन (क्र.सं. 35)

श्री महेन्द्र चौधरी (सरकारी उप मुख्य सचेतक): माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सलाहकार समिति के 35वें प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं।

(श्री महेन्द्र चौधरी)

कार्य सलाहकार समिति की बैठक सोमवार, दिनांक 13 फरवरी 2023 को मध्याह्न पश्चात् 3.00 बजे माननीय अध्यक्ष के वेश्म (चैम्बर) में हुई। समिति ने निर्णय लिया कि शुक्रवार, दिनांक 17 फरवरी 2023 से शनिवार, दिनांक 11 मार्च 2023 तक सदन में अग्रेतर लिये जाने वाले कार्य का बंटवारा निम्न प्रकार किया जाए:-

शुक्रवार, दिनांक 17 फरवरी 2023	1. गैर सरकारी कार्य दिवस। 2. नाथद्वारा मन्दिर (संशोधन) विधेयक, 2022; एवं 3. श्री सांवलियाजी मन्दिर (संशोधन) विधेयक, 2022; -पर विचार एवं पारण।
शनिवार, दिनांक 18 फरवरी 2023 से सोमवार, दिनांक 27 फरवरी 2023	बैठक नहीं होगी।
मंगलवार, दिनांक 28 फरवरी 2023 बुधवार, दिनांक 01 मार्च 2023 गुरुवार, दिनांक 02 मार्च 2023 शुक्रवार, दिनांक 03 मार्च 2023 शनिवार, दिनांक 04 मार्च 2023	आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2023-24 से संबंधित अनुदान की मांगों पर विचार एवं मतदान।
रविवार, दिनांक 05 मार्च 2023 से बुधवार, दिनांक 08 मार्च 2023	बैठक नहीं होगी।
गुरुवार, दिनांक 09 मार्च 2023 शुक्रवार, दिनांक 10 मार्च 2023 शनिवार, दिनांक 11 मार्च 2023	आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2023-24 से संबंधित अनुदान की मांगों पर विचार एवं मतदान।

(आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2023-24 से संबंधित अनुदान की शेष मांगें मुखबन्द का प्रयोग किया जाकर दिनांक 11 मार्च 2023 को मतदान हेतु प्रस्तुत की जाएंगी)

(श्री महेन्द्र चौधरी)

सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के 35वें प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि सदन कार्य सलाहकार समिति के 35वें प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है?

(स्वीकृत)

सदन द्वारा प्रतिवेदन पर सहमति प्रदान की गई।

श्री रूपाराम।

आय-व्ययक

आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2023-24 पर सामान्य वाद-विवाद

श्री रूपाराम (जैसलमेर): आज सुबह से ही बजट पर चर्चा हो रही है। पक्ष और विपक्ष अपने हिसाब से बजट पर किसने क्या किया, यह बता रहे थे। मैं इस मौके पर निवेदन करना चाहूंगा कि देश को आजाद हुए75 वर्ष हो चुके हैं। देश की आजादी से पहले जो स्थिति थी, वह किसी से छानी नहीं है। यहां राजस्थान में भाजपा और कांग्रेस दो ही पार्टियां अधिकतर शासन में रही हैं। देश को आजाद कराने के लिए 65 वर्ष तक संघर्ष किया, विपक्ष सामने विराजमान है, उनका रोल करीब-करीब नगण्य रहा है। इसी कांग्रेस पार्टी की चार-पांच पीढ़ी ने सभी धर्मों और वर्गों के लोगों के साथ संघर्ष करके देश को आजाद कराया और आजादी के बाद का यह 75 वर्ष का सफर है।

जब देश आजाद हुआ तब राजस्थान की जो स्थिति थी और जिन कामों की आवश्यकताएं थीं। 1951 में सरकार बनी और 1977 तक 27-28 वर्षों तक सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस का ही राज रहा। उन परिस्थितियों में 5-7 परसेंट लोग ही स्टेट में ऐसे थे, जिनको राज का स्वाद क्या है, पता था। बाकी 90-92 परसेंट लोगों को, वे किसी भी वर्ग के हों, किस भी जाति के हों, किसी भी धर्म के हों, उनको राज का क्या स्वाद होता है, खारा-मीठा, किसी को पता नहीं था तो उस बुरी हालत में पूरे इंडिया में और राजस्थान में भी 27-28 वर्ष तक कांग्रेस ने ही राज किया है और यहां तक लाये हैं।

आजादी के बाद में 75 वर्षों में 20 वर्ष भाजपा का राज रहा, 55 वर्ष कांग्रेस का रहा है। यह 15वीं सरकार है। पहले जो 14 सरकारें बनीं, चाहे किसी की भी सरकार हो, भाजपा की हो या कांग्रेस की हो, इन 5 वर्षों में

(श्री रूपाराम)

विपरीत परिस्थितियां आई हैं, ऐसी पिछली 14 सरकारों में नहीं आई थीं। पहले स्टेट में कांग्रेस की सरकार रही हो या भाजपा की रही हो, सेन्टर में कांग्रेस या गैर कांग्रेसी सरकार रही हो, कभी भी इस प्रकार का भेद-भाव नहीं था। जो भी फण्ड्स का एलोकेशन होता था, किसी स्टेट में हिल स्टेशन या डेजर्ट स्टेशन है या उसकी विकास दर कैसी है, उस ढंग से फण्ड्स का बंटवारा होता था।

राजस्थान स्टेट में चाहे राज बीजेपी का रहा हो या कांग्रेस का रहा हो, इस 15वीं सरकार से पहले राजस्थान में केन्द्र से अधिकतर योजनाओं में पैसा आता था। पेयजल की बहुत समस्याएं थीं तो पेयजल में 90 परसेंट शेयर सेंट्रल गवर्नमेंट का था, स्टेट को मात्र 10 परसेंट ही लगाना पड़ता था और कई योजनाओं में 60 परसेंट से अधिक शेयर केन्द्र का था, स्टेट का 40, 35 और मिनिमम 10 परसेंट था। ऐसी परिस्थितियों में राजस्थान स्टेट में जो रिसोर्सेज हैं, जो काम किया जाना है, इतने रिसोर्सेज नहीं हैं कि हम कम पीरियड में राजस्थान को उच्च स्टेज पर ले जाएं तो इस 15वीं सरकार में सेन्टर ने एकदम

(समय: 19.00 बजे)

ब्रेक लगा दिये। 90 परसेंट जो पीएचईडी के लिए देते थे उसको सीधा ही 50 परसेंट पर लाये। कई योजनाएं हैं जैसे बीआरजीएफ जिसमें करीब 14 जिलों में राजस्थान में पैसा मिलता था, उसको खतम कर दिया। बीएडीपी जिसमें चार जिलों में मिलता था, उसको खतम कर दिया तो इस प्रकार स्थितियां ऐसी बनीं कि स्टेट के पास फंड्स कम हैं।

देश आजाद होने के बाद में पहली बार इतनी बड़ी महामारी कोरोना आई जिसका लगभग दो वर्ष कार्यकाल रहा और 5-6 महीने पहले और 5-6 महीने बाद उसका डर व्याप्त रहा और यह भी रहा कि फिर आ जायेगी। तीसरी बार तो ऐसी विपरीत परिस्थितियों में माननीय अशोक गहलोत साहब ने जो पिछले चार बजट पेश किये, सीमित संसाधनों को देखते हुए महामारी में अधिक खर्च हुआ उसको भी देखते हुए 2 अकाल भी रहे, इन सब परिस्थितियों को देखते हुए पहला बजट पेश किया, तब भी विपक्ष के माननीय साथी कह रहे थे कि सिर्फ घोषणा की है, होगा कुछ नहीं। पहली बार हुआ। मैं खुद भी यहां आप लोगों के साथ बैठने से पहले राज का एक नौकर था।

सभापति महोदय, मैंने कभी भी ऐसा नहीं देखा कि बजट की घोषणा हुई और अप्रैल में जो वित्तीय वर्ष की शुरुआत होती है उसी में लैंड अलाटमेंट हो रही है। एडमिनिस्ट्रेटिव सेंक्शन निकल रही है, फाइनेंशियल सेंक्शन निकल

(श्री रूपाराम)

रही है, टेन्डर की प्रक्रिया हो रही है। कुछ काम आगे-पीछे होते हैं। पूरा सिस्टम होता है। कोई लैंड डिस्प्यूट हो, कुछ कारण हो वह अलग चीज है, लेकिन चूंकि मैं भी उधर से स्विच ओवर करके यहां आया तो मैंने हर बजट में यह भी सुना। यहां चर्चा में हम लोग अपनी बात कहते थे, विपक्ष के साथी अपनी बात कहते थे, लेकिन वास्तव में मेरे विधान सभा क्षेत्र में मैं देखूं तो जो काम हुए हैं, पंचायती राज जब से बना जैसलमेर जिले में तीन पंचायत समिति थीं जैसलमेर, सांकड़ा और सम। हम आधे बूढ़े हो गये तीन ही नाम लेते थे और उसके बीच में कई एमएलए बन गये, राज कांग्रेस का रहा, बीजेपी का रहा, तीन की सवा तीन भी नहीं हुई और अभी चार नयी पंचायत समिति बनीं, कुल सात पंचायत समितियां हैं।

सभापति महोदय, ऐसे ही ग्राम पंचायतें हैं। जब पंचायती राज बना उसके बाद में जो पंचायतें बनीं वो टोटल नयी पंचायतें 37 बनीं। 13 एमएलए रहे और 37 पंचायतें बनीं। अभी हम 2 एमएलए हैं और पीरियड चार वर्ष का है, ग्राम पंचायतें 66 बनीं। इस प्रकार 29 विभागों में से हमारे जैसलमेर जिले में करीब 14 विभाग ऐसे हैं जो देश आजाद होने के बाद में 14 सरकारों में जितना काम हुआ उतना एक सरकार में हो गया। इस प्रकार कोई जैसलमेर को अलग से तोहफा नहीं दिया है। वास्तव में जो काम हुए हैं अभी कुछ साथियों ने कहा व बहनों ने कहा कि काम हुए वो कांग्रेस एमएलए के क्षेत्र में हुए।

सभापति महोदय, अब चिरंजीवी योजना है 25 लाख कर दिये, पहले 10 लाख थे। अब उसके अन्दर कहां कांग्रेस है? चाहे पैसे वाला हो, गरीब हो, हिन्दू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, शहर का हो, गांव का हो, उत्तर, दक्षिण, पूर्व कहीं का हो, सभी के लिए है। सौ यूनिट बिजली फ्री है घर के लिए, दो हजार यूनिट किसान के लिए तो यह कहां वर्ग है? न वर्ग है, न एरिया है। इस प्रकार की 90 परसेंट योजनाएं, कुछ एरिया के हिसाब से स्पेसिफिक योजना हो सकती है, तो कोई भी ऐसी नहीं हैं और जितने भी, चूंकि मैं उनको रिपीट नहीं करूंगा, अलग-अलग विभागों की जो स्कीम्स हुई हैं विशेष करके महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, किसान के लिए, तो उनको मैं रिपीट नहीं करना चाहूंगा पर इन परिस्थितियों में पहले चार बजट में जो घोषणाएं हुईं लगभग 90 परसेंट पूर्ण हो गईं।

अब इसमें यह है कि आज अपन दो सौ विधायक हैं तो अपनी भी ड्यूटी है। आज मेरे विधान सभा क्षेत्र में जितने भी काम हुए हैं चारों साल के

(श्री रूपाराम)

मिला कर, अभी जो घोषणा हुई इसको मिला कर 95 घोषणाएं हुई हैं। अब 95 घोषणाओं को मैं रात को सोता हूं तो सपने में सोचता हूं उसकी जमीन के लिए बात करनी है, उसके लिए यह करना है, वह ठेकेदार ढीला चल रहा है, यह करना है, तो ड्यूटी अपनी भी है। आज अपन दो सौ विधायक हैं चाहे पक्ष में हों विपक्ष में हों, अपन सरकार का अंग हैं। सरकार अलग से, अशोक जी गहलोत साहब अकेले तो हैं नहीं। इस प्रकार पिछली सरकारों का मुझे ज्यादा ध्यान नहीं है, लेकिन लगभग कम्प्लशन हो गया है और अभी भी जो बजट की घोषणा हुई है 10 फरवरी को और सम्बन्धित प्रिंसिपल सेक्रेट्रीज वगैरह को माननीय मुख्य मंत्री जी ने, चूंकि मैं भी आफिसर रहा हूं तो मैं भी जाकर उनसे बात करता हूं कि हां इसका हम यह कर रहे हैं, इसका यह कर रहे हैं, तो अभी प्रकियाएं शुरू हो गई हैं। अब टाइम भले ही कम हो लेकिन अपन सब मिल कर करेंगे और ये घोषणाएं उसी ढंग से की गई हैं, जो भी घाटा-नफा हो वह सब बजट में आ गया।

श्री सभापति: दो मिनट में समाप्त करें।

श्री रूपाराम (जैसलमेर): तो अपने पास जो संसाधन उपलब्ध हैं उसी ढंग से घोषणाएं की गयी हैं और अपन सब लगेंगे। आगे राज किसका आयेगा वह जनता को तय करना है। वह फील्ड में जायेंगे और वह मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि वास्तव में पिछले 25-30 वर्ष से हम लोग भी देख रहे हैं किसका भी राज रहा हो, एक वर्ष पहले लोग हर गांव और ढाणी में सीधे ही कहते हैं कि अबकी बार तो इनको बदलना है। इस बार अब महीने तो सात-आठ रहे हैं, पूरे राजस्थान में मैं भी जाता हूं, कहीं भी यह नहीं है कि इनको बदलना है। अब कौन आयेगा, जनता होशियार है, अपने आप जब वोट होंगे तब वह बता देगी।

मेरा यह निवेदन है कि यह बजट वर्तमान में जो स्टेट की परिस्थिति है विभागवार और अपने पास जो संसाधन उपलब्ध हैं उनको देखते हुए समावेश करके और बहुत बढ़िया बजट माननीय मुख्य मंत्री जी ने दिया है और जो माननीय विधायक महोदय अपनी-अपनी बात कह रहे हैं तो अभी भी कई गुंजाइशें हैं, दो बार और भी होगा तो कमी-बेशी है तो उसमें और होगी। अपन को सबको मिल कर आगे जो भी राज आये, कोई काम अधूरे रह गये तो राज आयेगा तो वह पूरा करा देगा, तो अपन को मिल कर इसको आगे बढ़ाना चाहिये।

सभापति महोदय, मैं कुछ सुझाव स्टेट लेवल के और कुछ मेरे जिले

(श्री रूपाराम)

के देना चाहूंगा। स्टेट लेवल में, माननीय मुख्य मंत्री जी मैं निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान में अभी भी और पूरे इंडिया में जो स्थिति बनी है आठवीं के बाद लड़के और लड़कियों को साधरणतया 90 परसेंट माता-पिता साथ पढ़ाना नहीं चाहते। राजस्थान में 12 हजार कुछ जो ग्राम पंचायतें हैं, अभी भी कई ग्राम पंचायतें ऐसी हैं 70 परसेंट जहां ग्राम पंचायत मुख्यालय पर भी बच्चियों की स्कूल अलग से नहीं है, तो यह बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है।

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री रूपाराम (जैसलमेर): नहीं तो बच्चियां ड्रोप आउट होती हैं। जहां-जहां भी राजस्थान में बच्चियों के स्कूल विहीन जो ग्राम पंचायत मुख्यालय हैं उन सब में संसाधनों को देखते हुए और चरणबद्ध रूप से बच्चियों की स्कूलें हर ग्राम पंचायत मुख्यालय पर खोलें ताकि गांव-ढाणी की बच्चियां उस स्कूल में पढ़ लें।

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री रूपाराम (जैसलमेर): धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री छगनसिंह।

श्री छगनसिंह (आहोर): सभापति महोदय, बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बजट भाषण पर बोलने का मौका दिया।

सभापति महोदय, बजट भाषण पर बोलने से पहले कल जब मैं अपने क्षेत्र में था तो दोनों, राजस्थान पत्रिका और दैनिक भास्कर में मेरे जालोर का पृष्ठ पूरा-पूरा छपा हुआ था, उसमें चार वर्षों की घोषणा का पूरा-पूरा विवरण था जालोर जिले का। उसमें, मुख्य मंत्री जी, पूरा-पूरा लिखा हुआ है कि बजट में घोषणा तो खूब हुई लेकिन काम बीस परसेंट ही हो पाया। यहां पर जो चर्चा हो रही है अस्सी परसेंट काम हो गया। यहां तक कि जल जीवन मिशन का जालोर और जोधपुर दोनों का भी आया है, उसमें भी सबसे ज्यादा पीछे जालोर और जोधपुर है जो मुख्य मंत्री जी का खुद का जिला है, तो यह जल जीवन मिशन में पूरी तरह से और हर घोषणा जैसे कोई भी घोषणा है, इसका पूरे जिले का विवरण दिया हुआ है। एक भी योजना धरातल पर नहीं उतरी है। मैं कैसे इस बजट पर विश्वास करूं जब पुरानी कोई भी योजना धरातल पर नहीं उतरी है तो यह नयी योजना कैसे उतरेगी।

सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, मेरे क्षेत्र में

(श्री छगनसिंह)

जल जीवन मिशन के एफआर प्रोजेक्ट का जो टेन्डर होना था, पिछले साल बजट में घोषणा हुई थी, उससे पहले भी उसमें घोषणा हुई थी, लेकिन अभी तक वह टेन्डर नहीं हुआ है। आज भी जब हम अधिकारियों से बात करते हैं तो वह यही कहते हैं, सर, अभी तक ठण्डे बस्ते में है। लास्ट टाइम में किसी कारण से यह टेन्डर कैंसिल हुआ था लेकिन अभी भी उस पर कोई कार्यवाही नहीं है।

माननीय मंत्री जी बैठे हुए हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि यह बहुत ही महती योजना है। मेरे क्षेत्र में कई गांव ऐसे हैं जहां आज भी पानी नहीं पहुंच रहा है। हर घर जल की आवश्यकता है, जल जीवन मिशन के तहत आपको निवेदन है जैसे कंवला, नोरवा, मालगढ़, घाणा, बरवा की ढाणियां, भवरानी की ढाणियां, रसियावास खुर्द ऐसे कई गांव हैं, ऐसे 22 गांव जालोर पंचायत समिति के बाजरा सियाणा बेल्ट के सभी हैं, उन गांवों में जल जीवन मिशन के तहत पानी पहुंचना है। उसी प्रकार से एफआर प्रोजेक्ट का काम तत्काल शुरू करवा दीजिये, तत्काल इनके टेन्डर करवा दीजिये, मैं इस बजट की तो बात ही नहीं कर रहा, जो पुराने बजट की घोषणा है उसको लागू करने की बात कर रहा हूं।

राजस्थान की जल नीति की जब चर्चा होती है तो जल नीति में एक विषय होता है जल संसाधन, जब बांध बन जाते हैं तो बांध की जल नीति बनी हुई है अपने 2010 में, तो बांध बने उनमें जो नीचे का प्रवाह क्षेत्र होता है, उसमें अधिकतर में पानी नहीं होता है। कई गांव नदियों के किनारे बसे हुए थे, आज स्थिति यह है कि ऊपर बांध बन गये। जालोर जिले में मैं विशेषकर आहोर विधान सभा क्षेत्र की बात करूंगा, हमारे यहां तीन नदियां चलती थीं, तीनों नदियों में पानी था। बरसाती नदियां चलती थीं, दो-तीन महीने नदियां चलती थीं जिससे वहां पर सिंचाई के लिये पानी हो जाता था, पेयजल के लिये पानी हो जाता था। पिछले वर्षों में बांध बनने के बाद वहां नदियां सूख गईं। हमारा पूरा क्षेत्र सूखा हो गया। हमारे क्षेत्र में पेयजल भी उपलब्ध नहीं हो रहा है, सिंचाई की तो अलग बात है। मैं निवेदन करूंगा कि 2010 की जल नीति को अमलीजामा पहनाकर बांध के पानी को नदियों में छोड़ने का आप कुछ प्रावधान करें अन्यथा आने वाले समय में हमारा पूरा क्षेत्र सूखा हो जायेगा। जो जल नीति बनी हुई है, उसके अनुसार उसका जो हक बनता है, उतना पानी छोड़ दीजिए।

जल जीवन मिशन के तहत जो जवाई बांध पुनर्भरण की चर्चा हो रही है, उसको भी अमलीजामा पहनाया जाये। उसका भी अभी तक टेंडर हुआ है लेकिन अभी तक वर्क आर्डर नहीं हुआ है। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन

(श्री छगनसिंह)

करूंगा कि इस जल जीवन मिशन के तहत जो जवाई पुनर्भरण की चर्चा हो रही है, उस पर तत्काल काम शुरू किया जाये।

किसानों की अगर बात करें, हमारे क्षेत्र में 24 गांवों के लिए नहरों की व्यवस्था है। अभी जवाई बांध से 24 गांवों में पानी आ रहा है लेकिन बड़ा दु:ख होता है जब बारीबंदी बन जाती है, बारीबंदी बनने के बाद किसान समझता है कि मेरे 8 घंटे, 12 घंटे पानी आयेगा, इस हिसाब से वह जुताई करता है। जुताई करने के बाद जब पानी टेल क्षेत्र में आता है तो उसका खेत ऐसे ही सूखा रहता है। उसके नहरों का पानी तो नहीं आता लेकिन उसकी आंखों से जरूर पानी आता है। मैं सिंचाई मंत्री जी निवेदन करूंगा कि इस प्रकार की व्यवस्था करें कि जो टेल क्षेत्र में किसान हैं, उनको पूरा पानी कैसे मिले और जिन किसानों ने जुताई की है, उनको भी कोई न कोई अनुदान दिया जाये और अधिकारियों को भी पाबंद करें कि अगर इस प्रकार की हरकत हो रही है, किसान अगर परेशान हो रहा है, मैं उन पर भी कोई न कोई कार्रवाई करने की आवश्यकता महसूस करता हूं।

शिक्षा के क्षेत्र की बात करूं, शिक्षा में सभी बात करते हैं कि शिक्षा बहुत आवश्यक है। हर ग्राम पंचायत स्तर पर सीनियर हायर सैकण्डरी स्कूल की पूर्ववर्ती सरकार ने भी घोषणा की। अभी जो नई ग्राम पंचायत समिति बनी, उसमें भी इस सरकार ने घोषणा की लेकिन, सभापति महोदय, हालत यह है कि वहां पर न तो प्रधानाचार्य हैं, न व्याख्याता हैं, न शिक्षक हैं। जो शिक्षक बचे हैं, उनको कहीं न कहीं गैर शैक्षिक कार्यों में लगा दिया जाता है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि शिक्षकों की ड्यूटी अन्य सामाजिक कार्यों में न लगा कर कोई भी नवाचार करके अन्य किसी संस्था से यह कार्य करवाये जाएं। उसमें चाहे बीएलओ का काम हो, कुछ भी हो, एक अलग से यूनिट बनाई जाये और उनसे वह कार्य करवाया जाये क्योंकि जहां तक हम देखते हैं राजकीय विद्यालयों में अधिकतर गरीब और वंचित लोग पढ़ाई करते हैं और जब वहां पढ़ाई ही नहीं होगी तो फिर वही स्थिति आयेगी जिसकी हम यहां सदन में चर्चा कर रहे हैं। बार-बार चर्चा कर रहे हैं कि हम गरीबों का उत्थान करेंगे, गरीबों का भला करेंगे। बच्चे जहां पढ़ाई करते हैं, वहां शिक्षक नहीं होंगे तो पढ़ाई कैसे करेंगे और पढ़ाई नहीं होगी तो वह गरीब तबका गरीब ही रहेगा, वंचित तबका वंचित ही रहेगा। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि गैर शैक्षिक कार्यों में जिन शिक्षकों को लगाया जाता है, उनसे तुरंत ऐसे कार्य बंद करवाकर एक नई संस्था

(श्री छगनसिंह)

से वह कार्य करवाये जाएं जिससे आने वाले समय में बच्चों का भी भला होगा और जो योजना आयेगी, वह भी बाटम टू टाप कैसे पहुंचे वास्तव में इसका कार्य होना शुरू हो जायेगा और शिक्षक भी अपने मन से बच्चों को पढ़ायेंगे। उनको पता होगा कि अब हमें सिर्फ एक ही काम करना है, सिर्फ पढ़ाना है। इसलिए ऐसी व्यवस्था हमें करनी चाहिये।

अगर बिजली की बात करें, सभी ने बिजली की बड़ी-बड़ी बातें कीं। बिजली की 100 यूनिट की घोषणा भी हुई, अच्छी बात है। मेरा पूरा विधान सभा क्षेत्र गांवों में है, ऐसा कोई दिन नहीं होता कि मेरे हर गांव से फोन नहीं आता हो कि लाइट नहीं है। मैं बार-बार कहता हूं कि शाम को 6 से 10 बजे तक लाइट नहीं होती। जब लोगों को लाइट की आवश्यकता होती है, उस समय बिजली नहीं होती है। सुबह आवश्यकता होती है, उस समय बिजली नहीं होती है। यह किस प्रकार की व्यवस्था है? जब हम बिजली उत्पादन में पूरे भारत में प्रथम आ रहे हैं, आपने बजट भाषण में भी कहा है कि हम बिजली उत्पादन में पूरे भारत में प्रथम हैं तो फिर यह बिजली की कमी कहां हो रही है? बिजली कहां चोरी हो रही है, इस पर भी सरकार को संज्ञान लेना चाहिये। सिर्फ बजट भाषण में बोलने से और सिर्फ कहने से कुछ नहीं होगा, वास्तव में धरातल पर कार्रवाई नहीं हो रही है। जिस प्रकार से एक घोषणा हुई थी कि आने वाले समय में 2022 तक सभी किसानों को बिजली के कनेक्शन दिये जायेंगे। मैं मेरे जालोर जिले की बात कर रहा हूं, अभी तक 2014 तक के डिमांड भरे हुए के विद्युत कनेक्शन नहीं हुए 8 साल के तो अभी तक बाकी हैं। यह मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आपने जो घोषणा की है कि 2023 तक हम सभी को कनेक्शन दे देंगे...

श्री सभापति: दो मिनट में समाप्त करें।

श्री छगनसिंह (आहोर): मैं तो यह कह रहा हूं कि जिन किसानों के कनेक्शन हैं, ट्रांसफार्मर जल जाते हैं, 15-15 दिन तक किसान रोता है, बिजली विभाग में एक्स ईएन आफिस में जाकर 15-15 दिन तक बैठता है, अधिकारियों से कई बार बात करते हैं फिर भी उनको ट्रांसफार्मर नहीं मिलता है। इस प्रकार की व्यवस्था को सुधारने की आवश्यकता है। सभापति महोदय, किसानों की सिर्फ बात न करके इस पर कार्रवाई करनी भी जरूरी है।

सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य ने गौ माता पर बहुत बड़ी चर्चा की। हमारी वसुन्धरा जी का विजन था, विजन वह होता है कि आगामी समय

(श्री छगनसिंह)

में हम क्या फलीभूत कर सकते हैं? इसलिए एक गौ संवर्धन सेस लगाया था, उसी सेस से आज हम गौ माता के लिये अनुदान देते हैं। यह किसी का विजन था, इस प्रकार की सोच होनी चाहिये कि जो हम आज काम कर रहे हैं, वह लंबे समय तक फलीभूत कैसे हो, तो जो स्टांप पर और मदिरा पर सेस लगाया था, उसी सेस के कारण आज हम गौ माता को और नंदियों को अनुदान दे रहे हैं। मैं मेरे क्षेत्र की बात करूंगा, वहां एक भी नंदीशाला नहीं है। मैं निवेदन करूंगा बजट भाषण में नंदीशालाओं की सिर्फ चर्चा करने से कुछ नहीं होगा, हमें आवश्यकता है कि इस पर लंबी चर्चा न करके धरातल पर काम कैसे हो, इसकी मैं आवश्यकता महसूस करता हूं।

मैं लंबी चर्चा नहीं करते हुए, अभी चिकित्सा मंत्री जी बैठे हुए थे, चले गये, ऊण और संकवाली में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हर दृष्टि से जरूरी है। वहां पर 15-15 गांव लग रहे हैं, वहां पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की आवश्यकता है। जब मुख्य मंत्री जी रिप्लाई दें तो ऊण और संकवाली में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की घोषणा करावें। इसी प्रकार भाद्राजून तहसील मुख्यालय पर भी पीएचसी ही है, वहां तहसील मुख्यालय पर सीएचसी की सख्त आवश्यकता है।

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री छगनसिंह (आहोर): भाद्राजून, बागरा, आरआई सर्किल, भाद्राजून बागरा में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र की सख्त आवश्यकता है। रसियावास, खुर्द, पलासिया, गुढ़ारामा,..

श्री सभापति: समाप्त करें। श्री हीराराम।

श्री छगनसिंह (आहोर): सुमेरगढ़ खेड़ा, गोबिंदल्ला में सब सेंटर की आवश्यकता है। माननीय, अभी तो छह मिनट हुए हैं।

श्री सभापति: विराजिए। अंकित नहीं होगा। श्री हीराराम।

श्री हीराराम (बिलाड़ा): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बजट पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। अभी समय का अभाव होने के कारण मैं सीधा अपने बिलाड़ा विधान सभा क्षेत्र पर ही बोलूंगा।

माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय का बहुत-बहुत आभार प्रकट करता हूं उनको धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मेरे बिलाड़ा विधान सभा में औद्योगिक क्षेत्र खोला, जिससे उद्योग धंधा करने वाले जो लोग चेन्नई, बैंगलोर, मुम्बई वगैरह जा रहे थे, वह अभी यहीं धंधा करेंगे और औद्योगिक क्षेत्र में अपना काम संभालेंगे।

(श्री हीराराम)

दूसरा, बिलाड़ा नगरपालिका में सीवर लाइन के लिए घोषणा की, इसके लिए माननीय मुख्य मंत्री महोदय का बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं। बिलाड़ा एवं पीपाड़ शहर में उच्च स्तरीय खेल सुविधा हेतु खेल स्टेडियम की दोनों नगरपालिकाओं में घोषणा की, इसके लिए मैं मुख्य मंत्री महोदय का बहुत-बहुत आभार प्रकट करता हूं। पीपाड़ शहर में जल प्रदाय योजना हेतु 5.57 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की, इसके लिए मैं बहुत-बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। मैं मेरी विधान सभा की मुख्य मांगें रखता हूं।

माननीय सभापति महोदय, ग्राम पंचायत जालेली फौजदार में मुख्य मंत्री महोदय की सभा थी, प्रशासन गांवों के संग। जब वे पधारे थे तो वहां पर लोगों की मांग थी कि 16 गांवों को पानी देने के लिए बड़ा हौज बनायें और प्रोजेक्ट बनाकर यहां पर पानी की सप्लाई करें। माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने डीपीआर बनाने के आदेश दे दिये थे। इसकी 25 करोड़ 96 लाख की डीपीआर बनाकर जलदाय विभाग द्वारा राज्य सरकार को भिजवा रखी है। श्रीमान जी से निवेदन है और मंत्री महोदय भी विराजमान हैं, मेरी यह योजना स्वीकृत करायें। नगरपालिका बिलाड़ा में मीठा पानी देने की मांग करता हूं क्योंकि अब जो थर्ड स्टेज चालू हो जायेगा, इसमें 1799 करोड़ की योजना है। बिलाड़ा के लिए भी मैं मीठा पानी देने की मांग करता हूं। सभापति महोदय, बिलाड़ा में डांगियावास बड़ा कस्बा है, जहां काफी वर्षों से उप तहसील खोल रखी है, उसको तहसील में क्रमोन्नत करें, यह मैं मांग करता हूं।

बिसलपुर फाटा से ग्राम पंचायत पालासनी तक 9 किलोमीटर, लाम्बा से तिलवासनी तक 12 किलोमीटर एवं घाणामगरा से बिरावास तक 5 किलोमीटर डामर सडक स्वीकृत करवाने की कृपा करावें, क्योंकि मेरे को इस बजट में एक भी सड़क नहीं मिली है, इसलिए मैं मुख्य मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि मुझे ये रोड दें। ग्राम पंचायत बुचकल्ला, काकेलाव, भण्टिडा, मालकोसनी में उप स्वास्थ्य केन्द्र, इसके लिए हमारे वहां से प्रशासन के द्वारा भी मुख्य मंत्री जी के यहां पर भेजा गया है। वहां पर काफी समय से उप स्वास्थ्य केन्द्र है, इनको प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत करना अतिआवश्यक है।

माननीय सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा में ग्राम जेतीवास, ओलवी, मालकोसनी, भण्टिडा, इन ग्राम पंचायतों में 33/11 केवी जीएसएस स्वीकृत करवाया जाये। मेरे विधान सभा क्षेत्र में 5 साल में एक भी जीएसएस नहीं मिला है, इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि मुझे जीएसएस दिया

(श्री हीराराम)

जाये। ग्राम पंचायत फिटकासनी में राजकीय प्राथमिक विद्यालय को उच्च प्राथमिक विद्यालय में क्रमोन्नत कर बालिका विद्यालय में परिवर्तन करवाना अतिआवश्यक है, इसलिए इसको परिवर्तित किया जाये। नगरपालिका शहर में स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, बिलाड़ा को कन्या महाविद्यालय में क्रमोन्नत किया जाये, क्योंकि यहां 600 से ज्यादा बच्चियां हैं। औद्योगिक क्षेत्र बोरूंदा में लिग्नाइट का ज्यादा धंधा है, वहां पर आई.टी.आई. महाविद्यालय खोला जाये, इसकी मैं मांग करता हूं। पीपाड़ शहर में एडीजे कोर्ट स्वीकृत करवाने की मांग करता हूं। ग्राम पंचायत बोरूंदा में सीएचसी 2001 में खुली, लेकिन आज तक डाक्टरों के पद स्वीकृत नहीं हुए इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि वहां पर सीएचसी तो है, लेकिन पद नहीं हैं, इसलिए पद स्वीकृत कराकर वहां पर डाक्टर लगाये जायें, यह मैं मांग करता हूं। वहां पर लोगों का धरना चल रहा है और काफी समय से धरना देकर लोग बैठे हुए हैं। मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि यह जो सीएचसी 2001 से बनी है, इसके लिए डाक्टरों के पद सृजित करके डाक्टर लगाये जायें। पीपाड़ शहर में केन्द्रीय बस स्टैण्ड स्वीकृत करवाने की कृपा करावें। बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द, जय भारत।

श्री सभापति: श्री जोराराम कुमावत।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री महेन्द्र चौधरी (सरकारी उप मुख्य सचेतक): माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय आधा घंटा बढ़ाकर 8.00 बजे तक कर दिया जाए।

श्री सभापति: सदन का समय बढ़ाया जाए?

(स्वीकृत)

सदन का समय 8.00 बजे तक के लिए बढ़ाया गया।

आय-व्ययक

आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2023-24 पर सामान्य वाद-विवाद

श्री जोराराम कुमावत (सुमेरपुर): सभापति महोदय, वर्ष 2023-24 के बजट पर बोलने का मौका दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद। 10 फरवरी को माननीय

(श्री जोराराम कुमावत)

मुख्य मंत्री जी ने वर्ष 2023-24 का बजट पेश किया। राज्य सरकार के पिछले चार बजटों की तरह ही यह बजट भी घोषणाओं का बजट साबित हुआ। चार वर्षों का पर्याप्त समय मिलने के बाद भी सरकार अपनी चार वर्षों की जो घोषणाएं थीं, उनको धरातल पर नहीं उतार सकी। अब तो सिर्फ आठ महीने बाकी रह गये हैं, ये घोषणाएं कैसे धरातल पर उतरेंगी, यह चिन्ता का विषय है। यह बजट सिर्फ घोषणाओं का पिटारा है। इन थोथी घोषणाओं पर जनता विश्वास करने वाली नहीं है।

मुख्य मंत्री जी के पिछले कार्यकाल 2008-2013 के समय में भी इसी तरह से अन्तिम वर्ष के बजट में मुख्य मंत्री जी ने रेवड़ियां बांटी थीं, लेकिन वे भी धरातल पर नहीं उतरी थीं। इस बजट के पैरा संख्या-8 में मुख्य मंत्री जी ने बताया कि 500 करोड़ रुपये के युवा विकास एवं कल्याण कोष की घोषणा करता हूं, जो पैसा युवाओं के विकास पर खर्च होगा। सभापति महोदय, मैं आपके मार्फत सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि युवाओं को रेवड़ियां बांटकर देश के भविष्य को कमजोर नहीं करें। आप तो सिर्फ राज्य सरकार के सभी विभागों के जितने पद रिक्त हैं, उन रिक्त पदों पर भर्तियां निकालकर बिना पेपर लीक किये ईमानदारी से परीक्षा करवायें और सारी नौकरियां उन युवाओं को देंगे तो निश्चित रूप से युवाओं का भला हो जायेगा।

आज हम डीजल-पेट्रोल की बात करें तो राजस्थान के लोग जब गुजरात, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, असम या देश के अन्य प्रदेशों में जाते हैं तो वहां पर डीजल और पेट्रोल 10 से 14 रुपये तक कम में मिलता है। गुजरात में टैक्स कम है, दूसरे स्टेटों में टैक्स कम है। इस बजट में जनता आस लगाये बैठी थी कि राजस्थान के जो मुख्य मंत्री हैं, वे इस बजट में डीजल और पेट्रोल पर वैट कम करेंगे तो निश्चित रूप से हम लोगों को फायदा मिलेगा, लेकिन बजट में वैट घटाने का कोई प्रावधान नहीं किया, इससे जनता को निराशा हाथ लगी है। सभापति महोदय, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से भी निवेदन करना चाहता हूं कि आम लोगों को फायदा देने के लिए डीजल और पेट्रोल पर वैट घटायें, इससे निश्चित रूप से जनता को फायदा मिलेगा।

आज पूरे देश में सबसे ज्यादा महंगी बिजली राजस्थान में है और पिछले चार सालों में आपने कई बार बिजली की रेटें बढ़ायी हैं। कई बार यूनिट रेट बढ़ायी, स्थायी सेवा शुल्क बढ़ाया, फ्यूल चार्ज बढ़ाया, मीटर किराया बढ़ाया। इस तरह से 9 बार बिजली की रेटें बढ़ायी हैं। बजट में जरूर आपने

(श्री जोराराम कुमावत)

100 यूनिट मुफ्त बिजली देने की घोषणा की है, लेकिन 100 यूनिट मुफ्त देने के बाद भी बिजली कहां आती है, कब आयेगी, कब जायेगी? पता ही नहीं है। लोगों को पर्याप्त मात्रा में बिजली नहीं मिलती है। यदि बजट में बिजली की दरें घटायी होतीं तो निश्चित रूप से आम लोगों को यह सारा फायदा मिलता।

पाली जिले व राजस्थान भर में वर्ष 2022-23 खरीफ की फसल अकाल पड़ने व कम बरसात से खराब हुई, जिससे किसानों की खरीफ की फसलें 80 परसेंट नष्ट हो गयीं, लेकिन सरकार ने फसल खराबे का आदान-अनुदान किसानों को अभी तक नहीं दिया है और इस बजट में भी घोषणा नहीं की है, जिससे क्षेत्र का किसान आहत है। सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि 2022-23 के अकाल में जिन किसानों की फसलें नष्ट हुई हैं, उनके आदान-अनुदान की घोषणा इस पूरक बजट में करें, जिससे किसानों को फायदा मिले। इसी तरह वर्ष 2022-23 में रबी की फसल, पिछले महीने पाली, जालौर, सिरोही सहित पूरे राजस्थान में भारी बरसात हुई थी, रबी की फसलें पूरी तरह से नष्ट हो गयी हैं। उनकी गिरदावरी करवायें और किसानों की जो फसलें नष्ट हुई हैं, उनका भी आदान-अनुदान शीघ्र देने की व्यवस्था करायें। इस बजट में कहीं पर भी किसानों को आदान-अनुदान देने की घोषणा मुख्य मंत्री जी ने नहीं की है। निश्चित रूप से पूरक बजट में किसानों का आदान-अनुदान देने की घोषणा करायें, जिससे उनको भी फायदा मिले।

सभापति महोदय, आदिकाल से अपनी आजीविका चलाने के लिए खुले आसमान के नीचे मिट्टी की ईंटें, खिलौने, बरतन, मटके, मूर्तियां, दीपक इत्यादि सामग्री बनाने का कार्य कुम्हार जाति के लोग करते आ रहे हैं। कई बार बेमौसम बरसात आती है, जिससे खुले आसमान के नीचे मिट्टी की ईंटें व विभिन्न प्रकार की सामग्रियां बरसात के पानी से नष्ट हो जाती हैं और वे पानी में भीग कर खराब हो जाती हैं, गल जाती हैं। अचानक आयी आपदा से राजस्थान के लाखों परिवार पिछले महीने में बर्बाद हो गये, ऐसे परिवारों को राहत देने का कोई प्रावधान सरकार ने नहीं किया है। मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि पूरे राजस्थान में सर्वे कराकर, जिस तरह किसानों को आपदा में मुआवजा देने का प्रावधान है, उसी तरह का प्रावधान इन लोगों के लिए भी करके उनको मुआवजा देने की व्यवस्था करायें और पूरक बजट में इसकी घोषणा करायें, जिससे ऐसे वर्ग को भी फायदा मिले।

सभापति महोदय, पिछले चार सालों में मुख्य मंत्री जी ने जो बजट

(श्री जोराराम कुमावत)

पेश किये हैं, उनमें से कई घोषणाएं हैं जो कि पूरी नहीं हुई हैं। मेरे विधान सभा क्षेत्र में भी कई घोषणाएं पूरी नहीं हुई हैं। जैसे कि विकास पथ की घोषणा की थी, मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक भी विकास पथ नहीं बना है। मिनी विकास पथ की भी घोषणा दूसरे बजट में की थी, वह मिनी विकास पथ भी मेरे विधान सभा क्षेत्र में कहीं भी नहीं बना है।

मोहल्ला क्लिनिक की घोषणा की थी, वह मोहल्ला क्लिनिक भी मेरे विधान सभा क्षेत्र में कहीं पर भी नहीं खुला है। जवाई क्षेत्र को पर्यटन क्षेत्र में विकसित करने की घोषणा की थी लेकिन तीन साल बीत जाने के बाद भी अभी तक जवाई क्षेत्र में एक भी पैसा नहीं लगा है। तखतगढ़ में कन्या महाविद्यालय खोलने की घोषणा की थी। एक कन्या महाविद्यालय जरूर खुल गयी। एक प्राचार्य लगा हुआ है, बाकी सारे के सारे पद अभी रिक्त हैं। वहां पढ़ाने वाला कोई नहीं है, उलटा उन विद्यार्थियों के साथ अन्याय हो रहा है। इसी तरह से तखतगढ़ में उप-तहसील की घोषणा की थी लेकिन उप-तहसीलदार के अलावा वहां पूरे के पूरे पद खाली हैं जिससे लोगों को पूरा लाभ जो मिलना चाहिए, वह नहीं मिल रहा है।

प्रत्येक तहसील हैडक्वार्टर पर नंदीशाला खोलने की घोषणा की थी। मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक भी नंदीशाला अभी तक नहीं खुली है। प्रत्येक ग्राम पंचायत हैडक्वार्टर पर जो पशु चिकित्सालय खोलने की घोषणा की थी, चार पशु चिकित्सालय मेरे विधान सभा क्षेत्र में खोले गये, लेकिन पशुधन सहायक आज तक भी वहां नहीं लगे जिससे लोगों को उसका फायदा नहीं मिल रहा है। ग्रामीण बस परिवहन सेवा चालू करने की पिछले बजट में घोषणा की थी लेकिन मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक भी बस चालू नहीं हुई है। पिछले बजट में 22 फरवरी, 2022 तक जितने भी कृषि कनेक्शन हैं, उनको देने की भी घोषणा की थी, लेकिन मेरे विधान सभा क्षेत्र में अभी 2015 तक के भी कनेक्शन नहीं हुए हैं।

श्री सभापति: दो मिनट में समाप्त कीजिए।

श्री जोराराम कुमावत (सुमेरपुर): सभापति महोदय जी, मैं निवेदन करूंगा कि जल्दी से जल्दी कृषि कनेक्शन कराएं। नवीन ग्राम पंचायतें गलथनी और गुरड़ाई जो स्वीकृत की हैं, वहां पर भवन भी अधूरा पड़ा है, चारदीवारी नहीं है, शौचालय नहीं है और ग्राम पंचायतें विकास के कमरों में संचालित हैं। वह कार्य भी शीघ्र कराएं। ग्राम पंचायतों को राज्य वित्त आयोग का अनुदान

(श्री जोराराम कुमावत)

जो मिलता था, एक वर्ष में दो किस्तें मिलती थीं, पंचायत के खाते में जमा होती थी, वह आपने बिलकुल बंद कर दी। चार वर्षों से ग्राम पंचायतों को कमजोर करने का काम आपने जरूर किया है। डामर सड़कों से वंचित गांवों को ग्राम पंचायत हैडक्वार्टर से पिछली बार जोड़ने की भी घोषणा की थी, एक भी डामर सड़क से मेरा गांव नहीं जुड़ा है। प्रमुख देवस्थानों को डामर सड़क से जोड़ने की घोषणा की थी, एक भी देवस्थान नहीं जुड़ा है।

श्री सभापति: समाप्त कीजिए।

श्री जोराराम कुमावत (सुमेरपुर): सभापति महोदय जी, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि सुमेरपुर नगरपालिका को चुंगी का जो पहले पुनर्भरण का पैसा मिलता था, 01 करोड़ 40 लाख रुपया पहले हर महीने मिलता था जो वहां के कर्मचारियों की तनख्वाह देने और विकास के कार्यों में काम आता था, अभी पिछले दस माह से 80 लाख की कटौती सुमेरपुर नगरपालिका में की जा रही है, जिससे वहां पूरा का पूरा विकास कार्य ठप हो गया है। तनख्वाह देने को भी नगरपालिका के पास में पैसे नहीं हैं। विकास के काम भी बंद हो गये।

श्री सभापति: समाप्त कीजिए। श्री सुरेश मोदी। विराजिए।

श्री जोराराम कुमावत (सुमेरपुर): मैं पुन: आग्रह करूंगा कि इस पर विचार करें। जो पैसा कटौती की जा रही है, उन पैसों को वापस देने की व्यवस्था करें। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सुरेश मोदी (नीम का थाना): सभापति महोदय, राजस्थान सरकार का पांचवां बजट बहुत ही शानदार एवं युवाओं, किसानों, महिलाओं और आमजन को राहत प्रदान करने वाला है। चिरंजीवी योजना का दायरा बढ़ाना, गैस सिलेंडर 500 रुपये में देना, किसानों को दो हजार यूनिट तक की बिजली के बिल माफ करना एवं युवाओं के लिए पहली बार बहुत-सा खर्च किया जा रहा है। बहुत-से वक्ताओं ने बजट के बारे में बहुत सारी बातें कह दी हैं। समय की कमी को देखते हुए मैं सीधा मेरे विधान सभा क्षेत्र की कुछ बातों पर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

मेरे क्षेत्र की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी मांग जिला बनाने की है। पिछले दिनों सरकार ने एक कमेटी गठित करके जनता की आकांक्षाओं की पूर्ति का एक सपना दिखाया। मेरे विधान सभा क्षेत्र में पिछले दिनों अपनी मांग के समर्थन में हजारों लोगों ने नीम का थाना से जयपुर तक की 130

(श्री सुरेश मोदी)

किलोमीटर की पैदल यात्रा की, जिसमें मैं स्वयं भी शामिल था और शहीद स्मारक पर एक बहुत बड़ी सभा की एवं मुख्य मंत्री जी को ज्ञापन भी दिया। चार विधान सभा क्षेत्रों के विधायकों ने प्रस्तावित जिला नीम का थाना में जोड़े जाने की सहमति भी प्रदान कर दी है। अत: मैं मुख्य मंत्री जी से आग्रह करता हूं कि बजट सत्र में ही नीम का थाना को जिला बनाने की घोषणा करें।

सभापति महोदय, पिछले बजट में 8 हजार 800 करोड़ रुपये की पेयजल की कुम्भाराम लिफ्ट परियोजना स्वीकृत की गयी थी। परंतु दुर्भाग्य की बात है कि एक साल बीतने पर भी इस योजना का काम धरातल पर शुरू नहीं हुआ। पीने के पानी की मेरे क्षेत्र में बहुत बड़ी समस्या है एवं आगामी गर्मी कैसे बीतेगी, इस बात की बड़ी चिन्ता है। मेरा मुख्य मंत्री जी से निवेदन है कि इस योजना का काम शीघ्र शुरू करवाकर युद्धस्तर पर इसे पूरा किया जाए।

सभापति महोदय, राज्य में काफी प्रयासों के बाद भी बेरोजगारी एवं अपराध बढ़ रहे हैं। मैं मानता हूं कि इसका सबसे बड़ा कारण सिंचाई के पानी के अभाव में कृषि कार्य का बंद हो जाना है। मेरा सरकार से निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में यमुना का सिंचाई का पानी लाया जाए, जिससे इलाके में कृषि कार्य शुरू हो सकें, खुशहाली आये और बेरोजगारी और अपराध से मुक्ति मिले। वन क्षेत्र में और चरागाह में बहुत सारे लोग बसे हुए हैं। बहुत बड़ी समस्या है। गलत वन भूमि और चरागाह दर्ज हो गये हैं। बरसों से ये लोग रह रहे हैं। मेरा सरकार से आग्रह है कि इनको नियमित किया जाए और जो गलत वन क्षेत्र और चरागाह दर्ज हो गये हैं, उनको ठीक किया जाए। किसानों को पाले से हुए नुकसान का मुआवजा शीघ्र व सही-सही दिया जाए।

मेरे विधान सभा क्षेत्र में सिरोही पीएचसी को सीएचसी में क्रमोन्नत किया जाना बहुत आवश्यक है। यहां की ओपीडी बहुत अधिक है। यहां पर एक सीमेंट फैक्टरी भी स्थित है जिसमें हजारों लोग काम करते हैं। क्षेत्र की आबादी और क्षेत्रफल की दृष्टि से ये सबसे बड़ी पंचायत है और हाईवे और बाईपास पर स्थित है। यहां भवन भी बहुत अच्छा उपलब्ध है।

मेरी दूसरी बड़ी जरूरत कोला का नांगल में एक 33 केवी का सब-स्टेशन स्थापित करने की है। ये फीडर पाटन से रेलाकोला तक लगभग 35 किलोमीटर की लम्बाई का है और कोई भी फाल्ट आने पर सारी बिजली बंद हो जाती है। कई बार सारी-सारी रात बिजली नहीं आती है। अत: जनता को राहत प्रदान करने के लिए यहां सब-स्टेशन अभी स्वीकृत किया जाना बहुत

(श्री सुरेश मोदी)

आवश्यक है। सरकार बिजली के मामले में सेल्फ सफिशिएंट बताती है, लेकिन डिस्ट्रिब्यूशन की कमी की वजह से जनता को जो परेशानी है, जिसे सिस्टम को ठीक करके दूर किया जाना चाहिए।

नगरपालिका नीम का थाना और उसके पेरीफेरी क्षेत्र में बहुत बड़ी आबादी निवास करती है, यहां पर शुद्ध हवा और पर्यावरण सुधार के लिए कोई पार्क नहीं है। मेरे यहां एक जमीन उपलब्ध है, जहां पर शहर के जोहड़ का पानी जोहड़ भर जाने पर पाइप लाइन के जरिये इस जमीन में डाला जाता है, आवागमन के लिए सड़क के नजदीक तक स्थित है। अत: मेरा निवेदन है कि बहुत कम वित्तीय भार में जीवन के लिए एक बहुत उपयोगी कार्य किया जा सकता है। आपने कई जगह नेचर पार्क स्वीकृत किये हैं तो मैं मेरे यहां नीम का थाना में भी एक नेचर पार्क स्वीकृत करने का निवेदन करता हूं।

मेरी एक और बड़ी पंचायत गुहाला है, मैं उसे उप-तहसील या नगरपालिका बनाने का निवेदन करता हूं। मेरा विधान सभा क्षेत्र आबादी व क्षेत्रफल के हिसाब से सीकर जिले का सबसे बड़ा विधान सभा क्षेत्र है। इसमें काफी पहाड़ी क्षेत्र भी है। यहां पर सड़कों का बहुत अभाव है। अत: मेरा निवेदन है कि जनता को राहत प्रदान करने की दृष्टि से यहां पर सड़कें और स्वीकृत की जाएं। एक जो विधायकों की अनुशंसा पर 10 करोड़ की सड़कें स्वीकृत करने की मुख्य मंत्री जी ने घोषणा की है, मैं उसे बढ़ाकर 20 करोड़ करने की अनुशंसा करता हूं।

मेरे यहां जो सड़कें बहुत जरूरी हैं बलुपुरा जामावास होते हुए रामपुरा, गणेश्वर से जीराण, ठीकरिया से श्यामनगर, थोई से हीरो की ढाणी, पुराना बास से कोटडा, भगेगा से हरजनपुरा, हरजनपुरा से ढेराजोहड़ी, इस प्रकार 53 किलोमीटर लम्बी सड़कें हैं। मैं मुख्य मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि इस बजट में मुझे अतिरिक्त रूप से दी जाएं।

सभापति महोदय, मैं दो नये प्राथमिक स्कूल खोलने का भी मुख्य मंत्री जी से निवेदन करता हूं। आपने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत नवाचार किये हैं। बहुत अच्छा काम किया है। नये विद्यालय और खोलने की जो मांग आ रही है, आप इन्हें अवश्य पूरा करें।

इसी बजट सत्र में आपने 300 स्कूलों को क्रमोन्नत करने की घोषणा की है। मेरे हिसाब से यह बहुत कम है। मेरे यहां अकेले के ही प्राथमिक

(श्री सुरेश मोदी)

विद्यालय से उच्च प्राथमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने के लिए 3 पाटन ब्लाक में और 6 नीम का थाना ब्लाक में प्रस्ताव हैं। इसके अलावा उच्च प्राथमिक विद्यालय से माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नति की बहुत जरूरत है। अलग-अलग स्कूल हैं, नई कोठी, पौछलावाली, खातियों की ढाणी, हेमराजपुरा आदि करीब पांच स्कूलें मेरे यहां क्रमोन्नत करने की आवश्यकता है। अत: इस 300 की संख्या को बढ़ाया जाना बहुत आवश्यक है।

मेरे विधान सभा क्षेत्र में पाटन अलग से तहसील और पंचायत समिति है। यहां पर चिकित्सा विभाग की सीएचसी भी है, जहां पर ओपीडी व आईपीडी बहुत ज्यादा है। माइनिंग और क्रेशर का एरिया जोन होने की वजह से इस अस्पताल को उप जिला अस्पताल में क्रमोन्नत किया जाना बहुत आवश्यक है। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री शंकर सिंह रावत।

श्री शंकर सिंह रावत (ब्यावर): सभापति महोदय, आपने बजट पर बोलने के लिए मौका दिया, उसके लिए आपको धन्यवाद। सभापति महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि सरकार ने चिरंजीवी योजना लागू की है, उसमें 25 लाख का इलाज कराने के लिए तो आपने योजना लागू की है, लेकिन इसमें कमियां सुधारने का काम नहीं किया है। अमृतकौर अस्पताल में या किसी और अस्पताल में जहां पर भी यह योजना लागू हो रही है, उसमें सरकार के द्वारा इसकी जांच भी करानी चाहिए। चिरंजीवी योजना में जो मरीज जाता है उससे पैसे भी लिए जा रहे हैं और सरकार से भी चिरंजीवी योजना का लाभ लिया जा रहा है, इसकी जांच होनी चाहिए। राजस्थान में जहां भी अस्पताल हैं, उन सबकी जांच होनी चाहिए, ताकि पैसे का दुरुपयोग नहीं हो और उस गरीब को पूरा लाभ मिल सके।

सभापति महोदय, अंग्रेज़ी बबूल के मच्छरों से गाँवों में बीमारियां फैल रही हैं। हर गांव व पंचायत में, नरेगा द्वारा, इस योजना के द्वारा इन बबूलों को उखाड़कर फेंकने से गांव बीमारियों से वंचित रहेंगे। खाने में तेल की मिलावट हो रही है। हरी सब्जियां नाले के पानी से आ रही हैं। मिर्ची, मसाले मिलावटी व नकली हैं। शराब की फैक्ट्रियां भी पकड़ी जा रही हैं। यह सब राजस्थान में हो रहा है। इसमें अपन अगर चोरियां नहीं पकड़ेंगे, आपके खाद्य इंस्पेक्टर क्या कर रहे हैं? पकड़ते हैं, मुक़दमे बनाकर और अपनी जेब भरकर

(श्री शंकर सिंह रावत)

केस को रफा-दफा कर दिया जाता है। कितने लोगों को सज़ा दिलाई है? ऐसा एक सख्त कानून बनना चाहिए। उस अधिकारी को भय होना चाहिए कि मैं इस प्रकार के केस को रफा-दफा करूंगा तो मेरी नौकरी जा सकती है। सख्त कानून बनना चाहिए, ताकि उसकी जेब भरने की बजाय जनता को इसका लाभ मिल सके।

सभापति महोदय, गाय-भैंसें कम हो रही हैं, लेकिन राजस्थान में दूध बढ़ रहा है। कहीं भी शादी में दूध, घी, पनीर, जितना चाहो उतना मिल जाएगा। पहले कहीं शादी होती तो पहले व्यवस्था करनी पड़ती थी कि घी कहां से लाएंगे, दूध कहां से लाएंगे। आज हजार शादी हो, लेकिन जितना दूध चाहिए उतना दूध मिल जाएगा। इस पर भी सरकार को विचार करना चाहिए। आप एक तरफ तो कह रहे हो कि शुद्ध के लिए युद्ध चला रहे हैं। आज ही पेपर में आया है, शुद्ध के लिए युद्ध अभियान। यह अभियान किसके लिए चलाया जा रहा है? जनता को खाने-पीने की शुद्ध चीज मिले, उसके लिए चलाया जा रहा है या अधिकारियों की जेब भरने के लिए चलाया जा रहा है? यह समझ नहीं आ रहा है, तो इसके ऊपर भी कहीं ना कहीं कार्रवाई होनी चाहिए।

सभापति महोदय, अंग्रेज़ी शराब की बॉटल, जिस प्रकार जहरीली शराब की फैक्ट्रियां पकड़ी जाती हैं। खाने का तेल भट्टियों में गरम करके, गुड़ की भेली के रूप में वह आता है, गरम करके सरे-आम बेच रहे हैं। ऐसी फैक्ट्रियों पर सरकार क्यों नहीं कार्रवाई करती है? क्या जनता को मारने के लिए उनको छूट दे रखी है? क्या यही पैसा उनके अंतिम संस्कार तक भी काम आएगा? सरकार को सख्त कानून बनाना चाहिए ताकि आम जनता को बचाया जा सके। केवल चिरंजीवी योजना में 25 लाख रुपये करने से जनता नहीं बचेगी। इसलिए कहीं न कहीं इसमें सुधार होना चाहिए।

सभापति महोदय, कानून व्यवस्था के अन्दर, चाहे किसी भी डिपार्टमेंट को ले लीजिए। चाहे शिक्षा का क्षेत्र देख लीजिए, आज स्कूल में पढ़ने वाली बच्चियों के साथ शिक्षकों के द्वारा छेड़छाड़ के मुक़दमे राजस्थान में कितनी जगह दर्ज हुए हैं। गुरुजन के नाम पर ऐसे कलंकित लोग लगे हुए हैं क्या सरकार उनको कभी सज़ा देने का विचार रखती है? जहां मुक़दमे दर्ज हो गए, उनकी सेवाएं बर्खास्त होनी चाहिए, ताकि नये लोगों को नौकरी लगने का मौका भी मिल सके।

(श्री शंकर सिंह रावत)

सभापति महोदय, परसों के पेपर में आया, मसूदा में उच्च शिक्षिका लगी हुई है, एक अधिकारी पर मुकदमा दर्ज हुआ। क्या ऐसे अधिकारियों के खिलाफ सरकार कानून बनाकर, पूरे राजस्थान में कानून सुधारने का विचार रखती है? (व्यवधान) बोलने तो दो, साहब। डिमांड में रख लूंगा बात।

सभापति महोदय, मेरा दूसरा निवेदन है कि स्वरूपा गांव में बिजली पानी की सुविधा अभी भी नहीं है, अतः सुविधा दी जाए। पाली सीमा में सड़क बन चुकी है, लेकिन अजमेर की सीमा में वन विभाग के द्वारा नहीं बनाई जा रही। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने घोषणा की थी विजयनगर से ब्यावर तक रोड। माननीय सभापति महोदय, मैं बताना चाहूंगा वह सड़क आधी ही बनी है। विजयनगर की सीमा तक ही बनी है और ब्यावर की सीमा को छोड़ दिया गया है। इस पर भी विचार करना चाहिए और उस पर कार्रवाई होनी चाहिए।

टॉडगढ़ के अन्दर आईटी सेंटर खोलने के लिए मेरी मांग है। जवाजा में 33 केवी जीएसएस खुलना चाहिए। सम्राट पृथ्वीराज चौहान खेल स्टेडियम, ब्यावर में 20 करोड़ कम से कम, वहां पर स्टेडियम बनाने के लिए, आपने सब जगह घोषणाएं की हैं, यहां पर भी इसकी घोषणा करनी चाहिए।

अपराधियों के लिए कानून व्यवस्था में आपने रखा है। कोई भी अधिकारी आता है, जिस प्रकार नये डीजी आते हैं, यह लिखते हैं कि अपराधियों से पुलिस की मिलीभगत अब बर्दाश्त नहीं होगी। यह पेपर में और जनता को भ्रमित करने के लिए यह सब देते हैं। वह आने के बाद कहां सेट हो जाते हैं? वह एसीबी में पकड़े जाते हैं, कहीं भी पकड़े जाते हैं, उनके ऊपर सरकार कानून बनाकर, सख्ताई से उनकी सेवाएं बर्खास्त करने का नियम बनाने का विचार रखती है? जब तक आप सख्त कानून नहीं बनाओगे, तब तक इसी प्रकार से अपराध बढ़ते रहेंगे। पक्ष वाले कहेंगे हमारे आंकड़े कम हुए हैं, आपकी सरकार के समय आंकड़े बहुत ज्यादा थे। जनता को गुमराह करने वाला बजट अपने को पेश नहीं करना चाहिए। सख्ताई से पेश आना चाहिए। जनता को कैसे राहत मिल सकती है, ऐसे कानून बनाने चाहिए। आज गैंगस्टर अन्य स्टेट से आकर राजस्थान में आकर प्लानिंग बनाते हैं।

श्री सभापति: दो मिनट में समाप्त करें।

श्री शंकर सिंह रावत (ब्यावर): पेपरों में आता है कि यूपी के गैंगस्टर थे, अपने यहां के नहीं थे। यह गैंग कहां से मिली हुई है? आज जेलों में बैठे अपराधी बाहर वारदात में बिता रहे हैं। सारे हथियार कहां से आ रहे हैं? क्या

(श्री शंकर सिंह रावत)

उनको मोबाइल की सेवाएं उपलब्ध करवाकर ऐसे अपराधों को रोकने के लिए सरकार कोई सख्त कानून बनाने का विचार रखती है? उसको रखना चाहिए।

जिस प्रकार से सार्वजनिक निर्माण विभाग में आज करोड़ों का बजट दिया जा रहा है लेकिन माननीय मुख्य मंत्रीजी भी इस बात को स्वीकार कर चुके हैं कि अधिकारी और ठेकेदार दोनों की मिलीभगत से टेंडर हो रहे हैं, तो ऐसे ठेकेदारों के ऊपर सरकार कानून क्यों नहीं बनाने का विचार रखती है कि ऐसे ठेकेदारों का लाइसेंस निरस्त किया जाये? माननीय मुख्य मंत्रीजी जब भी जवाब दें तो इसके ऊपर अपनी बात कहें। यदि राजस्थान में भ्रष्टाचार खतम करना है और कानून-व्यवस्था को सुधारना है तो कहीं न कहीं इन सख्त नियमों को बनाना पड़ेगा, तब जाकर कहीं राहत मिल सकती है।

चाहे शिक्षा विभाग हो, चिकित्सा विभाग हो, अस्पतालों में डाक्टर्स वहां नहीं हैं, जिस जगह पर लगना चाहिए। आज जवाजा पी.एच.सी., टाडगढ़ सी.एच.सी., अमृतकौर अस्पताल, इनमें डाक्टर्स की कमी है। कभी भी इनके ऊपर नहीं सोचा गया कि, साहब, इनको वहां पर लगाया जाये।

अब जिस प्रकार स्कूलें खोलने के लिए राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, सरूपा, फतेहपुर देवल, फतेहपुर और देवल फतेहपुर, रावली, सेदरिया, टीलाखेड़ा, रामपुरा दूदा, मालीपुरा, इनको सैकण्डरी स्कूल बनवाया जाये।

इसी प्रकार सरमालिया में कृषि संकाय, दूधालेश्वर में कृषि संकाय, टाडगढ़ में कृषि संकाय और राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बड़ाखेड़ा में कृषि संकाय, जवाजा और राजियावास में संस्कृत संकाय ...(व्यवधान)

श्री सभापति: समाप्त करें। श्री बलजीत यादव।

श्री शंकर सिंह रावत (ब्यावर): राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, पटेल में कला संकाय को खोलने के लिए हमने निवेदन किया है। (व्यवधान)

श्री सभापति: कृपया शांत रहें। विराजिये। श्री बलजीत यादव।

श्री बलजीत यादव (बहरोड़): माननीय सभापति महोदय, आपने बजट पर चर्चा में भाग लेने का अवसर दिया, उसके लिए धन्यवाद।

माननीय सभापति महोदय, मैं सबसे पहले 2013 ...(व्यवधान)

श्री शंकर सिंह रावत (ब्यावर): माननीय सभापति महोदय, एक लाइन और ...(व्यवधान)

श्री सभापति: विराजिये।

श्री बलजीत यादव (बहरोड़): ...की भर्ती पूरी करने की मांग करता हूं और इसके साथ ही जो सी.एच.ए. के साथी लम्बे समय से आंदोलन कर रहे हैं, मैं सरकार से यह गुजारिश करता हूं कि सहानुभूतिपूर्वक इनकी मांगों पर विचार करके इनकी समस्या का समाधान करे।

माननीय सभापति महोदय, दुनिया विश्वास पर टिकी हुई है। हमारे यहां पर शादी-ब्याह भी होते हैं तो विश्वास पर होते हैं और हमारे यहां पर जुबान के ऊपर लोग अपनी जान तक दे देते हैं, यह मेरे हिन्दुस्तान का इतिहास रहा है, लेकिन मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, माननीय सभापति महोदय, मैं चार साल से यह मांग करता आ रहा हूं प्रत्येक सत्र में कि जिस प्रकार से 22 राज्यों में अलग-अलग कानून बनाकर राजस्थान के युवाओं को रोजगार पाने से रोका जा रहा है तो या तो केन्द्र सरकार कानून बनाकर और बने हुए उन कानूनों को स्टेट्स ने जो बनाये हैं उनको निष्प्रभावी करे, जिससे राजस्थान के बेरोजगार को भी रोजगार मिले और अगर ऐसा नहीं है तो राजस्थान की सरकार कोई बिल लाये, कानून बनाये, जैसे बिहार में बनाया, हरियाणा में बनाया, अन्य राज्यों में बना हुआ है, तो सरकार भी कानून बनाये जिससे कि राजस्थान के स्थानीय जवानों को सरकारी नौकरियों में 90 से 100 परसेंट आरक्षण मिले। प्राइवेट कम्पनियों में कम से कम 75 परसेंट का आरक्षण मिले।

अफसोस की बात है, माननीय सभापति महोदय, राज्य सभा चुनाव के वक्त मुख्य मंत्रीजी ने स्वयं मुझे यह वचन दिया था कि जल्दी ही यह बिल लाकर और हम यह कानून बनाएंगे। इतने दिनों से वेट करते रहे और अभी विधान सभा में यह जवाब आया कि ऐसा कोई कानून नहीं बनाने जा रहे हैं। +++ इसलिए मैंने यह मांग की कि पांच लाख भर्तियां निकालें। चुनाव के वक्त यह घोषणाएं हो जाती हैं ...(व्यवधान)

श्री सभापति: यह अंकित नहीं होगा। यह अंकित नहीं होगा।

श्री बलजीत यादव (बहरोड़): अभी कहा गया कि 1 लाख 82 हजार भर्तियां निकाली हैं। हमने कहा कि भर्ती कैलेण्डर जारी करें कि यह भर्ती तुरंत, एग्जाम की डेट दें, फिर रिजल्ट की डेट दें, फिर ज्वाइनिंग की छह महीने में डेट दें, जब तो हम यह मानेंगे कि सरकार की नीयत साफ है वरना केवल घोषणाओं में क्या रखा है? पांच लाख की वे भर्तियां निकालें। भर्ती प्रक्रिया में इतनी विसंगतियां हैं, माननीय सभापति महोदय, कोई भी भर्ती निकले तो

(श्री बलजीत यादव)

कभी किसी में दस क्वेश्चन गलत आते हैं, किसी के 20 के आन्सर गलत आते हैं, फिर उनको डिलीट कर दिया जाता है। क्या मजाक चल रहा है कि एक पेपर बनाने वाला वह पेपर यही नहीं बना सकता कि यह क्वेश्चन सही है या नहीं है, इनका आन्सर सही है या नहीं है? आन्सर-की जारी कर दी जाती है, फिर डिलीट कर दिया जाता है। गलती हो गयी, यह क्या मजाक कर रही है ये एजेंसीज? कैसे यह पेपर लीक नहीं होगा जो इतने लापरवाह लोग अगर एग्जाम करवायेंगे? यह पेपर लीक कभी नहीं रुकने वाला और इतना टफ पेपर क्यों दिया जाता है? माननीय सभापति महोदय, यह इसलिए दिया जाता है कि पढ़ने वाला बच्चा कांस्टेबल में भर्ती होना चाहता है, उसको आई.ए.एस. का पेपर पकड़ा दिया तो वह कैसे पढ़ेगा? उसका लेवल वही है तो वह सलेक्ट कैसे होगा? सॉल्व कैसे करेगा? जिसने पेपर चुरा लिया वह सॉल्व करके दे देगा, उसका सलेक्शन हो जायेगा, वह थानेदार बन जायेगा, वह अधिकारी बन जायेगा और वह अपने घर रोता चला जायेगा।

माननीय सभापति महोदय, यह मजाक चल रहा है राजस्थान के अंदर लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं राजस्थान की सरकार को कि आपने बलजीत यादव की सहनशक्ति को देखा है, शायद बलजीत यादव के सीने में धधकती हुई आग को आपने नहीं देखा है और मैं बलजीत यादव इसी सदन में आज घोषणा करता हूं, दो बार सूर्योदय से सूर्यास्त होने तक मैं दौड़ा कि इस सरकार का ध्यान आकर्षित करवाऊं, सड़क पर दौड़ कर भी करवाऊं, विधान सभा में भी करवाऊं पर पता नहीं क्यों सरकार को हमारी आवाज, हमारी पुकार, गरीब की सिसकी, उसके टूटे हुए सपने की सिसकी सुनाई नहीं दे रही है। इसी सदन में आज मैं यह घोषणा करता हूं कि 16 तारीख से 200 की 200 विधान सभा के मुख्यालय पर बलजीत यादव वही काले कपड़े पहनकर यह दौड़ लगायेगा, इन्हीं बेरोजगार किसान और मजदूरों की मांगों को लेकर ताकि सरकार चेते और हमारी मांगों को सीरियस ले और मुख्य मंत्रीजी मुझे दिया हुआ अपना वचन निभायें और जल्दी ही यह बिल लाकर वह कानून बनायें।

माननीय सभापति महोदय, कोचिंग के लिए घोषणा की, पहले दस हजार को फ्री करवाते थे, अब हम पच्चीस हजार को करवा देंगे। गरीब को, मजदूर को हम ऐसे करवा देंगे, एस.सी., एस.टी., ओ.बी.सी. को करवा देंगे, बी.पी.एल. में वह करवा देंगे, तो कितने लोग बी.पी.एल. के अंदर है, जनरल के,

(श्री बलजीत यादव)

ओ.बी.सी. के जिनको कोचिंग करवाओगे? आप 25 हजार को करवाओगे। बलजीत यादव विधायक है निर्दलीय, फ्री कोचिंग मेरे बहरोड़ में मैंने चालू की है, ईवन टेंथ, ट्वेल्थ के लिए भी चालू की है कि साइंस का बच्चा भी पढ़े, वहीं कालेज के प्रोफेसर, स्कूल के लेक्चरर बात करके, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो गरीब के बच्चों को फ्री पढ़ाते हैं, मैंने यह चालू की है। जब बलजीत यादव चालू कर सकता है तो क्या राजस्थान की सरकार चालू नहीं कर सकती?

मैंने मेरे यहां पर सरकारी स्कूल खोल रखे हैं, प्राइवेट स्कूलों में जाओ तो लूट मचा रखी है प्राइवेट स्कूल वालों ने, लेकिन सरकारी स्कूलों की हालत ऐसी है, माननीय सभापति महोदय, मैं सरकार से यह पूछना चाहता हूं कि सरकारी स्कूल में एक चपरासी नहीं है। चपरासी नहीं है तो स्कूल में झाड़ू कौन निकालेगा? उसकी सफाई कौन करेगा? मैंटीनेंस कैसे होगा? गाड़ी आपने ले ली एक करोड़ की। (व्यवधान)

श्री सभापति: एक मिनट रुकिये। एक मिनट।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

सदन का समय 8 बजकर 15 मिनट तक बढ़ाया जाता है।

आय-व्ययक

आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2023-24 पर सामान्य वाद-विवाद

श्री बलजीत यादव (बहरोड़): धन्यवाद, माननीय सभापति महोदय। गाड़ी आपने खरीद ली मर्सिडीज कि एक करोड़ की लेकर आ गये, सर्विस उसकी करवा नहीं रहे हो, मैंटीनेंस करवा नहीं रहे हो, टायर अगर उसका घिस गया तो टायर बदलवा नहीं रहे हो तो वह एक करोड़ की मर्सिडीज चलेगी क्या? तो चाहे मारूति 800 है, वह भी उससे अच्छी रहेगी इसलिए मैं सरकार से यह कहना चाहता हूं, ज्यादा बजट नहीं लगता।

माननीय सभापति महोदय, मैं एक निर्दलीय विधायक हूं। मेरे क्षेत्र की स्कूल में गार्डन बना रहा हूं, ट्रैक बना रहा हूं और स्विमिंग पूल तक सरकारी स्कूल में बनाकर छात्रों को मैं दे रहा हूं तो जब बलजीत यादव दे सकता है तो सरकार क्यों नहीं दे सकती?

(श्री बलजीत यादव)

माननीय सभापति महोदय, पैसा वहां पर खर्च किया जाता है जहां पर मोटे आसामियों से माल आ जाता है। माननीय सभापति महोदय, राजस्थान की जनता की अगर कोई वास्तव में असेट है, ताकत है तो अभी इस वक्त यह है कि जमीन नहीं है हिन्दुस्तान में और वह जो जमीन का बैंक है, लैण्ड बैंक है वह मेरे राजस्थान के पास है। अब नजर उसके ऊपर पड़ गयी है पूंजीपतियों की और इसलिए ये लुटाने में लग गये। उस अडानी को सोलर पार्क बनाने के लिए डेढ़ लाख बीघा जमीन देने की तैयारी यह सरकार कर रही है। अडानी के लिए यह बिल आ जायेगा कि कितनी जमीन ले लो, रिलायंस ले लो, कोई भी ले लो, टाटा ले लो लेकिन यहां के बेरोजगार युवाओं के लिए यह बिल नहीं आयेगा। यहां घर से भागने वाली छोरी को भगाने के लिए बिल आ जायेगा कि मां-बाप नहीं रोक सकते, भागने दो इस बच्ची को, मां-बाप का मुंह काला कर देने दो लेकिन बेरोजगारों के लिए नहीं आयेगा, किसानों के लिए नहीं आयेगा। मैं सरकार से यह मांग करता हूं कि आप इतने ज्यादा अहंकार में नहीं रहें, जो जनता बनाती है, वह जनता उतार भी देती है। जो सरकार गम्भीरता से जनता की बात नहीं लेती है उसको आगे खामियाजा भुगतना पड़ता है तो आपको भी खामियाजा भुगतना पड़ेगा।

शरीफ लोग समय आने पर जवाब देते हैं। पता ही नहीं लगता व्यक्ति को कि नीचे से जमीन खिसक रही है। उसको यह लगता है कि सब कुछ अच्छा चल रहा है लेकिन ऐसा है नहीं और मैं सरकार से यह मांग करता हूं कि सरकारी स्कूलों में कितने लगाने हैं? आपको बीस हजार चपरासी लगाने की जरूरत है। हर स्कूल में लग जायेगा, झाड़ू निकालेगा, सफाई रहेगी। छत टपक रही है तो उस छत की थोड़ी-सी मरम्मत करवा दो, जीर्णोद्धार के पैसे दे दो, स्कूल में ट्रैक बनवा दो, उसका गार्डन बनवा दो, उसको थोड़ा फर्नीचर दे दो। इसमें कोई बहुत ज्यादा पैसा नहीं लग रहा है।

आप मैट्रो ट्रेन जयपुर में ला रहे हो, आपकी मैट्रो ट्रेन खाली दौड़ रही है, तो क्यों लेकर आ गये मैट्रो ट्रेन? इन स्कूलों को कर देंगे सारे को तो यहां पर नौकरी कर लेंगे, यहां नहीं करेंगे तो अमरीका चले जायेंगे, इंग्लैंड चले जायेंगे, बाहर का पैसा लेकर आ जायेंगे, लेकिन कहते हैं कि हम यहां स्कूलों में चपरासी नहीं देंगे, फर्नीचर नहीं देंगे। प्राइवेट स्कूलों में लुटने के लिए जाओ तो वे प्राइवेट स्कूल उनसे ज्यादा अच्छे हैं। इतनी बड़ी-बड़ी शानदार बिल्डिंग्स हैं लेकिन बिना मैंटीनेंस के अभाव में सारी जर्जर हो रही हैं, वीरान हो रही हैं,

(श्री बलजीत यादव)

माननीय सभापति महोदय, लेकिन पता नहीं किसी को दिखता नहीं है या किसी को दर्द महसूस नहीं होता है? मेरी तो ये सारी की सारी समझ से परे हैं। सोलर

(समय: 20.00 बजे)

पार्क बनाने के लिए अडानी को दे रहे हो। भाई साहब से कोई पूछे कि आप डेढ़ लाख बीघा दे रहे हैं, राजस्थान को उससे क्या मिलेगा? कोई लेना देना नहीं। क्या अडानी हमारे को यहां बिजली देगा? नहीं देगा। क्या आपने कान्ट्रेक्ट किया कि कम से कम इतनी बिजली तो देगा, इस रेट में देगा। नहीं किया। अडानीजी बनायेंगे। जमीन रियायती दर पर लेंगे और फिर वह बेचेंगे। मुंह मांगे दाम पर बेचेंगे।

माननीय सभापति महोदय, दो रुपये, सवा दो रुपये यूनिट में जब कभी खरीदनी पड़ती थी कोई कमी आये तो, उस बिजली को कितनी रेट पर खरीदा है? 18 रुपये यूनिट तक बिजली को खरीदा है, फिर भी किसान गर्मी में रोता रहा। मुझे जाकर फैक्ट्रियों की बिजली काटनी पड़ी। मैंने कहा गांवों में बिजली दो। बच्चा पढ़ना चाहता है तो बिजली नहीं है। बिलख रहा है बच्चा गर्मी के अन्दर। कोई चिन्ता नहीं है। हम शहर में एसी में सोते हैं, हमें पता ही नहीं कि गांवों में कौन रो रहा है, कौन तड़प रहा है। किसको क्या दर्द है। किसी को परवाह ही नहीं है क्योंकि हमें खुद महसूस नहीं हो रहा। इसलिए मैं सरकार से कहना चाहूंगा कि ऐसा नहीं समझें कि कोई समझता नहीं है। हम भी अब समझने लग गये हैं जब से विधान सभा में आये हैं। पहले सोचते थे कि क्यों हो रहा है। अब समझने लग गये हैं कि यह खेला क्यों होता है। इसके पीछे कोई न कोई कारण होता है। ऐसे ही खेला नहीं होता है। जहां जरूरत नहीं है वहां पर फण्ड लुटा दो। जरूरत ही नहीं है। जहां पर सड़क बनानी है वहां सड़क का पैसा नहीं मिलेगा, जहां सड़क चमाचम है वहां के लिए करोड़ों ले जाओ। इसके ऊपर के लिए ले जाओ। मेरी समझ से बाहर है। अभी कई माननीय सदस्य बता रहे थे कि टूटी हुई सड़क बन नहीं रही है जिस सड़क को बनाने की जरूरत नहीं है उसी पर डामर डाल कर पैसे उठा रहे हैं तो यह सारा का सारा खेल कमीशनखोरी का खेल है।

माननीय सभापति महोदय, किसान के लिए मैंने कहा कि किसान को आप पानी दे दो और बिजली दे दो। वर्तमान में किसान के सामने सबसे बड़ी समस्या खड़ी हो गयी है पानी बिजली के साथ-साथ आवारा पशुओं की, उसकी पूरी फसल को नष्ट कर रहे हैं। मैंने सदन में कई बार मांग की। आप कह रहे हो कि तार की बाड़ लगायेंगे। उस बाड़ को कोई भी उखाड़ ले जाता है, कोई

(श्री बलजीत यादव)

खा जाता है। कितनी लगी, कितनी नहीं लगी। मैंने कहा कि जो नन्दी हैं उनकी नसबन्दी कर दो। उसमें कितना पैसा लगता है? यह किसी के दिमाग में नहीं आती? आदमियों की नसबन्दी कर दोगे लेकिन नन्दी की नसबन्दी नहीं करेंगे। वह नष्ट करता रहता है सारी की सारी फसलों को। उसमें कौनसा पैसा लग रहा है सरकार का, मेरी समझ से बाहर है। वास्तव में ही किसान को बर्बाद करना चाहते हैं या सोचना ही नहीं चाहते या तार-बाड़ का काम खतम नहीं हो जाए नसबन्दी कर दें तो। पता नहीं क्या सोच रखा है। हमें अनपढ़-सा किसान कहता कि, एमएलए साहब, जाकर कहना कि, इन नन्दियों की नसबन्दी कर दें, तो आगे तो बढ़ोतरी नहीं होगी। मैंने कहा कि मैंने विधान सभा में बोला। उन्होंने कहा कि ऐसी क्या बात हो गयी कि उनकी बात समझ में नहीं आ रही। पता नहीं क्यों नहीं समझ में आ रही।

ईआरसीपी में पिछली बार चार हजार करोड़ रुपये हुआ था, अब और कर दिया है। उससे पहले वाली सरकार भी कर गयी थी। एक फावड़ा चला नहीं है, बजट ही बजट जारी हो रहा है। अब जारी किया तो यह बताना चाहिए था कि इस डेट से टेण्डर होंगे, इस डेट से काम चालू होगा और इतने समय में हम वहां पानी पहुंचा देंगे, वहां तक खोद देंगे, लेकिन नहीं हुआ। हमारे प्रधान मंत्रीजी भी आये, वह भी और धड़कनें बढ़ा गये। उन्होंने कहा कि एक समिति बना दी है, समिति रिपोर्ट देगी। दूसरे स्टेट मध्य प्रदेश से वार्ता होगी, उसके बाद इस पर काम आगे बढ़ेगा। पंजाब से हमारा विवाद है, उस पर कुछ नहीं हो रहा है। दिल्ली से यमुना का विवाद है पानी का, उस पर कुछ नहीं हो रहा है। हरियाणा से विवाद है, उस पर कुछ नहीं हो रहा है। वह पानी तो आया नहीं। अब चम्बल जो आ रही थी, जो खतरे के निशान से बह रही थी, गंगाजी में जाकर समुद्र में गिर रही है तो मध्य प्रदेश क्या करेगा? मध्य प्रदेश को अगर ज्यादा है तो रोक ले उस पानी को। क्यों वहां जाने दे रहा है? बह के जा रहा है उसमें दिक्कत नहीं है। समुद्र में गिर जायेगा लेकिन राजस्थान का किसान प्यासा मर जायेगा, उसको पानी नहीं पीने देंगे। ऐसे कैसे चलेगा? केवल और केवल राजनीति करते जाओ। मरे वह किसान, मजदूर लुटता जाए। समर्थन मूल्य पर फसल आयेगी तो कहेंगे कि अभी नहीं खरीदेंगे। किसान की फसल जब दूसरे ले जायेंगे लालाजी, खरीद लेंगे वह। मजबूर होकर किसान बेच देगा, फिर खरीद चालू करेंगे। देश का 45 परसेंट बाजरा मेरा राजस्थान अकेला पैदा करता है लेकिन बाजरा को समर्थन मूल्य पर नहीं खरीदेंगे। हमारे बगल

(श्री बलजीत यादव)

के स्टेट के अन्दर बाजरा 2300-2400 रुपये क्विंटल में खरीदा जा रहा है और यहां पर किसान 1200 रुपये में बेचने को तैयार है। वह मजबूर है। बिक रहा है लेकिन उसको सरकार नहीं खरीदेगी। मैं सरकार से मांग करता हूं किसान को फसल का पूरा दाम मिले। समर्थन मूल्य मिनिमम प्राइस है, मैक्सिमम प्राइस नहीं है। क्या वह भी सरकार नहीं देना चाहती?

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री बलजीत यादव (बहरोड़): मिनिमम प्राइस से भी आधी रेट पर बेचने को मजबूर है लेकिन पता नहीं क्यों? सबके लिए बजट है।

श्री सभापति: समाप्त करें। श्री कालूराम मेघवाल।

श्री बलजीत यादव (बहरोड़): लेकिन किसान के लिए बजट नहीं है। जवान के लिए बजट नहीं है। गरीब विद्यार्थी के लिए बजट नहीं है। लाल डोरे के लिए मांग की किसान ने।

श्री सभापति: विराजिए।

श्री बलजीत यादव (बहरोड़): बस खतम कर रहा हूं, माननीय सभापति महोदय। मुझे पता है मेरी बात बहुत कड़वीसी लग रही है लेकिन एक मिनट में।

कब से लाल डोरा निश्चित है लेकिन उसको पट्टा नहीं मिल रहा है। प्रशासन गांवों के संग में भी नहीं मिल रहा है। आबादी के लाल डोरे का विस्तार नहीं कर रहे हो। वर्षों हो गये, क्या लोग बढे नहीं? जनसंख्या बढ़ी नहीं? यह बात समझ में नहीं आ रही है लेकिन उस लाल डोरे का विस्तार नहीं कर रहे हैं। विस्तार नहीं करोगे तो उसको पट्टा नहीं मिलेगा इसलिए मैं सरकार से मांग करता हूं कि उसका भी करे।

आजकल वीसी-वीसी खेलने का एक नया ट्रेंड चल गया है। भगवान, यहां पर कोरोना क्या आया, आकर वीसी छोड़ गया। मन में आये वही अधिकारियों को लेकर बैठ जाता है, आज चार घंटे इसकी वीसी है, फिर चार घंटे उसकी। दो-दो बार वीसी चलती है। सब कुछ एकदम जाम हो जाता है, सारा प्रशासन इसी में लग जाता है।

श्री सभापति: समाप्त करें, माननीय सदस्य। विराजिए। श्री कालूराम मेघवाल।

श्री बलजीत यादव (बहरोड़): प्रिंसिपल को वीसी में बुला लेते हैं, टीचर्स से तरह-तरह की सूचनाएं मांगते हैं। वह बच्चों को कैसे पढ़ायें? हर काम में लगा दिया।

श्री सभापति: विराजिए। अंकित नहीं होगा। श्री कालूराम।

श्री बलजीत यादव (बहरोड़): 000

श्री कालूराम (डग): माननीय सभापति महोदय, आपने बजट पर बोलने का मौका दिया इसलिए आपको धन्यवाद। मैं आज पूरी विधान सभा की तरफ से माननीय गुलाब चन्दजी कटारिया साहब को असम का राज्यपाल बनने पर बहुत-बहुत हार्दिक अभिनन्दन और बधाई देना चाहता हूं। आपने जिस प्रकार से विधान सभा में कार्य किये, वैसी हमें भी आगे प्रेरणा मिलती रहे।

मैं सबसे पहले आपकी घोषणाओं के बारे में बताना चाहता हूं कि आपने बेरोजगारों के विषय में पिछले बजट के पैरा 48 पर दो लाख युवाओं को रोजगार करने का वादा किया था कि हम दो लाख युवाओं को, शिक्षित बेरोजगारों को नौकरी देंगे, यह वादा आपका पूरा नहीं हुआ है। इसी प्रकार पैरा 49 पर आपने 17 जिलों में उद्योग क्षेत्र खोलने के लिए कहा था, उसमें मेरे जिले का पिड़ावा क्षेत्र भी था। पिड़ावा व मनोहर थाना क्षेत्र में एक उद्योग खोलने के लिए कहा था लेकिन वहां कोई उद्योग नहीं खुला। पैरा 55 में आपने ईडब्ल्यूएस के माध्यम से सामान्य श्रेणी के लोगों को 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया था कि उन लोगों को सहायता देंगे, उनको कोई सहायता नहीं मिली। बजट 2022-23 के पैरा 57 पर आपने घोषणा की थी कि पांच हजार दिव्यांग छात्राओं को स्कूटी देंगे और कालीबाई देवनारायण योजना के तहत 20 हजार स्कूटी देंगे, मेरे विधान सभा क्षेत्र में किसी बच्ची को और दिव्यांग को अभी तक कोई स्कूटी नहीं मिली।

पैरा नम्बर 62 में आपने कहा था 2022-23 में कि हम श्रमिक कार्ड की जो योजना चल रही है, इसमें जितने भी प्रकरण पेंडिंग है, उसका तीन महीने में निस्तारण कर देंगे। माननीय सभापति महोदय, आज दिन तक उसका कोई निस्तारण नहीं हुआ और किसी को इसका फायदा नहीं हुआ।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि एमएल.ए. लैड में जो 10 करोड़ रुपये मिलते हैं, वह मात्र अपने जिला कलेक्टर को, एक्स.ईएन. को उसका पावर दे दिया और एम.एल.ए. से उसका पावर छीन लिया। मैं मांग करता हूं कि 10 करोड़ की जगह 20 करोड़ किया जाये और एम.एल.ए. की अनुशंसा पर वह कार्य किया जाये। उन अधिकारियों को पता नहीं कि क्षेत्र में क्या काम हो रहा है और क्या कमी है।

(श्री कालूराम)

माननीय सभापति महोदय, हमारे क्षेत्र में जिस प्रकार से पहले एक विधायक को 50 हैण्डपम्प देते थे, उनको आपने बंद कर दिये। जल जीवन मिशन के माध्यम से सारी सड़कें टूट गयीं और आज गांवों में पानी नहीं मिल रहा है। सब जगह त्राहिमाम मच रही है, तो मैं आपको सदन के माध्यम से अवगत कराना चाहता हूं कि 50 हैण्डपम्प प्रत्येक विधायक को दिये जाएं।

माननीय सभापति महोदय, सबसे पहले मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र के बारे में आता हूं कि भवानीमंडी में करीब 75 हजार की आबादी है, वहां पर सी.एच.सी. है, उसको जिला अस्पताल में क्रमोन्नत किया जाये। ए.डी.एम. कार्यालय व उप-अधीक्षक कार्यालय खोला जाये। पचपहाड़ में आपने एक इंग्लिश मीडियम स्कूल खोला, उसकी जगह हिन्दी मीडियम बंद कर दिया। उस स्कूल में हिन्दी मीडियम स्कूल भी खोला जाये ताकि वहां के बच्चों को इसका फायदा मिल सके।

भवानीमंडी में जो पीपलाज नदी है उसमें प्रदूषित पानी बह कर जाता है। केन्द्रीय जल समिति ने भी घोषित किया था राजगढ़ पेयजल परियोजना से जोड़ने के लिए, मैं मांग करता हूं कि इसको राजगढ़ पेयजल परियोजना से जोड़ा जाये।

नगरपालिका भवानीमंडी में एक आनन्द कार्टन मिल के नाम से बहुत बड़ा घपला है। महाराजा झालावाड़ ने 156 बीघा जमीन दान में दी थी, उसको नगरपालिका ने 90 (क) करके वह एक निजी व्यक्ति को दे दी है। उस पर रोक लगाई जाये ताकि नगरपालिका की जनता के साथ धोखा नहीं हो और वहां की जनता को फायदा मिले।

फसल बीमा के माध्यम से आईसीआईसीआई बैंक से करीब सभी किसानों को रबी का बीमा मिला है, बाकी राष्ट्रीयकृत बैंकों से कहीं भी बीमा नहीं मिला। हमारे क्षेत्र में भी पाला गिरा है और पिछला सोयाबीन का मुआवजा भी बाकी है इसलिए मैं आपसे मांग करना चाहता हूं सोयाबीन का मुआवजा सहित पूरा बीमा मिलना चाहिए। सभी बैंकों से इसका मुआवजा दिलवाया जाये।

मेरे विधान सभा क्षेत्र भवानीमंडी में कन्या महाविद्यालय खोला जाये, क्योंकि वहां पर बच्चियों की संख्या करीब 2 हजार है। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने घोषणा की थी कि हम 500 बच्चियों की संख्या पर एक कन्या महाविद्यालय खोलेंगे। अभी तक वहां पर कन्या महाविद्यालय की घोषणा नहीं

(श्री कालूराम)

की गयी। मैं चाहता हूं कि 16 फरवरी को जब मुख्य मंत्रीजी जवाब दें तो डग और भवानीमंडी, दोनों जगह पर कन्या महाविद्यालय खोला जाये।

डग में नगरपालिका बनायी जाये। डग विधान सभा क्षेत्र है और वहां करीब 15-20 हजार की आबादी है तो वहां नगरपालिका बनायी जाये। 10 हजार की आबादी में आप नगरपालिका क्षेत्र बनाते हैं, इसलिये डग को नगरपालिका बनाया जाये। झालावाड़ जिला दूरी में करीब 150 किलोमीटर लम्बा क्षेत्र है, तो मैं मांग करता हूं कि भवानीमंडी को जिला घोषित किया जाये।

माननीय सभापति महोदय, शिक्षा के क्षेत्र में, मैं आपको बताना चाहता हूं कि शिक्षा के क्षेत्र में काफी कमियां हैं। मैं 11 तारीख को यहां से जाने के बाद कस्तूरबा गांधी विद्यालय में गया। कस्तूरबा गांधी विद्यालय में करीब 200 बच्चियां अध्ययनरत हैं। वहां पर दो बच्चियां तड़प रही थीं। वहां के अधिकारियों को पता नहीं था। मैं मेरी गाड़ी से ले जाकर अस्पताल में भर्ती कराया और वहां अस्पताल में मैंने खुद ने इलाज कराया। आपकी यह व्यवस्था है। आपकी व्यवस्था बिगड़ रही है। वहां पर स्टाफ नहीं है, आप वहां पर स्टाफ लगायें और जो भी अधिकारी इसका दोषी हो, उसको सस्पैण्ड करायें। मैंने कलेक्टर से बात की, जिला शिक्षाधिकारी से बात की और बी.ई.ओ. से बात की। यह बहुत गम्भीर विषय है, इनके खिलाफ जो भी उचित कार्रवाई हो, वह की जाये।

माननीय सभापति महोदय, बिजली के बारे में मैं आपको कहना चाहता हूं। जिस प्रकार से ग्रामीण क्षेत्र में लाइट कट रही है, बार-बार वहां पर ट्रिपिंग होता है और जो कनेक्शन आपने कहा था कि हम 2023 तक सम्पूर्ण कनेक्शन दे देंगे, बाकी आज दिन तक वहां पर कोई कनेक्शन नहीं हुआ है। 900 के करीब डिमांड राशि जमा हुई है, उसमें से मात्र 15-20 कनेक्शन दिये हैं। वहां पर उनके पास कोई सामान नहीं है, डी.पी. नहीं है। हमारे क्षेत्र में किसान परेशान हो रहे हैं। लाइट 8-9 घंटे जाती है, 24 घंटे में से 8-9 घंटे लाइट बंद रहती है। मैं मांग करता हूं कि आप बड़ेबड़े वादे करते हैं कि हम निःशुल्क बिजली देंगे, आप क्या निःशुल्क बिजली दोगे? महारानी साहब ने, हमारी वसुन्धरा राजे जी ने पहले 833 रुपये प्रति माह देने का काम किया था, उसको आपने तीन साल से बंद रखा और अब आप लोक-लुभावनी घोषणाएं बजट में कर रहे हैं। मैं मांग करता हूं कि समय पर बिजली दी जाये।

(श्री कालूराम)

माननीय सभापति महोदय, सबसे बड़ी समस्या हमारे क्षेत्र में पानी की है। मेरे क्षेत्र में से दो-तीन नदियां बहकर जाती हैं। चौमहला क्षेत्र में एक बड़ा बांध बनाया जाये। मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि डैम की घोषणा की जाये। जब आप घोषणा करें तो इसमें हमारे यहां के लिए डैम की घोषणा भी की जाये।

श्री सभापति: दो मिनट में समाप्त करें।

श्री कालूराम (डग): माननीय सभापति महोदय, मेरे क्षेत्र में करीब 10-12 गांव सड़कों से वंचित हैं, उनको सड़कों से जोड़ा जाये। माननीय सभापति महोदय, आपने एक और घोषणा की कि 350 की आबादी पर हम रोड देंगे, इसकी जगह आप 250 करें, क्योंकि 350 में काफी गांव बच जायेंगे। 2011 की जनगणना की जगह 2021 से करें। अगर 2021 से जोड़ेंगे तो 350 में बहुत सारे गांव आ जायेंगे। मेरे क्षेत्र में जो गांव बाकी हैं, मैं उनके नाम बता दूं- लाखाखेड़ी परमार, बोरखेड़ी, करमचन्द, सकतपुर, करनालिया, घटिया, बिरमाखेड़ी, गरड़ा, हड़मतिया मेहरा, डोबड़ा, मेंहदियाखेड़ी-दांताखेड़ा, खेजड़ियाखाल, टुगनी, मेहरपुरा, बांडी और गणेशपुरा आदि गांवों में सड़कों की बड़ी आवश्यकता है, इन सभी गांवों को सड़कों से जोड़ा जाये।

माननीय सभापति महोदय, मेरे क्षेत्र में एक स्टेट हाईवे निकल रहा है, उस स्टेट हाईवे की यह स्थिति है कि उस पर आम आदमी चल नहीं पाता है। उस पर पांच-पांच टोल हैं। मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि उसकी जांच करवायें और जो रोड बना था, आज उसको बने दस साल हो गये हैं, उस पर केवल पेचवर्क ही हो रहा है। उस पर आज दिन तक डामर नहीं हुआ और वह सड़क बिलकुल टूट चुकी है। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि उस सड़क को बनायें और बनाकर उसका सुदृढ़ीकरण करायें।

माननीय सभापति महोदय, हमारे क्षेत्र में कृषि के मामले में बड़ी समस्या है। पिछले बजट में हमारे यहां डग कृषि मंडी आपने घोषित की थी, बाकी मात्र घोषणाएं ही रह गयीं। मेन मण्डी की घोषणा की, न तो उसमें कोई चुनाव हुआ, न वहां पर कोई अधिकारी लगे, न उसको कृषि उपज मण्डी का दर्जा मिला। उसको स्वतंत्र कृषि उपज मंडी घोषित की जाये। जिस प्रकार से आपने जो-जो घोषणाएं कीं, यह सिर्फ लोक-लुभावनी घोषणाएं हैं, इनको

(श्री कालूराम)

धरातल पर उतारें। शिक्षित बेरोजगारों के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि कई बेरोजगार आज भी घूम रहे हैं।

श्री सभापति: सदन की बैठक मंगलवार, दिनांक 14 फरवरी 2023 के प्रात: 11.00 बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 20.15 बजे मंगलवार, दिनांक 14 फरवरी 2023 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

अनुपस्थित सदस्य का तारांकित प्रश्नोत्तर

जिला मुख्यालयों पर सैटेलाइट चिकित्सालय खोलने की कार्ययोजना

111. डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) वर्तमान में प्रदेश में चिकित्सकों के कितने पद स्वीकृत हैं व उक्त में से कितने पद रिक्त हैं? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार प्रत्येक पीएचसी में चिकित्सकों एवं महिला चिकित्सक का नया पद सृजित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(3) क्या सरकार पांच हजार से अधिक जनसंख्या वाली ग्राम पंचायतों में संचालित पीएचसी को सीएचसी में क्रमोन्नत करने तथा प्रत्येक जिला मुख्यालय पर जिला अस्पताल के अतिरिक्त नये सैटेलाइट चिकित्सालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) प्रदेश में वर्तमान में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अन्तर्गत चिकित्सकों के कुल 16566 पद स्वीकृत, 12570 कार्यरत व कुल रिक्त पद 3996 हैं।

उक्त रिक्त पदों में 2195 पद पदोन्नति के एवं 1801 पद चिकित्सा अधिकारी के सम्मिलित हैं।

चिकित्सा अधिकारी के 1801 रिक्त पदों के विरुद्ध 1765 चिकित्सा अधिकारी के पदस्थापन/नियुक्ति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। सूची परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) स्टाफिंग पैटर्न के अनुसार प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर एक चिकित्सा अधिकारी का पद सृजित करवाये जाने का प्रावधान है।

उपलब्धता अनुसार महिला/पुरुष चिकित्सक को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर लगाया जाता है।

(3) जी नहीं। भारत सरकार द्वारा ग्रामीण जनसंख्या आधारित निर्धारित मानदण्डानुसार 01 लाख की ग्रामीण जनसंख्या पर 01 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने का प्रावधान है।

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

राज्य में जिला मुख्यालय पर जिला चिकित्सालय, मेडिकल कालेज व अन्य चिकित्सा संस्थान (शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, डिस्पेन्सरी इत्यादि) स्वीकृत हैं, जिनके माध्यम से चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं।

प्रत्येक जिला मुख्यालय पर जिला चिकित्सालय के अतिरिक्त नये सैटेलाइट चिकित्सालय खोला जाना वर्तमान में विचाराधीन नहीं है।

(सूची पुस्तकालय में रखी गयी)

समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्न एवं उनके उत्तर

किशनगढ़ में अमृत जल योजना द्वितीय की स्वीकृति

126. श्री सुरेश टाक (किशनगढ़): क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ में अमृत जल योजना द्वितीय की स्वीकृति हेतु मुख्यालय को प्रस्ताव भिजवाया गया है? यदि हां, तो कब? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र में पेयजल व्यवस्था में सुधार हेतु अमृत जल योजना के उक्त प्रस्ताव को स्वीकृति देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ में किशनगढ़ कस्बे के लिए अमृत-2.0 में स्वीकृति हेतु 34.91 करोड़ की जल योजना के प्रस्ताव अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता क्षेत्र अजमेर के पत्र क्रमांक 5363-364 दिनांक 26.08.2022 द्वारा मुख्य अभियन्ता (शहरी एवं एन.आर.डब्ल्यू.) जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जयपुर को भिजवाये गये थे। (परिशिष्ट-अ)

(2) राज्य स्तरीय उच्चाधिकार प्राप्त समिति की अभिशंषा पर किशनगढ़ शहर हेतु राशि रु. 34.91 करोड़ की जल योजना का अमृत-2.0 के तहत आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार की अमृत योजना की एपेक्स कमेटी की बैठक दिनांक 04.01.2023 द्वारा अनुमोदन किया जा चुका है। योजना के तकनीकी प्रस्ताव बनाने का कार्य वर्तमान में प्रगति पर है। (परिशिष्ट-ब)

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

रानीवाड़ा की सहकारी संस्थाओं द्वारा साख सीमा बढ़ाने की कार्ययोजना

127. श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र रानीवाड़ा में कुल कितने किसान सहकारी

(श्री नारायण सिंह देवल)

संस्थाओं से फसली ऋण लेते हैं व उनकी तय साख सीमा कितनी है? स्वीकृत साख सीमानुसार किसानों का संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र के सहकारी बैंक, लैम्पस, पैक्स द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाले फसली ऋण पर साख सीमा तय करने के पश्चात् एक लाख पचास हजार रुपये तक की स्वीकृत साख सीमा वाले किसानों को क्या उक्त ऋण राशि एकमुश्त उपलब्ध कराई जा रही है? यदि हां, तो विगत दो वर्षों में उपलब्ध कराई गई ऋण राशि का संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि ऋणी किसानों के फसल बीमा प्रीमियम का भुगतान सहकारी संस्थाओं द्वारा उक्त ऋण राशि से किया जाता है? यदि हां, तो क्या फसल बीमा प्रीमियम भुगतान के पश्चात् किसानों को खाद, बीज एवं अन्य आवश्यक वस्तुओं की खरीद हेतु ऋण राशि शेष रहती है? यदि नहीं, तो क्या सरकार उक्त की साख सीमा को बढ़ाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब व कितनी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र रानीवाड़ा में जालौर केन्द्रीय सहकारी बैंक से सम्बद्ध ग्राम सेवा सहकारी समितियों द्वारा वर्ष 2022-23 में 14859 कृषकों को खरीफ फसल हेतु एवं 13742 कृषकों को रबी फसल हेतु अल्पकालीन फसली ऋण दिया गया, जिनके पक्ष में अधिकतम साख सीमा राशि रुपये 1.50 लाख तक स्वीकृत है।

स्वीकृत साख सीमानुसार कृषकों का संख्यात्मक विवरण निम्नानुसार हैः-

स्वीकृत साख सीमा	**वर्ष 2021-22**		**वर्ष 2022-23**	
	खरीफ	**रबी**	**खरीफ**	**रबी**
रुपये 25000 तक	2543	1969	2795	1842
रुपये 25000 से 50000 तक	3745	3549	4286	3586
रुपये 50000 से 1.00 लाख तक	4178	4547	4803	4640
रुपये 1.00 लाख से 1,49,999 तक	1593	2008	1833	2071
रुपये 1.50 लाख	969	1635	1142	1603

(सहकारिता मंत्री)

(2) जी हां। किसान स्वेच्छानुसार एकमुश्त अथवा किश्तों में ऋण राशि प्राप्त कर सकते हैं।

विधान सभा क्षेत्र रानीवाड़ा में विगत दो वर्षों में जालौर केन्द्रीय सहकारी बैंक द्वारा पैक्स/लैम्पस के माध्यम से निम्नानुसार ऋण उपलब्ध करवाया गया:-

(राशि लाखों में)

क्र.स.	**विवरण**	**वर्ष 2020-21**		**वर्ष 2021-22**	
		खरीफ	**रबी**	**खरीफ**	**रबी**
1	कृषकों की संख्या	11855	11511	13028	13708
2	ऋण राशि	3067.01	3296.96	4395.86	5034.38

(3) जी हां। कृषकों की प्रधानमंत्री फसल बीमा की प्रीमियम की राशि का भुगतान स्वीकृत ऋण राशि से किया जाता है।

जी हां। फसल बीमा प्रीमियम कटौती उपरान्त शेष रही राशि का उपयोग कृषक अपनी इच्छानुसार खाद-बीज एवं अन्य आवश्यक वस्तुओं की खरीद हेतु कर सकता है।

कोविड में मृत्यु होने पर राशन डीलरों को सहायता

128. श्री हमीर सिंह भायल (सिवाना): क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार कोविड से मृत राशन डीलरों को कोविड सहायता देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कितनी व अब तक कितने डीलरों को उक्त सहायता राशि का भुगतान कर दिया गया व कितनों को दिया जाना शेष है? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार राशन डीलरों को मानदेय देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कितना व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। कोविड 19 से संक्रमित होने तथा इलाज के दौरान असामयिक मृत्यु होने पर उसके आश्रित परिवार को रुपये 50 लाख की सहायता राशि देय है।

वर्तमान में 46 मृतक राशन डीलरों के आश्रितों को उक्त सहायता राशि प्रदान कर दी गई है तथा 43 प्रकरणों में नियमानुसार निस्तारण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री)

(2) राशन डीलरों को मानदेय दिये जाने के क्रम में प्रकरण परीक्षणाधीन है।

भादरा में चकबंदी हेतु गठित टीम

129. श्री बलवान पूनियां (भादरा): क्या उपनिवेशन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र भादरा में चकबंदी, मुरब्बाबंदी का कार्य कितने वर्षों से चल रहा है? उक्त कार्य को कब तक पूर्ण कर जमाबंदी संभला दी जावेगी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त चकबंदी के लिए अब तक कितनी टीमों का गठन हो गया है व वर्तमान में चकबंदी कर रही वाप्कोस कम्पनी को कितना भुगतान कब-कब किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) भादरा विधान सभा क्षेत्र की चकबंदी/मुरब्बाबंदी का वर्तमान कार्य दिनांक 15.05.2017 को वाप्कोस लिमिटेड के साथ अनुबन्ध कर कार्य शुरू किया गया था। वाप्कोस लिमिटेड द्वारा चकबंदी/मुरब्बाबंदी कार्य रिकार्ड राइटिंग के तहत अन्तिम चरण में चकवाइज जमाबन्दी लेखन का कार्य किया जा रहा है। जमाबन्दी लेखन का कार्य 31 अगस्त, 2023 तक पूर्ण करवाया जा कर जमाबन्दी राजस्व विभाग को संभलवाया जाना सम्भावित है।

(2) उक्त चकबन्दी मौके पर लागू करवाने एवं कम्पनी द्वारा किये गये कार्य जमाबन्दी लेखन की जांच एवं टिप्पणी हेतु आयुक्त उपनिवेशन विभाग, बीकानेर द्वारा छह बार टीम का गठन किया गया था। वाप्कोस लिमिटेड कम्पनी को कार्य के लिए निम्नानुसार भुगतान किया गया है:-

क्र.सं.	भुगतान स्वीकृति दिनांक	भुगतान की गई राशि
1	26.12.2017	59,00,000
2	28.03.2018	1,15,05,000
3	29.03.2018	78,40,000
4	28.01.2019	1,49,55,000
5	30.03.2020	42,55,000
	योग:-	**4,44,55,000**

(उपनिवेशन मंत्री)

इस प्रकार कम्पनी को कुल 4,44,55,000/- रुपये का भुगतान किया जा चुका है तथा कार्य देरी से करने के कारण कम्पनी पर जीएफ एण्ड एआर नियम के तहत 10 प्रतिशत शास्ति लगाई गई है।

खादी उत्पादों के विक्रय को बढ़ावा देने की कार्ययोजना

130. श्री अमृतलाल मीणा (सलूम्बर): क्या खादी एवं ग्रामोद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) सरकार द्वारा विगत चार वर्षों में खादी एवं ग्रामोद्योग संस्थाओं को आत्मनिर्भर व आधुनिक तकनीक से युक्त बनाने के लिए क्या प्रयास किये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) प्रदेश में विगत चार वर्षों में खादी उत्पादों का उत्पादन एवं विक्रय कितना रहा? सरकार द्वारा खादी उत्पादों के विक्रय को बढ़ाने के लिए उक्त अवधि में क्या प्रयास किये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राजस्थान राज्य में खादी संस्थाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड एवं खादी और ग्रामोद्योग आयोग के माध्यम से विभिन्न योजनाओं के तहत विगत चार वित्तीय वर्षों में 52.32 करोड़ रुपये की राशि संस्थाओं को उपलब्ध करायी गयी है, जिसका विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

इसके तहत खादी और ग्रामोद्योग आयोग एवं बोर्ड द्वारा संस्थाओं को आत्मनिर्भर व आधुनिक तकनीक से युक्त बनाने हेतु उपरोक्त योजनाओं में उन्नत तकनीक के साधन/सरंजाम यथा न्यू मॉडल चर्खा (एन.एम.सी.), लूम, बटाई मशीन, वार्पिंग मशीन, जिगर एवं कलेन्डरिंग मशीन इत्यादि क्रय करने, वर्कशेड, कच्चा माल क्रय करने हेतु, बिक्री संवर्धन एवं कत्तिन व बुनकरों के पारिश्रमिक भुगतान आदि सुविधा प्रदान करने हेतु उक्तानुसार अनुदान/ऋण राशि उपलब्ध कराई गई है।

(2) विगत चार वर्षों में खादी उत्पादों का, राशि 404.05 करोड रुपये का उत्पादन तथा राशि 688.14 करोड़ रुपये की बिक्री हुई, जिसका वर्षवार विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

खादी उत्पादों के विक्रय को बढ़ावा देने हेतु भण्डार नवीनीकरण योजना के तहत 3.55 करोड़ रुपये के अनुदान की स्वीकृति जारी की गई है, जिसका वर्षवार विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(खादी एवं ग्रामोद्योग मंत्री)

राज्य में उत्पादित खादी उत्पादों की बिक्री को बढ़ावा देने के लिए फुटकर बिक्री पर सरकार द्वारा वर्ष 2018-19 व 2020-21 में 20 प्रतिशत (राज्य सरकार द्वारा 5 प्रतिशत तथा 10+5 प्रतिशत रिबेट (छूट) खादी ग्रामोद्योग आयोग, नई दिल्ली द्वारा अनुमत) 2019-20 एवं 2021-22 गांधी जयन्ती के उपलक्ष्य में बिक्री को बढ़ावा देने के लिए विशेष रिबेट/छूट (राज्य सरकार द्वारा 35 प्रतिशत तथा 10+5 प्रतिशत रिबेट (छूट) खादी ग्रामोद्योग आयोग, नई दिल्ली द्वारा अनुमत) कुल 50 प्रतिशत रिबेट/छूट प्रदान की गई है। आदेशों की प्रति परिशिष्ट-स पर संलग्न है।

खादी उत्पादों की बिक्री को बढ़ावा देने के लिए राज्य में जिला, संभाग एवं राष्ट्र स्तरीय प्रदर्शनियों का आयोजन किया जाता है। विगत चार वर्षों के प्रदर्शनियों में खादी और ग्रामोद्योगी उत्पादों के बिक्री का विवरण परिशिष्ट-द पर संलग्न है।

(विवरण व प्रति पुस्तकालय में रखे गये)

इलेक्ट्रिक वाहनों की गतिशीलता बढ़ाने की कार्ययोजना

131. श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): क्या परिवहन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार द्वारा प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहन गतिशीलता को बढ़ाने के लिए कोई कदम उठाये गये हैं? यदि हां, तो क्या? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार सरकारी अधिकारियों व कर्मचारियों को इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) उपलब्ध कराने के लिए कोई योजना प्रारम्भ करने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार पेट्रोल, डीजल या सीएनजी पर होने वाले व्यय में बचत हेतु विभागों तथा स्वायत्तशासी संस्थाओं में भी इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) की खरीद करने का विचार रखती है? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। ई-वाहनों को पंजीयन में मोटरयान कर एवं ग्रीन टैक्स में पूर्ण छूट प्रदान की गई है। विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

माननीय मुख्य मंत्री महोदय की बजट घोषणा 2021-22 के क्रम में राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद को प्रोत्साहन देने हेतु इलेक्ट्रिक वाहनों के

(राज्य मंत्री, परिवहन)

क्रेताओं को SGST राशि का पुनर्भरण एवं एकमुश्त अनुदान दिये जाने का प्रावधान किया गया है। SGST राशि का पुनर्भरण समस्त प्रकार के इलेक्ट्रिक वाहनों पर देय है। एकमुश्त अनुदान राशि दोपहिया व तिपहिया इलेक्ट्रिक वाहनों पर बैटरी क्षमता अनुसार देय है। इस संबंध में विभागीय कार्यालय आदेश संख्या 10/2021 दिनांक 16.07.2021 के द्वारा इलेक्ट्रिक वाहनों को दिये जाने वाले अनुदान की अवधि को कार्यालय आदेश संख्या 2/2022 के अंतर्गत दिनांक 31.08.2022 तक प्रभावी किया गया था। प्रति परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

दिनांक 31 अगस्त, 2022 को इलेक्ट्रिक वाहन नीति की अधिसूचना जारी कर दी गई है एवं दिनांक 1 सितम्बर, 2022 से इलेक्ट्रिक वाहन नीति राज्य में लागू हो चुकी है। नीति के अनुसार इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद को प्रोत्साहन देने हेतु आधुनिक बैटरी (Advanced Batteries like Lithum-ions) युक्त इलेक्ट्रिक वाहनों के क्रेताओं को SGST राशि का पुनर्भरण एवं एकमुश्त अनुदान दिये जाने का प्रावधान किया गया है। विवरण परिशिष्ट-3 संलग्न है।

(2) जी नहीं। सरकार इस प्रकार की कोई योजना शुरू नहीं कर रही है।

(3) जी नहीं। सरकार अभी इस तरह का विचार नहीं रखती है।

(विवरण व प्रति पुस्तकालय में रखे गये)

प्रतापगढ़ में केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा आवंटित बजट

132. श्री रामलाल मीणा (प्रतापगढ़): क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला प्रतापगढ़ में वर्ष 2019 से माह दिसम्बर, 2022 तक केन्द्र सरकार व राज्य सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं में प्रतिवर्ष कितना-कितना बजट किस-किस योजना में आबंटित किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त योजनाओं की निविदा प्रक्रिया में अनियमितता से धन का दुरुपयोग किया जा रहा है? यदि हां, तो क्या सरकार दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रतापगढ़ जिले में वर्ष 2019 से दिसम्बर 2022 तक केन्द्र सरकार ओर राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं में प्रतिवर्ष आबंटित किये गये बजट की वर्षवार सूचना परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(राज्य मंत्री, जनजाति क्षेत्रीय विकास)

(2) जी नहीं। कार्यों की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति उपरांत कार्यकारी एजेन्सी द्वारा नियमानुसार टेण्डर प्रक्रिया संपादित की जाती है।

(सूचना पुस्तकालय में रखी गयी)

कोटा शहर के आबादी क्षेत्रों से हाईटेंशन लाइनों को हटाने की कार्ययोजना

133. श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): क्या ऊर्जा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) कोटा शहर में विगत चार वर्षों में हाईटेंशन लाइनों से कितने लोगों की मृत्यु व कितने घायल हुए? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त शहर के आबादी क्षेत्रों से गुजर रही हाईटेंशन लाइनों को हटाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त अवधि में उक्त शहर के आबादी क्षेत्र से कितनी हाईटेंशन लाइनों को हटाया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) कोटा शहर में विगत 4 वर्षों में हाईटेंशन विद्युत लाइनों से लोगों की मृत्यु व घायलों का संख्यात्मक विवरण परिशिष्ट "अ" पर उपलब्ध है।

(2) कोटा शहर में हाईटेंशन लाइनें विद्युत विनियम में निर्धारित सुरक्षा मापदण्डों के अनुसार खींची गई हैं। कालांतर में निवासियों द्वारा विद्युत लाइन के नीचे या समीप नियम विपरीत अनधिकृत निर्माण कर लिया जाता है। विद्युत सुरक्षा की दृष्टि से घातक लाइनों को आवेदक या संस्था द्वारा शिफ्टिंग हेतु आवेदन करने पर शिफ्टिंग कार्य पर होने वाले खर्चे की 50 प्रतिशत राशि आवेदक द्वारा एवं शेष 50 प्रतिशत राशि कोटा शहर में विद्युत वितरण का कार्य सम्भाल रही डिस्ट्रीब्यूशन फ्रेन्चाइजी द्वारा वहन किये जाने का प्रावधान है।

प्रसारण निगम की हाईटेंशन लाइनों को हटाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(3) विगत 4 वर्षों में कोटा शहर में आबादी क्षेत्र से हटाई गई हाईटेंशन विद्युत लाइनों का विवरण परिशिष्ट "ब" पर उपलब्ध है।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

परबतसर में इंजीनियरिंग कालेज की स्थापना

134. श्री रामनिवास गावड़िया (परबतसर): क्या तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार परबतसर में राजकीय इंजीनियरिंग कालेज खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार परबतसर में विद्यार्थियों के लिए उक्त कालेज एवं विद्यार्थियों के आवास हेतु छात्रावास खोलने का भी विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। परबतसर जिला नागौर एवं संभाग अजमेर में आता है। अजमेर संभाग में बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय के अंतर्गत अभियांत्रिकी महाविद्यालय अजमेर, महिला अभियांत्रिकी महाविद्यालय अजमेर एवं राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा के अंतर्गत एमएलवीटीई, भीलवाड़ा संचालित है जिनमें वर्ष 2022-23 में कुल सीटों 1493 के विरुद्ध 693 प्रवेश हुए हैं एवं अजमेर संभाग में बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय के अंतर्गत 02 निजी अभियांत्रिकी महाविद्यालय संचालित हैं जिनमें वर्ष 2022-23 में कुल सीटों 435 के विरुद्ध 116 प्रवेश हुए हैं। विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

वर्तमान में परबतसर में राजकीय इंजीनियरिंग कालेज खोलने का प्रस्ताव विभाग में विचाराधीन नहीं है।

(2) भाग सं. 01 के दृष्टिगत इंजीनियरिंग कालेज एवं विद्यार्थियों आवास हेतु छात्रावास खोलने का प्रस्ताव विभाग में विचाराधीन नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

जहाजपुर में नवीन 108 एम्बुलेंस

79. श्री गोपी चन्द मीणा (जहाजपुर): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर में वर्तमान में कितनी 108 एंबुलेंस उपलब्ध हैं तथा उक्त की वर्तमान स्थिति क्या है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त क्षेत्र में 108 खराब एंबुलेंस को सुधरवाने एवं अतिरिक्त नवीन 108 एंबुलेंस उपलब्ध कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वर्तमान में विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर में चार 108 आपातकालीन एम्बुलेंस उपलब्ध हैं।

सीएचसी पण्डेर पर प्रतिस्थापित 108 आपातकालीन एम्बुलेंस रजि. नम्बर RJ14PB8348 को नाकारा किये जाने हेतु टिप्पणी प्राप्त हुई है, जिसके स्थान पर वर्तमान में सेवाप्रदाता द्वारा रिजर्व एम्बुलेंस का संचालन किया जा रहा है। उक्त के अतिरिक्त समस्त 108 एम्बुलेंस चलायमान स्थिति में है।

(2) वर्तमान में बिन्दु संख्या 01 में वर्णित 108 आपातकालीन एम्बुलेंस द्वारा अपनी-अपनी लोकेशन के साथ आस-पास के क्षेत्र को शामिल करते हुए आमजन को आपातकालीन सेवायें निःशुल्क उपलब्ध करवाई जा रही हैं।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत आबादी के आनुपातिक आधार पर एम्बुलेंस का अनुमोदन किया जाता है। तदनुसार एम्बुलेंस वाहनों का नवीन परिनियोजन किया जाता है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा स्वीकृत पीआईपी वित्तीय वर्ष 2022-24 में प्रति एक लाख की आबादी पर एक बीएलएस और प्रति पांच लाख की आबादी पर एक एएलएस एम्बुलेंस का अनुमोदन प्राप्त है।

जयपुर शहर के जयपुरिया हास्पिटल में महिला चिकित्सकों के रिक्त पदों को भरने की योजना

80. श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री कालीचरण सराफ)

(1) क्या यह सही है कि जयपुरिया हास्पिटल, जयपुर में महिला चिकित्सालय एवं मातृ शिशु कल्याण केन्द्र भी संचालित है? यदि हां, तो वर्तमान में उक्त के लिए कितने-कितने बेड्स निर्धारित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त हास्पिटल में निर्धारित बेड्स हेतु कितने स्त्री एवं बाल रोग विशेषज्ञ चिकित्सकों की आवश्यकता है एवं वर्तमान में उक्त श्रेणी के कितने चिकित्सक पदस्थापित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त श्रेणी के रिक्त पदों पर चिकित्सक पदस्थापित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) राजकीय जयपुरिया हास्पिटल में महिला चिकित्सालय एवं मातृ-शिशु कल्याण केन्द्र संचालित नहीं है। चिकित्सालय वर्तमान समय में आर.यू.एच.एस. मेडिकल कालेज से सम्बद्ध है। चिकित्सालय में कुल 400 बेड हैं जिनमें स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग में 100 बेड का वार्ड संचालित है एवं 24 घंटे प्रसूति सेवाएं प्रदान की जा रही हैं।

(2) राजकीय जयपुरिया चिकित्सालय में वर्तमान समय में 60 बेड का शिशु वार्ड, 16 बेड का एनआईसीयू व 8 बेड का पीआईसीयू कार्यरत है। पदों की आवश्यकता व पदस्थापित चिकित्सकों का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(3) जी हां। रिक्त पदों पर चिकित्सक पदस्थापित किया जाना एक सतत प्रक्रिया है। राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर नियमानुसार एवं आवश्यकतानुसार चिकित्सकों के रिक्त पदों को भरे जाने की कार्यवाही की जाती है।

देवली-उनियारा में नवीन उप स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की योजना

81. श्री हरीश चन्द्र मीना (देवली-उनियारा): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र देवली-उनियारा में विगत चार वर्षों में कितने उप स्वास्थ्य केन्द्र खोले गये? स्थानवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र में नवीन उप स्वास्थ्य केन्द्र

(श्री हरीश चन्द मीना)

खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कहां-कहां व कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र देवली-उनियारा में विगत 4 वर्षों में आठ उप स्वास्थ्य केन्द्र खोले गये, जिनका संस्थानवार विवरण निम्न प्रकार है:-

वर्ष	**खोले गये उप स्वास्थ्य केन्द्रों की संख्या**	**उप स्वास्थ्य केन्द्र का नाम**
2020	1	रिजोदा
2021	5	चंदवाड
		कुडिया,
		पाडली
		बालागढ़
		श्यावता
2022	2	बिलोता
		श्योराजपुरा
कुल	**8**	

(2) भारत सरकार द्वारा ग्रामीण जनसंख्या आधारित निर्धारित मानदण्डानुसार सामान्य क्षेत्र में 5 हजार एवं जनजाति/रेगिस्तानी क्षेत्रों में 3 हजार की ग्रामीण जनसंख्या पर 1 उप स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने का प्रावधान है।

वर्ष 2011 की अनुमानित ग्रामीण जनसंख्या के आधार पर निर्धारित मानदण्डानुसार पंचायत समिति देवली में 43 उप स्वास्थ्य केन्द्रों की आवश्यकता के विरुद्ध 53 उप स्वास्थ्य केन्द्र एवं पंचायत समिति उनियारा में 34 उप स्वास्थ्य केन्द्रों की आवश्यकता के विरुद्ध 48 उप स्वास्थ्य केन्द स्वीकृत हैं। इस प्रकार पंचायत समिति देवली एवं उनियारा में उप स्वास्थ्य केन्द्र मानदण्ड से अधिक स्वीकृत होने के कारण उप स्वास्थ्य केन्द्र खोला जाना वर्तमान में विचाराधीन नहीं है।

टोंक में महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं का स्थायीकरण

82. श्रीमती इन्द्रा (बामनवास): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्रीमती इन्द्रा)

(1) जिला टोंक में कार्यरत कितनी महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं का प्रोबेशन पूर्ण होने के बाद स्थायीकरण किया गया तथा कितनों को किन कारणों से अब तक स्थायीकरण से वंचित रखा गया है? शेष का स्थायीकरण कब तक कर दिया जायेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक द्वारा निदेशक (अराजपत्रित) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान को प्रेषित पत्र क्रमांक 1279 दिनांक 27 सितम्बर, 2022 में सम्मिलित किन-किन महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को किन कारणों से अब तक स्थायीकरण से वंचित रखा गया है? सरकार उक्त का अब कब तक स्थायी करने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जिला टोंक में कार्यरत 99 महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं का प्रोबेशनकाल पूर्ण होने के बाद स्थायीकरण आदेश जारी किये जा चुके हैं। 12 महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के स्थायीकरण प्रस्ताव नियमानुसार पूर्ण करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है, जिसके पश्चात् इनके भी स्थायीकरण आदेश शीघ्र जारी कर दिये जायेंगे।

(2) मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक के पत्र क्रमांक 1279 दिनांक 27.09.2022 के द्वारा कुल 23 एएनएम के स्थायीकरण प्रस्ताव निदेशालय को प्रेषित किये गये हैं। उक्त सभी एएनएम के स्थायीकरण आदेश जारी किये जा चुके हैं।

झुंझुनूं में मोबाइल वेटेरिनरी सेवा के लिए पदों का सृजन

83. श्री सुभाष पूनिया (सूरजगढ़): क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार द्वारा बजट में 102 मोबाइल वेटेरिनरी सेवा प्रारम्भ करने की घोषणा की गई है? यदि हां, तो कब? वर्तमान में कितनी मोबाइल वेटेरिनरी सेवा संचालित हैं? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) जिला झुंझुनूं में वर्तमान में उक्त कितनी सेवाएं संचालित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या मोबाइल वेटेरिनरी सेवा के लिए सरकार द्वारा पद सृजित कर दिये हैं? यदि हां, तो कितने व उनमें से कितने पद रिक्त हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। वर्तमान सरकार की वित्तीय वर्ष 2021-22 की बजट घोषणा के बिन्दु संख्या 87 में 108 एम्बुलेंस की तर्ज पर 102 मोबाइल वेटेरिनरी सेवा शुरू करने का उल्लेख है। वर्तमान में इस बजट घोषणा के तहत 102 मोबाइल वेटेरिनरी सेवा प्रारम्भ नहीं हुई हैं।

(2) बजट घोषणा वित्तीय वर्ष 2021-22 की अनुपालना में प्रदेश में 102 मोबाइल वेटेरिनरी सेवा प्रारम्भ नहीं हुई है।

(3) जी नहीं। प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2021-22 की बजट घोषणा की अनुपालना में स्वीकृत मोबाइल वेटेरिनरी सेवा के लिए पृथक् से कोई पद सृजित नहीं किये गये हैं।

उदयपुर ग्रामीण में मृतक पशुओं को डालने हेतु जमीन का आवंटन

84. श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): क्या पर्यावरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या विधान सभा क्षेत्र उदयपुर ग्रामीण में पेरीफेरी क्षेत्र की पंचायतें नाई, बूझड़ा, सीसारमा, मौरेया क्षेत्र में मृत पशुओं को अन्यत्र जगह डालने से प्रदूषण फैल रहा है व उक्त की सारी गंदगी पिछोला झील में आती है, जिससे पानी दूषित हो रहा है? क्या सरकार उक्त क्षेत्र में मृत पशुओं को डालने के लिए जमीन आबंटित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(स्थगित)

आहोर में नये बैरियर बनाने पर विचार

85. श्री छगनसिंह (आहोर): क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र आहोर में 2019 से माह दिसम्बर, 2022 तक कितने बैरियर बनाये गये हैं?

(2) क्या उक्त विधान सभा क्षेत्र के आईपुरा, आकोली नदी, जवाई नदी पर भी बैरियर बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(श्री छगनसिंह)

(3) क्या यह सही है कि कटकेश्वर बांध पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त का पुन: निर्माण कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र आहोर में जल संसाधन विभाग द्वारा वर्ष 2019 से माह दिसम्बर, 2022 तक कुल 7 सब सरफेस बैरियर निर्मित किये गये हैं।

(2) विधान सभा क्षेत्र आहोर के आईपुरा में 2, आकोली नदी पर 3 तथा जवाई नदी पर 18 सब सरफेस बैरियर के प्रस्ताव तैयार किये गये हैं, जिनमें से जवाई नदी पर 2 सब सरफेस बेरियर (कानीवाडा व रसियावास) की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति राशि रुपये 185.89 लाख की दिनांक 22.12.2022 को जारी की जा चुकी है एवं निविदा आमंत्रित कर ली गई हैं। शेष सब सरफेस बैरियर के प्रस्तावों पर स्वीकृति उपरांत बजट उपलब्धतानुसार कार्यवाही की जानी प्रस्तावित है।

(3) पंचायती राज विभाग के अधीन स्थित कटकेश्वर बांध वर्तमान में आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है। इसकी मरम्मत एवं जीर्णोद्धार के प्रस्ताव की स्वीकृति होने पर बजट उपलब्धतानुसार कार्य कराया जाना प्रस्तावित हैं।

सुजानगढ़ व बीदासर तहसीलों में स्वीकृत जे.जे.एम. कार्य

86. श्री मनोज कुमार (सुजानगढ़): क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) सुजानगढ़ व बीदासर तहसील में स्वीकृत जेजेएम कार्य की पूर्ण होने की अवधि क्या है तथा वर्तमान में कितना कार्य पूर्ण हो चुका है तथा कितना शेष है? शेष कार्य कब तक पूर्ण हो जाएगा? सरकार द्वारा निर्धारित अवधि में कार्य पूर्ण नहीं होने पर क्या पैनल्टी तय की गई है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त तहसीलों के लिए उक्त कार्य हेतु कितनी राशि स्वीकृत की गई है तथा योजना में कितने गांव सम्मिलित किये गये हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) चूरू जिले की सुजानगढ़ और बीदासर तहसील में वर्ष 2011 की

(जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री)

जनगणनानुसार क्रमश: 94 व 69 कुल 163 आबाद ग्राम अवस्थित है। वृहद् पेयजल परियोजना रतनगढ़-सुजानगढ़ के संवर्धन एवं रेक्ट्रोफिटिंग कार्य के अन्तर्गत सुजानगढ़ तहसील के 80 ग्राम व बीदासर तहसील के 53 ग्रामों को सम्मिलित करते हुए कुल 210 ग्रामों हेतु, जल जीवन मिशन के तहत राज्य स्तरीय योजना स्वीकृति समिति (एस.एल.एस.एस.सी.) की 20वीं बैठक दिनांक 11.02.2021 में राशि रुपये 198.80 करोड़ की स्वीकृति जारी की गई थी। उक्त कार्य हेतु मैसर्स रियान वाटरटेक प्रा.लि. कलकत्ता व मैसर्स पी.सी. स्नेहलक, प्रा.लि. अहमदाबाद के संयुक्त उपक्रम को दिनांक 28.12.2021 को राशि रु. 142.90 करोड़ का कार्यादेश जारी किया गया है। योजना के कार्य प्रारम्भ करने व पूर्ण करने की नियत तिथि क्रमश: 07.01.2022 व 06.04.2023 है। कार्य की समयावधि 15 माह है व वर्तमान में इस कार्य का 35.07 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो गया है। योजना पर आज दिनांक तक राशि 48.68 करोड़ रुपये का व्यय किया जा चुका है।

तहसील सुजानगढ़ के शेष 14 ग्राम व तहसील बीदासर के 16 ग्राम की एकल ग्राम योजना के अन्तर्गत एस.एल.एस.एस.सी. की विभिन्न बैठकों में कुल राशि रुपये 16.43 करोड़ की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की गई है। इन एकल ग्राम योजनाओं में स्वीकृत 30 ग्रामों में से 27 ग्रामों का कार्य पूर्ण किया जाकर शेष ग्रामों का कार्य वर्तमान में प्रगति पर है।

उक्तानुसार वृहद् परियोजना एवं अन्य योजनाओं के शेष रहे कार्य चरणबद्ध रूप से माह अक्टूबर, 2023 तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है। योजनाओं की प्रगति का विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

वृहद् पेयजल परियोजना रतनगढ़-सुजानगढ़ के संवर्धन एवं रेक्ट्रोफिटिंग कार्य के अन्तर्गत संवेदक फर्म द्वारा निर्धारित प्रोरेटा प्रगति प्राप्त नहीं करने के कारण नियमानुसार राशि रुपये 1.405 करोड़ की शास्ति आरोपित की जा चुकी है।

(2) सुजानगढ़ तहसील के 94 ग्रामों एवं बीदासर तहसील के 69 ग्रामों हेतु वृहद् परियोजना एवं अन्य योजनाओं के तहत क्रमश: राशि रुपये 82.75 करोड़ एवं 59.58 करोड़ की स्वीकृति जारी की गई है। विवरण परिशिष्ट-अ में निहित है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

बाड़मेर में स्थापित ट्यूबवैल

87. श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र बाड़मेर में वर्ष 2018 से माह दिसम्बर, 2022 तक कितने ट्यूबवैल खोदे गये? उक्त ट्यूबवैलों के लिए कितनी राशि स्वीकृत हुई व कितनी राशि व्यय की गई? पंचायतवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त अवधि में कितने हैण्डपम्प स्वीकृत हुए व कितने खोदे गये तथा कितने नाकारा घोषित हो चुके हैं व कितने चालू हालत में हैं? पंचायतवार संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वर्ष 2018 से दिसम्बर, 2022 तक कुल 151 ट्यूबवैलों एवं 15 ओपनवैलों की स्वीकृति जारी की गई। स्वीकृत 151 ट्यूबवैलों एवं 15 ओपनवैल में से 142 ट्यूबवैल एवं 14 ओपनवैल का वेधन कार्य किया जाकर चालू कर दिये गये हैं। इस प्रकार स्वीकृति के अन्तर्गत शेष रहे 9 ट्यूबवैल एवं 01 ओपनवैल का कार्य वर्तमान में प्रगति पर है। उक्त योजनाओं हेतु स्वीकृत राशि रुपये 3821.78 लाख के विरुद्ध राशि रुपये 1737.12 लाख का व्यय किया जा चुका है। पंचायतवार विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) उक्त अवधि में कुल स्वीकृत 225 हैण्डपम्पों में से 196 हैण्डपम्पों का वेधन कार्य किया गया। इनमें से 8 हैण्डपम्प सूखे पाये गये एवं 188 हैण्डपम्प चालू कर दिये गये हैं। शेष 29 हैण्डपम्पों के वेधन का कार्य वर्तमान में प्रगति पर है। उक्त अवधि में विधान सभा क्षेत्र बाड़मेर में कोई हैण्डपम्प नाकारा घोषित नहीं किया गया। पंचायतवार विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

जैतारण में समर्थन मूल्य पर मूंग की खरीद

88. श्री अविनाश (जैतारण): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र जैतारण में विगत तीन वर्ष में समर्थन मूल्य पर कितने क्विंटल मूंग की खरीद की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या समर्थन मूल्य पर मूंग की खरीद पिछले वर्षों की तुलना में कम की गई है? यदि हां, तो कारण सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त विधान सभा क्षेत्र में मूंग तुलाई व परिवहन हेतु किस फर्म

(श्री अविनाश)

को किस आधार पर ठेका दिया गया? क्या उक्त प्रक्रिया की निविदा निकाली गई है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या उक्त अवधि में फर्म के विरुद्ध कोई शिकायत प्राप्त हुई है? यदि हां, तो उक्त पर क्या कार्यवाही की गई व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र जैतारण में स्थित खरीद केन्द्र जैतारण क्रय विक्रय सहकारी समिति लि. पर गत तीन वर्षों में समर्थन मूल्य पर क्रय किये गये मूंग का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	वर्ष	मूंग खरीद मात्रा (क्वि. में)	लाभान्वित किसान
1.	2020-21	0.00	0
2.	2021-22	0.00	0
3.	2022-23	19,853.50	1,156

(2) जी नहीं। जैतारण क्रय विक्रय सहकारी समिति लि. पर समर्थन मूल्य खरीद योजनान्तर्गत पिछले दो वर्षों (2020-21 एवं 2021-22) में मूंग की खरीद शून्य रही है।

(3) वर्ष 2022-23 में पाली जिला स्तर पर कोई भी निविदा प्राप्त नहीं होने के कारण निविदा कमेटी के अध्यक्ष जिला कलेक्टर, पाली के अनुमोदन से जैतारण क्रय विक्रय सहकारी समिति को हैण्डलिंग कार्य स्थानीय कृषि मंडी की दरों पर एवं परिवहन कार्य पीडीएस दर पर करने हेतु उप रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, पाली द्वारा अधिकृत किया गया था, जिसके क्रम में जैतारण क्रय विक्रय सहकारी समिति लि. द्वारा कोटेशन आमंत्रित करने हेतु दिनांक 21.10.2022 को सूचना जारी की गई। समिति को प्राप्त तीन कोटेशन में फर्म डिडेल एण्टरप्राइजेज, अरनियाला (मेड़ता) की दरें न्यूनतम होने पर उक्त फर्म को हैण्डलिंग/परिवहन कार्य का ठेका समिति के कार्यादेश दिनांक 31.10.2022 द्वारा दिया गया।

(4) समर्थन मूल्य योजनान्तर्गत मूंग खरीद वर्ष 2022-23 में जैतारण क्रय विक्रय सहकारी समिति लि. पर हैण्डलिंग/परिवहन कार्य करने वाली फर्म मैसर्स डिडेल इंटरप्राइजेज, अरनियाला (मेड़ता) के विरुद्ध कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

खींवसर में मदरसों को देय अनुदान

89. श्री नारायण बेनीवाल (खींवसर): क्या अल्पसंख्यक मामलात मंत्री यह बताने की कृपा करेगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र खींवसर में कुल कितने मदरसे सरकारी व निजी स्तर पर संचालित हैं व उक्त में से कितने पंजीकृत एवं अपंजीकृत हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त मदरसों में कुल कितने विद्यार्थी अध्ययनरत हैं? क्या सरकार द्वारा मदरसों को अनुदान दिया जा रहा है? यदि हां, तो वित्तीय वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 में दी गई अनुदान राशि का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त मदरसों में निर्धारित मापदण्ड के अनुसार कार्मिक नियुक्त हैं? यदि हां, तो कितने-कितने कार्मिक कहां-कहां पर नियुक्त हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र खींवसर में राजस्थान मदरसा बोर्ड, जयपुर के अधीन कुल 10 मदरसे पंजीकृत हैं, जिनका विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

राजस्थान मदरसा बोर्ड में केवल राजस्थान मदरसा बोर्ड से पंजीकृत मदरसों के रिकार्ड का ही संधारण किया जाता है।

(2) उक्त पंजीकृत मदरसों में कुल 598 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं, सरकार द्वारा सितम्बर 2021 में 25,000 रुपये की राशि विभिन्न मदरसों में मदरसा सुविधा अनुदान के तहत जारी की गई, जिसका विवरण परिशिष्ट-'अ' पर संलग्न है।

(3) मदरसा बोर्ड के तहत पैराटीचर्स की उपलब्धता एवं आवश्यकता दृष्टिगत रखते हुए पैराटीचर्स लगाये जाते हैं। उक्त मदरसों में कार्यरत शिक्षा सहयोगियों की संख्या परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

सूरतगढ़ में सी.एस.आर. के तहत किये गये कार्य

90. श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री रामप्रताप कासनियां)

(1) सरकार द्वारा कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) की राशि देने के क्या-क्या प्रावधान हैं?

(2) जिला श्रीगंगानगर में कुल कितनी कंपनियां हैं जो सीएसआर के दायरे में आती हैं? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) विधान सभा क्षेत्र सूरतगढ़ में उक्त कंपनियों द्वारा विगत चार वर्षों में सीएसआर के तहत कौन-कौनसे कार्य करवाये गये? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) कारपोरेट कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा कम्पनी (कारपोरेट सामाजिक दायित्व नीति) नियम, 2014 दिनांक 01.04.2014 से लागू किये गये हैं, जिसके तहत सीएसआर के दायरे में आने वाली कम्पनियों द्वारा उनके विगत 3 वर्षों में अर्जित शुद्ध लाभ के औसत का 2 प्रतिशत कम्पनी की सीएसआर कमेटी द्वारा निर्धारित नीति अनुसार शिडयूल-VII (परिशिष्ट-1) में सम्मिलित सीएसआर गतिविधियों पर ही व्यय किये जाने का प्रावधान है।

सीएसआर संबंधी नियम केन्द्र सरकार द्वारा बनाये गये हैं जिसके अनुसार कंपनी के सीएसआर कार्यक्रम/योजनाओं को अनुमोदित एवं लागू करने हेतु उस कंपनी की सीएसआर समिति पूर्णतः सक्षम है।

(2) श्रीगंगानगर जिला में सीएसआर के दायरे में आने वाली 06 कम्पनियां हैं-

1- श्री सीमेन्ट पावर लि. उदयपुर-उदासर तह. सूरतगढ़

2- सूरतगढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन, प्रभातनगर तह. सूरतगढ़

3- सूरतगढ़ सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट, प्रभात नगर, सूरतगढ़

4- कल्पतरू पावर ट्रांसमिशन लि., पदमपुर

5- खण्डेलिया आयल एंड जनरल मिल्स, रीको श्रीगंगानगर

6- पतंजलि फूड लि. उद्योग विहार, श्रीगंगानगर

(3) विधान सभा क्षेत्र सूरतगढ़ में कम्पनियों द्वारा विगत 4 वर्षों में सीएसआर के तहत किये गये कार्यों की सूची परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(सूचियां पुस्तकालय में रखी गयीं)

आसीन्द में सिरेमिक जोन

91. श्री जब्बर सिंह सांखला (आसीन्द): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र आसीन्द की ग्राम पंचायत मोड का निम्बाहेड़ा में सिरेमिक जोन खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार सिरेमिक जोन को निजी क्षेत्र में देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र आसीन्द के ग्राम पंचायत मोड का निम्बाहेड़ा में सिरेमिक जोन स्थापित करने का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। जिला कलेक्टर भीलवाड़ा के आदेश दिनांक 06.06.2005 द्वारा ग्राम मोड का निम्बाहेड़ा, तहसील आसीन्द की 102.62 हैक्टेयर भूमि औद्योगिक प्रयोजनार्थ, आवासीय प्रयोजनार्थ, वित्तीय व वाणिज्यिक योजनाओं के लिए आरक्षित की गई है, का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) सिरेमिक जोन को निजी क्षेत्र में देने का प्रस्ताव उद्योग विभाग के स्तर पर विचाराधीन नहीं है। यद्यपि निजी क्षेत्र की कम्पनी ''इम्पीरियल टैक्स इण्डस्ट्रियल पार्क प्रा. लि.'' द्वारा उक्त भूमि के आबंटन हेतु उद्योग विभाग को निवेदन किया गया था। जिसे उद्योग विभाग के पत्र दिनांक 03.02.2022 द्वारा यह सूचित किया जा चुका है कि वह भूमि आबंटन हेतु राजस्व विभाग में आवेदन प्रस्तुत करें। उसके उपरान्त उद्योग विभाग द्वारा उक्त भूमि रीको के पक्ष में आबंटन करने हेतु राजस्व विभाग में दिनांक 18.08.2022 को प्रकरण प्रेषित किया गया है। आवेदन की प्रक्रिया राजस्व विभाग में प्रक्रियाधीन है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

देवस्थान विभाग में सेवागीर-पुजारियों की भर्ती का परिणाम

92. श्री पानाचन्द मेघवाल (बारां-अटरू): क्या देवस्थान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 2013 में सेवागीर व पुजारियों की भर्ती निकाली गयी थी? क्या उक्त के परिणाम जारी हो गये हैं? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री पानाचन्द मेघवाल)

(2) क्या उक्त परीक्षा में चयनित लोगों को नियुक्ति दे दी गयी है? यदि नहीं, तो क्यों व अब उक्त चयनित लोगों को कब तक नियुक्ति दे दी जायेगी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) देवस्थान विभाग के सेवागीर, पुजारी एवं प्रबंधक ग्रेड-2 की भर्ती से सम्बन्धित परीक्षा का आयोजन मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर द्वारा दिनांक 02.02.2014 को किया गया, जिसका परिणाम दिनांक 12.09.2022 को जारी किया गया।

(2) उक्त परीक्षा में अभी तक किसी को नियुक्ति नहीं दी गई। मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर द्वारा दस्तावेजों की जांच प्रक्रिया अभी चल रही है। दस्तावेज जांच उपरान्त चयनित आवेदकों को नियुक्ति देने की प्रक्रिया अमल में लायी जावेगी।

रेवदर में बस स्टैण्डों पर विश्राम भवन निर्माण

93. श्री जगसी राम (रेवदर): क्या परिवहन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र रेवदर के बस स्टैण्डों पर यात्री सुविधाओं हेतु विगत चार वर्षों में कोई कार्य कराये गये हैं? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र में परिवहन निगम के बस स्टैण्डों पर आधुनिक सुख सुविधाओं युक्त विश्राम भवन का निर्माण कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। विधान सभा क्षेत्र रेवदर में राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम स्वामित्व के निम्न 2 बस स्टैण्ड हैं:-

1. आबू रोड
2. मण्डार

आबू रोड बस स्टैण्ड पर यात्रियों हेतु सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हैं। निगम की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ नहीं होने के कारण विगत 4 वर्षो में आबू रोड बस स्टैण्ड पर कोई कार्य नहीं करवाया गया है।

(राज्य मंत्री, परिवहन)

मण्डार कस्बे में स्थित निगम के बस स्टैण्ड पर विगत कई वर्षों से बस संचालन नहीं किया जा रहा है। उक्त बस स्टैण्ड कस्बे से 2 किलोमीटर दूर होने एवं समुचित यात्रीभार उपलब्ध नहीं होने के कारण विगत चार वर्षों में इस बस स्टैण्ड पर कोई कार्य नहीं करवाया गया है।

पंचायती राज विभाग के अनुसार विधान सभा क्षेत्र रेवदर अन्तर्गत पंचायत समिति रेवदर की 39 ग्राम पंचायतों एवं आबू रोड की 21 ग्राम पंचायतों के बस स्टैण्डों पर यात्री सुविधाओं हेतु विगत चार वर्षों में कोई कार्य नहीं करवाये गये हैं।

विधान सभा क्षेत्र रेवदर अन्तर्गत पंचायत समिति रेवदर की 39 ग्राम पंचायतों में से ग्राम पंचायत रेवदर एवं मण्डार पर बसों का ठहराव होता है, जहां पूर्व से यात्री प्रतीक्षालय बने हुए हैं। विधान सभा क्षेत्र रेवदर अन्तर्गत पंचायत समिति आबू रोड की 21 ग्राम पंचायतों में से ग्राम पंचायत बहादुरपुरा, गिरवर (गिरवर वार्ड), चण्डेला, मुंगथला, सुरपगला पर बस स्टोप हैं, जहां पूर्व में यात्री प्रतीक्षालय बने हुए हैं।

स्थानीय निकाय विभाग के अनुसार नगरपालिका आबू रोड द्वारा बस स्टैण्ड आबू रोड में यात्री सुविधाओं हेतु कोई कार्य नहीं कराया गया है।

(2) विधान सभा क्षेत्र रेवदर में निगम स्वामित्व के आबू रोड बस स्टैण्ड पर यात्रियों हेतु सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हैं।

बसों के Stands पर यात्री सुविधाओं के विस्तार हेतु राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2022-23 के बजट में "...Roadways (RSRTC) एवं निजी बसों के Stands के उन्नयन व Repair संबंधी कार्य लगभग 125 करोड़ रुपये की राशि से कराये जाने प्रस्तावित हैं।" घोषणा की गई है। उक्त घोषणा के क्रम में आबू रोड बस स्टैण्ड पर विकास कार्य करवाये जाने हेतु प्रस्ताव प्रक्रियाधीन है।

विधान सभा क्षेत्र रेवदर के मण्डार कस्बे में स्थित निगम स्वामित्व के बस स्टैण्ड पर विगत कई वर्षों से बस संचालन नहीं किया जा रहा है। उक्त बस स्टैण्ड पर यात्रियों हेतु विश्राम गृह एवं अन्य सुविधाएं उपलब्ध हैं किन्तु निगम के सीमित संसाधनों के कारण इस बस स्टैण्ड पर आधुनिक सुख-सुविधाओं युक्त विश्राम भवन का निर्माण कराने का फिलहाल कोई विचार नहीं है।

चन्देरिया में रोडवेज बस स्टैण्ड की स्थापना

94. श्री चन्द्रभान सिंह आक्या (चित्तौड़गढ़): क्या परिवहन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र चित्तौगढ़ के चन्देरिया क्षेत्र में बसों के ठहराव नहीं होने के कारण चित्तौड़गढ़ बस स्टैण्ड जाना पड़ता है? यदि हां, तो क्या सरकार चन्देरिया में रोडवेज बस स्टैण्ड का निर्माण कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

विधान सभा क्षेत्र चित्तौड़गढ़ के चन्देरिया में सीमेंट फैक्ट्री, ट्रांसपोर्ट मार्केट एवं रेलवे फाटक होने के कारण अधिकांशत: यातायात अवरुद्ध रहता है। अत: यात्रियों की सुविधा एवं वाहनों के निर्धारित समय पर गंतव्य स्थान पर पहुंचाने के उद्देश्य से चित्तौड़गढ़-भीलवाड़ा मार्ग पर निगम की बसों का संचालन कपासन चौराहा (चन्देरिया से लगभग 3 किलोमीटर दूर) से नरपत खेड़ी होते हुए किया जा रहा है तथा कपासन चौराहा से यात्रियों को निगम बसों में बैठाया/उतारा जाता है।

चन्देरिया में निगम स्वामित्व की कोई भूमि उपलब्ध नहीं होने एवं निगम की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ नहीं होने के कारण चन्देरिया में निगम बस स्टैण्ड का निर्माण कराने का फिलहाल कोई विचार नहीं है।

आमेर में बंद की गई परिवहन सेवा का पुन: संचालन

95. श्री सतीश पूनियां (आमेर): क्या परिवहन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र आमेर के ग्रामीण क्षेत्रों में विगत कई वर्षों से संचालित पथ परिवहन निगम की कई बसों का संचालन बंद कर दिया गया है? यदि हां, तो क्यों? विगत तीन वर्षों से अब तक बंद की गई बसों के रूट सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि जयपुर से राधाकिशनपुरा-खन्नीपुरा-जयपुर से चौंप वाया राजावास-चेतावाला-खोराश्यामदास, ग्राम पंचायत चीथवाड़ी वाया रिसाणी-भूरथल-नांगल पुरोहितान-राजावास तथा जयपुर से रोजदा तथा जयपुर से कंवरपुरा एवं चांदपोल से झोटवाड़ा, बैनाड़ होते हुए नांगल सिरस ग्राम पंचायत मुख्यालय तक ग्रामीण बस सेवाएं बंद हैं? यदि हां, तो क्यों?

(3) क्या सरकार उक्त अवधि के दौरान बंद की गई परिवहन बस

(श्री सतीश पूनियां)

सेवाओं को पुन: प्रारम्भ करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के सीमित संसाधनों के कारण विधान सभा क्षेत्र आमेर के ग्रामीण क्षेत्रों में विगत तीन वर्षों में बन्द की गई निगम बसों का मार्गवार विवरण परिशिष्ट "1" पर संलग्न है।

(2) राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की जयपुर-रोजदा-खन्नीपुरा-राधाकिशनपुरा हेतु एक वाहन नियमित रूप से निम्नानुसार संचालित की जा रही है:-

मार्ग	प्रस्थान समय
चांदपोल (जयपुर)-राधाकिशनपुरा	19.30
राधाकिशनपुरा-चांदपोल (जयपुर)	06.15

चांदपोल-जालसू-झोटवाड़ा-बैनाड़-चतरपुरा-आसोजाई हेतु एक वाहन (चार परिचक्र) नियमित रूप से निम्नानुसार संचालित की जा रही है:-

मार्ग	प्रस्थान समय
चांदपोल (जयपुर)-जालसू	19.30 07.40
जालसू-चांदपोल (जयपुर)	06.10 09.10

शेष प्रश्नगत मार्गों पर निगम बसों का संचालन निगम के सीमित संसाधनों के कारण बन्द किया गया है।

(3) राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के सीमित संसाधनों के कारण उक्त अवधि में बन्द की गई बस सेवाओं को पुन: प्रारम्भ करने का फिलहाल कोई विचार नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

नोखा में खराब ट्रांसफार्मरों को बदलने की कार्ययोजना

96. श्री बिहारीलाल (नोखा): क्या ऊर्जा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) सरकार द्वारा तकनीकी रूप से खराब व जले हुए ट्रांसफार्मर को कितने दिन में बदलने का प्रावधान किया गया है? विधान सभा क्षेत्र नोखा में

(श्री बिहारीलाल)
माह जनवरी, 2020 से माह दिसम्बर, 2022 तक खराब ट्रांसफार्मरों को निश्चित समयावधि में नहीं बदलने के क्या कारण रहे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार खराब ट्रांसफार्मरों को यथा समय में ठीक करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) कृषि श्रेणी के अतिरिक्त अन्य वितरण ट्रांसफार्मर जलने/खराब होने की सूचना प्राप्त होने/संज्ञान में आने पर निम्न समयावधि में ट्रांसफार्मर को बदले जाने का प्रावधान हैः-

1. क्लास 1 शहरों में 8 घंटे के भीतर।
2. शहरी क्षेत्रों में 8 घंटे के भीतर।
3. ग्रामीण क्षेत्रों में 24 घंटे के भीतर।

कृषि श्रेणी के वितरण ट्रांसफार्मर जलने/खराब होने की सूचना प्राप्त होने/संज्ञान में आने पर वर्तमान में सामान्य परिस्थितियों में ट्रांसफार्मर 72 घंटे में बदलने का प्रावधान है, किन्तु निम्न परिस्थितियों में ट्रांसफार्मर 72 घंटे में बदलने की बाध्यता नहीं हैः-

- उपभोक्ता पर बकाया राशि होने पर।
- ट्रांसफार्मर चोरी होने पर।
- ट्रांसफार्मर के मीटर बाक्स की वैल्डिंग टूटी पाये जाने पर।

विधान सभा क्षेत्र नोखा में उपरोक्त प्रावधानों की अनुपालना में माह जनवरी 2020 से दिसम्बर 2022 तक वितरण ट्रांसफार्मर जलने/खराब होने की सूचना प्राप्त होने/संज्ञान में आने पर यथासंभव उपरोक्त समयावधि में ही बदले गये हैं यद्यपि वर्ष 2020 में घोषित वैश्विक महामारी कोविड-19 के चलते केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर घोषित लोकडाउन, गाइडलाइन व वैश्विक महामारी कोविड-19 से उपभोक्ता व कार्मिकों की सुरक्षा के दृष्टिगत निर्धारित समय से अधिक समय लगा। साथ ही वर्ष 2022 में पिछले वर्षो से हुई अतिवृष्टि, आकाशीय बिजली एवं बरसात के लगातार लम्बे समय तक चलने के कारण अधिक मात्रा में वितरण ट्रांसफार्मर जले/खराब हुए थे, जिससे ट्रांसफार्मर बदलने में निर्धारित समय से अधिक समय लगा।

(2) जी हां। वर्तमान में खराब वितरण ट्रांसफार्मरों को रिपेयर करवाने हेतु रेट कान्ट्रेक्ट के अंतर्गत वितरण ट्रांसफार्मरों को रिपेयर करवाने का कार्य

(राज्य मंत्री, ऊर्जा)

प्रगति पर है जिससे रिपेयर किये गये वितरण ट्रांसफार्मर उपलब्ध हो रहे हैं एवं यथासंभव तय समयावधि में बदले जा रहे हैं।

सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने हेतु अनुदान

97. श्री कान्ति प्रसाद (थानागाजी): क्या ऊर्जा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में सौर ऊर्जा में अधिकतम विद्युत उत्पादन तथा न्यूनतम कीमत पर आम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिये क्या कोई कार्ययोजना प्रस्तावित है? यदि हां, तो क्या? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार द्वारा घरों में सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने हेतु अनुदान दिया जाता है? यदि हां, तो कितना? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश में सौर से विद्युत उत्पादन को प्रोत्साहित करने हेतु "राजस्थान सौर ऊर्जा नीति-2019" जारी की गई है। सौर ऊर्जा से अधिकतम विद्युत उत्पादन करने एवं न्यूनतम कीमत पर आम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए किये जा रहे कार्यों/प्रयासों का विवरण परिशिष्ट "अ" पर उपलब्ध है।

(2) जी हां। भारत सरकार के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा घरों की छतों पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने हेतु रूफटॉप सोलर योजना (फेज-II) के अन्तर्गत बेंचमार्क लागत या कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा पारदर्शी बोली के माध्यम से खोजी गई लागत, जो भी कम हो उस राशि पर 3 किलोवाट तक की क्षमता का सौर ऊर्जा सयंत्र स्थापित करने हेतु लागत का 40 प्रतिशत एवं 3 किलोवाट से अधिक व 10 किलोवाट तक की क्षमता का सौर ऊर्जा सयंत्र स्थापित करने हेतु लागत का 20 प्रतिशत अनुदान राशि दिये जाने का प्रावधान है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया।)

बाड़ी में नवीन 220 केवी ग्रिड सब-स्टेशन की स्थापना

98. श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): क्या ऊर्जा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि बजट घोषणा 2022-23 में बाड़ी स्थित 132 के.वी. ग्रिड सब-स्टेशन को 220 के.वी. ग्रिड सब-स्टेशन में क्रमोन्नत करने की घोषणा की गई थी? यदि हां, तो उक्त को क्रमोन्नत नहीं करने के क्या कारण हैं? क्या सरकार उक्त के स्थान पर बाड़ी में नवीन 220 के.वी. ग्रिड सब-स्टेशन स्वीकृत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी हां। 132 केवी ग्रिड सब-स्टेशन बाड़ी को 220 केवी ग्रिड सब-स्टेशन में क्रमोन्नत करने की घोषणा बजट 2022-23 में की गयी थी।

इसको क्रमोन्नत करने के लिए 3.5 हैक्टेयर भूमि की आवश्यकता है। पूर्व से स्थापित 132 केवी ग्रिड सब-स्टेशन बाड़ी के पास कोई भी सिवायचक/चरागाह की भूमि उपलब्ध नहीं है तथा 132 केवी ग्रिड सब-स्टेशन के निकटतम वन विभाग की भूमि है। अन्य निकटतम भूमि 01 किलोमीटर दूरी पर ग्राम पगुली में उपलब्ध है, जो कि वर्तमान 132 केवी ग्रिड सब-स्टेशन को क्रमोन्नत करने हेतु तकनीकी रूप से साध्य नहीं है।

बाड़ी में नवीन 220 केवी ग्रिड सब-स्टेशन बनाने का अन्य कोई प्रस्ताव वर्तमान में विचाराधीन नहीं है।

माण्डलगढ़ में संचालित आयुर्वेदिक औषधालय

99. श्री गोपाल लाल शर्मा (माण्डलगढ़): क्या आयुर्वेद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र माण्डलगढ़ में कुल कितने आयुर्वेदिक औषधालय संचालित हैं? उक्त में कितने पद स्वीकृत हैं व कितने पदों पर अधिकारी, कर्मचारी कार्यरत हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त आयुर्वेदिक औषधालयों में स्वीकृत स्टाफ का पदस्थापन करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार बन्द पड़े आयुर्वेदिक औषधालयों को पुन: प्रारंभ करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र माण्डलगढ़ में 33 आयुर्वेद औषधालय एवं 01 ब्लॉक आयुष चिकित्सालय संचालित है, जिसमें आयुर्वेद के साथ होम्योपैथी एवं यूनानी चिकित्सा सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। उक्त चिकित्सालय/औषधालय में चिकित्सक, नर्स/कम्पाउण्डर एवं परिचारक के स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों का पदवार विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) जी हां। रिक्त पदों को निम्नानुसार कार्यवाही की जाकर भरे जाने हैं:-

नर्स/कम्पाउण्डर- 704 कनिष्ठ आयुर्वेद नर्स/कम्पाउण्डर पदों में से 579 पदों पर नियुक्ति प्रदान की जा चुकी है। शेष 125 पद न्यायिक प्रक्रिया के कारण रोके गये हैं, जिसके पूर्ण होते ही नियमानुसार उक्त पदों को भरने की कार्यवाही की जा सकेगी।

(राज्य मंत्री, आयुर्वेद)

चिकित्साधिकारी- 639 आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों के पदों पर भर्ती हेतु वित्त विभाग से सहमति प्राप्त कर नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

परिचारक - रिक्त पदों पर भर्ती की कार्यवाही हेतु वित्त विभाग से स्वीकृति प्राप्त कर नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जा सकेगी।

(3) उक्त विधान सभा क्षेत्र में कोई भी चिकित्सालय/औषधालय बंद नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

बूंदी में राजकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय की स्थापना

100. श्री अशोक डोगरा (बूंदी): क्या तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या सरकार छात्रों की सुविधा हेतु बूंदी जिला मुख्यालय पर राजकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी नहीं। बूंदी जिला कोटा संभाग के अंतर्गत आता है। कोटा संभाग में राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा के संघटक अभियांत्रिकी महाविद्यालय कोटा, अभियांत्रिकी महाविद्यालय, बारां एवं अभियांत्रिकी महाविद्यालय, झालावाड़ में वर्ष 2022-23 में कुल 1,355 सीटों के विरूद्ध 577 प्रवेश ही हुए हैं एवं कोटा संभाग में राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा के सम्बद्ध तीन निजी अभियांत्रिकी महाविद्यालय संचालित हैं जिनमें वर्ष 2022-23 में कुल 830 सीटों के विरुद्ध 120 प्रवेश ही हुए हैं। विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

वर्तमान में बूंदी जिला मुख्यालय पर राजकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय खोलने का कोई प्रस्ताव विभाग में विचाराधीन नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

परिशिष्ट

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास व आवासन मंत्री) द्वारा आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2023-24 के सम्बन्ध में सदन पटल पर रखा गया अंश

40. प्रदेश में संस्कृत शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से -

I. बूंदी, बारां, झालावाड़, करौली, भीलवाड़ा, नागौर, टोंक, पाली, सिरोही, जालोर, जैसलमेर, बाड़मेर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, श्रीगंगानगर एवं हनुमानगढ़ जिलों में संस्कृत महाविद्यालय शुरू किये जाएंगे। इससे समस्त जिलों में संस्कृत महाविद्यालय स्थापित हो जाएंगे।

II. साबूवाना (टिब्बी)-हनुमानगढ़ में संस्कृत महाविद्यालय एवं मारवाड़ (मुण्डवा)-नागौर में शास्त्री स्तर का राजकीय महाविद्यालय खोला जायेगा। साथ ही, राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय, हमीरगढ़-भीलवाड़ा को शास्त्री स्तर पर क्रमोन्नत किया जायेगा।

III. संस्कृत महाविद्यालयों एवं विद्यालयों के नवीन भवन, अतिरिक्त कक्षा कक्ष के निर्माण तथा जीर्णोद्धार हेतु लगभग 20 करोड़ रुपये व्यय किये जाएंगे।